नई दिल्ली, गुरुवार
25 जुलाई, 2024
राजधानी
मूल्य ₹ 5.00
पृष्ठ 16+4=20

दैनिक जागरण

www.jagran.com
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

राजधानी में रेलवे से जुड़ीं परियोजनाओं पर खर्च होंगे 2,582 करोड़ 7

नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में पदक के सबसे बड़े दावेदार 14

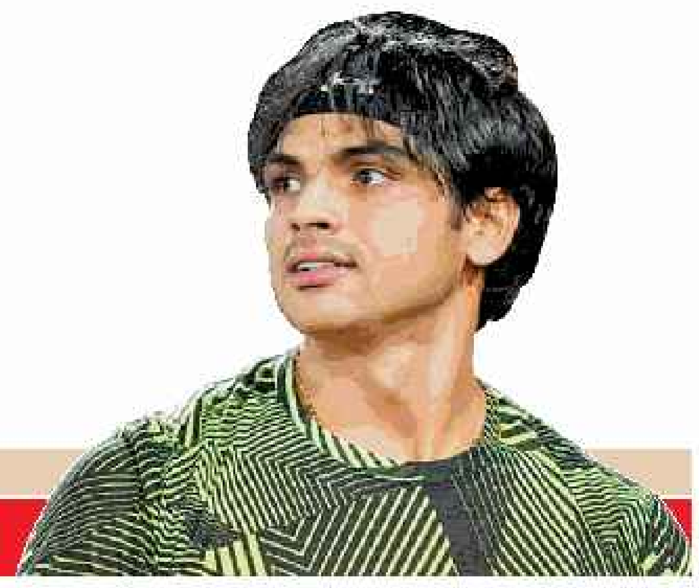

दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही ध्वस्त कर देगी भारत की `एडी-1'

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने बढ़ाया एक और अहम कदम

- डीआरडीओ ने ओडिशा में समुद्र तट से किया सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने दी बधाई
- अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है यह इंटरसेप्टर मिसाइल

ओडिशा के चांदीपुर समुद्र तट पर परीक्षण के दौरान उड़ान भरतीं पृथ्वी 2 और एडी 1 मिसाइलें ● डीआरडीओ

भारत की मिसाइल क्षमता

मिसाइल का नाम	मारक क्षमता (किलोमीटर में)
अग्नि- 1	1,200
अग्नि- 2	3,500
अग्नि- 3	5,000
अग्नि-4	4,000
अग्नि-5	8,000
प्रहार	150
पृथ्वी- 1	150
पृथ्वी- 2	350
धनुष	400
ब्रम्होस	500
निर्भय	1,000
शौर्य	3,500

नोट: कुछ मिसाइलें सेना में शामिल हैं और कुछ के परीक्षण हो रहे हैं।

जासं, बालेश्वर : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बुधवार को ओडिशा में समुद्र तट से शक्तिशाली इंटरसेप्टर मिसाइल एडी-1 (एयर डिफेंस) का सफल परीक्षण कर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और अहम कदम आगे बढ़ाया। यह परीक्षण करने के लिए पहले चांदीपुर में अब्दुल कलाम द्वीप स्थित लांच पैड थ्री से पृथ्वी-2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट के रूप में दागी गई। इसके चार मिनट बाद ही भद्रक जिले के धामरा में स्थित परीक्षण केंद्र से इंटरसेप्टर मिसाइल एडी-1 लांच की गई जिसने टारगेट बनी पृथ्वी-2 मिसाइल को सफलतापूर्वक मार गिराया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए डीआरडीओ की सराहना की और विज्ञानियों की टीम को बधाई दी है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डा. समीर वी कामत ने भी पूरी टीम को बधाई दी है। एडी-1 समुद्र आधारित एंडो-एटमास्फेरिक बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो दुश्मन की पांच हजार किलोमीटर रेंज वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (आइसीबीएम) को मार गिराने में सक्षम है। यह मिसाइल दुश्मन की मिसाइल को भारत की धरती को छूने से पहले ही आसमान में नष्ट कर देगी।

तत्काल मिला अलर्ट: सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पृथ्वी-2 को बैलिस्टिक टारगेट मिसाइल बनाकर शाम 4.20 बजे लांच किया गया। इसे जमीन और समुद्र में तैनात रक्षा प्रणाली ने तत्काल पहचाना और एडी-1 इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली को अलर्ट किया। 4.24 बजे एडी-1 मिसाइल लांच की गई। यह परीक्षण युद्धक हथियार प्रणाली से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरा, जिनमें लंबी दूरी के सेंसर और संचार प्रणाली भी शामिल है। इस परीक्षण में मिसाइल से जुड़ा डाटा के परीक्षण के लिए युद्धक पोत सहित विभिन्न स्थानों पर ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे।

स्वदेशी तकनीक से किया गया लैस: एडी-1 मिसाइल का लक्ष्य तक सटीक रूप से मार्गदर्शन करने के लिए इसे स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली से लैस किया गया है। इसकी गति 5,367 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंटरसेप्टर एडी-1 को अंतरमहाद्वीपीय मिसाइलों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से ही बनाया गया है। ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों से निबटने में अपनी बढ़ती क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। एडी-1 के परीक्षण के लिए चांदीपुर के आसपास के 10 गांवों के 10,581 लोगों को अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया गया था।

संपादकीय

बजट से आगे की चुनौती: बजट में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर कई अच्छी पहल हुई हैं, लेकिन उनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि उन पर अमल कैसे होता है। **जीएन वाजपेयी** का विश्लेषण।

नौकरशाही की जकड़न से निकले शिक्षा: जो उच्च शैक्षिक पद वर्ष 1975-80 तक शिक्षविदों के पास होते थे, अब उन सब पर नौकरशाह काबिज हैं। **जगमोहन सिंह राजपूत** का दृष्टिकोण। ● पेज 10

जागरण विशेष

पर्यावरण प्रहरी बन विकास को गति देता सीमावर्ती गांव

उत्तरकाशी: चीन सीमा के निकट वाइब्रेंट विलेज में शामिल उत्तरकाशी जिले का झालागांव पर्यावरण प्रहरी बनकर सतत विकास को भी गति दे रहा है। ● पेज 14

अंदर पढ़ें

काठमांडू में विमान दुर्घटना में 18 लोगों की मौत

काठमांडू: नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार को एक निजी कंपनी का विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक बच्चे समेत 18 लोगों की मौत गई है। विमान का पायलट गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विमान में चालक दल के दो सदस्य समेत 19 लोग सवार थे। ● पेज 16

विश्वास.News

आप नेता संजय सिंह का एडिटेड वीडियो प्रसारित ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज 8

लोकसभा में सरकार ने दिखाया विकास का दूरदर्शी लक्ष्य, तीर छोड़ता रहा विपक्ष

लोकसभा में मानसून सत्र के बीच बुधवार को कांग्रेस सदस्य कुमारी सैलजा ने आम बजट 2024 की कई खामियां गिनाईं ● प्रेट्र

लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बोलते भाजपा सदस्य बिप्लव कुमार देब ● एएनआइ

- बजट पर चर्चा के दौरान बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले पैकेज को लेकर हमलावर रहे विपक्षी दलों के नेता
- भाजपा सदस्यों ने किया पलटवार, बिप्लव बोले- 400 पार करेंगे और 2047 तक सत्ता में रहेगा राजग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पूरा विपक्षी खेमा लगभग समान लकीर पर चला। राजग सरकार को घेरने के लिए आरोप तो कई लगाए, लेकिन सबसे अधिक जोर इसी आरोप पर रहा कि इस बजट के माध्यम से सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देकर अपने गठबंधन सहयोगियों को साधने का प्रयास किया है। हालांकि, सरकार की ओर से भी उसी धार के साथ पलटवार किया गया। सत्ता पक्ष ने सरकार की योजनाएं व उपलब्धियां गिनाते हुए विकास का दूरदर्शी लक्ष्य दिखाया और दावा किया कि 400 सीटें भी पार करेंगे और 2047 तक राजग की सरकार भी रहेगी।

विपक्ष की ओर से बजट पर चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस सदस्य कुमारी सैलजा ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने बजट में तमाम खामियां गिनाते हुए तंज कसा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है। उनका इशारा बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिए जाने को लेकर था। साथ ही प्रश्न भी खड़े किए कि हरियाणा को कुछ क्यों नहीं दिया गया? आरोपों की इसी धार को विपक्षी खेमे के अन्य नेताओं ने भी आगे बढ़ाया। कांग्रेस के शशि थरूर ने सरकार पर योजनाओं के नाम बदलने को लेकर तंज कसा कि आयुष्मान वेलनेस सेंटर का नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। भाजपा को उत्तर प्रदेश से सबक लेना चाहिए कि वह मंदिर का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करे।

सरकार की ओर से भाजपा सांसदों ने अपने तरीके से विपक्ष को जवाब दिया। बिप्लव कुमार देब ने कांग्रेस पर तंज कसा-कांग्रेस कह रही है कि भाजपा 400 पार नहीं कर सकी, जबकि खुद कांग्रेस लगातार तीन चुनावों को मिलाकर भी 240 सीटों का आंकड़ा नहीं छू सकी। उन्होंने दावा किया-हम 400 पार करेंगे और 2047 तक राजग सरकार भी रहेगी, जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उन्होंने कहा-कांग्रेस की कुमारी सैलजा ने इसे कुर्सी बचाओ बजट नाम दिया है। इसका मतलब है कि उन्हें बिहार और आंध्र प्रदेश की जरूरत नहीं है। उन्होंने संविधान के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। कहा-जिस कांग्रेस ने सिर्फ एक व्यक्ति इंदिरा गांधी के लिए देश पर आपातकाल थोपा, 70 बार संविधान में संशोधन किए, वह आज संविधान की प्रति लेकर घूम रही है। इसी तरह भर्तृहरि महताब ने कहा कि पहली बार किसी केंद्र सरकार ने विभिन्न प्राकृतिक और मानव संसाधन संपन्न पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के विकास में नीतिगत हस्तक्षेप किया है। उन्होंने जवाब दिया-विपक्षी दलों ने कहा है कि ओडिशा के लिए बजट में कोई घोषणा नहीं है। उन्हें पूर्वोदय योजना की घोषणा देखनी चाहिए, जिसमें राज्य के चहुंमुखी विकास की बात कही गई है। ये पांच राज्य विकसित भारत के इंजन साबित होंगे। विपक्ष के आरोप निराधार हैं कि इस बजट पर लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर है, बल्कि इसमें मोदी सरकार का दूरदर्शी सोच दिखाई देता है।

विशेष आयोजन >> पेज 12,13
संबंधित >> पेज 7,15 व संपादकीय

जम्मू-कश्मीर में आतंकी जेल जाएंगे या फिर जहन्नुम

- केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में किया एलान
- कहा-मोदी सरकार की आतंकवाद पर जीरो टालरेंस की है नीति

राज्यसभा में बुधवार को बोलते केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ● एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर की गुलाबी तस्वीर खींचते हुए कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश में शांति बहाल हो चुकी है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि पिछले साल ही क्षेत्र में दो करोड़ 11 हजार पर्यटक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हाल में हुईं आतंकी गतिविधियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। वह अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टालरेंस की नीति पर चलती है।

केंद्रीय मंत्री राय ने बुधवार को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी के एक सवाल के जवाब में कहा, 'मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आतंकी या तो जेल में होंगे या जहन्नुम जाएंगे। हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे।' राय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में 28 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के भी कुछ अफसर बलिदान हुए हैं, जोकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा बलों ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक करीब 900 आतंकियों को मार गिराया है। वर्ष 2004-2014 के बीच जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की 7,217 घटनाएं हुईं थीं। जबकि इसी अवधि में 2,892 आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की जानें गईं थीं। लेकिन अब जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 69 प्रतिशत की कमी आई है। केंद्र शासित प्रदेश के लोग अब शांतिपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं और यहां सुरक्षा की पूरी गारंटी है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में पिछले तीन सालों में पर्यटन क्षेत्र में सालाना औसत 15.13 प्रतिशत विकास दर में इजाफा हुआ है। यहां इस साल जनवरी से जून के बीच कुल 1,08,41,009 पर्यटक पहुंचे। यह कोरोना काल के बाद से पर्यटकों की रिकार्ड आमद है। संबंधित >> पेज 16

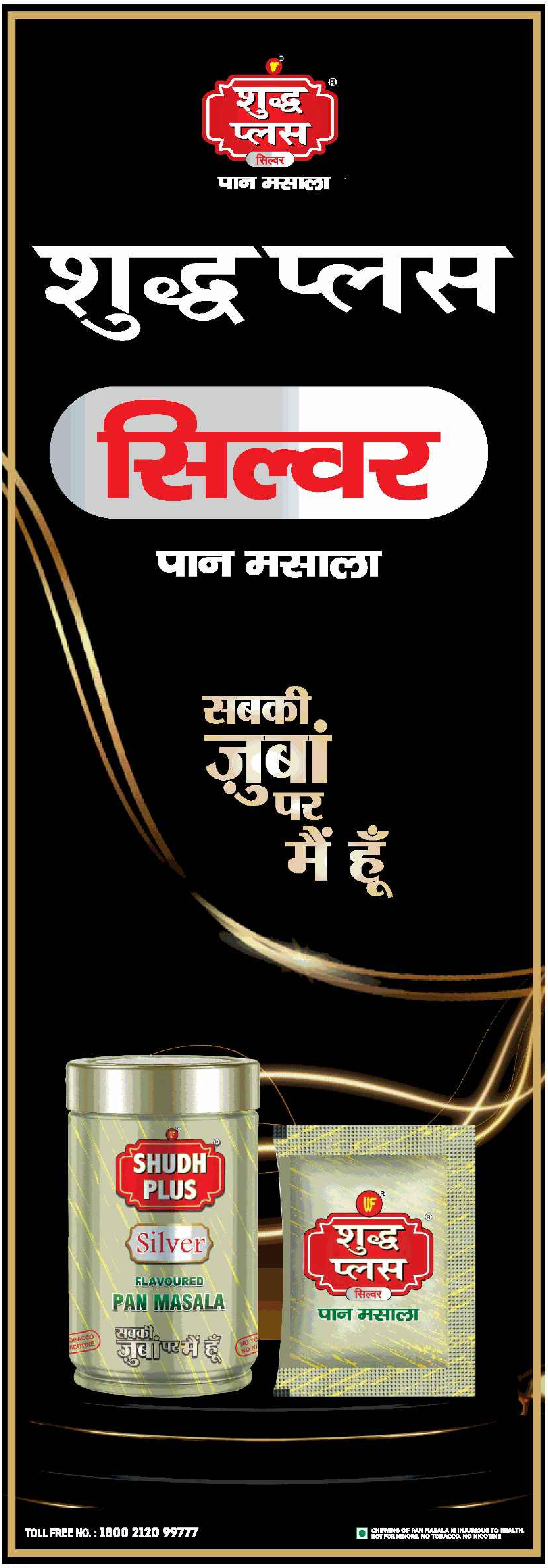

****

एयर क्वालिटी इंडेक्स

बुलंदशहर		
आज का अनुमान	73	संतोषजनक
बुधवार	65	संतोषजनक
शादीपुर		
आज का अनुमान	71	संतोषजनक
बुधवार	63	संतोषजनक
मंदिर मार्ग		
आज का अनुमान	80	संतोषजनक
बुधवार	71	संतोषजनक
नरेला		
आज का अनुमान	128	मध्यम
बुधवार	120	मध्यम
बवाना		
आज का अनुमान	88	संतोषजनक
बुधवार	79	संतोषजनक
गुरुग्राम		
आज का अनुमान	97	संतोषजनक
बुधवार	88	संतोषजनक
गाजियाबाद		
आज का अनुमान	96	संतोषजनक
बुधवार	87	संतोषजनक
ग्रेटर नोएडा		
आज का अनुमान	144	मध्यम
बुधवार	134	मध्यम
फरीदाबाद		
आज का अनुमान	127	मध्यम
बुधवार	118	मध्यम
नोएडा		
आज का अनुमान	75	संतोषजनक
बुधवार	76	संतोषजनक

0	50	अच्छा
51	100	संतोषजनक
101	200	मध्यम
201	300	खराब
301	400	बहुत खराब
401	500	गंभीर
501 से आगे		आपातकालीन

भाजपा सांसदों ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात

भाजपा के दिल्ली के सभी सातों सांसदों (बाएं से दाएं) योगेंद्र चंदोलिया, प्रवीन खंडेलवाल, रामवीर सिंह बिधूड़ी, मनोज तिवारी, हर्ष मल्होत्रा, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें संसद की कार्यवाही में गंभीरता से भागीदारी करने की सलाह दी। कहा कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुनने और हल कराने का प्रयास करना चाहिए ● सौजन्यः एक्स

रील बनाने पर 'स्पाइडरमैन' का चालान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: द्वारका की ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी के बोनट पर बैठकर रील बनवाते स्पाइडरमैन की पोशाक पहने व्यक्ति व कार चालक को पकड़ा है। पुलिस को एक्स पर इन दोनों युवकों के खिलाफ शिकायत मिली थी। जिसपर कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने इनका 26 हजार रुपये का चालान किया है।

ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि द्वारका की सड़कों पर स्कार्पियो कार के बोनट पर स्पाइडरमैन की पोशाक पहने एक व्यक्ति के रील बनाने को लेकर शिकायत मिली थी। उक्त व्यक्ति इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसिद्ध होने के लिए रील बनवा रहा था। इस दौरान रील बना रहा चालक सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिससे सड़क पर अन्य गाड़ी चालकों को परेशानी हो रही थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक सर्किल मोबाइल अभियोजन टीम के साथ-साथ स्थानीय पुलिस की टीम ने स्कार्पियो कार (नंबर डीएल 9सी बीसी3398) का पता लगाया और द्वारका के रामफल चौक के पास दोनों को ढूंढ निकाला। स्पाइडरमैन की पोशाक पहने व्यक्ति की पहचान नजफगढ़ के आदित्य व चालक की पहचान महावीर एन्क्लेव के गौरव सिंह के रूप में हुई। वाहन के मालिक और चालक पर खतरनाक ड्राइविंग, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने और सीटबेल्ट न पहनने के लिए मुकदमा किया गया है, जिसमें अधिकतम 26 हजार रुपये का जुर्माना या कारावास या दोनों हो सकते हैं। इसी वर्ष अप्रैल में भी इसी आरोपित के खिलाफ यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई थी।

इंटरनेट मीडिया में प्रसिद्ध होने के लिए रील बनवा रहा था युवक ● वीडियो ग्रैब

रिज में पेड़ कटाई का मुद्दा सीजेआइ के पास

नई दिल्ली, प्रेट्र: दिल्ली रिज वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के मामले में नया पेंच सामने आया है। दरअसल, पेड़ों की कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न पीठों के समक्ष दो अलग-अलग अवमानना के मामले लंबित हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह न्यायिक औचित्य में विश्वास करता है और नहीं चाहता कि कोई विरोधाभासी आदेश पारित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि विरोधाभासी आदेशों से बचने के लिए यह उचित होगा कि रिज से संबंधित मामलों की सुनवाई एक ही पीठ द्वारा की जाए।

शीर्ष न्यायालय ने आश्चर्य जताया कि जब एक पीठ के पास पहले से ही मामला था तो दूसरी पीठ को इस पर गौर करना चाहिए था। अब सीजीआइ तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई कौन सी पीठ करे।

भलस्वा की डेरियां चार सप्ताह में हों स्थानांतरित

हाई कोर्ट ने कहा- चार हफ्ते में मंजूरी प्रक्रिया पूरी कर जरूरी कदम उठाए डूसिब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: चार सप्ताह के अंदर भलस्वा से सभी डेरियों को घोघा डेरी कालोनी में स्थानांतरित करने का आदेश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में सभी डेरी कालोनियों से अनधिकृत निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। भलस्वा और गाजीपुर डेरियों के पास दुधारू मवेशियों को कचरा खाने से रोकने के लिए कार्रवाई करने में एमसीडी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों की अक्षमता को देखते हुए अदालत ने भलस्वा डेरी कालोनी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि इस दलील में दम है कि भलस्वा डेरी कालोनी को स्थानांतरित करने के लिए 30 एकड़ भूमि की जरूरत है और घोघा डेरी कालोनी में 83 एकड़ की अप्रयुक्त भूमि उपलब्ध है। ऐसे में भलस्वा की सभी डेरियों को एमसीडी समेत अन्य एजेंसियों को घोघा कालोनी स्थानांतरित करने का निर्देश देते हैं।

पीठ ने कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब), दिल्ली सरकार मंजूरी की प्रक्रिया को पूरा करके चार सप्ताह में इसके लिए जरूरी कदम उठाए। डेरी कालोनियों में अनधिकृत निर्माण के संबंध में अदालत ने एमसीडी और डूसिब को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मदनपुर खादर और घोघा डेरी कालोनी सहित सभी डेरी कालोनियों में सभी अनधिकृत निर्माण हटा दिए जाएं। अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि भूखंड को अपनी मूल स्थिति में वापस लाया जाए, ताकि इन कालोनियों में मवेशियों के लिए आवंटन किया जा सके। अदालत ने उक्त आदेश दिल्ली में डेरियों की स्थिति के संबंध में याचिकाकर्ता सुनयना सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले में पूर्व में अदालत को सूचित किया गया था कि दिल्ली में सभी नौ नामित डेरी कालोनियों की स्थित खराब है।

डेरी कालोनियों में सैलून, शोरूम व जिम पर जताई हैरानी

हाई कोर्ट ने पेश की गई तस्वीरों पर गौर करते हुए कहा कि कुछ डेरी कालोनियों में बड़े पैमाने पर सैलून, शोरूम, जिम और इंटरनेट कैफे का अनधिकृत निर्माण हुआ है। कालोनियों का चरित्र अब डेरी कालोनी का नहीं रह गया है। वहां वाणिज्यिक शोरूम चल रहे हैं और कई मंजिलों तक ऊंची इमारतें बनाई गई हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि इन कालोनियों में कोई चरागाह नहीं है और डेरी भूखंड आवंटियों द्वारा रखे गए मवेशियों के लिए भूखंड के भीतर कोई जगह नहीं है। मदनपुर खादर डेरी के संबंध में पीठ ने राय दी कि डेरी भूखंड मालिकों द्वारा सभी कानूनों का उल्लंघन करके वहां मवेशियों को रखा जा रहा है।

'लोक अभियोजकों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली में लोक अभियोजकों (पीपी) की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कई निर्देश पारित किए हैं। स्वतः संज्ञान लेकर मामले पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के सभी जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पीपी को कार्यालय स्थान सहित उचित तकनीकी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि पीपी को हर साल 10 हजार रुपये ड्रेस भत्ता दिया जाए। पीपी को अदालत में पोशाक में उपस्थित होना होता है।

SHRI GORAKSHNATH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE
Arogya Dham, Balapar Road, Sonbarsa, Gorakhpur-273007

MEDICAL FACULTY ENROLMENT

Applications are invited for the filling up the following posts at Shri Gorakshnath Medical College Hospital and Research Centre, Gorakhpur running under Mahayogi Gorakhnath university Gorakhpur.

Sr. No.	Department	Professor	Associate Professor	Assistant Professor	S R	Tutor
1.	Anatomy	01	01	02	01	03
2.	Physiology	01	01	01	01	02
3.	Biochemistry	01	01	01	01	02

The appointment will be made under the prescribed qualifications by National Medical Commission (NMC) and University Rules. Interested candidates may send their application with CV by email to deputyregistrar@mgug.ac.in or WhatsApp (9415266014) till 05th August, 2024.

Registrar

MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, MORADABAD

e-TENDER NOTICE
"REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR SELECTION OF AN AGENCY FOR SETTING UP A PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) FOR MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY, MORADABAD (U.P.)"
e-TENDER ID No.- 2024_MDA_940850_1
e-TENDER REFERENCE No.- 05/MDA/CE/2024-25 Dated: 24.07.2024
Online e-TENDERS are invited from Consultant Companies "FOR SELECTION OF AN AGENCY FOR SETTING UP A PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)" FOR MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD as per e-Tender published on https://etender.up.nic.in The Technical e-TENDER shall be opened as per e-Tender dates or afterwards. The details of submission of e-TENDER are available in the RFP document uploaded on the https://etender.up.nic.in and the Moradabad Development Authority website https://mdamoradabad.gov.in Moradabad Development Authority reserves the right to cancel any or all the e-TENDER or annul the Bidding process without assigning any reason thereof.

Secretary,
Moradabad Development Authority,
New Moradabad, Uttar Pradesh- 244001
Email: mdamoradabad2019@gmail.com
Phone: 0591 2796666

पेड़ों की कटाई के खिलाफ याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कारिडोर निर्माण के कारण पेड़ों की कटाई के खिलाफ सिद्धार्थ एक्सटेंशन के निवासियों की याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) समेत अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई चार अक्टूबर को होगी। याचिकाकर्ता सिद्धार्थ एक्सटेंशन पाकेट सी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दायर कर कहा कि 82.15 किमी की इस परियोजना के लिए 40 पेड़ों को काटा जाना है।

हरियाणा सरकार — **निविदा सूचना**

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधिकरण का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खोलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रुपये में	बोर्ड/निगम/प्राधिकरण की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/संपर्क विवरण/ ईमेल
1	मार्केट कमेटी पलवल	फल एवं सब्जी मंडी और अनाज मंडी और बाजार समिति पलवल कार्यालय के भीतर सफाई, झाड़ू लगाना और अनाज मंडी और सब्जी मंडी क्षेत्र के भीतर नालियों की सफाई और अनाज मंडी और सब्जी मंडी पलवल के पीछे की ओर सेवा सड़कों की सफाई और झाड़ू लगाना, सप्ताह में हर दिन। और शहर के बाहर (नगर परिषद पलवल द्वारा तय स्थान) अपने स्वयं के ट्रैक्टर - ट्रॉली / डंपर द्वारा अपने जोखिम पर दैनिक डंप, कचरा, कीचड़ और धूल को साफ किया।	23.07.2024 29.07.2024	EMD 20420/-	https://etenders.hry.nic.in	8059133494 mcpalwal@rediffmail.com

आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

PRDH-13/2025/80/28161/I/67/7

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

यातायात निर्देशिका

22.07.2024 से 02.08.2024 तक

काँवड़ श्रद्धालुओं का आवागमन

हर साल हिंदू चंद्र माह "श्रावण" के दौरान, भक्त (कांवड़िए) "श्रावण शिवरात्रि" पर शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए गोमुख, गंगोत्री धाम और हरिद्वार से पवित्र "गंगा जल" लेकर पैदल यात्रा करते हैं। पवित्र कांवड़ यात्रा सावन (श्रावण माह) के पहले दिन से शुरू होती है, जो इस वर्ष को दिनांक 22.07.2024 से शुरू हो गई है। इसका समापन चतुर्दशी तिथि यानी दिनांक 02.08.2024 को होगा क्योंकि इसी दिन भगवान शिव को पवित्र गंगा जल चढ़ाया जाएगा। इस यात्रा के दौरान कांवड़िए बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचते हैं और इन्हीं में से कुछ दिल्ली की सीमाओं से होते हुए हरियाणा और राजस्थान जाते हैं। इस वर्ष कांवड़ियों की अपेक्षित संख्या लगभग 15-20 लाख है।

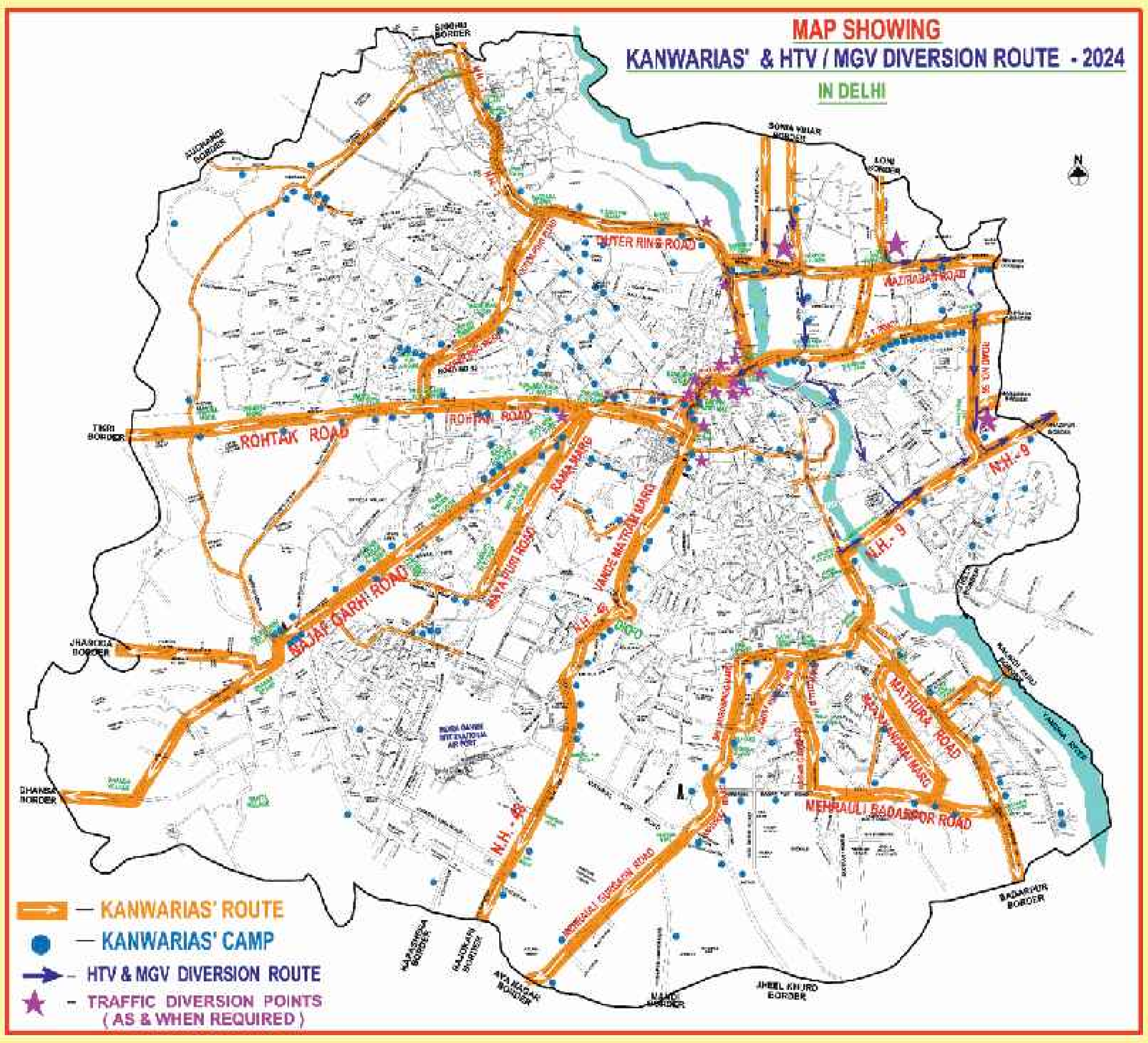

श्रद्धालु कांवड़ लेकर निम्नलिखित मार्गों से गुजरेंगे:

- अप्सरा बॉर्डर - शाहदरा फ्लाईओवर - सीलमपुर 'टी' प्वाइंट - आईएसबीटी फ्लाईओवर बुलेवार्ड रोड - रानी झांसी रोड - फैज रोड - अपर रिज रोड - धौला कुआं - एनएच-8 और हरियाणा के लिए रजोकरी बॉर्डर से बाहर निकलें।
- भोपुरा बॉर्डर - वजीराबाद रोड - लोनी फ्लाईओवर - गोकुलपुरी 'टी' प्वाइंट - 66 फुटा रोड - सीलमपुर 'टी' प्वाइंट - एनएच1 और आगे नए आईएसबीटी ब्रिज की ओर।
- यूपी से लोनी बॉर्डर से लोनी फ्लाईओवर तक प्रवेश/निकास या यूपी से सोनिया विहार बॉर्डर - पुस्ता रोड - खजूरी फ्लाईओवर - वजीराबाद रोड से प्रवेश/निकास।
- भोपुरा बॉर्डर - वजीराबाद रोड - वजीराबाद ब्रिज - बाहरी रिंग रोड - मुकरबा चौक - एनएच 1 और सिंघु बॉर्डर या मुकरबा चौक से निकास/प्रवेश - एनएच 1 - बवाना रोड और औचंदी बॉर्डर या मधुबन चौक - पीरागढ़ी से निकास/प्रवेश और निकास/प्रवेश टिकरी बॉर्डर से हरियाणा के लिए।
- महाराजपुर बॉर्डर, रोड नंबर 56, गाजीपुर बॉर्डर - एनएच 24 - रिंगरोड - मथुरा रोड और हरियाणा के लिए बदरपुर बॉर्डर से निकास।
- कालिंदी कुंज - मथुरा रोड - बदरपुर बॉर्डर।
- कालिंदी कुंज - मथुरा रोड - मोदी मिल - मां आनंद माई मार्ग - एम.बी. रोड।
- न्यू रोहतक रोड (जखीरा टी-प्वाइंट से टिकरी बॉर्डर तक)।
- नजफगढ़ रोड (जखीरा से नजफगढ़ तक)।
- रोहतक रोड जखीरा से मादीपुर से पीरागढ़ी चौक से नांगलोई चौक से मुंडका से टिकरी बॉर्डर तक।
- नजफगढ़ रोड - जखीरा से उत्तम नगर तक, नजफगढ़ फिरनी रोड से झारोदा बॉर्डर तक।
- आउटर रिंगरोड - मधुबन चौक से पीरागढ़ी चौक से केशोपुर मंडी से जिला केंद्र जनकपुरी तक।
- देव प्रकाश शास्त्री मार्ग - खन्नपुरी चौक से लोहा मंडी तक।

भारी भीड़ वाले दिनों के दौरान डायवर्जन योजना:

- उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भारी परिवहन वाहनों (एचटीवी) को मोहन नगर से एनएच-24 की ओर मोड़ दिया जाएगा और ऐसे किसी भी यातायात को भोपुरा के माध्यम से वजीराबाद रोड और/या अप्सरा बॉर्डर के माध्यम से जीटी रोड की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सिटी बसों को छोड़कर भारी परिवहन वाहनों (एचटीवी) को जीटी रोड पर शाहदरा और वजीराबाद रोड की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- आउटर रिंग रोड पर जीटी करनाल रोड से आने वाली सिटी बसों को छोड़कर भारी वाणिज्यिक परिवहन वाहनों को सीधे एनएच -24 की ओर मोड़ दिया जाएगा और उन्हें वजीराबाद रोड और जीटी रोड पर शाहदरा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- लोनी रोड (शाहदरा की ओर) से आने वाली सिटी बसों को छोड़कर भारी वाणिज्यिक परिवहन को बाहरी रिंग रोड से बाहर निकलने के लिए वजीराबाद रोड पर डायवर्ट किया जाएगा।
- सोनिया विहार, पीटीएस वजीराबाद पुस्ता, पुस्ता रोड जैसे आंतरिक क्षेत्र से आने वाली सिटी बसों को छोड़कर भारी वाणिज्यिक परिवहन को एनएच -24 लेने के लिए वजीराबाद रोड के माध्यम से बाहरी रिंग रोड की ओर मोड़ दिया जाएगा।

इन दिनों में, कांवड़ियों की आवाजाही और सड़क किनारे "कांवड़िया शिविर" स्थापित होने के कारण, कई स्थानों पर यातायात की भीड़/रुकावट का अनुभव होता है। आमतौर पर नजफगढ़ फिरनी, रोहतक रोड, पंखा रोड, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नांगलोई-नजफगढ़ रोड, आउटर रिंग रोड, रानी झांसी रोड पर बर्फ खाना चौक से फायर स्टेशन, बुलेवार्ड रोड और आजाद मार्केट चौक, गोकुल पुरी फ्लाई ओवर, 66 फुटा रोड, मौजपुर चौक, बदरपुर टी पॉइंट, मथुरा रोड पर ट्रैफिक अत्यधिक होता है। इसी तरह, एनएच-08 पर धौला कुआं मेट्रो स्टेशन से रजोकरी बॉर्डर तक यातायात भीड़ का अनुभव होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अप्सरा बॉर्डर और महाराजपुर बॉर्डर से गाजीपुर की ओर जाने वाले वाहनों के यातायात को डायवर्ट करने के कारण एनएच-24 पर भी भीड़भाड़ रहेगी।

मोटर चालकों और सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा और देरी से बचने के लिए अपने आवागमन की योजना पहले से बनाने की सलाह दी जाती है।

इन महत्वपूर्ण सड़कों और चौराहों के अलावा, पूरी दिल्ली में कई स्थानों पर कांवड़ियों की आवाजाही कम संख्या में देखी जाती है।

दिल्ली यातायात पुलिस ने कांवड़ियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की आवाजाही को अलग-अलग करने और आम जनता और श्रद्धालुओं की असुविधा कम करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं और सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात नियमों का पालन करने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। कांवड़िया आवागमन की इस अवधि के दौरान, यातायात उल्लंघन की जांच मौके पर ही चालान द्वारा की जाएगी और उल्लंघन की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की जाएगी जिसके बाद चालानी कार्यवाही की जाएगी।

यातायात निर्देशिका के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

आम जनता और वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें और सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और निम्न माध्यमों से अपडेट रहें

https://traffic.delhipolice.gov.in https://www.facebook.com/dtptraffic https://twitter.com/dtptraffic https://www.instagram.com/dtptraffic 8750871493

ट्रैफिक प्रहरी बनें — Google Play या App Store से ऐप डाउनलोड करें — 24 घंटे ट्रैफिक हेल्पलाइन: 011-25844444/1095 — तुरंत पुलिस सहायता पाने के लिए 112 पर कॉल करें।

DP/9884/2024

****

नई दिल्ली, गुरुवार
25 जुलाई, 2024
राजधानी
मूल्य ₹ 5.00
पृष्ठ 16+4=20

दैनिक जागरण

www.jagran.com
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

पीयूसी जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी दिल्ली सरकार 7
परीक्षा प्रक्रिया को फ्राड बताने पर माफी मांगें राहुल: रविशंकर प्रसाद 15

सुरक्षा संबंधों को और मजबूत बनाएंगे भारत व ब्रिटेन • पेज15

jagran.com वेबसाइट पर पढ़ें

क्या है टेबल-टापरनवे
नेपाल विमान हादसे के बाद सुर्खियों में टेबल-टाप रनवे, क्या है ये और भारत में कितने रनवे ऐसे हैं?

दैनिक जागरण सप्तरंग
तकनीक की दुनिया का

अधिक सिम न बन जाए समस्या!
पेमेंट फंसने पर क्या करें उपाय
• जागरण सिटी

शंभू बार्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

पंजाव व हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से वार्ता के लिए स्वतंत्र समिति गठित करने का दिया प्रस्ताव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शंभू बार्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच कायम अवरोध खत्म करने के लिए स्वतंत्र वार्ताकारों की समिति बनाकर मसले को हल करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने समिति के गठन के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार से एक हफ्ते में नाम सुझाने को कहा है, यह भी कहा कि अगर सरकार नाम नहीं बताएंगी तो कोर्ट स्वयं तय कर लेगा। मामले को अगले सप्ताह सुनवाई पर लगाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से फिलहाल शंभू बार्डर पर यथास्थिति कायम रखने को कहा। जिसका अर्थ है कि अभी शंभू बार्डर बंद ही रहेगा। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से यह भी कहा कि वे शंभू बार्डर से चरणबद्ध ढंग से बैरिकेडिंग हटाने के बारे में भी सुझाव दें।

- दोनों राज्यों से नाम सुझाने को कहा, अन्यथा अदालत खुद तय करेगी
- कहा- किसानों व सरकार में विश्वास की कमी, तटस्थ लोगों के जरिये करें बात
- हरियाणा ने एक हफ्ते में बार्डर खोलने के हाई कोर्ट के आदेश को दी है चुनौती

ये आदेश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध दाखिल हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। हाई कोर्ट ने एक सप्ताह में शंभू बार्डर खोलने का आदेश दिया था। बुधवार को हरियाणा सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 500-600 ट्रैक्टर ट्राली, जिन्हें बख्तरबंद टैंकों की तरह माडिफाइ किया गया है, शंभू बार्डर पर मौजूद हैं। अगर उन्हें दिल्ली आने की इजाजत दी गई तो दिल्ली में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। इन दलीलों पर कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य सरकार ट्रैक्टर ट्रालियों को इजाजत दिए बगैर स्वयं से बार्डर क्यों नहीं खोलती। पीठ ने किसानों के साथ वार्ता कर मसला हल करने के प्रयास किए जाने पर जोर दिया। सरकार से कहा कि आपको मुद्दे का हल निकालना चाहिए। सालिसिटर जनरल का कहना था कि वे दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन टैंकर और जेसीबी से नहीं आ सकते। पीठ ने कहा कि यहां सरकार और किसानों के बीच विश्वास की कमी है। पूछा कि क्या आपने किसानों से बातचीत की कोई पहल की है। आपके मंत्री स्थानीय मुद्दों को समझे बिना किसानों के पास जाते हैं। आपके पास कोई तटस्थ लोग क्यों नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि विश्वास बहाली के उपाय करने होंगे। कोर्ट के सुझाव पर मेहता ने कहा कि किसी सोते हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का स्वांग कर रहा हो उसे नहीं जगाया जा सकता। पिछली बार का 2020-21 का प्रदर्शन तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध था, लेकिन वे तो वापस लिए जा चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट का विचार है कि कुछ स्वतंत्र तटस्थ व्यक्तियों द्वारा किसानों से वार्ता की जाए, उनकी बात समझी जाए और उन्हें भी बताया जाए कि यह मांग ठीक है और यह ठीक नहीं है।

युद्ध टैंक की तरह माडिफाइ किए गए हैं ट्रैक्टर >> पेज 11
संबंधित >> पेज 11

पूजा खेडकर नहीं पहुंचीं अकादमी, बढ़ेंगी मुश्किलें

देहरादून: नियुक्ति फर्जीवाड़े में घिरीं वर्ष 2023 बैच की प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी पूजा खेडकर को 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में रिपोर्ट करना था। पूजा अकादमी नहीं पहुंची हैं। ऐसे में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। • पेज 15

केनेडी हत्याकांड पढ़कर ट्रंप पर थामस ने किया था हमला

वाशिंगटन: अमेरिका में 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के इरादे से फायरिंग करने वाला थामस क्रुक्स पूरी तैयारी से आया था। उसने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जान एफ केनेडी की हत्या से संबंधित जानकारियों को गूगल पर पढ़कर वारदात की तैयारी की थी। • पेज 16

संघ की गतिविधियों में कर्मियों के शामिल होने पर आपत्ति नहीं

- मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में केंद्र सरकार ने दाखिल किया शपथ पत्र
- बताया-दशकों पुराने आदेशों में कर दिया गया है संशोधन
- शपथ पत्र को रिकार्ड पर लेकर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष शपथ पत्र देकर कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने संबंधी दशकों पुराने आदेश में संशोधन कर दिया है। केंद्र सरकार ने यह शपथ पत्र उस याचिका के तहत प्रस्तुत किया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने की मनाही को चुनौती दी गई थी। सितंबर 2023 में दायर याचिका में कहा गया है कि आरएसएस गैर राजनीतिक संगठन है और याचिकाकर्ता को अन्य संगठनों की तरह इसकी गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार है। केंद्र के शपथ पत्र को रिकार्ड पर लेते हुए कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।

दरअसल, मप्र हाई कोर्ट में यह याचिका केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी पुरुषोत्तम गुप्ता ने एडवोकेट मनीष नायर के माध्यम से दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आरएसएस द्वारा की जाने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों से प्रभावित होकर याचिकाकर्ता एक सक्रिय सदस्य के रूप में आरएसएस में शामिल होना चाहते हैं और उसकी गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 1966 से आरएसएस की गतिविधियों को राजनीतिक गतिविधियां मानकर केंद्रीय कर्मचारियों के इसकी गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इससे सेवानिवृत्त कर्मी भी प्रभावित होते हैं। संघ की गतिविधियों में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है। यह मौलिक अधिकारों का हनन है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एडवोकेट हिमांशु जोशी ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने वर्ष 1966, 1975 और 1980 में पारित आदेशों में संशोधन कर दिया है और इनमें से आरएसएस का नाम हटा दिया है।

बिहार में परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक होगी कैद

- नियुक्ति एवं प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी अब संज्ञेय अपराध
- एक करोड़ तक जुर्माना भी होगा, विधेयक पारित

बिहार विस में बोलते सीएम नीतीश कुमार • प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना: मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को बिहार विधानसभा में नियुक्ति व प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी के विरुद्ध लाए गए विधेयक पर चर्चा से विपक्ष के सदस्य अनुपस्थित रहे। पेपर लीक पर लगातार हमलावर रहे विपक्ष की अनुपस्थिति पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आश्चर्य प्रकट किया। कहा- गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई इन्हें (विपक्ष) पसंद नहीं है। चौधरी ने ही बिहार परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 को पेश किया था। विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण विधेयक पर आए संशोधन प्रस्ताव भी ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिए गए। इन प्रविधानों को कानूनी रूप देने के लिए पेश विधेयक को विधानसभा में ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। अब प्रवेश एवं नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में गड़बड़ी संज्ञेय अपराध हो गया है। इसके तहत किसी दोषी को न्यूनतम तीन और अधिकतम 10 साल की सजा के अलावा एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रविधान किया गया है।

नए कानून के दायरे में हैं ये संस्थान
बिहार लोकसेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद, अन्य कोई प्राधिकरण, जो राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित हो।

चौधरी ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में ऐसा ही कानून केंद्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षाओं के लिए संसद में पारित किया था। राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि वह भी अपने क्षेत्राधिकार में इसे लागू करें। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से देश और राज्यों में परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले आए। पहली बार परीक्षा में गड़बड़ी के अपराध को संज्ञेय घोषित किया गया है।

****

13 करोड़ की कोकेन के साथ अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने एक ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश कर एक अफ्रीकी ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित से करीब 13 करोड़ की कोकेन बरामद की है। वह पिछले काफी समय से एनसीआर में ड्रग्स की तस्करी कर रहा था।

पुलिस उपायुक्त राजेश देव ने बताया कि आरोपित की पहचान अफ्रीका के आइवरी कोस्ट निवासी गनहोर सर्ज पैकोम के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक विदेशी सिंडिकेट क्षेत्र में कोकेन की तस्करी कर रहा है। 15 जून को आश्रम स्थित हरिनगर में छापेमारी कर दो ड्रग्स पेडलर नाइजीरिया निवासी एनने चुक्वा और लिबिनस उचे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनसे 386 ग्राम कोकेन बरामद की थी। इनके खिलाफ सनलाइट कालोनी थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपितों ने पूछताछ में ड्रग्स बेचने वाले का नाम नहीं बताया था। तब से ही पुलिस दोनों शातिरों को ड्रग्स बेचने वाली की तलाश कर रही थी। पुलिस टीम ने हरिनगर में ही छापेमारी कर गनहोर को गिरफ्तार कर लिया। गनहोर ही दोनों को ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। आरोपित से करीब 13 करोड़ रुपये कीमत की 1.321 किलोग्राम कोकीन सहित सात मोबाइल, एक स्कूटी व 11,900 रुपये, पैकिंग सामग्री और एक डिजिटल वजन मापने की मशीन बरामद की है।

अवैध रूप से भारत में रह रहा था आरोपित: तस्कर वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रह रहा था। वह अपनी मां के साथ आइवरी कोस्ट में रहता था। उसने मार्च 2022 में भारत के लिए वीजा जारी करवाया था। इसकी अवधि सात सितंबर 2022 को खत्म हो गई थी। तब से ही आरोपित अवैध रूप से भारत में रहकर ड्रग तस्करी कर रहा था।

दिल्ली की गृह सचिव बनीं चंचल यादव

राज्य, जागरण . नई दिल्ली: एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में कार्यरत आठ आइएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। आइएएस अधिकारी चंचल यादव को दिल्ली में गृह सचिव बनाया है। इन आठ अधिकारियों में से छह आइएएस अधिकारी वे हैं, जो दिल्ली सरकार में तबादला होकर तो आ गए थे, लेकिन इन्हें तैनाती नहीं मिली थी। वर्ष 1996 बैच के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी ए अनबरासु को लोक निर्माण विभाग में प्रधान सचिव के साथ-साथ दिल्ली जल बोर्ड में सीईओ का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। वरिष्ठ आइएएस अधिकारी निखिल कुमार भूमि एवं संपदा विभाग में सचिव पद पर तैनात होंगे। वर्ष 2010 बैच की आइएएस अधिकारी आरती लाल शर्मा की तैनाती डीडीए में हुई है। वर्ष 2010 बैच के आइएएस अधिकारी जितेंद्र यादव को एमसीडी में अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर तैनात किया गया है। वर्ष 2011 बैच के आइएएस अधिकारी रवि झा नई दिल्ली के उपायुक्त की भूमिका निभाएंगे। दानिक्स अधिकारी मराठे ओंकार गोपाल की एमसीडी में तैनाती की गई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे कृष्ण मोहन उप्पू जो 2009 बैच के आइएएस अधिकारी हैं वह आबकारी आयुक्त के तौर पर अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उन्हें इससे मुक्त कर दिया गया है।

तीन मिनट से ज्यादा जाम में फंसे होने पर नहीं होगी टोल वसूली

जासं, फरीदाबाद: फरीदाबाद-गुरुग्राम आवागमन के दौरान बंधवाड़ी टोल पर लगने वाले जाम को लेकर डीसीपी ट्रैफिक उषा ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने टोल वसूलने वाली कंपनी को नोटिस भेजकर उनके अधिकारियों को तलब किया है। बृहस्पतिवार को अपने कार्यालय में डीसीपी अधिकारियों संग बैठक करेंगी। साथ ही उन्होंने थाना प्रभारी विनोद कुमार को निर्देश दिए हैं कि इस टोल पर यदि वाहन चालक को लाइन में लगे हुए तीन मिनट से अधिक हो गए तो टोल वसूली नहीं होनी चाहिए।

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से उप.मुख्य बिजली इन्जीनियर (निर्माण) उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के अधीन निम्नलिखित कार्यों के लिये दी गई तिथि को 15.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:- कार्य का नाम: Tender No. EL/C/JP/ABR-TRAH/T/05/2024 नई बीजी लाइन कार्य के संबंध में आबू रोड और तरंगा हिल सेक्शन के बीच 60 से 116 किमी तक संचार आउट केबल द्वारा एलटी/एचटी विद्युत ओवरहेड पावर लाइन ट्रैक क्रोसिंग का संशोधन. कार्य की अनुमानित लागत: Rs.24628202.00 बयाना राशि जो जमा करनी है: Rs. 273200.00 कार्य पूर्ण होने की तिथि: 24 Months निविदा प्रपत्र जमा कराने व खुलने की तारीख व समय:16.08.2024 Upto 15.00 Hrs. 16.08.2024 at 15.30 Hrs. उपरोक्त ई निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट का पता: www.ireps.gov.in

891-AJ/24

गुमशुदा/अपहृत की तलाश

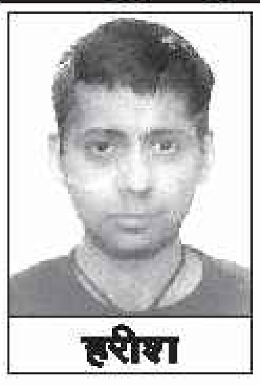

हरीश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति (फोटो में दर्शाया गया) जिसका नाम हरीश पुत्र नरेश कुमार निवासी ए-2/104, सेक्टर-17, रोहिणी, दिल्ली जो दिनांक 20.07.2024, प्रातः 08:00 बजे से अपने घर से लापता/अपहृत हैं। इस संदर्भ में एक एफआईआर सं./ डीडी न. 58-ए, दिनांक 21.07.2024 को थाना के.एन. काटजू मार्ग, जिला रोहिणी, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। स्थानीय पुलिस ने इनका पता लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। जिसका हुलिया नीचे दिया गया है:-

लिंग: पुरुष, आयु: 28 वर्ष, कद: 5' 4" फीट, रंग: सांवला, चेहरा: लम्बा, शरीर: पतला, पहनावा: लाल रंग की टी-शर्ट, काले रंग की पैंट और पैरों में काले रंग की चप्पल पहनी हुई है।

अगर किसी को इस गुमशुदा व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले तो निम्नलिखित पते पर सूचित करें:-

थाना प्रभारी
थाना: केएन काटजू मार्ग, रोहिणी, दिल्ली
फोन: 011-27571171
मो. नं.: 8750870327

वेबसाइट: http://cbi.nic.in
ई-मेल: cic@cbi.gov.in
टेली. न.: 011-24368638/24368641
फैक्स नं.: 011-24368639

DP/9678/RD/2024

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
क्षेत्रीय कार्यालय: निधि भवन, सैक्टर-5, जागृति विहार, मेरठ

प्रेस विज्ञप्ति

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रत्येक जिले में "निधि आपके निकट" कार्यक्रम का आयोजन करता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भागीदारी बनाते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ अपने सभी सम्मानित भविष्य निधि सदस्यों/नियोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं जैसे भविष्य निधि दावापत्रों के भुगतान, सदस्यों के खाते से संबंधित विवरण को अद्यतन करने, नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि का लाभ ना प्रदान करने संबंधी इत्यादि शिकायतों के निपटारे हेतु निम्नलिखित स्थानों पर दिनांक 29.07.2024 को प्रातः 9.00 से "निधि आपके निकट" कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सभी भविष्य निधि सदस्य/नियोक्ता/पेंशनर अपनी समस्याओं से संबंधित दस्तावेजों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

जनपद	स्थान
सहारनपुर	Venue: Woodcraft Design & Development Society Near Vikas Bhawan, Delhi Road, Saharanpur
मेरठ	Venue: Elegant Automobiles Pvt. Ld. 122, Tejgarhi, Opposite HDFC Bank, Garh Road, Meerut
मुजफ्फरनगर	Venue: Royal Building System ,Khasra No. 155, Sisona Road, Vill- Bajheri, NH-58, Byepass, Muzaffarnagar
बिजनौर	Venue: Bajaj Hindustan Sugar Ltd., Bilai, Bijnor
बागपत	Venue: Holychild Academy, Khekra Baghpat
हापुड़	Venue: Salasar Techno Engineering Limited, Khasra No. 265, 281-283 Village-Parsaun, Post-Jindal Nagar District-Hapur
गाजियाबाद	Venue: b4S Solutions (P) Ltd. S-40, Harsha Compound Loni Road, Mohan Nagar, Ghaziabad
शामली	Venue: Amar Splints Pvt. Ltd., Ind. Area, Kairana Road, Shamli
बुलन्दशहर	Kisaan Techno Forged Pvt. Ltd. Gurjar Rd, Sikandrabad, U.P.

(नितिन उत्तम), क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II

कार्यालय–अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल मेरठ
अपर आयुक्त उद्योग परिसर, सूरजकुण्ड रोड, मेरठ

पत्रांक 693 /ग्रा0अ0वि0/निविदा पत्रा0/गा0बाद0/2024–25 दिनांक 12.07.2024

–:: ई–प्रक्योरमेन्ट निविदा सूचना ::–

1. महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल, मेरठ के द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 में ए, बी एवं सी श्रेणी भवन में कार्य की लागत सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई–टेण्डरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। बिड डाक्यूमेन्ट के साथ संलग्न बिल ऑफ क्वान्टिटी में अंकित दरों में जी0एस0टी0 के अतिरिक्त अन्य सभी कर सम्मिलित हैं, जी0एस0टी0 का भुगतान सरकार के निर्देशानुसार नियमानुसार अलग से किया जायेगा। निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र में अंकित एस0बी0डी0 के अन्तर्गत न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में सभी शर्तों का भली–भाँति अध्ययन कर लें।

2. कार्य से सम्बंधित विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख जी0एस0टी0 रहित)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य–धनराशि। जी0एस0टी0 सहित में	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की पंजीयन की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गाजियाबाद	कन्या वैदिक इण्टर कॉलेज गाजियाबाद का जीर्णोद्धार/रेनोवेशन कार्य।	63.56	1.25	2714.00	06 माह	श्रेणी ए, बी एवं सी (भवन)

3. वेबसाइट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि :– 05.08.2024।
4. वेबसाइट पर बिड डाक्यूमेन्ट उपलब्धता की तिथि एवं समय 05.08.2024 प्रातः 10:00 बजे से।
5. प्री–बिडमीटिंग की तिथि एवं समय – 12.08.2024 प्रातः 11:00 बजे। बैठक हेतु स्थल कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल मेरठ।
6. बिड डाक्यूमेन्ट डाउनलोडिंग प्रारम्भ करने की तिथि एवं समय– 05.08.2024 प्रातः 10:00 बजे से
7. ई–निविदा के माध्यम से ई–निविदा डालने की प्रारम्भ तिथि –09.08.2024 प्रातः 10:00 बजे से।
8. ई–निविदा के माध्यम से ई–निविदा डालने की अन्तिम तिथि एवं समय 16.08.2024 दोपहर 04:00 बजे तक
9. ई–निविदा के माध्यम से प्राप्त निविदा खोलने की तिथि एवं समय –17.08.2024 दोपहर 12:30 बजे।
10. टेण्डर प्रक्रिया से पूर्व का कोई भी शपथ–पत्र मान्य नहीं होगा।
11. निविदा ऑनलाइन वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध होगी एवं इसी साइट पर डाली जाएगी।
12. निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज–10 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जोकि किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी सम्भावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई–निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें।

(रविकान्त वर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग मेरठ परिमण्डल, मेरठ।
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से

UP-217603 दिनांक 22.07.2024 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल सं0-1, मुजफ्फरपुर।
Mobile No : 9470001292, E-mail : eercd1muz@gmail.com

अतिअल्पकालीन शुद्धि पत्र

इस कार्यालय का पत्रांक 982 (अनु0) दिनांक 24.06.2024 एवं पी0 आर सं0-002574 (आर0सी0डी0) 2024-25 जो दिनांक 27.06.2024 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है के वर्णित कार्य को अपरिहार्य कारणवश अल्पकालीन ई-निविदा के निर्धारित अवधि का विस्तार किया जाता है, जो निम्नप्रकार है:-

क्र0		पूर्व का निर्धारित अवधि	संशोधित अवधि
1	Period for Download of tender document	from 24.07.2024 to 29.07.2024 upto 15:00 hrs (From Website: www.eproc2.bihar.gov.in)	from 07.08.2024 to 12.08.2024 upto 15:00 hrs (From Website: www.eproc2.bihar.gov.in)
2	Date, time & place of pre-bid meeting	26.07.2024 at 11:00 hrs. at the Office of the Chief Engineer, North, RCD, Patna	09.08.2024 at 11:00 hrs. at the Office of the Chief Engineer, North, RCD, Patna
3	Last date & time for uploading Tender document by bidder	30.07.2024 upto 15:00 hrs. on www.eproc2.bihar.gov.in	13.08.2024 upto 15:00 hrs. on www.eproc2.bihar.gov.in
4	Last date, time and place for submission of original instrument of EMD (in case of manual mode only)	31.07.2024 upto 15:00 hrs. in the office of the following (i) Executive Engineer, Road Division No.-1, Muzaffarpur, (ii) Superintending Engineer, North Bihar Circle, (iii) Chief Engineer, North RCD, Patna	14.08.2024 upto 15:00 hrs. in the office of the following (i) Executive Engineer, Road Division No.-1, Muzaffarpur, (ii) Superintending Engineer, North Bihar Circle, (iii) Chief Engineer, North RCD, Patna
5	Date, time & Place of opening of technical bid	01.08.2024 at 15:30 hrs. on www.eproc2.bihar.gov.in	16.08.2024 at 15:30 hrs. on www.eproc2.bihar.gov.in
6	Date, time & place of opening of Financial Bid	16.08.2024 at 15:30 hrs. on www.eproc2.bihar.gov.in	02.09.2024 at 15:30 hrs. on www.eproc2.bihar.gov.in

अन्य शर्तें पूर्वत रहेंगी।

PR- 04519 (R C D) 2024-25

कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमण्डल सं0–1, मुजफ्फरपुर।

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

कार्यालय – अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड, गाजियाबाद।

पत्रांक:– 664 /ग्रा0अ0वि0/ निविदा – 09 /2024–25 दिनांक 18.07.2024

निविदा सूचना–09(द्वितीय कॉल)

1. महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड गाजियाबाद द्वारा निम्नलिखित कार्यों की प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में क्लास "ए, बी, सी व डी" मार्ग/भवन श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा डालने योग्य होंगे। निविदादाता किसी एक अथवा समस्त कार्य की निविदा डाल सकता है। निविदादाता से अपेक्षा की जाती है, कि निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्र के क्लॉज सं0–3 में अंकित न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में शर्तों का भली–भाँति अध्ययन कर लें।

2. कार्य का विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	विधान सभा क्षेत्र/जनपद	योजना का नाम	कार्य का नाम	निर्माण लागत (रु0 लाख में) जी0एस0टी0 रहित	बिड सिक्योरिटी (रु0 लाख में) EMD	निविदा प्रपत्र का मूल्य जी0एस0टी0 सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुरादनगर/गाजियाबाद	मा0 विधायक श्री अजीत पाल त्यागी द्वारा प्रस्तावित	नेहरूनगर शिव मन्दिर के पास नन्दन पार्क में ओपन जिम स्थापित करवाने का कार्य।	8.45	0.43	766.00	4 माह

निविदा प्रपत्र अधिशासी अभियन्ता, के कार्यालय से प्रत्येक कार्य दिवस में 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक दिनांक 12.08.2024 से 17.08.2024 तक प्राप्त की जा सकती है तथा डाक द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त धनराशि 200.00 देकर प्राप्त की जा सकती है तथा इसके लिए दिनांक 16.08.2024 सायं 4.00 बजे तक अनुरोध स्वीकार किया जायेगा। डाक में देरी से निविदा प्राप्त करने के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। निविदा प्रपत्र अधिशासी अभियन्ता, के कार्यालय में दिनांक 19.08.2024 को 12.00 बजे तक जमा की जा सकती है जिनको दिनांक 19.08.2024 को 12.30 बजे अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में बिड खोली जायगी।

इच्छुक निविदा दाता अधिक जानकारी कार्य से संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड–गाजियाबाद।

UP-217606 दिनांक 22.07.2024 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है

कार्यालय–अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल मेरठ
अपर आयुक्त उद्योग परिसर, सूरजकुण्ड रोड, मेरठ।

पत्रांक 647 /ग्रा0अ0वि0/निविदा पत्रा0/गौतमबुद्धनगर/2024–25 दिनांक 12.07.2024

–:: ई–प्राक्योरमेन्ट निविदा सूचना ::–

1. महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ परिमण्डल, मेरठ के द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 में 'ए' 'बी' 'एवं सी' श्रेणी भवन में कार्यों की लागत सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई–टेण्डरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। बिड डाक्यूमेन्ट के साथ संलग्न बिल ऑफ क्वान्टिटी में अंकित दरों में जी0एस0टी0 के अतिरिक्त अन्य सभी कर सम्मिलित हैं, जी0एस0टी0 का भुगतान सरकार के निर्देशानुसार नियमानुसार अलग से किया जायेगा। निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है, कि निविदा डालने से पूर्व निविदा प्रपत्रों में अंकित एस0बी0डी0 के अन्तर्गत न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में सभी शर्तों का भली–भाँति अध्ययन कर लें।

2. कार्य से संबंधित विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख जी0एस0टी0 रहित)	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य। धनराशि। जी0एस0टी0 सहित में	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार के पंजीयन की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्धनगर	श्री कृष्ण इण्टर कॉलेज गढ़ी चौखण्डी, गौतमबुद्धनगर में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य।	105.03	2.10	2714.00	08 माह	श्रेणी 'ए एवं बी' (भवन)
2	गौतमबुद्धनगर	राणा संग्राम सिंह इण्टर कॉलिज, बिसाहड़ा, गौतमबुद्धनगर में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य।	78.37	1.57	2714.00	08 माह	श्रेणी 'ए एवं बी' (भवन)

3. वेबसाइट पर निविदा प्रकाशित होने की तिथि–14.08.2024।
4. वेबसाइट पर बिड डाक्यूमेन्ट उपलब्धता की तिथि एवं समय –14.08.2024 प्रातः 10:00 बजे से।
5. प्री–बिडमीटिंगकीतिथि एवं समय–16.08.2024 प्रातः 11:00 बजे। बैठक हेतु स्थल–कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल–मेरठ।
6. बिड डाक्यूमेन्ट डाउनलोडिंग प्रारम्भ करने की तिथि एवं समय–14.08.2024 प्रातः 10:00 बजे से।
7. ई–निविदा के माध्यम से ई–निविदा डालने की प्रारम्भ तिथि–14.08.2024 प्रातः 10:00 बजे से
8. ई–निविदा के माध्यम से ई–निविदा डालने की अंतिम तिथि एवं समय–20.08.2024 दोपहर 04:00 बजे तक।
9. ई–निविदा के माध्यम से प्राप्त निविदा खोलने की तिथि एवं समय–21.08.2024 दोपहर 12:30 बजे।
10. टेण्डर प्रक्रिया से पूर्व का कोई भी शपथ–पत्र मान्य नहीं होगा
11. निविदा ऑनलाइन वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध होगी एवं इसी साइट पर डाली जाएगी।
12. निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज–10 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जोकि किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। सभी सम्भावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ई–निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें।

(रविकान्त वर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
मेरठ परिमण्डल, मेरठ।

UP-217596 दिनांक 22.07.2024 विज्ञापन वेबसाइट www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
PATNA WEST ROAD DIVISION, ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT
Opp. Telephone Bhawan, R. Block, Patna
Telephone/Fax–0612–2507971 ; E-mail:-ee-rd-patnawest-bih@nic.in

CORRIGENDUM

In NIT No – RCD/01/PatnaWest/2024-25 & PR No. 003566 (RCD) 2024-25 in "Construction of Foot Over Bridge at St. Karens School Near of Khagul Under Patna West Road Division, Patna for the year 2024-25 & Construction of FOB Lift at Rukanpura under Patna West Road Division, Patna for the year 2024-25 as being revised as follows -

News paper S No.	As per e-paper / News paper published	Read as (after issue of corrigendum)
3.	Period for download of Tender Documents From 24.07.2024 to 30.07.2024 (upto 15.00 hrs) from website : www.eproc2.bihar.gov.in	Period for download of Tender Documents From 05.08.2024 to 12.08.2024 (upto 15.00 hrs) from website : www.eproc2.bihar.gov.in
4	Date, Time & Place of Pre-Bid Meeting Date – 26.07.2024 at 11:00 hrs at the office of Chief Engineer (South), Chhajjubagh, RCD, Bihar, Patna.	Date, Time & Place of Pre-Bid Meeting Date – 10.08.2024 at 11:00 hrs at the office of Chief Engineer (South), Chhajjubagh, RCD, Bihar, Patna.
5.	Last date & time for uploading tender documents by bidder. From 24.07.2024 to 31.07.2024 till time 15.00 hrs. on www.eproc2.bihar.gov.in	Period of uploading tender documents by bidder. From 05.08.2024 to 13.08.2024 till time 15.00 hrs. on www.eproc2.bihar.gov.in
6.	Date, Time & Place of opening of Technical Bid Date – 01.08.2024 Time – 15.30 Hrs. Place on website : www.eproc2.bihar.gov.in	Date, Time & Place of opening of Technical Bid Date – 14.08.2024 Time – 15.30 Hrs. Place on website : www.eproc2.bihar.gov.in
8.	Date, time & place of opening of Financial Bid Date – 16.08.2024 Time – 15.30 Hrs. Place: On website : www.eproc2.bihar.gov.in	Date, time & place of opening of Financial Bid Date – 25.08.2024 Time – 15.30 Hrs. Place: On website : www.eproc2.bihar.gov.in

Work Mentioned in Part – 02 of Sl. No. – 7 of NIT No – RCD/01/Patna west/2024-25 (PR No - 003566 (RCD) 2024-25) is deleted due to inevitable reason.

नोट : उक्त निविदा की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

PR. No. 004573 (RCD) 2024-25

Executive Engineer,
Patna West Road Division, Patna.

For further details please visit : www.state.bihar.gov.in/prdbihar

बिहार में शराब का व्यापार, बिक्री एवं सेवन अवैध है।
इससे संबंधित शिकायत इस नंबर पर दर्ज करायें, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।
टॉल फ्री नं– 15545 या 1800 345 6268

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
CORRIGENDUM

Following changes are hereby made in tenders called vide this office letter NO.PW-JD/E-Tender/2024-25-2704-06 Dated 09-07-2024 scheduled to be opened on dated 30-07-2024, through Online system are here by cancelled due to technical/administrative reasons:-

Job No	Name of Work	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Cost of Tender Form (Rs.)	Time Allowed	Class
1	Balance work of Dochi Bouli Badhauli Raika road km 0/0 to 2/510 under NABARD (SH:- ROFD, CD works, M/T works side drain and road infrastructure etc.)	15109863	302200	5000	6 Month	Class C

No. 0955/2024-25

Executive Engineer
HPPWD Division Jubbal, Jubbal

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान

No. :- F-2(01)Acct/Contract/2024-25/52 - 54 Date : 22/07/2024

ई-निविदा सूचना संख्या : 14/2024-25

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यों मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

निविदा कार्यो की कुल लागत	:	रुपये 490.57 लाख (10 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड / अपलोड करने की अवधि	:	24.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे से 02.08.2024 को सांय 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथी	:	25.07.2024 को प्रातः 10.00 बजे से 02.08.2024 को सांय 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथी	:	05.08.2024 को प्रातः 11.00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBN No. : ITU2425WSOB00123 To ITU2425WSOB00132

अधिशाषी अभियन्ता - द्वितीय
उदयपुर विकास प्राधिकरण

राज.संवाद/सी/24/279

NAGAR NIGAM, GORAKHPUR

Ref No: 134/Amc/NNG/2024-25 Date: 24.07.2024

Expression of Interest (EOI)

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FROM ANY PRIVATE/FIRM/ NGO/ORGANISATION FOR Development for providing Commercial complex Interalia Multilevel Parking in Golghar area on premium plus Rental Basis in Gorakhpur.

The Bidders have to participate through Online E-Procurement website http://etender.up.nic.in. EOI document can be seen and obtained from website http://etender.up.nic.in. Interested bidders/Firms may view and download EOI document and upload their proposals, duly filled, online as per schedule given below-

S.No.	Description	Date	
1	Start Date for document download	27.08.2024	
2	Date of Pre-bid meeting	06.08.2024	12:00 PM
3	Last Date of Online submission of proposal	16.08.2024	05:00 PM
4	Opening of proposal	17.08.2024	11:00 AM

For the further details contact during office hour on phone number 8810709350

Add. Municipal Commissioner
Nagar Nigam, Gorakhpur

Municipal Commissioner
Nagar Nigam, Gorakhpur

गुमशुदा लड़की की तलाश

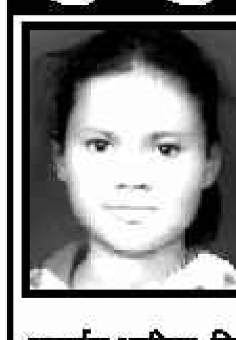

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह लड़की (फोटो में प्रदर्शित) जिसका नाम: ज्योति, पुत्री: श्री पारस, निवासी: छोटू राम स्कूल, मस्जिद वाली गली, बख्तावरपुर, दिल्ली, उम्र: 15 साल, कद: 5 फुट 4 इंच, रंग: सांवला, चेहरा: गोल, शरीर: मध्यम, पहनावा: सफेद रंग की फ्रॉक जिसपर आसमानी रंग की प्रिंट है एवं पैरों में काले रंग के चप्पल पहने हुए है, दिनांक 18.07.2024 समय 09.00 बजे सुबह को अपने घर थाना अन्तर्गत अलीपुर, दिल्ली से लापता हो गयी है।

इस संदर्भ में FIR No. 438/24, Dated 18.07.2024 थाना अलीपुर, दिल्ली में दर्ज किया गया है।

पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अब तक इस लड़की के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस लड़की के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

ईमेल : cic@cbi.gov.in — थाना प्रभारी
वेबसाइट : http://cbi.nic.in — थाना- अलीपुर, दिल्ली
फैक्स : 011-24368639 — फोन: 011-27202265, 7065035325
दूरभाष : 011-24368638, 24368641

DP/9663/ON/2024

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त प्रिंस कुमार पुत्र श्री मात निवासी क्यू–7/124, मंगोलपुरी, दिल्ली ने case FIR No. 277/2021 U/s 188 IPC, थाना राज पार्क, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त प्रिंस कुमार मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त प्रिंस कुमार फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि case FIR No. 277/2021 U/s 188 IPC, थाना राज पार्क, दिल्ली के उक्त अभियुक्त प्रिंस कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद/मुकदमा का उत्तर देने के लिए दिनांक 07.09.2024 को या उससे पूर्व हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री एकानी अग्रवाल
महानगर दण्डाधिकारी (उत्तर पश्चिम)
कमरा नं. 107, प्रथम तल
रोहिणी कोर्ट, नई दिल्ली

DP/9468/OD/2024(Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त रवि राठौड़, पुत्र राजेन्द्र राठौड़ पता: एच.नं. 40, एए, डीडीए जनता फ्लैट्स पश्चिम विहार दिल्ली ने FIR No. 164/22 U/s 392/34 IPC पुलिस थाना पश्चिम विहार, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त रवि राठौड़ मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त रवि राठौड़ फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No. 164/22 U/s 392/34 IPC पुलिस थाना पश्चिम विहार, दिल्ली के अभियुक्त रवि राठौड़ से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 16.10.2024 या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री अंकित करन सिंह
एम.एम. – 08 पश्चिम–जिला
तीस हजारी कोर्ट दिल्ली

DP/9483/OD/2024

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त मो. जहांगीर अमान, पुत्र: मो. युनूस, पता: बिल्डिंग नं. – WZ–429 ए, द्वितीय तल, पप्पू (हरिसन) हार्डवेयर स्टोर के ऊपर, माता मंदिर के पास, गांव – नारायणा, नारायणा, दिल्ली–110028 एवं अन्य पता: मकान नं. 857, कटरा, हिंदू, फराश खाना, डाक खाना वाली गली, दिल्ली–110006 ने आपराधिक मुकदमा सं. 39247/19, U/s 138 NI ACT के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उन पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त मो. जहांगीर अमान मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त मो. जहांगीर अमान फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि आपराधिक मुकदमा सं. 39247/19, U/s 138 NI ACT के उक्त अभियुक्त मो. जहांगीर अमान से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 31.08.2024 को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री के. बी. राठौड़
07वें अति. वरि. सिविल जज एवं एसीजेएम
कमरा सं. डी–30, तृतीय तल, न्यू न्याय मंदिर
भद्रा, अहमदाबाद (गुजरात)

DP/9471/WD/2024
(Court Matter)

हरियाणा सरकार — शुद्धिपत्र

क्र. स.	बोर्ड निगम/ प्राधिकरण का नाम	पुरानी संदर्भ /निआसू सं.	शुद्धिपत्र की प्रकृति	बोर्ड निगम /प्राधिकरण की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ईमेल
1	एचवीपीएनएल	NIT NO 20/CWD-VOI-XVII/HVPN/2024-25 DATED 12.06.2024 ONLINE TENDER ID 2024_HBC_377186_1	बोली खोलने की तिथि 23.07.2024 को (11.00 बजे), ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि 29.07.2024 को (13.00 बजे) तक बढ़ाई गई है (समितियां एवं ठेकेदार)	www.hvpn.org.in	0172-2583789 pro@hvpn.org.in
2.	एचवीपीएनएल	DNIT NO 83151 DATED 07.06.2024 EPC-D NO 109/PD&C	शुद्धिपत्र-2 के खोलने की तिथि 23.07.2024 सहित ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण की नियत तिथि को 29.07.2024 को 17.00 बजे तक बढ़ाया गया है।	www.hvpn.org.in	0172-2583789 pro@hvpn.org.in
3.	एचवीपीएनएल	NIT NO 1329 QDP -1449 DATED 10.06.2024	ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि 30.07.2024 को 17.00 बजे तक बढ़ाई गई है।	www.hvpn.org.in	0172-2583789 pro@hvpn.org.in
4.	एचवीपीएनएल	NIT NO 19/CWD-VOI-XVII/HVPN/2024-25 DATED 12.06.2024 ONLINE TENDER ID NO 2024_HBC_377184_1	बोली खोलने की तिथि 23.07.2024 को (11.00 बजे), ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि 29.07.2024 को (13.00 बजे) तक बढ़ाई गई है (समितियां एवं ठेकेदार)	www.hvpn.org.in	0172-2583789 pro@hvpn.org.in
5.	एचवीपीएनएल	NIT NO 06/CWD-VOI-XVII/ HVPN/2024-25 DATED 06.06.2024 ONLINE TENDER ID NO 2024_HBC_373358_1	बोली खोलने की तिथि 23.07.2024 को (11.00 बजे), ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि 29.07.2024 को (13.00 बजे) तक बढ़ाई गई है (समितियां एवं ठेकेदार)	www.hvpn.org.in	0172-2583789 pro@hvpn.org.in

PRDH-13/2025/100/28172/I/67/7 — आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

****

हरियाणा सरकार
म्हारा हरियाणा
नॉन-स्टॉप हरियाणा
हम हरियाणवी
अब 24 घंटे बिजली पाते हैं
प्रदेश के 5816 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध
वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 538 गांवों को मिलती थी 24 घंटे बिजली
ट्रांसफार्मर खराब या चोरी होने पर किसानों से कोई शुल्क नहीं
9.5 लाख गरीब परिवारों के
मिनिमम मासिक चार्ज (MMC) अब खत्म
निरंतर हर घर को
बिजली उपलब्ध हो रही है
सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा
www.prharyana.gov.in
Follow us on
@diprharyana

****

दिल्ली जल बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

कार्यालय मुख्य अभियंता (एसडीडब्ल्यू) मार्फत
अधिशासी अभियंता (एसडीडब्ल्यू)-III एसटीपी यमुना विहार, वजीराबाद रोड दिल्ली-110053
ईमेल: eesdw3.djb@nic.in

विषय: प्रेस निविदा सूचना- एन.आई.टी. सं.-01 (2024-25)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	ई-प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन में अपलोडिंग की तिथि/निविदा आईडी	अनुमानित लागत/धरोहर धनराशि एवं निविदा शुल्क	निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि
1.	यमुना विहार एसपीएस में नये निर्मित चैंबर हेतु 02 नग पम्प सेट का एस/आई/टी/सी तथा अन्य संबंधित कार्य	19.07.2024/ 2024_DJB_259750_1	आईटम दर, ईएमडी रु. 68,000/-, निविदा शुल्क रु. 500/-	02-08-2024 को अप 03.00 बजे

इस संबंध में आगामी विवरण https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखा जा सकता है।
पीआरओ (जल) द्वारा जारी.
वि.सं. जे.एस.वि. 012 (2024-25)

(हर्षवर्धन)
अधिशासी अभियंता (एसडीडब्ल्यू)-III

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Telephone No. 01970233116, E-mail ID: ee-deh-hp@nic.in

INVITATION FOR BIDS (IFB)

The **Executive Engineer Dehra Division HPPWD Dehra H.P.** on behalf of Governor of H.P. invites the item rate bids, in the electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost (Rs.)	Starting date for downloading Bid.	Earnest Money.	Deadline for submission of Bid.	Tender Form Cost
1	Construction of Aadarsh Gram Sukh Aashray Parisar / Complex at Jawalamukhi (Luthan) Tehsil Jawalamukhi Distt. Kangra HP (SH:-C/o Building portion , Sanitary installation rain Harvesting tank & septic tank etc.	1,05,42,74,530.00	05.08.2024	Rs 2,10,86,000/-	13.08.2024	Rs 5000/-

The bidders are advised to note other details of tender form the department website .www.hptenders.gov.in. **Date of opening of tender 14.08.2024**

Executive Engineer,
Dehra Division HP.PWD., Dehra Pin No. 177101.
Tel. No. 01970-233116. e-mail:- ee-deh-hp@nic.in

1005 HIM LOK SAMPARK

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KURUKSHETRA

(Under the Ministry of Education, Govt. of India)
KURUKSHETRA-136119 (HARYANA)

Advt. No. 73/2024

Spot Round MBA Admission Programme for the Session 2024-26

Department of Business Administration NIT, Kurukshetra is seeking applications from bright aspirants for the vacant seats of its 2-year, full time MBA Programme for the sessions 2024-26 (SPOT Round). Admission is based on weightages for the valid score of CAT/CMAT/MAT/XAT and any other National Level Test of 2023-2024 and performance in GD & PI. Admission counseling will be held on the same day in the Institute.

Application form and other information can be downloaded from the Institute Website: www.nitkkr.ac.in. The date of the SPOT Round MBA Admission is August 16th, 2024 (Reporting Time: 09:00 AM and no entry after 10:00 AM).

Registrar I/c

Government of Jammu & Kashmir
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER SEWERAGE & DRAINAGE DIVISION No: Ist SULIMAN COMPLEX DALGATE SRINAGAR
Notice Inviting e-Tendering
Fresh Short Term e-NIT No: 06 of 2024-25

For and on behalf of Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, e-tenders are invited in Two Cover System (Technical and financial) on Percentage basis from Registered Government Contractors having established workshop facility for execution of similar nature of works for Rate Contract for the maintenance work as detailed below. The work description, class of contract, performance security etc. are prescribed against the work given in below table.

S. No	Name of work	Cost of work	Earnest money @2%	Cost of T/doc. (In rupees)	Time of completion	Class of contract	Call
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rate Contract for Repairs, Replacements and maintenance of Electrical items / Equipment installed within Eight (08) numbers Intermediate Pumping Stations around Dal Periphery, 02 no feeding pumping stations of STP and 17.08 MLD Sewage Treatment Plant Brari-Numbal for 01 year	25.01	50020/=	1500/=	01 Year	Electrical Contractors Registered with D.I.C	2nd
2	Rate Contract for Repairs, Replacements and Maintenance of Mechanical items/equipment installed within Eight (08) numbers Intermediate Pumping Stations around Dal Periphery,02 no feeding pumping stations of STP and 17.08 MLD Sewage Treatment Plant Brarinambal for 01 year.	14.44	28880/=	500/=	01 Year	Mechanical Contractors Registered with D.I.C	2nd

Position of Funds: **Available**
Accord of TS: **Accorded**

The bidding documents consisting of qualifying information, eligibility criteria, specifications, set of terms and conditions of contract and other details can be seen / downloaded from the departmental website www.jktenders.gov.in as per schedule of dates given below:

1	Date of publishing	23-07-2024
2	Period of downloading of bidding documents	23-07-2024 to 31-07-2024 up-to 4:00 PM
3	Bid submission Start Date	23-07-2024 from 4:00 PM
4	Bid submission End Date	31-07-2024 up-to 4:00 PM
5	Date & time of opening of bids	01-08-2024 at 11:00 AM Or any other convenient date.

Tender Receiving Authority : **Executive Engineer S&D Division Ist (UEED) Sgr. Sulaiman Complex Dalgate Srinagar**

Sd/-
Executive Engineer
S&D Division Ist
Srinagar

DIPK-3443/24 DT. 23.7.24

-प्रेस विज्ञप्ति-

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक स.एसपीएमयू/एनयूएचएम/बजट/2024-25/61/1555-2 दिनाक 18.06.2024 में जनपद गौतमबुद्धनगर में शहरी आशा के नवीन स्वीकृत 341 पद एव पूर्व में स्वीकृत/रिक्त 26 पद कुल 367 पदों पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार चयनित किये जाने हेतु नियत प्रारूप पर इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 08.08.2024 की सांय 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, 8वां तल, सेक्टर-39, नोयडा में पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है. नियत तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें। साक्षात्कार आदि की सूचना अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल पर दी जायेगी।

रिक्तियों का विवरण

क्र. स.	नगरीय प्रा.स्वा.केन्द्र पर आशा के रिक्त पदों का विवरण	अर्ह शैक्षिक योग्यता / आयु सीमा	वांछित अनुभव (यदि हो)	रिक्त पद के सापेक्ष अनुमोदित मानदेय (रू. प्रति माह)
1	4	5	6	8
1.	**यूपीएचसी बरौला** - बरौला -12 **यूपीएचसी भंगेल** -भंगेल -03, सलारपुर-4, याकूबपुर - 6, ककराला -1, ककराला पुस्ता -4 नगला, चरणदास-1, अगोर-1, जीतराम कालोनी-1, नयागांव -3, इलाहाबांस 3, भूड़ा-4, शाहदरा -2, गढ़ी शाहदरा -1, नलगढ़ा-1, **यूपीएचसी चिपयाना**- चिपयाना -7, छपरोला 5, गिरधपुर-2 **यूपीएचसी दादरी**- दादरी - 45, **यूपीएचसी हरोला**- हरोला -4, सेक्टर-20-01, सेक्टर-10 जे.जे.-1, सेक्टर-8 जे.जे.-2, सेक्टर-9 जे.जे.-2, **यूपीएचसी होशियारपुर**- होशियारपुर-3, मोरना-2, मिझोड-4, **यूपीएचसी कासना-कासना**-16, बल्ला की मड़इया-3, बिरोंडा-2, रेप्चर-4, कायमपुर-1, पीएचआई-3 -1, सीएचआई-3 - 1, सीएचआई-4-1, सेक्टर-36-1, सेक्टर-37-1, सिगमा-1-1, सिगमा-2-1, सिगमा -4 -1, स्वरण नगरी- 1. **यूपीएचसी नयाबांस** -नयाबांस- 4, सेक्टर-16 जे.जे. - 2, सेक्टर-17 जे.जे. -1 **यूपीएचसी रायपुर**-रायपुर-3, बख्तावरपुर-2, गेझा-4, नगली शकपुर-1, वाजिदपुर- 6, **यूपीएचसी सदरपुर**-सदरपुर-20, अच्छापुर-4, छलेरा-3. **यूपीएचसी सर्फाबाद** -सर्फाबाद -10, सोरख पुस्ता-7, छिजारसी कालोनी 8, बेटपुर-6, बहलोलपुर-4, ममूरा-8, गढ़ी चोखंडी-5, बरुई-1, पर्थला खंजरपुर-3, सेक्टर-122 लाल फ्लेट-2, सेक्टर-122 व्हाईट फलेट-2 **यूपीएचसी सेक्टर-22**- सेक्टर-22-1, बिरानपुरा -2, चौड़ा सादतपुर-4 नवादा-2, वजिदपुर-2, सेक्टर-12-1, सेक्टर-22-1, सेक्टर-55-1, सेक्टर-56-2, **यूपीएचसी सूरजपुर**-सूरजपुर-20, देवला-6, हबीबपुर-2, जलपुरा-4, अलिवर्दिपुर-2, सुतियाना-2, हबीबपुर-6, हल्दौनी-3, कुलेसरा-8, ईंट जन्ता फलेट-1, जीता जन्ता फलेट-1, **यूपीएचसी तिगड़ी**-तिगड़ी-7, पुराना हैबतपुर-5, यूसुफपुर चेक सेवरी-1. **यूपीचसी तुगलपुर**-तुगलपुर-4, अल्फा-2 बीटा-2 गामा-2, डेल्टा-3, उमेगा 2, पी3-1, पी4 -1, **कुल पद 367**	हाईस्कूल-उत्तीर्ण इण्टरमीडिएट को 1 अतिरिक्त अंक उच्च शिक्षित को 1 अतिरिक्त अंक (सम्बन्धित क्षेत्र की निवासी होना आवश्यक है/विवाहित/ विधवा/तलाकशुदा / पति से अलग हो गई, महिला को प्राथमिकता दी जायेगी) आयु 20 से 45 वर्ष के बीच हो। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वरियता दी जायेगी। जे० एन०एन०यू० आर० एम० / यूनिसेफ (एम एस नेट) एवं भारत सरकार द्वारा संचालित अन्य संस्थाओ में कार्य करने वाले अभ्यर्थी को उनके अनुभव के आधार पर अंक दिये जायेगे।	वरियता प्रदान किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा पठनीय अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ सलग्न की जाये।	विभाग के कार्यक्रमों में निर्धारित मानक पूर्ण करने पर प्रतिमाह प्रतिपूर्ति रू. 2000/- देय होगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम
2. आवेदक के पिता/पति का नाम
3. निवास/पत्राचार का पता (मो.न. सहित)
4. शैक्षिक योग्यता
5. अनुभव प्रमाण पत्र
6. जन्मतिथि
7. अन्य प्रपत्रों का उल्लेख किया जायें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित

NODAL OFFICER
NUHM (G.B. NAGAR)

CHIEF MEDICAL OFFICER
GAUTAM BUDH NAGAR

Office of Superintending Engineer, 9th Circle
Himachal Pradesh Public Works Department
Address:- 9th Circle, HPPWD., Nurpur. Mail ID hp-kan2@nic.in Phone No. 01893-220098

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

List of Important Dates of Bids for Construction/Upgradation of Road using New Technology "Cement Treated Base" under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and their Maintenance for five year. Accordingly Superintending Engineer 9th Circle, HPPWD., Nurpur on behalf of Governor of Himachal Pradesh invites Percentage rate bids, in electronic tendering system for construction of below mentioned roads:-

Sr. No.	Name of Employer for Execution of Contract Bond	District	Package No.	Name of work	Period of completion	Estimate Cost Excluding of GST (in lacs) Construction	Maintenance	Total cost excluding GST (in lacs)	Bid Security (in lacs)
	Package No. NCTB- 01								
1.	Chief Engineer (KZ) HPPWD D/shala.	Kangra	HP04-355	Up-gradation of Kopra to Hasol road Km. 0/0 to 8/200. (CTB Work).	12 months	661.95	49.31	711.26	14.25
	Package No. NCTB- 02								
2.	-do-	-do-	HP04-327	Up-gradation of Indora via Kursain to Kathgarh road Km 0/0 to 7/160. (CTB Work).	18 months	1980.53	99.27	2079.80	41.60
			HP04-326	Up- gradation of Malkroli to Changrara Km. 0/0 to 9/350. (CTB Work).					
	Package No. NCTB- 03								
3.	-do-	-do-	HP04-323	Upgradation of Bain Indorian Miani Mihwan to Barota road Km. 0/0 to 12/850. (CTB Work).	18 months	1849.60	77.27	1926.87	38.55
	Package No. NCTB- 04								
4.	Chief Engineer (KZ) HPPWD D/shala.	Kangra	HP04-325	Up- gradation of Ganagth Gheta road Km. 0/0 to 8/700 (CTB Work).	18 months	1601.01	135.89	1736.90	34.74
			HP04-324	Up- gradation of Madhoh Tappa Indpur Plahghat road. Km. 0/0 to 13/900 (CTB Work).					
	Package No. NCTB- 05								
5.	-do-	-do-	HP04-322	Up- gradation of Ghandran to Rehan via Mokiroad. Km. 0/0 to 20/600. (CTB Work).	18 months	2175.11	123.87	2298.98	45.98

2. Date of Publishing of e-procurement notice through News Papers:- 01-08-2024
3. Publishing date of Bid on-line:- 01-08-2024 (10.00 AM).
4. Start Date of downloading of bids :- 02-08-2024 (11.00 AM).
5. Deadline for submission of bids:- 16-08-2024 (5.00 PM).
6. Date of opening of bids:- 17-08-2024 (11.00 AM).

Pre-bid meeting on dated 07-08-2024 at 11:30 AM.
For further details please log on to https://pmgsytendershp.gov.in RO No. 0981

Superintending Engineer,
9th Circle, H.P.P.W.D., Nurpur-176202
Email: hp-kan2@nic.in, 01893-220098.

कार्यालय जिला पंचायत हापुड़।
अति अल्पकालीन निविदा सूचना

जिला पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों/विशेषज्ञ एव अन्य सरकारी विभागों मे पंजीकृत फर्म/ठेकेदारों से **सामान्य टेंडर व्यवस्था के माध्यम से दिनॉक 27.07.2024 को अपरान्ह 02 बजे तक** कार्यालय जिला पंचायत हापुड में रखे गये टेण्डर बाक्स हेतु आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाए उसी **दिनॉक को अपरान्ह 03 बजे से कार्यालय जिला पंचायत में सक्षम अधिकारियों एवं उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोले जायेगें।** यदि उक्त दिनॉक को कोई उपयुक्त टेंडर प्राप्त नही होता है, उक्त कार्य की निविदा दिनॉक 27.07.2024 को अपरान्ह 12.00 बजे तक आमंत्रित किये जायेगें, तथा उसी दिनॉक को अपरान्ह 01 बजे खोली जायेंगी।

कार्य की निविदा, निविदा आमंत्रण की दिनॉक से पूर्व कार्य दिवसो की तिथियों मे निर्धारित निविदा मूल्य जमाकर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक टेडर दरो के साथ वॉछित शपथ पत्र अंकन 100.000 के स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी सहित) निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक कार्य का अनुबंध 10 प्रतिशत की अस्थाई धरोहर राशि पर किया जायेगा। प्रत्येक निविदा के साथ टेंडर दाता को 02 प्रतिशत धरोहर राशि की एफ० डी.आर./ एन.एस.सी./ नकद, प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग जो कि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हापुड के पदनाम मे बंधक होगी, संलग्न करनी होगी। कोई भी निविदादाता जिला पंचायत के मा० अध्यक्ष/मा. जिला पंचायत सदस्य/अधिकारी एवं कर्मचारीगणों का सगा सम्बंधी नहीं होना चाहिए। कार्यो के भुगतान की कार्यवाही शासन द्वारा उक्त मद में अनुदान एवं मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत ही की जायेगी। पंजीकृत ठेकेदारों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य अनुभवी ठेकेदार टेंडर प्रक्रिया में शामिल होता है तो उसके लिए प्रथमतः आय कर प्रमाण पत्र, अनुभव तथा जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्य जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस मे कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। टेंडर हेतु कार्य का विवरण निम्नवत है।

कमांक	मद का नाम	प्राक्कलित धनराशि (जी.एस.टी. सहित)	धरोहर राशि (रु.) 02 प्रतिशत	टेंडर मूल्य + जी.एस.टी. (रु. में)	कार्य की अवधि
1.	श्रावण मास के अवसर पर ग्राम बछलोता-काकोडी सम्पर्क मार्ग पर छपकौली शिव मन्दिर गेट की ओर अस्थाई प्रकाश व्यवस्था कार्य जनरेटर से। (समुचित मात्रा में बल्ली, एल०ई०डी० बल्ब सहित 7 दिनों के लिए।	117425	2400	277	7 दिन निरन्तर देखरेख एव व्यवस्था

उपरोक्त कार्यों की समाप्ति दिनॉक 03.08.2024 तक रहेगी, तथा कार्य का मरम्मत/रखरखाव निरन्तर चलता रहेगा। उक्त समय प्रतिबंधित कार्य है, कार्य समय पर समाप्त न हो सकने की स्थिति में शेष कार्य अन्य माध्यम से स्वीकृत ठेकेदारों के जोखिम व मूल्य पर पूर्ण करा लिया जायेगा, तथा जमा अस्थाई धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। निविदा स्वीकार होने की दशा मे कार्य का अनुबन्ध तत्काल कराकर दिनाक 28.07.2024 से कार्य प्रारम्भ करना होगा। उपरोक्त कार्य की अवधि आवश्यकतानुसार अभियता के निर्देशानुसार पुनः रांशोधित की जा सकती है।

अभियता
जिला पंचायत हापुड

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, हापुड़।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना
(ई-टेंडरिंग द्वारा)

कार्य का नाम तथा स्थान	Sr.DEN-III के तहत APNL-BPLN सेक्शन पर LC No. 10 (किमी 10.704) के बदले LHS
कार्य की अनुमानित लागत (रु)	Rs. 21,95,545.78/-मात्र
धरोहर राशि (रु)	Rs. 43,900 /-मात्र
कार्यालय का पता	वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता-C, तृतीय तल, संकेत एवं दूरसंचार ब्रांच, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली-110055
निविदा प्रपत्र जमा करने तथा निविदा खुलने का दिनांक तथा समय।	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने का समय दिनांक 22.07.2024 / निविदा खुलने का दिनांक 14.08.2024 1500 बजे तक
वेब साइट एवं नोटिस बोर्ड का स्थान जहां से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है	उत्तर रेलवे की वेब साइट www.ireps.gov.in पर देखें या देखें नोटिस बोर्ड, तृतीय तल, संकेत एवं दूरसंचार ब्रांच, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली-110055

निविदा संख्या: 558-सिग्नल-10-एन-टेंडर-1427 दिनांक: 22.07.2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 2281/24

पुलिस विभाग **जिला गुरुग्राम**

नीलामी से पहले वाहन क्लेम करने की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस कमिश्नरेट के थाना न्यू कॉलोनी, गुरुग्राम में 16 वाहनों को पुलिस एक्ट व मोटर वाहन एक्ट के तहत पुलिस कब्जा में लिया गया है, जिनकी कानूनी प्रक्रिया के तहत नीलामी की जानी है। अतः वाहन के मालिकों को सूचित किया जाता है कि अगले 06 माह तक वाहनों का रजिस्ट्रेशन नम्बर, ईन्जन नम्बर व चेसिस नम्बर निचे दी गई लिस्ट में चैक करके अपने वाहन के क्लेम के लिए थाना न्यू कॉलोनी, गुरुग्राम के मालखाना प्रभारी के मोबाईल नम्बर 9873670001 पर सम्पर्क कर सकते है। इन वाहनों की लिस्ट पूर्ण विवरण सहित गुरुग्राम पुलिस की वेबसाईट http://gurgaon.haryanapolice.gov.in पर भी उपलब्ध है।

SR. NO	VEHICLE NO.	MARKA	ENGINE NO.	CHASSIS NO.
1	DL3SCE8594	M/C PLETINA	DZZRDG65821	MD2A18AZ3DRG16349
2	HR26DJ6636	M/C I SMART HERO	JA06EPHHC10636	MBLJA06AXHHC10470
3	HR26DC0256	M/C APACHE	OE4PG2122224	MD634KE47G2P76674
4	RJ14SM6128	M/C DISCOVER	DXEBNB56845	MD2DSDXZZNAB55286
5	HR26CW1972	ACTIVA	D13A2814861	MA3FXEB1S00211381
6	HR26DQ9518	ACTIVA	JF50E77072446	ME4JF50AEJ7072432
7	HR28D0907	HERO HONDA SPL	HA10EA99E28990	MBLHA10EJ99E14344
8	DL9ST3574	M/C HERO GLAMOUR	06LASMSI69	06MAYC00086
9	HR26X9485	HERO SPL	20880	4356
10	HR26DF1620	ACTIVA	JF50E75063550	ME4JF507DH7063519
11	HR26BH2307	M/C HERO PASSION	HA10EDAGM20033	MBW1A10AH AGM44123
12	HR26EL1762	ACTIVA	JF91ED0092920	ME4JF913KLD093689
13	DL3SBM9973	HONDA TWISTER	JC47E0056520	ME4JC472FA8038
14	HR26BU6162	M/C PULSER	DKGBVB22209	MD2DHDKZZVCB98855
15	HR26CQ2713	M/C	HA10EWFHF02836	MBLHA10BLOFHR14949
16	WITHOUT NO.	AUTO	NIL	MBX009101K229198

PRDH-1084/11/2551/2025/28179/67/7

हरियाणा सरकार
निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड /निगम/ प्राधिकरण का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खोलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रुपये में	बोर्ड/ निगम/ प्राधिकरण की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ ईमेल
1	एचवीपीएनएल	132 केवी सब स्टेशन एचवीपीएनएल डिंग (सिरसा) में 01 अदद पुराने एवं अप्रचलित 132 केवी गैस सर्किट कंट्रोलर (मेक सीजीएल) कंट्रोलिंग 132/33 केवी 40/50 एमवीए टी1 टी/एफ को बदलना।	22.07.2024 29.07.2024	1.59 LACS	www.hvpn.org.in	0172-2583789 PRO@HVPN.ORG.IN
2	एचवीपीएनएल	66 केवी सब स्टेशन ओसवाल स्टील (फरीदाबाद) में ट्वीन जैबरा कंडक्टर सहित डबल बस बार से सिंगल जैबरा कंडक्टर सहित 66 केवी डबल बस बार का संवर्द्धन।	11.07.2024 12.08.2024	1.58 LACS	www.hvpn.org.in	0172-2583789 PRO@HVPN.ORG.IN
3	एचवीपीएनएल	66 केवी डी/सी पाली-खेड़ी गुजरां लाइन (6वी3608) को समायोजित करने से 220 केवी सब स्टेशन पाली फरीदाबाद में 2 अदद 66 केवी आउटगोईंग बेज की क्रिएशन।	04.07.2024 05.08.2024	600365/-	www.hvpn.org.in	0172-2583789 PRO@HVPN.ORG.IN
4	एचवीपीएनएल	66 केवी सब स्टेशन भूपानी एचवीपीएनएल फरीदाबाद में 2 अदद 66 केवी आउटगोईंग बेज की क्रिएशन।	04.07.2024 05.08.2024	6.16 LACS	www.hvpn.org.in	0172-2583789 PRO@HVPN.ORG.IN
5	एचवीपीएनएल	66 केवी डी/सी पल्ला ए-4 लाइन के एक सर्किट के लिलो को बैक टू बैक व्यवस्था के साथ समायोजित करने के लिए 66 केवी एस/एसटीएन सेक्टर-31 फरीदाबाद में 01 नंबर 66 केवी लाइन बे का निर्माण (6वी3798)	09.07.2024 09.08.2024	3.27 LACS	www.hvpn.org.in	0172-2583789 PRO@HVPN.ORG.IN
6	एचवीपीएनएल	22 केवी सब स्टेशन ए-5, फरीदाबाद में अतिरिक्त 25/31.5 एमवीए, 66/11 केवी टी/एफ प्रदान करना।	29.06.2024 29.07.2024	7.63 LACS	www.hvpn.org.in	0172-2583789 PRO@HVPN.ORG.IN

PRDH-13/2025/120/28159/I/67/7 आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

---

हरियाणा सरकार
निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड /निगम/ प्राधिकरण का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खोलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रुपये में	बोर्ड/ निगम/ प्राधिकरण की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ ईमेल
1	डीएचबीवीएन	डीएचबीवीएनएल के अधिकार क्षेत्र में टर्नकी आधार पर 3 33 केवी सबस्टेशनों की सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (सिविल कार्यों सहित) - डीएचबीवीएनएल के परिचालन सर्कल के अंतर्गत दौलताबाद, गुरुग्राम-I, डीएचबीवीएनएल के परिचालन सर्कल के अंतर्गत बिडोला, भिवानी और डीएचबीवीएनएल के परिचालन सर्कल के अंतर्गत सुरतिया।	19.07.2024 14.08.2024	23.03 CRORES	www.dhbvn.org.in	01662-223216 cepdc@dhbvn.org.in
2	डीएचबीवीएन	फुट सर्वे करने, सिस्टम डिजाइन करने, सामग्री की आपूर्ति, 11 केवी ओवरहेड नेटवर्क को 11 केवी भूमिगत नेटवर्क में परिवर्तित करके मौजूदा 11 केवी के नवीनीकरण / आधुनिकीकरण / उन्नयन / विस्तार / विभाजन के लिए निर्माण के लिए एनआईटी संया टीएसजीपी -08 के तहत आवंटित कार्य के खिलाफ फर्म के जोखिम और लागत पर शेष कार्यों को पूरा करना, 11 केवी आरएमयूएस, एलटी पैनल आदि का प्रावधान, एनआईटी संया के तहत 'ओपी' सर्कल, डीएचबीवीएन गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में और गुरुग्राम के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। टीएसजीपी-17/2024-25 दिनांक 19.07.2024.	19.07.2024 12.08.2024	49.93 CRORES	www.dhbvn.org.in	0124-4286730 sesmartcity@dhbvn.org.in
3	डीएचबीवीएन	फुट सर्वे करने, सिस्टम डिजाइन करने, सामग्री की आपूर्ति, 11 केवी ओवरहेड नेटवर्क को 11 केवी भूमिगत नेटवर्क में परिवर्तित करके मौजूदा 11 केवी के नवीनीकरण / आधुनिकीकरण / उन्नयन / विस्तार / विभाजन के लिए निर्माण, 11 केवी आरएमयूएस, एलटी पैनल इत्यादि का प्रावधान, एनआईटी संया के तहत 'ओपी' सर्कल, डीएचबीवीएन गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में और गुरुग्राम के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फर्म के जोखिम और लागत पर शेष कार्यों को पूरा करना। टीएसजीपी-16/2024-25 दिनांक 19.07.2024.	19.07.2024 12.08.2024	17.53 CRORES	www.dhbvn.org.in	0124-4286730 sesmartcity@dhbvn.org.in

PRDH-13/2025/160/28168/I/67/7 आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

---

हरियाणा सरकार
निविदा सूचना

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	बंद होने की तिथि खोलने की तिथि	राशि/ईएमडी (लगभग) रुपये में	विभाग की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/संपर्क विवरण/ ईमेल
1	लोनिवि भ एवं म गुरुग्राम	वर्ष 2024-25 के लिए फतेहाबाद जिले की सड़क आईडी 5367 और 5545 में भूना फतेहाबाद रोड एसएच-2 के सी/वी में किमी 19.700 से किमी 47.375 तक वृक्षारोपण कार्य का वार्षिक रखरखाव 01/08/24 से 31/08/25 तक 08 महीने की एमटीसी +1 अन्य कार्य	23.07.2024 30.07.2024	32.98 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9717214202 zilesinghhort@gmail.com
2	पंचायती राज सोनीपत	गांव सलीमपुर तरोली ब्लॉक सोनीपत में गऊ घाट से मंदिर वाला तालाब का निर्माण। सीएम कोड 25284 +3 कार्य।	CLOSING DATE 29.07.2024	38.54 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9416391006 prexeeng.snp@gmail.com
3	पंचायती राज सोनीपत	गांव दोदवा ब्लॉक सोनीपत में कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण। एचजीवीवाई +8 कार्य।	CLOSING DATE 29.07.2024	34.46 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9416391006 prexeeng.snp@gmail.com
4	पंचायती राज सोनीपत	गांव एन.पी. चोलका ब्लॉक खरखोदा में फिरनी का निर्माण।	CLOSING DATE 29.07.2024	09.77 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9416391006 prexeeng.snp@gmail.com
5	पंचायती राज सोनीपत	वीएएनजीवाई योजना के अंतर्गत हरमन वाला तालाब से हरसाना माइनर ब्लॉक राई से गांव बिंदरोली में आरसीसी नाले का निर्माण।	CLOSING DATE 29.07.2024	32.75 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9416391006 prexeeng.snp@gmail.com
6	पंचायती राज फरीदाबाद	डांगरः- गांव डांगर ब्लॉक फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद में एससी श्मशान घाट में वाटर टैंक का निर्माण। एचआरडीएफ +9 कार्य।	23.07.2024 30.07.2024	125.55 LACS	https://etenders.hry.nic.in	23085501667 prexeeng.ftb@hry.nic.in
7	पंचायती राज भिवानी	बीआर 1623- गांव रोहनत ब्लॉक बवानी खेड़ा में राज कुमार पुत्र रति राम के मकान से विनोद पुत्र शिव कुमार के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल गली का निर्माण +17 कार्य।	22.7.2024 29.07.2024	145.98 LACS	https://etenders.hry.nic.in	01664243927 prexeeng.bhw@hry.nic.in
8	लोनिवि भ एवं म नरवाना	जिला जींद में उचाना में कम्पोजिट कार्यालय की वार्षिक मरम्मत।	22.07.2024 05.08.2024	4.20 LACS	https://etenders.hry.nic.in	8398098075 pwd-eepd-narwana@hry.nic.in
9	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा हिसार	आउटलेट आरडी 19650/आर एवं 18000/आर और 12320/एल खैरामपुर डिस्टी. में वाटरकोर्स की भूमिगत पाइप लाइन बिछाना/लाइनिंग +3 कार्य।	CLOSING DATE 29.07.2024	11.99 LACS	https://etenders.hry.nic.in	01662230030 xenawsdnhsr@gmail.com
10	पंचायती राज पिंजौर पंचकुला	खोलमोला-जीपी गांव खोलमोला ब्लॉक पिंजौर पीकेएल शिवालिक रोड में स्कूल की चारदीवारी का निर्माण +1 कार्य।	23.07.2024 30.07.2024	9.71 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9466110204 kumar.satish.9417@gmail.com
11	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडी डबवाली	पाइपलाइन, गांव में डिराइजिंग मेन और वितरण पाइपलाइन बिछाने और जल कार्य जलालआना में विविध कार्य। सीएच. से जलालआनाः 'गांव जलालआना जिला सिरसा में एमजीजीबीवाई कॉलोनी में बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण और जलापूर्ति सुविधाएं प्रदान करने का अनुमान (माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जन संवाद के दौरान मांग) [कार्य कोड- पीयूएच/2023-24/102078] (शीर्ष - पी-01-38-4215-01-102-93-94-एन-वी- ग्रामीण जलआपूर्ति (एसपी) - (जलापूर्ति का संवर्द्धन) +1 कार्य	22.07.2024 01.08.2024	431.59 LACS	https://etenders.hry.nic.in	8730000001 ee.mandidabwali@gmail.com
12	पंचायती राज ढांड कैथल	गांव अहून में मेहला पट्टी श्मशान घाट में लोगों हेतु बैठने के शैड का निर्माण, गांव अहून में श्री नोरन नंबरदार के मकान से श्री धर्म सिंह पुत्र श्री दीपा सिंह के मकान तक आईपीबी गली का निर्माण +1 कार्य।	23.07.2024 30.07.2024	16.44 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9416292181 sdoprdhand@gmail.com
13	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा करनाल	वर्ष 2024-25 हेतु डब्ल्यू/एस मैकेनिकल मंडल में एसएस बीआर. एवं बुटाना बीआर. के आरडी 83200 में गेट्स एवं गियरिंग सिस्टम की विशेष मरम्मत।	24.07.2024 30.07.2024	EMD 4000/-	https://etenders.hry.nic.in	9991831221 xen-wsmkrl.irr@gov.in

PRDH-11/2025/260/28170/I/67/7 आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

****

आज का मौसम

बृहस्पतिवार को सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने के आसार है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसार है।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
25 जुलाई	34.0	26.0
26 जुलाई	35.0	27.0
नोएडा		
25 जुलाई	35.0	28.0
26 जुलाई	36.0	28.0
गुरुग्राम		
25 जुलाई	34.0	30.0
26 जुलाई	35.0	29.0

डिग्री सेल्सियस में

दिसंबर तक ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार करने का दिया निर्देश

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जो ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इसे दिसंबर तक तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसे देखते हुए पीडब्ल्यूडी ने पिछले सप्ताह इस पर काम कर रहीं दोनों सलाहकार कंपनियों के साथ बैठक की है और प्रगति रिपोर्ट ली है। पीडब्ल्यूडी ने तीनों जल निकासी के प्रमुख नालों नजफगढ़ बेसिन, बारापुला बेसिन व यमुनापार बेसिन को लेकर कंपनियों को 31 दिसंबर तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर लेने की हिदायत दी। इसी के आधार पर जलभराव की समस्या से समाधान दिलाने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान पर काम शुरू होगा।

आइटीओ के समीप विकास मार्ग पर जलभराव से गुजरते वाहन • चंद्र प्रकाश मिश्र

लोक निर्माण विभाग की योजना ऐसे ड्रेनेज मास्टर प्लान को तैयार करना है, जिस पर काम किया जा सके और इसे लागू करने में जनता को ज्यादा असुविधा न हो।इसे लेकर दिल्ली को तीन भागों में बांटकर काम किया जाएगा। दिल्ली ड्रेनेज मास्टर प्लान का उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के अंदर जल निकासी में सुधार करना है। इसके अनुसार करीब 30-35 वर्षों के लिए जल निकासी के संदर्भ में एक मास्टर प्लान तैयार करना है। प्लान के तहत यह पता लगाया जाना है कि किस नाली का स्लोप खराब है, कौन सी नाली कहां मिलती है और किस नाली को किस नाले से जोड़ना है। इतना ही नहीं, हर नाली और नाले की योजना बनाई जानी है।वर्ष 1911 में दिल्ली का पहला मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किया गया था। वर्ष 1968 में इसकी समीक्षा हुई और वर्ष 1976 में ड्रेनेज प्रणाली तैयार की गई थी। उस समय दिल्ली की आबादी 60 लाख थी। अब आबादी दो करोड़ से अधिक है।

दिल्ली में हैं 201 प्राकृतिक नाले: दिल्ली में 201 प्राकृतिक नाले हैं, जो तीन प्राकृतिक जल निकासी बेसिन के जरिए यमुना में गिरते हैं। नजफगढ़ नाले में 123 ड्रेन मिलते हैं। वहीं बारापुला नाले में 44 ड्रेन और ट्रांस यमुना बेसिन में 34 नाले मिलते हैं। नजफगढ़ नाला 63.06 प्रतिशत ड्रेनेज एरिया को कवर करता है। बारापुला 24.28 प्रतिशत और ट्रांस यमुना बेसिन 12.66 प्रतिशत ड्रेनेज एरिया को कवर करता है।

नाले-नालियों की लंबाई 3,740 किलोमीटर है

दिल्ली में छोटे-बड़े करीब 2,846 नाले-नालियां हैं और इनकी लंबाई करीब 3,740 किलोमीटर है।इसमें नालों का एक बड़ा हिस्सा पीडब्ल्यूडी के पास है और पीडब्ल्यूडी इसका नोडल विभाग भी है। जल निकासी के दिल्ली में तीन बड़े नाले हैं। इसमें ट्रांस यमुना, बारापुला और नजफगढ़ हैं।इसके अलावा कुछ बहुत छोटे नाले अरुणा नगर और चंद्रवाल भी हैं, जो सीधे यमुना में गिरते हैं।

P.K. GROUP OF INSTITUTIONS
MATHURA (U.P.)
Courses Approved by AICTE/ UGC
Faculty of Engineering & Technology:
POLYTECHNIC
B.TECH
M.TECH
(Lateral Entry in Diploma & B.Tech)
ADMISSION OPEN
2024-25
अपने करियर की मजबूत नींव रखिए हमारे साथ
प्राइवेट कंपनी/ प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी हमारे संस्थान से इंजीनियरिंग कोर्स पूर्ण कर पदोन्नति हेतु अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सीट सीमित है प्रवेश हेतु शीघ्र संपर्क करें।
Campus:Hathras Road, Sonai, Mathura (U.P.)
Mob.: +91-9897379333
www.pkuniversity.edu.in

QUALITY SINCE 1980
KANODIA
कानोडिया कोल्हू ब्रांड
कच्ची घानी और पीली सरसों का तेल

सात नवजात की अस्पताल में हुई थी मौत, आग की वजह पता नहीं

बेबी केयर न्यू बोर्न अस्पताल अग्निकांड में आरोपपत्र दाखिल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली: विवेक विहार के बेबी केयर न्यू बोर्न अस्पताल में 25 मई की रात आग में झुलसकर सात नवजातों की मौत हुई में करीब दो माह बाद भी दिल्ली सरकार का विद्युत व दमकल विभाग यह पता नहीं लगा पाए है कि आग कैसे लगी थी। विद्युत विभाग ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में शार्ट सर्किट को आग का कारण नहीं माना है। पुलिस ने इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। विवेक विहार थाना ने अस्पताल संचालक डा. नवीन खीची व अस्पताल के डा. आकाश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, किसी व्यक्ति की जान को नुकसान पहुंचाना, लापरवाही से मौत समेत कई धाराओं में प्राथमिकी की थी। दोनों आरोपित को जमानत नहीं मिली है।

पुलिस ने आरोपत्र में बताया है कि बेबी केयर अस्पताल का लाइसेंस मार्च में ही खत्म हो गया था। अवैध रूप से अस्पताल चल रहा था। अस्पताल पांच बेड का था, नियमों का उल्लंघन कर 12 नवजात को अस्पताल में भर्ती किया हुआ था। अस्पताल में न अग्निशमन यंत्र थे और न ही निकास की उचित व्यवस्था थी। डा. आकाश को बच्चों के इलाज के लिए रखा हुआ था। वह बीएएमएस डाक्टर है। नियम के अनुसार बीएएसएस डाक्टर बच्चों का इलाज नहीं कर सकते। इसके लिए एमडी डाक्टर चाहिए होता है। नवजातों में अस्पताल कार्यरत नर्सों को दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए, लेकिन अस्पताल की नर्सों को इतना अनुभव नहीं था। दो राहगीरों ने आग की सूचना पुलिस को दी थी, जबकि सीसीटीवी में दिख रहा है कि आकाश को 11 बजे ही आग लगने का पता चल गया था। उसने पुलिस को सूचना देने के बजाय अस्पताल के संचालक नवीन से फोन पर बात करता रहा था। यदि समय पर पुलिस को सूचना मिलती तो बच्चों की जान बच सकती थी। नियम के अनुसार 20 आक्सीजन सिलेंडर ही अस्पताल में रखे जा सकते हैं। हादसे के वक्त सिलेंडर की संख्या 31 थी। अस्पताल की छत पर एक रसोई बनाई हुई थीं। वहां पर एक कर्मचारी चाय व खाना बनाता था।

विवेक विहार स्थित बेबी केयर न्यू बोर्न अस्पताल • जागरण आर्काइव

दिल्ली में रेलवे के विकास पर खर्च होंगे 2,582 करोड़

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: दिल्ली में रेलवे के आधारभूत ढांचा को मजबूत करने और रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम चल रहा है। इससे जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं और संरक्षा कार्य पर इस वर्ष 2,582 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अंतरिम बजट में इसके लिए 2,577 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया था, जिसमें पांच करोड़ रुपये और बढ़ा दिए गए हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2009-2014 तक दिल्ली को प्रत्येक वर्ष औसत 96 करोड़ रुपये मिलते थे। अब यह लगभग 27 गुना बढ़ गया है। यूपीए के शासनकाल में रेलवे के आधारभूत ढांचा, संरक्षा आदि पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में इन कामों में तेजी आई है। वर्ष 2009-14 तक दिल्ली में एक किलोमीटर भी नई रेल लाइन नहीं बिछाई गई। उसके बाद प्रतिवर्ष 2.4 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई है। 302 किलोमीटर नई लाइन बिछाने का काम चल रहा है जिस पर कुल 4,778 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सुरक्षित रेलवे लाइन पार करने और सड़क यातायात में होने वाली परेशानी दूर करने के लिए पिछले 10 वर्षों में दिल्ली 13 नए फ्लाईओवर व अंडरपास बनाए गए हैं।

पिछले वर्ष से 105 करोड़ रुपये अधिक मिले: रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष के बजट में भी 2,477 करोड़ रुपये दिल्ली को मिले थे। इस वर्ष इसमें 105 करोड़ की वृद्धि की गई है। बजट बढ़ने से रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, यात्रियों सुविधाओं में सुधार के साथ ही संरक्षा कार्य में तेजी आएगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव •

- रेल मंत्री ने कहा, यूपीए के शासनकाल से 27 गुना अधिक बजट दिया गया

दिल्ली में विकसित हो रहे 13 अमृत स्टेशन

अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है।नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, नरेला, आदर्श नगर, आनंद विहार, बिजवासन, दिल्ली छावनी, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली शाहदरा, सब्जी मंडी, सफदरजंग और तिलक ब्रिज।

भाजपा का यह कुर्सी बचाने वाला बजट

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: केंद्रीय बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने दूसरे दिन भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। आप के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सदस्य डा. संदीप पाठक ने बुधवार को कहा कि इस बार का बजट बेहद निराशाजनक रहा है। केंद्र सरकार ने इस बजट में दिल्ली और पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को दिल्ली में हुई आइएनडीआइ गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। उनका शुगर लेवल बार-बार कम हो रहा है। इस पर एलजी चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि आप यह नहीं खा रहे हैं, वह नहीं खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक इंसान की जान का सवाल है और आप इस तरह का घटिया मजाक कर रहे हैं।

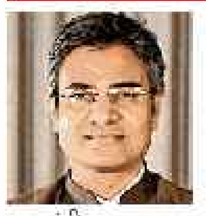

संदीप पाठक

- पाठक ने कहा कि दिल्ली-पंजाब के साथ किया सौतेला व्यवहार

तथ्यहीन बयानबाजी कर रही है आप

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी केंद्रीय बजट को लेकर तथ्यहीन बयानबाजी कर रही हैं। वह यह झूठ फैला रही हैं कि बजट में दिल्ली को कुछ नहीं मिलता है। प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने दिल्ली के विकास और अन्य मद में साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। यह राशि इस अवधि में दिल्ली सरकार के अपने बजट से भी अधिक है। सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट का लाभ समाज के हर वर्ग को मिलेगा। केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार की योजनओं से दिल्लीवासियों को वंचित कर रही है।

वीरेंद्र सचदेवा

- दिल्ली की वित्त मंत्री झूठ फैला रही हैं कि बजट में दिल्ली को कुछ नहीं मिला: सचदेवा

मुद्दा

पढ़ें जागरण सिटी

वित्त आयोग का गठन करने के लिए एलजी को पत्र लिखा

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं विधायक विजेंद्र गुप्ता ने छठे दिल्ली वित्त आयोग के गठन के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उपराज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है, पांचवें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश मार्च 2021 तक लागू थी। अप्रैल 2021 में छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन हो जाना चाहिए था। इसका गठन नहीं होने से दिल्ली सरकार पांचवें दिल्ली वित्त आयोग की पुरानी सिफारिश के आधार पर नगर निगम को धन प्रदान कर रही है। यह गैर संवैधानिक और दिल्लीवासियों के साथ अन्याय है। पहले भी दिल्ली सरकार ने चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिश को लागू नहीं किया था।

क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर को पांच दिन की ईडी की हिरासत में भेजा

- अमेरिकी महिला से धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले में एजेंसी ने किया था गिरफ्तार
- अमेरिकी महिला से 3.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र: मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने क्रिप्टोकरेंसी हैंडलर लक्ष्य विज को पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने बुधवार को बताया कि विज को मनी लांड्रिंग मामले में 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

एजेंसी ने एक्स पर पोस्ट किया कि 22 जुलाई को पीएमएलए के तहत क्रिप्टो करेंसी हैंडलर लक्ष्य विज को गिरफ्तार किया था। उसे 23 जुलाई को विशेष न्यायालय (पीएमएलए) नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उसे पांच दिन की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने सात दिन के लिए हिरासत मांगी थी, लेकिन विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने 28 जुलाई तक के लिए ही हिरासत मंजूर की।

इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी 23 जुलाई को मनी लांड्रिंग मामले में लक्ष्य विज को पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। यह मामला एक अमेरिकी महिला के साथ चार लाख डालर (लगभग 3.35 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी और फर्जी संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से मनी लांड्रिंग से जुड़ा है। विशेष अदालत ने आदेश में कहा कि वाट्सएप संदेशों के अंश और धन के स्रोत का पता लगाने के साथ ही इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए आरोपित लक्ष्य विज को 28 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा जाता है। आरोपित के वकील नितेश राणा ने हिरासत की मांग का विरोध किया और कहा कि गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। ईडी ने कहा कि विज का मामला सीबीआइ की ओर से प्रफुल्ल गुप्ता और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले पर आधारित है, जिसमें कथित तौर पर आपराधिक साजिश रचने और अमेरिकी नागरिक के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।

पीयूसी जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाएगी दिल्ली सरकार

- डीएमआरसी और आइजीएल से अपनी साइटों पर पीयूसी जांच केंद्र बनाने का किया अनुरोध
- पीयूसी जांच केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश, कुछ केंद्रों को दिए गए नोटिस

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए पीयूसी जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाने के प्रयास में दिल्ली सरकार शहर के भीतर नए पीयूसी जांच केंद्र स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्थानों को चिह्नित कर रही है। इस सिलसिले में परिवहन विभाग ने दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) से अपनी साइटों पर नए पीयूसी जांच केंद्र खोलने का अनुरोध किया है।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि पीयूसी जांच केंद्रों की संख्या में वृद्धि करके हम वाहनों के प्रदूषण जांच को आसान बनाना चाह रहे हैं। वर्तमान में दिल्ली में 900 से अधिक पीयूसी जांच केंद्र हैं, जिनमें 700 से अधिक पेट्रोल पंपों पर स्थित हैं। इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्य परिवहन विभागों को प्रत्येक पेट्रोल पंप पर पीयूसी जांच केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया था। हाल ही में परिवहन विभाग ने पाया कि कुछ पीयूसी जांच केंद्र इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। नतीजतन प्रवर्तन टीमों को गैर-अनुपालन वाले पीयूसी जांच केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें ऐसे पीयूसी जांच केंद्रों के संचालन का निलंबन भी शामिल है। परिवहन विभाग ने बंद पीयूसी जांच केंद्रों का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए पेट्रोप पंपों पर बंद पड़े पीयूसी को लेकर कारण बताओ नोटिस देना शुरू कर दिया है।

विज्ञापन संख्या 65/2024
भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड - इंडिया)
में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
आवेदकों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि
16 अगस्त, 2024 है।
नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदनों को
लोक उद्यम चयन बोर्ड में अग्रेषित करने की अंतिम तिथि
27 अगस्त, 2024 है।
जानकारी के लिए वेबसाइट
https://pesb.gov.in
में लॉग इन करें।

डील ऑफ द वीक
have great stories to tell
मीनिमम छुट्टी, मैक्सिमम मौज!
अगस्त लाँग वीकेन्ड सेल
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त | रक्षा बंधन 19 अगस्त | जन्माष्टमी 26 अगस्त
• सबसे अच्छी कीमत की गारंटी • ₹ 40 000.00 तक की छूट
• हर बुकिंग पर गारंटीड गुडीज़

एस्कॉर्टेड इंटरनेशनल हॉलिडेज़, फ़्लाइट्स के साथ
5 दिन - अज़रबैजान @ ₹ 85 800.00 | मलेशिया - सिंगापुर 7 दिन @ ₹ 98 500.00 | 7 दिन - वियतनाम @ ₹ 1 32 900.00
भारत और उसके आसपास छुट्टियां
6 दिन - लद्दाख @ ₹ 22 500.00 | 5 दिन - श्रीलंका @ ₹ 38 600.00 | 7 दिन - कश्मीर @ ₹ 38 950.00
कीमतें प्रति वयस्क व्यक्ति के लिए हैं और इनमें शामिल हैं : एक्स-दिल्ली हवाई किराया (जहां निर्दिष्ट किया गया है), वीज़ा शुल्क, क्वालिटी होटल्स, भोजन, इंश्योरेंस और साइटसीइंग यात्रा कार्यक्रम के अनुसार. सभी प्रचलित टैक्स मौजूदा दरों पर लागू हैं
अपनी निकटतम स्टोर में कॉल करें
Connaught Place: 9619471251
GK 2 M Block: 9167685180
Punjabi Bagh: 8291226157
Pitampura: 9167433175
Rohini: 8291283717
RDC, Ghaziabad: 9619605891
Laxmi Nagar: 9167433568
Netaji Subhash Place: 8291458224
Noida - Sec 18: 8291224852
South Extension Part 2: 8879229851
thomascook.in | Thomas Cook
*नियम व शर्तें लागू. कोई भी बुकिंग करने से पहले हमारे सेल्स स्टाफ़/ thomascook.in / शर्तें व एफ्क्यू की मदद से सभी संबंधित विवरणों की पुष्टि कर लें.

MANGALAYATAN UNIVERSITY
ALIGARH
Learn Today to Lead Tomorrow
NAAC A+ GRADE Accredited University
Recognized by UGC | Member of AIU | Approved by NCTE | Approved by PCI | Approved By BCI | Approved By NCISM

5000+ Students from India & Abroad | 70+ Wide range of course | 400+ Top Corporate Recruiters | 150+ High-Tech Laboratories & Computer Labs | 350 Bedded Hospital | 25000+ Alumni Trust Base
ADMISSION OPEN 2024-25
PROGRAMS OFFERED
ENGINEERING | COMPUTER APPLICATION | MANAGEMENT
COMMERCE | BIOTECH | AGRICULTURE | PHARMACY | NURSING
GNM | PARAMEDICAL | BAMS | LAW | JOURNALISM | FINE ARTS
EDUCATION | APPLIED SCIENCE | ARTS | FORENSIC SCIENCE
POLYTECHNIC DIPLOMA | LIBRARY SCIENCE | HOTEL MANAGEMENT | Ph.D
HIGHLIGHTS:
300+ Top Faculties
150+ Labs for Experimental Learning
Incubation Centers for Nurturing Start-Ups
93% Placement in the last 5 years
100+ Patents granted and published
2000+ Research Articles Published in Renowned Journals
30 Acre Starts Area for outdoor and indoor games
Separate Hostels for Boys and Girls
DISTANCE & ONLINE PROGRAMS
B.Sc | BA | BBA | B.Com
BCA | B.Lib | B.A (JMC)
MA | M.Sc | M.Com | MBA | MCA
M.SC | M.Lib | PGDCA
Approved DEB of UGC
Contact:- 079696 62588
www.muonline.ac.in
Extended NCR, 33rd Milestone, Mathura-Aligarh Highway, Beswan, Aligarh, Uttar Pradesh 202145
MANGALAYATAN UNIVERSITY ALIGARH Learn Today to Lead Tomorrow
09359 555 555
07500 011 188
www.mangalayatan.in
admissions@mangalayatan.edu.in

वर्षा और बादलों की आवाजाही ने गर्मी से दिलाई राहत

अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में दर्ज की गई गिरावट, आज हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: बुधवार सुबह हुई झमाझम और दिन में रुक रुककर होती रही हल्की बरसात ने दिल्ली वासियों को गर्मी से तो कुछ राहत दिलाई ही, तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। बृहस्पतिवार को भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है।

बुधवार सुबह जब दिल्ली वासी सोकर उठे तो बाहर काले घने बादल छाए हुए थे। देखते ही देखते तेज वर्षा शुरू हो गई, जो लगभग डेढ़ घंटे तक चलती रही। इसके बाद भी दिन भर बादल छाए रहे और बीच-बीच में रुक रुककर बूंदाबांदी अथवा हल्की वर्षा होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटे में 27.0 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई जबकि सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक 9.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

वर्षा और बादलों की आवाजाही का असर तापमान पर भी देखने को मिला। अधिकतम तापमान जहां सामान्य से एक डिग्री कम 33.8 डिग्री दर्ज किया गया। इसी तरह से न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 24.8 डिग्री रिकार्ड किया गया। हवा में नमी का स्तर 100 से 74 प्रतिशत रहा। इसके चलते दिल्ली वासियों को गर्मी व उमस का सामना भी करना पड़ा।

मौसम विभाग का अनुमान है कि बृहस्पतिवार को भी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बादलों की आवाजाही भी दिनभर बनी रहेगी। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 और 26 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है।

वहीं, मौसम की मेहरबानी से दिल्ली की हवा भी लगातार साफ बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का एक्यूआइ 97 रहा। इस स्तर की हवा को 'संतोषजनक' श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के दौरान भी वायु गुणवत्ता का स्तर लगभग इसी के आसपास रहने की संभावना है।

कहां कितनी वर्षा (मिमी में)

स्थान	सुबह 8:30 तक	शाम 5:30 तक
सफदरजंग	27.0	9.0
पालम	17.8	1.6
लोधी रोड	24.2	0.9
रिज क्षेत्र	26.6	0.7
आयानगर	14.2	0.8
दिल्ली विवि	29.0	1.0
नरेला	34.0	0.0
नजफगढ़	10.5	0.0
पीतमपुरा	9.5	0.0

नई दिल्ली में बुधवार को झमाझम वर्षा हुई, इस दौरान छाते के माध्यम से बच्चों को भीगने से बचाकर लेकर जाती महिला • प्रेट्र

फर्जी काल सेंटर से 19 आरोपित गिरफ्तार

जासं, फरीदाबाद: साइबर थाना पुलिस ने एक फर्जी काल सेंटर से पांच युवतियों सहित 19 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। काल सेंटर से साइबर ठगी की जाती थी। आरोपितों के कब्जे से 45 लैपटाप और 19 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। सेक्टर-सात चौकी पुलिस को पता चला कि कुछ लोग फर्जी काल सेंटर चला रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एसीपी साइबर क्राइम अभिमन्यु ने साइबर थाना बल्लभगढ़ और सेक्टर-सात चौकी की पुलिस टीम के साथ मौके पर जाकर छापा मारा।

गिरफ्तार आरोपितों में काल सेंटर प्रबंधक राकेश, दिल्ली के प्रदीप कुमार, आपसन, अमन राज, जेवियर, नितिन शर्मा, चरणदीप सिंह, विनोद राम, निशांत गोस्वामी, अमित, राजू, सांचों पटूटीन, आदर्श कुमार निवासी नोएडा, अलविश निवासी गाजियाबाद, महिला आरोपित सना, निशा, येंगरकुमला, चुंबेनी निवासी दिल्ली तथा रक्षा निवासी नोएडा के नाम शामिल है।

कारोबारी की वोल्वो कार बनी आग का गोला, बाल-बाल बचे

- चरखी दादरी से गाजियाबाद अपने घर जा रहे थे खनन कारोबारी
- एनएच 334बी पर झरोठ गांव के पास अचानक कार में लगी आग

राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी पर वोल्वो कार में लगी आग • वीडियो ग्रेब

संवाद सहयोगी, जागरण • सोनीपत: राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी पर बुधवार की शाम झरोठ गांव के पास गाजियाबाद के खनन कारोबारी की लग्जरी कार वोल्वो में अचानक आग लग गई। कारोबारी ने जब कार में धुआं उठता हुआ देखा तो कार को आनन-फानन में रोका और बाहर निकले। कुछ ही देर में आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

गाजियाबाद के गोविंदपुर के रहने वाले योगेंद्र वोल्वो बी-04 कार से चरखीदादरी से अपने घर जा रहे थे। उनका माइनिंग का कारोबार है। उन्होंने कहा कि अचानक कार में दो बार झटका सा लगा। इसके बाद कार से धुएं के साथ आग की लपटें भी दिखाई देने लगीं, इस पर कारोबारी ने कार को सड़क किनारे किया और उतर गए।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफार्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

आप नेता संजय सिंह का एडिटेड वीडियो प्रसारित

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली: इंटरनेट मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में संजय सिंह को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। वहां पर उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उनका वजन जेल जाने से पहले 70 किलोग्राम था, लेकिन अब कुछ ही महीनों में उनका वजन 8.5 किलो तक गिर गया है और 81.5 किलोग्राम हो गया है। यूजर्स इस वीडियो को संजय सिंह पर तंज कसते हुए और उनका मजाक उड़ाते हुए शेयर कर रहे हैं।

पड़ताल: जांच के दौरान हमें पूरा वीडियो एक न्यूज चैनल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 15 जुलाई, 2024 को अपलोड किया गया था। संजय सिंह ने जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर यह प्रेस कान्फ्रेंस की थी। वीडियो में 24.29 मिनट से उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है।'

निष्कर्ष: विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि संजय सिंह के प्रसारित वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। संजय सिंह की जुबान फिसल गई थी। पहले उन्होंने कहा था कि केजरीवाल का वजन 70 किलोग्राम से 8.5 किलोग्राम घटकर 81.5 किलो हो गया है। हालांकि, उन्होंने तुरंत ही सुधार करते हुए कहा कि वजन 8.5 किलोग्राम घटकर 61.5 किलो हो गया है।

क्या हो रहा है प्रसारित

फेसबुक यूजर सुशील कुमार ने 19 जुलाई, 2024 को प्रसारित वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'अरविंद केजरीवाल का वजन 70 केजी में 8.5 किलो वजन कम होने के बाद 81.5 केजी हो गया है। यह बहुत अधिक पढ़े लिखे नेता संजय जनता को बता रहे हैं।'

झूठी खबर और अफवाहों का सच जानने के लिए विश्वास न्यूज के वाट्सएप चैनल को फालो करने के लिए कोड स्कैन करें।

26 गैर-नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए सलाहकारों की नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी के 26 गैर-नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास कार्य के लिए सलाहकारों की नियुक्ति कर दी है। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) ने उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटित किए जाने वाले 40 प्रतिशत क्षेत्र के लिए एक आर्किटेक्चर कंसल्टेंट फर्म को सूचीबद्ध किया है।

गुरुग्राम नगर निगम पर लगाया 50 हजार जुर्माना

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़: पालतू जानवरों की प्रतिबंधित नस्ल से संबंधित मामले के तथ्यों से अनभिज्ञ अधिकारी को नियुक्त करने पर नाराजगी जताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुग्राम नगर निगम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। संबंधित अधिकारी से यह राशि वसूलने को निगम स्वतंत्र होगा। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने समीर बर्मा एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए हैं। गुरुग्राम नगर निगम के दायरे में पालतू पशुओं के रूप में रखे जाने वाले प्रतिबंधित नस्लों के संबंध में यह मामला 2022 से हाई कोर्ट में लंबित है। निगम की ओर से 15 अप्रैल को हलफनामे के माध्यम से स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें प्रतिबंधित नस्लों की बारीकियों की जांच और नियंत्रण के लिए उठाए कुछ कदमों के बारे में बताया गया था। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने नगर निगम से स्पष्ट पूछा था कि प्रतिबंधित श्रेणियों से संबंधित कुल कितने कुत्तों को निवासियों द्वारा पालतू पशुओं के रूप में रखा गया है, कुल कितने प्रतिबंधित नस्ल के कुत्तों को पंजीकृत किया गया है। मामला 22 जुलाई को हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो निगम के वकील ने जवाब देने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक सेनेटरी इंस्पेक्टर को नियुक्त किया है, लेकिन वह मामले के तथ्यों से परिचित नहीं है और उसके पास अपेक्षित डाटा नहीं है।

मंत्री ने आटो चालकों को समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: दिल्ली के आटो यूनियनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से मुलाकात की। उन्होंने मंत्री के समक्ष अपने समस्याएं रखीं, जिस पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि दिल्ली सरकार हमेशा आटो चालकों का साथ देती रही है और हम आगे भी सरकार से सहयोग मिलने की उम्मीद करते हैं। परिवहन मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को उनके सभी समस्याओं का यथा शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि परिवहन विभाग ने बुराड़ी से हटाकर राजपुरा रोड पर कार्यालय बनाया है, लेकिन अभी वहां वाटर कूलर नहीं लगा है और वेटिंग एरिया भी नहीं बना है। उन्होंने कहा कि आटो का लाइसेंस बनवाने लिए आटो चलाकर टेस्ट देना पड़ता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने नया नियम बना दिया है कि अगर आटो चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना है तो कार चलाकर टेस्ट देना होगा। इससे उन आटो चालकों को दिक्कत हो रही है, जिनको कार चलानी नहीं आती है और वह आटो का लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे हैं। इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर अधिकारियों से बात कर इसके समाधान का रास्ता तलाशेंगे।

दैनिक जागरण क्लासीफाइड
कम दाम, ज्यादा काम

आवश्यकता

आवश्यकता है एक फील्ड बॉय की जो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्टर्स से प्लास्टिक बैग का ऑर्डर ले सके, जिसे कम से कम 5 साल का अनुभव हो। 9871005444, 9811020224

सूचना

सूचित किया जाता है कि कौशल्या देवी पत्नी स्व. देवेन्द्र भाटी R/o म.न.71, गाँव हरी नगर, नियर बड़ी चौपाल, बदरपुर नई दिल्ली-44 (आधार कार्ड न. 8934 0345 6118) अपने पुत्र रोहित भाटी व अपनी बहू प्रीती नागर को अपने एक मकान न. सी-1/132, खसरा न.936, जो कि सी-ब्लॉक, हर्ष विहार, हरी नगर विस्तार पार्ट-3, बदरपुर नई दिल्ली से बेदखल करती हूँ और अगर भविष्य में मेरे पुत्र रोहित भाटी व बहू प्रीती नागर किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना किसी भी अन्य व्यक्ति से करते है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं ही होंगे इससे मेरे मुवक्किल का किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नही होगा। दिलीप भोई (एडवोकेट)

My client Om Prakash S/o Sh. Chothmal R/o F-1/117, Sultanpuri, Delhi-110086 severe all relations and debar his sons Rajesh Kumar, his wife Pooja Katyal and Sachin, his wife Neha from entire moveable/immovable properties due to their arrogant and hostile behaviour. My client shall not be responsible for their acts, debts and deeds in future. Aashi Agarwal, Advocate

मेरी मुवक्किल सुरेश पत्नी स्वर्गीय श्री विनोद कुमार निवासी: डब्लु जेड-174, हरिजन कॉलोनी, ब्लॉक डब्लू जेड, तिलक नगर, तिलक नगर एस ओ, वेस्ट दिल्ली-18, ने अपनी पुत्री पदमा को उसके दुर्व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल-अचल सम्पति से बेदखल कर अपने सभी संबंध-बिच्छेद कर लिए हैं, भविष्य मे उसके किसी भी कृत्यों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगी। नरेंद्र सांगवान (अधिवक्ता)

मेरे मुवक्किल राजपाल सैनी निवासी- ख.न. 8/19, 9/11, गली न.6, भटा रोड, स्वरूप नगर, लिबास पुर, दिल्ली-42 ने अपनी पत्नी रजनी सैनी के अपने साथ गलत आचरण व दुर्व्यवहार करने के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है भविष्य में मेरी पत्नी रजनी सैनी के किसी भी कार्य के लिए मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नही होगें। (शशीकान्त, अधिवक्ता)

सार्वजनिक सूचना

अवर न्यायाधीश सप्तम, मौकाम-दरभंगा

अंजु राय - वगैरह............वादीगण
बनाम
राजकुमार राय ....प्रतिवादी

हकीयत वाद संख्या-607/2023

नोटिस बनाम - राजकुमार राय पुत्र स्व0 रामविलास राय वर्तमान पता - प्लॉट नं. 24 के एच नं0 304/254/109 ग्राउण्ड फ्लोर स्ट्रीट नं. 2, ब्लॉक डी नेयर बाई दयावती पब्लिक स्कूल, भीखाजी मुकुन्दपुर, न्यू दिल्ली 110042

चूँ नोटिस के आपलोगों को अगाह किया जाता है कि वादी ने खिलाफ आप लोगों के अदालत हाजी में हकीयत का उपरोक्त वाद दायर किया है जिसमें अदालत से सम्मन वो भी रजिष्टर्ड सम्मन के हाजिर होकर मुनासिब पैरवी करने को ताकीद किया गया लेकिन आपलोग हाजिर अदालत नहीं हो रहे हैं। इसलिए वजरिए गजैट नोटिस आप लोगों को सूचित किया जाता है कि तारीख 16/08/2024 वक्त 10.30 बजे दिन में असालतन ख्वाह वकालतन हाजिर होकर मुनासिब पैरवी करें, वरना आप लागों की गैर हाजिरी में एक तरफा सुनवाई कर फैसला फरमाया जावेगा। इसे ताकीद जानें।

अवर न्यायाधीश सप्तम्, व्यवहार न्यायालय, दरभंगा

मेरी मुवक्किल शकुंतला पत्नी श्री उमा शंकर निवासी हाउस नंबर 1791, ए-ब्लॉक, फेस-2, मेट्रो विहार, होलंबी कलां, नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली-82 अपने पुत्र आशीष और पुत्रवधू संगीता को उनके गलत व्यवहार के कारण अपने सभी संबंध विच्छेद एवं अपनी चल-अचल संपत्ति से बेदखल करती है। यदि कोई व्यक्ति उनके साथ संबंध रखता है तो उसके लिए मेरी मुवक्किल किसी भी तरह से भविष्य में जिम्मेदार नहीं होगी। Surander Kumar (Advocate)

नाम परिवर्तन

I, Kartayva Gupta S/o, Sunil Kumar Gupta R/o C-320, Vivek Vihar, Delhi 110095 have changed my name to Kartavya Gupta for all purposes

I, JAIPAL SINGH S/o Munshi Ram R/o Plot No. 13-B Kh.No. 421, Karan Vihar, Ph-1, Kirari Extn., Rohini, Delhi-110086 have changed my name from JAI PAL to JAIPAL SINGH for all future purposes.

I, Deepa Arya, wife of Bhuwan Chandra, resident of RZC-321, AMBIKA ENCLAVE, NIHAL VIHAR, NANGLOI, WEST DELHI-110041 do hereby declare that my name has been incorrectly recorded as " Deepa " in my husband 's service records. My correct name is " Deepa Arya ".

उत्तर रेलवे

निविदा रद्द करना

प्रशासनिक कारण के कारण एन आई टी संख्या डब्लू.टी.सी.-06-24-25 को रद्द कर दिया गया है। जिसे 31.07.2024 को खोला जाना है।

काम के नाम और विस्तृत नीचे दिये गए है :-

1. उप मुख्य अभियंता/टी.एम.सी./ना. उत्तर रेलवे स्टेट एन्ट्री रोड, नई दिल्ली के अधीन टीएमएमसी लोकेशन, एलकोडी और टीकेडी में यूटीवी 2001, 2002, 2004, 3061 और 10072 ट्रैक मशीनों का पीओएच।

2. काम की अनुमानित लागत (रुपये): 24641384.56

No.1-W/Dy.CE/TMC/LNDLS/Tender Corresp. Dated: 24.07.2024 2263/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

PSPCL पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(पंजीकृत कार्यालय पीएसईबी मुख्य कार्यालय माल पटियाला 147001)
कार्यालय: अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, डी.एस. मंडल, लुधियाना
क्वार्टर नं. 20, टाइप 5, पावर कॉलोनी 2, सराभा नगर, लुधियाना 141001
मोबाइल नं. 96461 13015,
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U40109PB2010SGC033813

ई निविदा नं. 01/डी.एस.मंडल लुधियाना/2024-25 तिथि 23.07.2024

अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता/डी.एस. मंडल लुधियाना क्वार्टर नं. 20, टाइप-5, पावर कॉलोनी-2, सराभा नगर, लुधियाना-141001 द्वारा निम्नानुसार एक नं. ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

1) मैस. के.एस. अलवाड़ा, गांव कुंभ, अमलोह रोड, मंडी गोबिंदगढ़ के पक्ष में भार को बढ़ाने के लिए 66 केवी लाइन के निर्माण करवाने के लिए, उपभोक्ता की फंडिंग के तहत कार्य के लिए, और ढांचों का निर्माण और कंडक्टर सहित अन्य बाकार और पीएसपीसीएल द्वारा उपलब्ध निर्देशों के अनुसार इस कार्य से संबंधित सभी कार्य आदि किये जायेंगे। (जमा अनुमान)

विस्तृत निविदा पत्र सूचना और निविदा स्पेसिफिकेशन https://eproc.punjab.gov.in पर तिथि 26.07.2024 को शाम 5.00 बजे के बाद पर देखा जा सकता है।

नोट: संशोधन, यदि कोई है, तो https://eproc.punjab.gov.in पर देखा जा सकता है।

C-485/24 R.No. 76155/12/3168/2023/35999

रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र

चाणक्यपुरी, दिल्ली-110021

निविदा संख्या 01245064A विषय: CRIS (मुख्यालय), चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में 1 वर्ष की अवधि के लिए एंटवायरस वार्षिक रखरखाव अनुबंध (AMC) की खरीद। निविदा समापन तिथि: 14.08.2024 (बुधवार) 15:30 बजे। निविदा पहले वेबसाइट www.ireps.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य में संशोधन/विस्तार के लिए कृपया www.ireps.gov.in देखें।

रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

निविदा संख्या 01245072A

विषय: जीआरसी और एसीकेयान सुरक्षा के लिए व्यापक नियंत्रण और कार्य प्रबंधन सुधार की खरीद। समापन तिथि: 20.08.2024 (मंगलवार) 15:30 बजे। प्री बोली बैठक: 01.08.2024 (11.00 बजे) क्रिस आईटीपीआर्क बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस हॉल, तीसरी मंजिल, आईटीओ के पास नई दिल्ली-110002 निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.ireps.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। भविष्य में संशोधन/विस्तार के लिए कृपया www.ireps.gov.in देखें।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से, मुख्य कार्यशाला प्रबंधक, उत्तर रेलवे, सी एंड डब्ल्यू वर्कशॉप, जगाधरी वर्कशॉप/यमुनानगर निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित करते हैं:

कार्य का नाम	जगाधरी कार्यशाला में दो वर्षों के लिए 1600 एलएचबी (1552 पीओएच और 48 एनपीओएच) और 1200 आईसीएफ पीओएच कोच के अंडरफ्रेम की स्क्रैपिंग, स्प्रे और पेंटिंग और 1600 एलएचबी कोच के अंडरफ्रेम की धुलाई और आईसीएफ कोच के 600 आईसीएफ बोगी सेट की स्क्रैपिंग, सफाई और पेंटिंग।
कार्य स्थल	सी एंड डब्ल्यू वर्कशॉप, जगाधरी वर्कशॉप उत्तर रेलवे
निविदा मूल्य	₹79,28,783.30 निविदा प्रपत्र की लागत Nil
धरोहर राशि	कार्यशाला के अनुसार / बिड सिक्योरिटी ₹1,58,600/-
कार्य पूर्ण करने की अवधि	स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 24 महीने
निविदा फार्म को जमा करने की तारीख एवं समय	14.08.2024 को 15:30 बजे तक
टैंडर खोलना	14.08.2024 को 15:35 बजे तक। रेलवे निविदा बंद करने के बाद किसी भी समय निविदा खोलने का अधिकार रखता है। वेबसाइट विवरण: www.ireps.gov.in

सं.: 8-8/42/Tender/2023-24/P3 दिनांक: 23.07.2024 2257/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

इलेक्ट्रॉनिक निविदा ई-प्रणाली के अन्तर्गत मदों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य सामग्री प्रबंधक, उत्तर रेलवे नई दिल्ली-110001 द्वारा इच्छुक फर्मों से निम्नलिखित मदों के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र0 सं0	निविदा संख्या	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	अंतिम तिथि
01	82248836B	इंसुलिन बाइफैसिक एस्पार्ट इंज (इंसुलिन एस्पार्ट और इंसुलिन एस्पार्ट प्रोटामाइन 30/70) कैट्रिज 100IU प्रति एमएल 3 एमएल प्रत्येक (इंटरमीडिएट एक्टिंग	7638 Nos	17.08.2024

निविदा शर्तें- 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानी www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी।

टेंडर नोटिस सं:- Inj. Medicines दिनांक: 24.07.2024 2258/24

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

ई-खुली निविदा सूचना

मंडल अभियंता सम्पदा, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्यों के लिए खुली निविदा दिनांक 16.08.2024 को 16:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन तत्काल खोली जाएगी।

क्र.सं. (ए) कार्य का नाम : सहायक मंडल अभियंता/सम्पदा-IV के अधीन वरिष्ठ खंड अभियंता/शकूरबस्ती के कार्य क्षेत्र में टाइप-I और II क्वार्टरों में शौचालय, स्नानघर, रसोईघर और कमरे के फर्श की मरम्मत हेतु।

अनुमानित लागत	धरोहर राशि	समापन अवधि
रु. 74,99,999.00	रु. 1,50,000.00	06 महीने

क्र.सं. (बी) कार्य का नाम : सहायक मंडल अभियंता/सम्पत्ति-I के अधीन वरिष्ठ खंड अभियंता/ट्रांजिट कैंप के कार्य क्षेत्र में एनडीसीआर बिल्डिंग में क्लेम कार्यालय की भारी मरम्मत कार्य हेतु।

अनुमानित लागत	धरोहर राशि	समापन अवधि
रु. 99,99,994.33	रु. 2,00,000.00	06 महीने

क्र.सं. (सी) कार्य का नाम : सहायक मंडल अभियंता/सम्पत्ति-I के अधीन वरिष्ठ खंड अभियंता/ट्रांजिट कैंप के कार्य क्षेत्र में केएसएस की मरम्मत का कार्य छज्जा, फर्श, सीवर लाइन ग्रिल और विविध कार्य हेतु।

अनुमानित लागत	धरोहर राशि	समापन अवधि
रु. 99,99,972.70	रु. 2,00,000.00	06 महीने

1. निविदा दिनांक: 16.08.2024 को 15:00 बजे तक जमा की जा सकती है एवं तत्काल खोली जाएगी।

सं.: 128-डब्लयू/288/निविदासूचना/24-25/डब्लयू-ई/टेंडर नं: 13 (ए, बी, सी) दिनांक: 24.07.2024 2280/2024

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

Classifieds दैनिक जागरण
YOU CAN BOOK CLASSIFIED ADVT. OVER PHONE In Delhi-NCR
For More Details Contact

पूर्व मध्य रेल

खुली ई-निविदा सूचना

(निर्माण विभाग)

भारत के राष्ट्रपति के तरफ से निम्न कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सं.: ELC/S/MHX/ETEN/06/24-25

पटना 800004 में निविदा पट पर देखा जा सकता है। हिन्दी एवं अंग्रेजी की तुलना में किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अंग्रेजी में प्रकाशित सूचना को सही माना जायेगा। उप मुख्य विद्युत अभियंता/निर्माण/साउथ पू.म.रे./महेन्द्रूघाट/पटना

पीआर/00748/सीओएनएस/ईएलईसी/टी/24-25/40

बागवानी विभाग, हरियाणा

बागवानी विभाग, हरियाणा एकीकृत बागवानी विकास केन्द्र
एनएच-2, होडल, पलवल-121106
ईमेल आईडी: ihdchodal@gmail.com फोन नं. 01275-237052

शुद्धि पत्र

खुशहाल बागवानी

एकीकृत बागवानी विकास केन्द्र होडल पलवल में प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एकीकृत बागवानी विकास केन्द्र होडल पलवल (हरियाणा) पर वर्ष 2024-25 मे विभाग द्वारा चलाई जा रही बागवानी स्कीम व संरक्षित संरचना में सब्जियों की देखरेख व रख-रखाव पर प्रशिक्षण से संबंधित पांच दिवसीय प्रशिक्षण करवाया जाना है। हरियाणा राज्य के सभी जिलों के किसान दिनांक 25-07-2024 से प्रातः 11:00 बजे से उद्यान विभाग की वेबसाइट (kaushal.hortharyana.gov.in) के माध्यम से उक्त प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण के लिए एकीकृत बागवानी विकास केन्द्र होडल पर सीटों की संख्या 20 सीटें प्रति प्रशिक्षण है। प्रशिक्षार्थी का चयन ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जाएगा। आवेदनकर्ता अपने जरूरी कागजात जैसे कि आधार कॉर्ड, परिवार पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रशिक्षण के दौरान प्रथम दिन अपने साथ लेकर आये। प्रशिक्षण के दौरान रात्रि ठहराव की व्यवस्था नहीं होगी।

दिनांक	अवधि	विषय	सीटों की संख्या
02.09.2024 से 06.09.2024 तक	5	बागवानी योजनाएं व संरक्षित संरचना में सब्जियों की देख रेख व रख-रखाव पर प्रशिक्षण	20
09.09.2024 से 13.09.2024 तक	5	बागवानी योजनाएं व संरक्षित संरचना मे सब्जियों की देख रेख व रख-रखाव पर प्रशिक्षण	20
16.09.2024 से 20.09.2024 तक	5	बागवानी योजनाएं व संरक्षित संरचना मे सब्जियों की देख रेख व रख-रखाव पर प्रशिक्षण	20
07.10.2024 से 11.10.2024 तक	5	बागवानी योजनाएं व संरक्षित संरचना मे सब्जियों की देख रेख व रख-रखाव पर प्रशिक्षण	20
21.10.2024 से 25.10.2024 तक	5	बागवानी योजनाएं व संरक्षित संरचना मे सब्जियों की देख रेख व रख-रखाव पर प्रशिक्षण	20

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हरियाणा सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई Covid-19 के सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए केन्द्र अधिकारी (मो. 9671001096, 9306442755) से संपर्क कर सकते हैं। चयन सूची विभाग की वेबसाइट (kaushal.hortharyana.gov.in) पर अपलोड कर दी जाएगी।

नोट:- प्रशासनिक कार्यों से प्रशिक्षण को अवधि को आगे/ पीछे किया जा सकता है।

विषय वस्तु विशेषज्ञ
एकीकृत बागवानी विकास केन्द्र
होडल पलवल

PRDH-1149/11/657/2025/28150/67/7

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधिकरण का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खोलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रुपये में	बोर्ड/निगम/प्राधिकरण की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/संपर्क विवरण/ईमेल
1	नगर परिषद बहादुरगढ़	नगर परिषद बहादुरगढ़ में जोन सं.01 (वार्ड सं. 01 से 10) में स्ट्रीट लाइट का संचालन एवं रखरखाव +3 कार्य।	CLOSING DATE 27.07.2024	1.64 CRORE	https://etenders.hry.nic.in	9416188946 eo-bahadurgarh@ulbharyana.gov.in

आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

PRDH-13/2025/40/28165/I/67/7

हरियाणा सरकार — निविदा सूचना

क्र. सं.	बोर्ड/निगम/प्राधिकरण का नाम	कार्य सूचना निविदा का नाम	खोलने की तिथि बंद होने की तिथि (समय)	राशि/ईएमडी (लगभग) रुपये में	बोर्ड/निगम/प्राधिकरण की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/संपर्क विवरण/ईमेल
1	एचएसआईआईडीसी	आईएमटी सोहना में ग्राम विकास योजना के अंतर्गत गांव रेवासां में सीसी सड़क का निर्माण।	24.07.2024 02.08.2024	82.59 LACS	https://etenders.hry.nic.in	9811978811 ia.sohna@hsiidc.org.in

आगामी जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं : www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

PRDH-13/2025/40/28158/I/67/7

हरियाणा लोक सेवा आयोग

बेज़ नं. 1-10, ब्लॉक-बी, सेक्टर-4, पंचकूला

विज्ञापन संख्या 38/2024 प्रकाशन की तिथि: 24.07.2024

हरियाणा लोक सेवा आयोग निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

i) पद का नाम: मत्स्य विभाग, हरियाणा में उप निदेशक मत्स्य / समकक्ष पद (ग्रुप-ए)।

ii) पदों का श्रेणीवार विभाजन :

श्रेणी	पदों की संख्या
सामान्य / अनारक्षित	02

a) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि: 26.07.2024

b) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 16.08.2024 सायं 05:00 बजे तक।

c) शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 16.08.2024 सायं 05:00 बजे तक।

अधिक जानकारी के लिए, http://hpsc.gov.in पर लॉग ऑन करें

दिनांक: 24/07/2024

सचिव
हरियाणा लोक सेवा आयोग
पंचकूला

PRDH-1156/13/261/2025/28174/67/7

Horticulture Department, Haryana

Integrated Horticulture Development Centre,
NH-2, Hodal, Palwal-121106
Email ID:- ihdchodal@gmail.com, Ph. No. 01275-237052

भोजन की व्यवस्था हेतु कुटेशन आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एकीकृत बागवानी विकास केन्द्र होडल पर वर्ष 2024-25 के लिए किसानो के लिए विभिन्न प्रकार के 5 दिनों का प्रशिक्षण व क्यू पी. कोर्स करवाएं जाने है। इन प्रशिक्षणों में प्रदेश से प्रगतिशील किसानो व प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन प्रशिक्षणों में किसानो के लिए सुबह की चाय / सनैस्क, दोपहर का भोजन व सायं की चाय / सनैक्स इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु खुले बाजार से मोहर बंद कुटेशन आमत्रित की जाती है।

क्रम सं.	कार्य का विवरण	प्रतिदिन किसानो की संख्या	मुल्य प्रति प्लेट सभी कर सहित (रूपय)
1	केन्द्र पर जी0एस0टी0 पंजीकृत फर्म द्वारा सुबह की चाय / सनैस्क, व अन्य सामग्री, दोपहर का भोजन व साय की चाय / सनैक्स इत्यादि की व्यवस्था करने बारे।	20 किसान	

इच्छुक फर्म अपनी कुटेशन अपनी फर्म के लेटर हेड पर दिनांक 24.07.2024 से 05.08. 2024 तक साय: 05.00 बजे तक कार्यालय मे केवल दस्ती तौर पर जमा करवाना सुनिश्चित करे। कुटेशनों की आंकलन कमेटी द्वारा आंकलन करने उपरांत सबसे कम मुल्य वाली कुटेशन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। कुटेशन स्वीकृत / अस्वीकृत करने के सभी अधिकार केन्द्र की आंकलन कमेटी के पास होंगे। इस सम्बंध मे विस्तृत जानकारी के लिए डॉ. दिनेश तेवतिया और श्री आमिर सुहैल डी.ई.ओ. (Mob No. 9671001096) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

विषय वस्तु विशेषज्ञ
एकीकृत बागवानी विकास केन्द्र
होडल पलवल।

PRDH-1149/11/658/2025/28156/67/7

****

हरियाणा सरकार

राज्य स्तरीय शहरी स्थानीय निकाय

जनप्रतिनिधि सम्मेलन

25 जुलाई, 2024 । दोपहर 2:00 बजे
ऑडिटोरियम, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार

- शहरी स्थानीय निकायों को मज़बूती प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 में लगभग ₹5,800 करोड़ के बजट का प्रावधान
- पालिकाओं के अधीन आने वाली 800 अनाधिकृत कॉलोनियां अधिकृत की
- इन कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने हेतु ₹1000 करोड़ के बजट का प्रावधान
- शहरी स्वामित्व योजना के तहत 5000 आवेदकों की हुई रजिस्ट्री
- शहरी क्षेत्र के लाल डोरा में स्थित लगभग 6.85 लाख प्रॉपर्टी धारकों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरु

मुख्य अतिथि
श्री नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री, हरियाणा

अध्यक्षता
श्री सुभाष सुधा
राज्य मंत्री, शहरी स्थानीय निकाय
(स्व.प्र.), हरियाणा

कार्यक्रम से जुड़ने के लिए क्यू आर कोड स्कैन करें

सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा www.prharyana.gov.in | Follow us on @diprharyana

****

संपादकीय जागरण

गुरुवार, 25 जुलाई, 2024: श्रावण कृष्ण – 5 वि. 2081

अनुशासन की सीढ़ी ही सफलता के गंतव्य तक पहुंचाती है

बजट के विरोध की रस्म

यह बजट आने के पहले से स्पष्ट होता है कि विपक्षी दल किसी न किसी बहाने उसका विरोध करेंगे। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। विपक्षी दल इस आरोप के सहारे बजट का विरोध कर रहे हैं कि उसमें अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। इस विरोध का आधार बिहार और आंध्र प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विशेष घोषणाएं किया जाना है। बिहार के लिए लगभग 60 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं घोषित की गई हैं। इसके पीछे एकमात्र कारण यह नहीं है कि इन दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ दल भाजपा के प्रमुख सहयोगी हैं। इसका कारण यह भी है कि बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है और आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार ने उसे विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया था। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि लोकसभा चुनाव के साथ हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिये यह गारंटी दी थी कि वह इस राज्य को दस वर्ष के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करेगी। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस के नेता बिहार के लिए भी विशेष सहायता देने की मांग करते रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि दिल्ली में तो कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए बिहार पर अतिरिक्त कृपा की, लेकिन पटना में उसके दल के ही नेता यह आरोप लगाने में लगे हुए हैं कि बजट में राज्य को कुछ नहीं मिला। बेहतर हो कि कांग्रेस यह स्पष्ट करे कि उसके किन नेताओं की बात को सही माना जाए?

कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की कथित अनदेखी का आरोप लगाकर संसद के भीतर-बाहर हंगामा कर सकते हैं, लेकिन वे इस झूठ को सच साबित नहीं कर सकते कि शेष राज्यों को कुछ नहीं मिला। यह झूठ इसलिए नहीं चलने वाला, क्योंकि एक तो पूर्वोदय योजना में जिन पांच राज्यों को शामिल किया गया है, उनमें बिहार और आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त ओडिशा, बंगाल एवं झारखंड भी हैं और दूसरे, असम को बाढ़ नियंत्रण तथा महाराष्ट्र को सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन दिया गया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर को औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय सहायता का प्रविधान है। यदि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में केंद्रीय सहायता देने के मामले में अन्य राज्यों का नाम नहीं लिया तो इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा है। अच्छा हो कि विपक्षी नेता प्रचार पाने के लिए विरोध की बेतुकी रस्म निभाने के बजाय बजट दस्तावेज पढ़ें। उन्हें पता चलेगा कि बजट में राज्यों को किस मद में कितना धन मिलने वाला है।

निराशाजनक स्थिति

दिल्ली में कम वर्षा में ही सड़कों और अंडरपास में जलभराव और उसके कारण भीषण यातायात जाम लगना अत्यंत निराशाजनक है। बुधवार को राजधानी में 27 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई, जो बहुत अधिक नहीं कही जा सकती। इसके बावजूद यमुनापार, दक्षिण, दक्षिण-पूर्वी व नई दिल्ली जिला जलभराव से सर्वाधिक प्रभावित रहा। जखीरा अंडरपास में भारी जलभराव हो गया, ट्रैफिक पुलिस को यहां मार्ग बंद करना पड़ा और वाहनों को दूसरे रास्तों पर भेजा गया। एनएच-नौ, मोती बाग, तुगलक रोड, अक्षरधाम फ्लाईओवर व आरके पुरम में जलभराव से वाहन चालकों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

राजधानी में जलभराव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच कर लापरवाही के लिए उन्हें दंडित करना चाहिए

राष्ट्रीय राजधानी में जरा सी वर्षा पर ही ऐसे हालात होना अस्वीकार्य है। ऐसे में, संबंधित सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यह स्थिति दर्शाती है कि विगत माह भारी वर्षा के बाद हुए जलभराव से कोई सीख नहीं ली, जिसका खामियाजा दिल्लीवासियों को भुगतना पड़ा। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और एमसीडी के उच्चाधिकारियों को जलभराव रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से पूछना चाहिए कि उन्होंने जून के अंतिम सप्ताह में हुई भारी जलभराव की स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या प्रयास किए। उनकी कार्यप्रणाली की जांच की जानी चाहिए और लापरवाही के लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, ताकि अधिकारी जलभराव को कुछ महीनों की अस्थायी समस्या समझकर इसे हल्के में लेने के बजाय इसके स्थायी समाधान के उपाय करें और दिल्लीवासियों को राहत मिले।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या आम बजट के प्रावधानों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे?

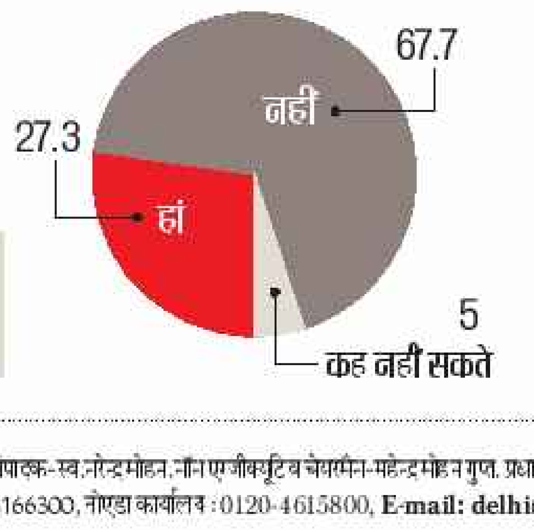

आज का सवाल
क्या बिहार और आंध्र को मिले पैकेज पर विपक्षी दलों की आपत्ति सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

बजट से आगे की चुनौती

जीएन वाजपेयी

बजट में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर कई अच्छी पहल हुई हैं, लेकिन उनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि उन पर अमल कैसे होता है

केंद्रीय बजट एक प्रकार से फरवरी में आए अंतरिम बजट का ही विस्तार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें कृषि उत्पादकता एवं उसका उत्थान, कौशल एवं रोजगार, समावेशन एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की राह पर बढ़ने जैसी नौ प्राथमिकताओं का उल्लेख किया। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से खेती-किसानी की दशा-दिशा सुधरने की आस बढ़ी है। विभिन्न फसलों की प्रस्तावित 109 किस्मों से भी उत्पादकता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये किस्में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ रही प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं के विरुद्ध कवच का काम करेंगी। दलहन-तिलहन को प्राथमिकता, डिजिटल क्राप सर्वे के अतिरिक्त किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ एवं भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने जैसे उपाय उपज को पहुंचने वाले नुकसान को घटाने एवं कीमतों में स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ की बड़ी राशि आवंटित की गई है। बड़े पैमाने पर आल-वेदर रोड का निर्माण, तीन करोड़ ग्रामीण आवासों का निर्माण, विकास की मुख्यधारा में महिलाओं को शामिल करने के साथ ही आदिवासी क्षेत्र आर्थिकी के निर्माण जैसी पहल वंचित वर्गों के जीवन एवं आजीविका पर दूरगामी एवं दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ेगी।

रोजगार की चुनौती का समाधान करने के लिए इंटर्नशिप से लेकर भत्ते के माध्यम से नियोक्ताओं को अतिरिक्त भर्तियों पर प्रोत्साहन जैसी पहल से अच्छे परिणामों की अपेक्षा है। कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने से जहां युवाओं को रोजगार की दृष्टि से प्रशिक्षित होने में सहायता मिलेगी, वहीं उद्योगों के लिए कुशल कर्मियों की आपूर्ति हो सकेगी। भारत में विकास की विद्यमान संभावनाओं को भुनाने में कामकाजी आबादी में महिलाओं की अपेक्षाकृत कम भागीदारी एक अवरोध मानी जाती रही है, जिसे दूर करने के लिए सरकार प्रयासरत है। कार्यशील आबादी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल और ऐसी अन्य सुविधाएं क्रांतिकारी सिद्ध हो सकती हैं। शहरों में काम करने वालों के लिए डोरमेट्री जैसी आवासीय पहल भी उपयोगी सिद्ध होगी। रोजगार के मोर्चे पर पर्यटन को भी प्राथमिकता दी गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र विकसित करने से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव है, क्योंकि इसमें कुशल एवं अकुशल, दोनों प्रकार के लोग चाहिए। साथ ही सैर-सपाटे पर केंद्रित एक आर्थिक-व्यवस्था भी खड़ी हो सकेगी।

रोजगार के लिहाज से बेहद अहम एमएसएमई क्षेत्र को भी सरकार ने अपनी वरीयता सूची में रखा है। उनके लिए वित्तीय पहुंच से लेकर तकनीकी सहायता एवं नियमन में सहूलियत जैसे उपाय किए गए हैं। देश के 100 शहरों में 'इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्कों' से भी विनिर्माण क्षेत्र को बड़ा संबल मिलने की उम्मीद है। इसी साल ऐसे 12 पार्क विकसित करने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है। यदि एक बार ऐसा हो गया तो भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ जाएगा। इसी तरह क्रिटिकल मिनरल मिशन से दुर्लभ तत्वों की उपलब्धता बढ़ेगी, जो नए दौर की आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहद आवश्यक हैं।

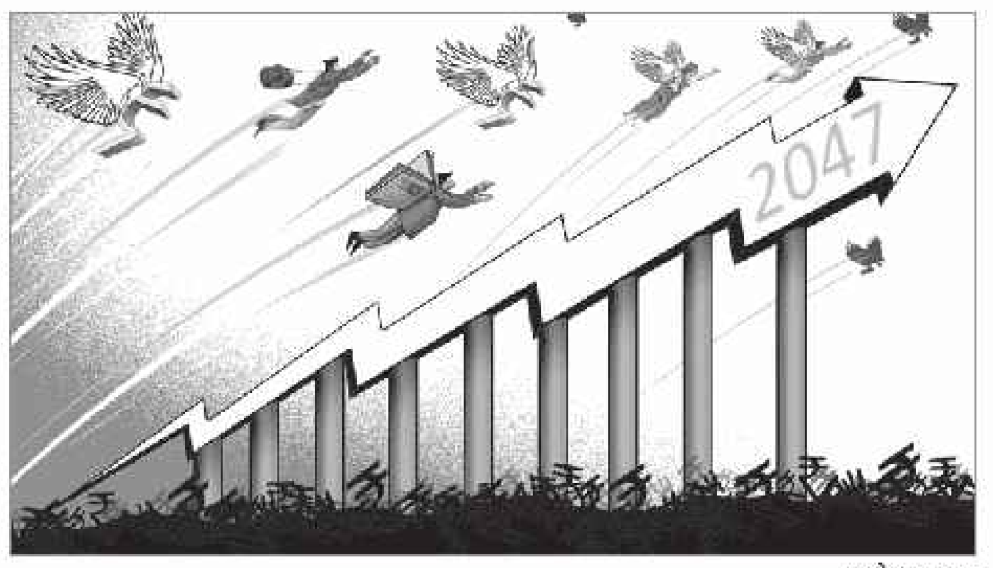

अवधेश राजपूत

शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन से सिरे चढ़ने वाली योजना उन करोड़ों लोगों के लिए बड़ी राहत का सबब होगी, जो दयनीय परिस्थितियों में रहने को विवश हैं। हमारे शहर आर्थिक वृद्धि के इंजन हैं और रचनात्मक विकास गतिविधियों के जरिये ही उन्हें गति देकर कायाकल्प संभव है। सोलर पैनल पर आधारित मुफ्त घर बिजली योजना भी बाजी पलटने वाली सिद्ध हो सकती है। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर ट्रांसमिशन पाथवेज, माड्यूलर न्यूक्लियर प्लांट और एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट भी सराहनीय पहल रहीं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन भी विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। बेहतर बुनियादी ढांचा न केवल सुगमता बढ़ाने से लेकर ढुलाई जैसी कई लागतों को घटाता है, बल्कि उद्योगों को लिए एक अनुकूल परिवेश का निर्माण भी करता है। वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए विभिन्न कदम भी भविष्य के साथ कदमताल का प्रयास दिखते हैं। बिहार में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक एवं लाजिस्टिक हब जैसी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का पैकेज भी समय की मांग के अनुरूप ही है, क्योंकि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि बिहार आज भी सबसे पिछड़े और न्यूनतम जीडीपी प्रति व्यक्ति वाले राज्यों में से एक है। इसी तरह आंध्र प्रदेश को विभिन्न संस्थानों के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये की मदद को भी आवश्यक ही कहा जाएगा, क्योंकि इस राज्य को अमरावती के रूप में अपनी नई राजधानी विकसित करनी है। ध्यान रहे कि इस राज्य के विभाजन के समय केंद्र सरकार के स्तर पर उससे कुछ वादे किए गए थे। ऐसे कदम भले ही गठबंधन की राजनीति की मजबूरियां कहे जाएं, लेकिन इससे भारतीय संघ एवं राज्यों के बीच भरोसे का पुल और मजबूत होगा।

वित्त मंत्री ने भूमि एवं श्रम से जुड़े सुधारों पर आगे बढ़ने के साथ ही प्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर समीक्षा की बात भी कही है। अर्थव्यवस्था लंबे समय से ऐसे सुधारों की बाट जोह रही है। एंजेल टैक्स को समाप्त करके सरकार ने उचित ही किया। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने में भी सरकार सफल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर अभी और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यही बात वृद्धि को धार देने वाले अन्य तमाम क्षेत्रों पर भी लागू होती है। प्रतिभूति लेनदेन को लेकर पूंजीगत लाभ कर में कुछ बढ़ोतरी को लेकर असहजता सामने आ रही है, लेकिन इस कवायद में सभी प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत लाभ कर को एक स्तर पर लाने का प्रयास दिखता है। भले ही बजट को शेयर बाजार की तात्कालिक सलामी न मिली हो, लेकिन यह बजट 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की राह प्रशस्त करता है। बजट में बहुत अच्छी पहल की गई हैं, लेकिन उनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि उन पर अमल कैसे होता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार अपनी सक्षमता एवं योजनाओं को तेजी से अमल में लाने के मोर्चे पर अर्जित प्रतिष्ठा की कसौटी पर खरी उतरेगी।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

नौकरशाही की जकड़न से निकले शिक्षा

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा नीट-यूजी को दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन यह कहना कठिन है कि उसके फैसले से परीक्षा आयोजक एजेंसी एनटीए की साख बहाल होने जा रही है। बात केवल एनटीए की ही नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में समूचे देश में अनेक परीक्षाएं कदाचार का शिकार हुई हैं। व्यापम जैसे लज्जाजनक प्रकरण के बाद भी केंद्र और राज्यों की बड़ी संस्थाएं पर्चा-लीक रोक न पाएं तो यह या तो घोर अक्षमता है या संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। देखा जाए तो इसमें देश की न्याय व्यवस्था की शिथिलता की भी भूमिका है। न्यायिक प्रक्रिया के प्रति भय-मुक्त होकर समाज विरोधी तत्व लगातार फल-फूल रहे हैं। यह दिखाता है कि विश्व को नैतिकता और जनसेवा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी के देश ने व्यावहारिकता में उनके जीवन मूल्यों एवं सिद्धांतों को लगभग भुला दिया है। यदि ऐसा हर स्तर पर न हुआ होता तो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए कुछ लोग करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों को घोर आपदा तथा कष्टकर अवसाद में नहीं झोंकते। यह सब करने वाले पढ़े-लिखे लोग हैं। चूंकि किसी न किसी अध्यापक ने ही इन सबको कभी पढ़ाया होगा, लिहाजा समूचे शिक्षक वर्ग के लिए भी यह गहन मंथन का समय है, क्योंकि देश के भविष्य का निर्माण और नई पीढ़ी का नैतिकता, मानव-मूल्यों तथा सदाचार से परिचय कराने का उत्तरदायित्व तो उनका ही है। हालांकि यह भी सही है कि इस उत्तरदायित्व निर्वहन में व्यवस्था-तंत्र की सजगता और संसाधनों की पूर्ति/आपूर्ति का प्रभाव पड़ता है।

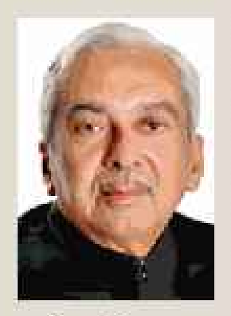

जगमोहन सिंह राजपूत

जो उच्च शैक्षिक पद वर्ष 1975-80 तक शिक्षाविदों के पास होते थे, अब उन सब पर नौकरशाह काबिज हैं

नीट मामले में प्रेस कांफ्रेंस करते शिक्षा मंत्री • फाइल

जब हम गर्व के साथ प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को याद करते हैं, तब उन गुरुकुलों तथा ज्ञान-केंद्रों के सहज संचालन में गुरु के लिए जो सम्मान मिलता था, जिस सहजता से संसाधनों की व्यवस्था होती थी, उसे अक्सर भूल जाते हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि शिक्षा में उत्कृष्टता तभी संभव होती है जब अध्यापकों को 'अफसरों' का भय न हो, संस्था में आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों और उसे परिवार संचालन की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता न हो। यह चिंता की बात है कि आज देश में बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ बढ़ा है। उनमें प्रतिस्पर्धा का तनाव भी प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। कोचिंग संस्थाओं की निर्ममता को झेलने के लिए बच्चे बाध्य हैं। माता-पिता उनके भविष्य की आशंकाओं से व्यथित हैं। यदि स्कूल ठीक से चलें, अध्यापक समय से अपना कार्य करें, पाठ्यक्रम समयानुसार परिवर्तित होते रहें, परीक्षा व्यवस्था पर फिर से लोगों का विश्वास लौटाया जाए, तभी बच्चों को कुछ राहत मिल सकेगी। यह लक्ष्य कठिन है, लेकिन प्रबुद्ध देशवासियों को इस दिशा में आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करने होंगे।

वह शिक्षा अधूरी है जिसमें केवल लिखित परीक्षा के अधिकाधिक अंक ही जीवन-लक्ष्य मान लिए गए हों। ऐसी स्थिति में व्यक्ति और व्यक्तित्व विकास की अपेक्षा अर्थहीन हो जाती है। दूसरे विश्व युद्ध में अत्यंत अपमानजनक स्थिति में पहुंचे जापान ने जब राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तो उसने कार्य संस्कृति, समय-पालन तथा कर्मठता से राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग तैयार करने को सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य माना। इसकी सबसे पहली सीढ़ी बने स्कूल अध्यापक। उनके प्रयास से अगले दस-बारह साल में युवाओं की ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई, जो अपने सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व निर्वहन में पूरी तरह सक्षम थी। यदि भारत में भी ऐसे अध्यापक, कुलपति, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के अध्यक्ष परीक्षा केंद्रों के संचालन का उत्तरदायित्व निभा रहे होते, तो पेपर लीक की समस्या नहीं होती।

हमारे देश के साथ आज एक बड़ी समस्या यह है कि हमने नौकरशाही प्रशासन और अकादमिक प्रशासन के अंतर को पहचानने से इन्कार कर दिया है। जो उच्च शैक्षिक पद 1975-80 तक शिक्षाविदों के पास होते थे, अब वे सब केवल नौकरशाहों के पास हैं। राज्यों में पाठ्यपुस्तक निगम, स्कूल बोर्ड तथा राष्ट्रीय स्तर पर सीबीएसई, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के शीर्ष पदों पर शिक्षाविद् क्यों नियुक्त नहीं हो सकते हैं? डा. कोठारी की अध्यक्षता में बने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने इंडियन एजुकेशन सर्विस (आइईएस) की स्थापना की संस्तुति की थी। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, समय-समय पर विद्वत वर्ग की ओर से प्रयास होते रहे, मगर इस पर हुआ कुछ नहीं। कारण स्पष्ट है कि नौकरशाह इसके लिए तैयार नहीं है। लगता है वह अपने प्रभाव क्षितिज में किसी का प्रवेश नहीं चाहते।

जब भी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की चर्चा होती है, तब संस्थागत स्वायत्तता की ओर सभी का ध्यान अवश्य जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ राज्य सरकारों तथा राज्यपालों के संबंध जिस ढंग से जनता के समक्ष उभरे हैं, उस पर केवल शर्मिंदा ही हुआ जा सकता है। किसी भी विश्वविद्यालय के सुचारु रूप से चलने तथा उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए राज्य सरकार और राज्यपाल के समन्वित सहयोग तथा मार्गदर्शन की महती आवश्यकता होती है। इनमें से एक कुलपति नियुक्त करे और दूसरा उसे निरस्त करे तो इससे लोकतंत्र का विकृत चेहरा ही उभरता है। आज फर्जी डिग्री बांटने वाले अनेक संस्थान भी चिह्नित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही अधिकांश राज्यों में शिक्षा संस्थानों में नियुक्तियों को लेकर पारदर्शिता और योग्यता का अभाव नजर आता है। यह सामान्य समझ से परे है कि राज्यों में अध्यापकों की नियुक्ति की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? यदि किसी राज्य में कई साल से रिक्त पदों की संख्या लाखों में हो तो किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी ही होगी।

(लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव तथा पंथक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्संग

सत्संग एक ऐसा साधन है, जिसके जरिये व्यक्ति को मानव जीवन के मूल उद्देश्य की जानकारी मिलती है तथा वह सद्-मार्ग की ओर उन्मुख होता है। एक किसान अपने खेत को बार-बार जोत कर उसमें बीज डालता है। फसल उगने पर उसमें से खरपतवार आदि को निकालता है तब जाकर वह अच्छी फसल प्राप्त करता है। इसी प्रकार संत-महात्माओं से सत्संग सुनने, उस पर चिंतन-मनन करने तथा अच्छे-बुरे का अवलोकन करने से ही हमारे विचार स्वच्छ एवं स्पष्ट बनाते हैं।

जीवन में सुख-दुख धूप-छांव की तरह आते-जाते रहते हैं। फिर भी बहुत से लोग जो ज्ञान प्राप्त करके उत्तम मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, कई बार जीवन में थोड़े से कष्ट आने पर ही घबरा जाते हैं और अपने मार्ग को बदल देते हैं। ईश्वर से उनका विश्वास कम हो जाता है और वे पुनः कष्टों को निमंत्रण दे बैठते हैं। कोई भी सफलता दृढ़निश्चय एवं परिश्रम से ही प्राप्त होती है। इसलिए अध्यात्म मार्ग के पथिक को कभी मन में नकारात्मक सोच को स्थान नहीं देना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रारंभ में जैसी लगन होती है वैसी ही जीवनपर्यंत होनी चाहिए। यदि हम भक्त प्रह्लाद को देखें तो उनके जीवन में बहुत कष्ट आए, लेकिन उन्होंने कभी भक्ति के पथ को नहीं छोड़ा। उन्हें यह दृढ़विश्वास था कि परमात्मा की शक्ति ही सर्वोपरि है, जो कण-कण में समाई हुई है। प्रह्लाद के इस विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए ही भगवान ने उनकी परीक्षा ली।

आज के इस व्यस्त जीवन में व्यक्ति इतना उलझा हुआ है कि परिवार के भरण-पोषण के चिंतन एवं भागदौड़ में स्वयं को तथा जीवन के मूल उद्देश्य को भूलता जा रहा है। सबसे बड़ी भूल हम अपने आत्मा के साथ कर रहे हैं, जो कि परमात्मा का ही अंश है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मकल्याण करना है। यही बंधनों से मुक्ति और आनंद का एकमात्र उपाय है। इसमें सत्संग सबसे बड़ा सहायक होता है।

अवधविहारी शुक्ल

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

राजस्व के नए स्रोत खोजना भी जरूरी

'वित्तीय अनुशासन पर कायम सरकार' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में धर्मकीर्ति जोशी बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिरता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वित्तीय अनुशासन के साथ ही विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। वर्तमान आर्थिक परिवेश में वित्तीय अनुशासन की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। सरकार द्वारा इस पर जोर देकर दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के वित्तीय संसाधनों का प्रभावी और जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग हो। हालांकि वित्तीय अनुशासन का पालन करते समय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकासात्मक परियोजनाएं और सामाजिक कल्याण योजनाएं प्रभावित न हों और समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिले। केवल बजट में कटौती और खर्चों को नियंत्रित करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ-साथ नए राजस्व स्रोतों को भी तलाशना जरूरी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करके और वित्तीय साक्षरता अभियान चलाकर सरकार राजस्व की निगरानी और संग्रह में सुधार कर सकती है। वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके करों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली से न केवल जनता का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी। नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर नए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

पहचान बताने में क्या डर

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कांवड़ रूट में नेम प्लेट वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा कर संवैधानिक कानूनी एवं व्यावहारिक पक्ष लिया है। योगी सरकार का फरमान कांवड़ यात्रियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचाने के लिए जारी किया गया लगता है। समाज के एक वर्ग ने इस विषय पर मतभिन्नता व्यक्त की है किन्तु जाति, धर्म छिपाकर बोगस पहचान लगाने को भी निंदनीय, असामाजिक एवं गैर कानूनी गतिविधि कहा जा सकता है। मामला सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में है इसलिए दोनों पक्षों को अपना विचार जन भावना एवं कानूनी पहलुओं के साथ रखना चाहिए।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

संतुलित बजट

24 जुलाई के अंक में संपादकीय विकसित भारत का लक्ष्य पढ़ा। इस बार के बजट में सरकार के अनुभव साफ दिखा। राज्यों को साथ लेकर चलने का बजट है। यही सच्चाई है कि राज्य जब तक केंद्र के साथ कदमताल नहीं करेंगे, विकसित देश का सपना पूरा नहीं होगा। उन्हें एक मंच पर आना या लाना ही होगा। इसकी शुरुआत दिख रही है। सरकार ने रोजगार को लेकर तत्परता दिखाई है। यह सचाई है कि सरकारी नौकरियां बहुत नहीं बढ़ सकती। लिहाजा निजी सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल हुई है। कुल मिलाकर इसे संतुलित बजट कहा जा सकता है।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग दिल्ली

वित्तीय अनुशासन जरूरी

'वित्तीय अनुशासन पर कायम सरकार' शीर्षक आलेख में धर्मकीर्ति जोशी ने मोदी सरकार के इस बार के बजट को रेवड़ियों से परे बताया है, जो वित्तीय अनुशासन के लिए उपयुक्त है। पूरे बजट पर नजर डालें तो आम लोगों के लिए यह बजट न पाकेट ढीली करने वाला है और न ही बचत करने वाला। लोग संतुष्ट हैं कि सरकार आवश्यक क्षेत्रों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोली है। इससे देश का विकास होगा। देश का चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कुल व्यय 47,65,768 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 6.1 प्रतिशत अधिक है। मोदी सरकार की नई नीतियों में भारत के युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया। बजट में युवा कौशल कार्यक्रमों के साथ-साथ युवा भारतीयों के लिए शीर्ष 500 कंपनियों में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम की भी घोषणा की गई। सरकार ने मध्य वर्ग के लिए भी एलान किया। मोदी सरकार ने सात लाख 75 हजार तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। कैंसर की तीन दवाएं, सोना-चांदी से बने गहने व चमड़े से बने सामान को भी सस्ता किया। बजट में लिए गए फैसले से चंद्रबाबू नायडू को राहत मिली, क्योंकि टीडीपी के सांसद के लिए लोस अध्यक्ष का पद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद में ज्यादा संख्या में मंत्रालयों की मांग करने के बजाय, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के लिए फंड सुरक्षित कर लिया। वहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के बावजूद नीतीश कुमार गदगद हैं।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

पोस्ट

बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए किए गए प्रविधान विपक्षी दलों के उन आरोपों की हवा निकालने वाले सिद्ध हुए कि मोदी सरकार सहयोगी दलों की उपेक्षा करती है।
राहुल शिवशंकर@RShivshankar

केंद्र से मिले पैकेज के रूप में बिहार के पास अपनी नियति बदलने का एक स्वर्णिम अवसर है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार की इस सहायता का वहां पूरी तरह सदुपयोग किया जाएगा।
मोनिका वर्मा@TrulyMonica

बजट तब भी आते थे, जब खबरिया चैनल नहीं थे। तब बजट पर इतनी चर्चा नहीं होती थी। बजट देश का है, आपके घर का नहीं। आप अपने घर का बजट देखो और उसे संतुलित रखो। बजट देश की आधारभूत संरचना के लिए होता है और सरकार की कमाई मुख्यतः आपके टैक्स से ही होती है। अमात्य राक्षस@capt_mishra

सरकार नए-नए टैक्स लगाकर आमदनी बढ़ाने के जितने तरीके अपनाती है, लोग टैक्स बचाने की उतनी ही तरकीबें ढूंढ लेते हैं। केवल नौकरीपेशा लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका वेतन ही टैक्स कटने के बाद मिलता है। ये वही लोग हैं जिनका पूरा जीवन रोटी-कपड़ा-मकान की कशमकश में निकल जाता है।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जनपथ

अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम,
चाहें ऐसी नौकरी जिसमें हो आराम।
जिसमें हो आराम हाथ ना पांव हिलाएं,
बिन मेहनत मिल जाय उसे घर बैठे खाएं।
जो खटता दिन रात भरे वो ही सारे कर,
जो न करे कुछ काम बना बैठा वह अजगर!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन ... प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेंद्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित. संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय संपादक-प्रदीप कुमार शुक्ल*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 35 अंक 8

****

अपराध की खबरें

भजन करते कथावाचक की हार्ट अटैक से मृत्यु

राजगढ़ : मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में भागवत कथा के दौरान कथावाचक भागवताचार्य पंडित गोपाल कृष्ण महाराज को भजन प्रस्तुत करते समय व्यासपीठ पर हार्ट अटैक आ गया। श्रद्धालु पहले तो कुछ समझ नहीं सके, लेकिन जब उन्हें बेसुध पाया तो तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। (नईदुनिया प्रतिनिधि)

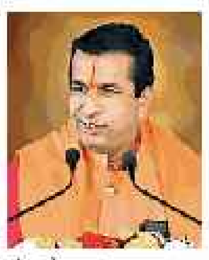

पं. गोपाल कृष्ण ● फाइल फोटो

ध्रुव राठी को भाजपा नेता की मानहानि में समन

नई दिल्ली : साकेत कोर्ट ने भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ की ओर से दायर मानहानि के मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। राठी पर आरोप है कि उनके द्वारा अपलोड किए वीडियो में सुरेश को 'हिंसक और अपमानजनक' ट्रोल कहा गया। ऐसे मामले के अनुसार, ध्रुव राठी ने गत सात जुलाई को अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया था। आरोप है कि इसमें राठी ने विवादास्पद टिप्पणी की। (जासं)

युद्धपोत में लगी आग के बाद लापता नाविक का शव मिला

नई दिल्ली: मुंबई स्थित नौसेना डाकयार्ड में युद्धपोत आइएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी भीषण आग के बाद लापता हुए नाविक सितेन्द्र सिंह का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम को आग लगने के बाद युद्धपोत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक ओर झुक गया है। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा कि काफी खोजबीन के बाद नाविक सितेन्द्र सिंह का शव बरामद कर लिया गया। (प्रेट्र)

बरेली में युवक का जबरन करा दिया मतांतरण!

बरेली : बरेली में पिछले वर्ष लापता एक युवक मुस्लिम परिवार के चंगुल में है। बुधवार को थाने पहुंचे उसके पिता ने आरोप लगाया कि उसका जबरन मतांतरण करा दिया गया। अब निकाह का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया बंधक बनाने, धोखाधड़ी-विश्वासघात करने, मारपीट का मामला प्रतीत हो रहा। इन्हीं धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई। विवेचना में यदि मतांतरण और निकाह के आरोप की पुष्टि हुई तो धाराएं बढ़ा दी जाएंगी। प्रेमशंकर ने कहा कि उनका बेटा फार्मा कंपनी में नौकरी करता था। पिछले वर्ष घर से ड्यूटी के लिए निकला, लेकिन वापस नहीं आया। (जासं)

झारखंड के 27 प्रवासी श्रमिकों की हुई वापसी

रांची : विदेश मंत्रालय की पहल पर कई दिनों से कैमरून में फंसे राज्य के 27 अप्रवासी मजदूरों की स्वदेश वापसी हुई। वापस लौटे श्रमिकों में बोकारो के 18, गिरिडीह के चार और हजारीबाग के पांच श्रमिक हैं। ये सभी बीते 29 मार्च से वहां की अलग-अलग कंपनियों में कार्यरत थे। इन प्रवासी श्रमिकों ने 16 जुलाई को एक्स हैंडल पर गुहार लगाई थी कि उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। (राब्यू)

15 आरोपितों के खिलाफ एक लाख पेज का आरोप पत्र

अहमदाबाद : गुजरात पुलिस ने राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन अग्निकांड मामले में महानगर पालिका के निलंबित नगर योजना अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गेमिंग जोन मालिकों समेत 15 आरोपितों के खिलाफ एक लाख पेज का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। टीआरपी गेमिंग जोन में गत 25 मई को आग लग गई थी। इसमें 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई थी। शवों की हालत ऐसी हो गई थी कि पहचानने के लिए डीएनए परीक्षण करना पड़ा था। (राब्यू)

अदालतें अतिक्रमण को प्रोत्साहित नहीं कर सकतीं : सर्वोच्च न्यायालय

रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की सुनवाई में कोर्ट ने टिप्पणी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 50,000 से अधिक लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र और रेलवे के साथ बैठक करें। सुप्रीम कोर्ट रेलवे द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें शीर्ष अदालत के पिछले साल पांच जनवरी के आदेश को रद करने की मांग की गई है। इसमें हल्द्वानी में रेलवे द्वारा दावा की गई अपनी 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर शीर्ष कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

याचिका में कहा गया था कि रेलवे परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए जमीन की एक पट्टी तत्काल उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि पिछले साल मानसून के दौरान पटरियों की सुरक्षा करने वाली एक रिटेनिंग दीवार को गिरा दिया गया था। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को यह योजना बनाकर देनी होगी होगी कि इन लोगों का पुनर्वास कैसे और कहां किया जाएगा। पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां भी शामिल थे। कोर्ट ने कहा, "मान लिया जाए कि वे अतिक्रमणकारी हैं, लेकिन वे दशकों से वहां रह रहे हैं। स्थिति से कैसे निपटा जाए।'

बरी होने के बाद फैसला हटाने की मांग कर सकते हैं या नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट बुधवार को कानून के इस जटिल सवाल पर गौर करने को तैयार हो गया कि क्या आपराधिक मामले में दोषमुक्त होने के बाद कोई आरोपित भूलने के अधिकार के तहत डिजिटल मंच समेत सार्वजनिक मंचों से फैसले को हटाने की मांग कर सकता है। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालती आदेश से ऐसे फैसले को सार्वजनिक मंच से हटाने के बेहद गंभीर परिणाम होंगे। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बेंगलुरु स्थित कानूनी वेबसाइट आइकनन साफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की दलील पर संज्ञान लेते हुए कहा, 'कोई अदालत यह आदेश कैसे दे सकती है?" पीठ ने कहा कि अदालतें खुद ही संवेदनशील मामलों में लोगों के नाम हटा देती हैं या उनकी पहचान छिपा देती हैं। ऐसे में पूरे फैसले को हटाने का आदेश देना दूर की कौड़ी है। अगर ऐसा किया गया तो वाणिज्यिक मामलों में भी लोग ऐसे आदेश की मांग करने लगेंगे। सजा पूरी करने के बाद दोषी भी ऐसी मांग करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का ट्रिब्यूनलों को ई-कोर्ट परियोजनाओं में शामिल करने से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ई-कोर्ट परियोजना में ट्रिब्यूनलों को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य देशभर की अदालतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना है। जनहित याचिका में कहा गया है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जैसे अर्ध-न्यायिक पैनलों को राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। एनजेडीजी ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत आता है जो देश की न्यायपालिका के कंप्यूटरीकरण पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने से संबंधित है। इसकी निगरानी कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा किया जाता है।

एनजेडीजी पोर्टल अदालतों में शुरू किए गए, लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डाटा का एक राष्ट्रीय भंडार है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस बारे में न्याय विभाग से संपर्क कर सकते हैं। एनजेडीजी ई-कोर्ट परियोजना का हिस्सा है। यह जिला न्यायालयों, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को देखता है और यह न्यायाधिकरणों को बिल्कुल नहीं देखता है।'

मुंबई समुद्र तट से 200 नाटिकल मील दूर चीन के जहाज झोंग शैन मेन में गंभीर रूप से घायल चालक दल के चीनी सदस्य को एयरलिफ्ट करता भारतीय नौसेना का हेलीकाप्टर। दूसरे चित्र में गंभीर रूप से घायल चालक दल के चीनी सदस्य को भारतीय नौसेना ने बुधवार को सफलतापूर्वक बचा लिया ● एएनआइ

आतंकी फंडिंग में नक्सली के ठिकानों पर एनआइए का छापा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची : झारखंड में आतंकी फंडिंग मामले की जांच कर रही एनआइए की टीम ने कुख्यात नक्सली रवींद्र गंझू से जुड़े दो लोगों के ठिकानों पर बुधवार को छापेमारी की। करीब सात घंटे तक चली छापेमारी में टीम ने एक ईंट भट्ठा कारोबारी के आवास से 36 लाख 30 हजार रुपये भी बरामद किए हैं।

एनआइए की टीम एक व्यवसायी के आवास पर भी पहुंची। टीम को सूचना मिली थी कि ईंट भट्ठा कारोबारी व व्यवसायी नक्सली रवींद्र के लेवी-रंगदारी के रुपयों का निवेश करते हैं। रवींद्र पर झारखंड सरकार ने 15 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। एनआइए ने उसपर पांच लाख रुपये का इनाम रखा है। रवींद्र पर करीब 55 मामले दर्ज हैं। रुपयों की बरामदगी मामले में व्यवसायी रोहित का कहना है कि सारा पैसा कारोबार का है। जबकि दूसरे व्यवसायी जितेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि उनका किसी नक्सली या अपराधी से कोई संबंध नहीं है।

82 लाख के इनामी का केस लेने की तैयारी में एनआइए

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● भोपाल: मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष अगस्त में पकड़े गए 82 लाख रुपये के इनामी नक्सली अशोक रेड्डी का केस एनआइए अपने हाथों में लेने की तैयारी कर रही है। एनआइए ने मप्र पुलिस से मामले की पूरी जानकारी मांगी है। रेड्डी का मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नेटवर्क था।

युद्ध टैंक की तरह माडिफाइ किए गए हैं ट्रैक्टर

तृतीय पृष्ठ से आगे

मेहता ने पीठ के सुझाव से सहमति जताई और कहा कि वह इस पर निर्देश लेंगे, लेकिन इस बीच यह अदालत हाई कोर्ट के शंभू बार्डर खोलने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दे। कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते में उचित निर्देश ले लीजिए, तब तक यथास्थिति कायम रहेगी।

कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि सरकार भी इस तरह हाईवे बंद नहीं कर सकती। एक वर्ष से अधिक समय हो गया है और नेशनल हाईवे ब्लाक नहीं किया जा सकता। मेहता ने कहा कि नेशनल हाईवे पर जेसीबी और ट्राली नहीं चल सकती। मोटर वाहन कानून भी इसकी मनाही करता है। उन लोगों ने ट्रैक्टर ट्रालियों को टैंक की तरह बना रखा है, जैसे सेना प्रयोग करती है। ट्रैक्टर वास्तव में युद्ध टैंक की तरह माडिफाइ किए गए हैं। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने बार्डर खोलने का समर्थन करते हुए कहा कि इससे पंजाब की आर्थिक सेहत भी प्रभावित होती है।

शंभू बार्डर पर जुटे किसानों का इंतजार बढ़ा

जागरण संवाददाता, पटियाला : दिल्ली कूच के लिए पांच महीने से ज्यादा समय से शंभू बार्डर पर पक्का मोर्चा लगाए, किसानों का इंतजार बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद और बढ़ गया है। किसान इस आशा में बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को लागू रखेगा और हरियाणा सरकार जल्द ही नेशनल हाईवे को खोल देगी। इसी उम्मीद के चलते किसानों का पिछले कुछ दिनों से शंभू बार्डर पर भी जुटना शुरू हो गया था।

किसानों का इंतजार सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद बढ़ गया, कोर्ट ने बार्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वहां यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देने के साथ ही किसानों से बातचीत के लिए स्वतंत्र समिति बनाने और हरियाणा सरकार को चरणबद्ध बार्डर खोलने के लिए सुझाव मांगा है। बुधवार को शंभू बार्डर पर किसानों ने सभा की। भारतीय किसान यूनियन भटेड़ी के अध्यक्ष जंग सिंह भटेड़ी ने बताया कि उन्हें उम्मीदें थी कि हाईवे खोलने के आदेश आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बिहार में विधानपार्षद का रिजार्ट-स्कूल जब्त

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : ईडी ने विधानपार्षद (एमएलसी) राधाचरण सेठ और उनके पार्टनर व ब्रादर्स कंपनी के एमडी अशोक कुमार गुप्ता की दो संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद एमएसडी पब्लिक स्कूल और मनाली (हिमाचल प्रदेश) में मौजूद इंटर कॉन्टिनेंटल रिजार्ट शामिल हैं।

'मात्र 600 मिली शराब मिलने पर 8.7 लाख का जुर्माना उचित नहीं'

जागरण संवाददाता, जागरण ● पटना: स्कार्पियो से मात्र 600 मिली लीटर शराब बरामद होने पर आबकारी अधिकारियों ने वाहन छोड़ने के एवज में 8.71 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। पटना हाई कोर्ट ने उसे अपराध के अनुपात से अधिक कठोर सजा करार दिया है। इसके साथ हाई कोर्ट ने जुर्माना घटाकर 25 हजार रुपये कर दिया। न्यायाधीश पीबी. बजनत्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने बुधवार को अनिल कुमार यादव की रिट याचिका को खत्म करते हुए यह निर्णय सुनाया।

मामला जमुई जिले का है, जहां वर्ष 2022 में अनिल यादव की स्कार्पियो से पुलिस ने 600 मिली शराब बरामद की थी। शराबबंदी कानून के तहत जमुई के जिला अधिकारी ने उक्त स्कार्पियो को जब्त करने का आदेश दिया। उसके विरुद्ध अनिल ने उत्पाद आयुक्त के यहां अपील दर्ज किया। सुनवाई के दौरान अनिल ने शराबबंदी नियमावली के नियम-12 के तहत जुर्माना देकर गाड़ी को छुड़ाने हेतु गुहार लगाई थी।

गंगोत्री राजमार्ग मलबा आने से अवरुद्ध, कांवड़ यात्री फंसे

गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन जोन में एनडीआरएफ के जवानों ने रोप लगाकर इस तरह कांवड़ यात्रियों व स्थानीय लोगों को भूस्खलन जोन पार करवाया ● जागरण

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार की देर रात से बुधवार की शाम तक बिशनपुर के पास करीब 15 घंटे तक मलबा आने से अवरुद्ध रहा। इस दौरान पांच हजार से अधिक कांवड़ यात्री और स्थानीय लोग हाईवे के दोनों ओर फंसे रहे। गंगोत्री से लौट रहे पैदल कांवड़ यात्रियों को एनडीआरएफ के जवानों व आपदा प्रबंधन की क्विक रिस्पांस टीम ने सुरक्षित निकाला। राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए शाम को सुचारू किया जा सका। इसके बाद दोनों ओर फंसे पांच सौ से अधिक छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही हो पाई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गुरुवार को देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इन तीन जिलों में वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, गुजरात में भारी वर्षा के चलते हुई विभिन्न घटनाओं में लगभग आठ लोगों की मौत हो गई। भारी वर्षा के चलते राज्य के बड़े हिस्से में नदियों और बांधों के उफनने से कई गांवों में पानी भर गया है। विभिन्न गांवों में फंसे 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

कैदी को ताजमहल घुमाने ले गई हरियाणा पुलिस

जागरण संवाददाता, आगरा : कैदी को पेशी पर लेकर आगरा पहुंची हरियाणा पुलिस उसे ताजमहल का दर्शन कराने चली गई। एचआर-05 नंबर की गाड़ी से पहुंचे पुलिसकर्मी कैदी को हथकड़ी में लेकर टिकट खिड़की तक पहुंचे। प्रवेश करते समय सुरक्षाकर्मियों ने हथकड़ी देखकर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। मामला बिगड़ता देख पुलिस टीम वापस चली गई। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। घटना मंगलवार दोपहर तीन बजे की बताई जा रही है।

ताजमहल परिसर में कैदी को घुमाता हरियाणा पुलिस का जवान। इसका एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रहा है ● सौइंटरनेट मीडिया

हरियाणा के करनाल जिले के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली सफेद रंग की गाड़ी ताजमहल पहुंची। इसमें से हथियारों से लैस चार पुलिसकर्मी और हथकड़ी में एक शख्स उतरा। ताजमहल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने हथियार के साथ प्रवेश करने से उन्हें रोक दिया। इसके बाद एक पुलिसकर्मी उनके हथियार लेकर स्थानीय पुलिसकर्मियों के साथ बैठ गया। शेष तीनों पुलिसकर्मी कैदी को लेकर ताजमहल के पूर्वी गेट की ओर चले गए। खिड़की से टिकट खरीदकर प्रवेश के लिए पहुंच गए। वहां तैनात एएसआइ व एडीए कर्मचारियों ने कैदी को अंदर जाने से रोक दिया।

बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे युवा कांग्रेस नेताओं पर लाठीचार्ज, 80 घायल

जागरण टीम, पटना : महंगाई, बेरोजगारी व अपराध में वृद्धि, पेपर-लीक प्रकरण, बिहार को विशेष दर्जा तथा अग्निवीर योजना के विरोध में बुधवार को युवा कांग्रेस ने राजधानी पटना में प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा घेराव के लिए निकले युवा कांग्रेसियों को पुलिस ने बोरिंग रोड चौराहा पर ही रोक लिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने जब बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वाटर कैनन का उपयोग कर पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी डटे रहे। अंततः नोक-झोक के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लाठीचार्ज से लगभग 80 नेता-कार्यकर्ता घायल हो गए। सात-आठ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

वहीं, लाठीचार्ज के दौरान ही पुलिस व बी-सैप (बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस) के कुछ जवान बैरिकेडिंग पर गिर पड़े। बी-सैप के एक जवान का सिर फट गया। दूसरे की आंख में चोट आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों का आरोप है कि कांग्रेसियों के पथराव में जवान घायल हुए हैं। पटना सदर के एसडीएम श्रीकांत कुण्डलिक खांडेकर ने प्रदर्शन को हिंसक बताया है। सचिवालय डीएसपी (द्वितीय) साकेत कुमार का कहना है कि बिना अनुमति जुलूस निकाला गया था। पुलिसकर्मियों को झंडे में लगे डंडे से पीटा गया। उपद्रव बढ़ने पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। मजिस्ट्रेट के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई है।

बुधवार को बोरिंग रोड चौराहा के पास युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करती पुलिस ● जागरण

KRIBHCO
Cooperative and beyond...
कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) की स्थापना के लिए विक्रेताओं की पूर्व-योग्यता

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको) एक बहु-राज्य सहकारी समिति है, जिसका हजीरा (सूरत) में एक विशाल उर्वरक परिसर है, जो पूरे भारत में जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर पीएमकेएसके की स्थापना के लिए पूर्व-योग्य विक्रेताओं की एक व्यापक सूची तैयार करना चाहता है। फेसेड/फ्रंटेज, फ्लेक्सी चार्ट, फर्नीचर, इंटरनेट कनेक्शन, टीवी/डिस्प्ले आदि की आपूर्ति और स्थापना का अनुभव रखने वाले विक्रेता हमारी वेबसाइट www.kribhco.net पर उपलब्ध विवरणों के अनुसार अपने लेटर हेड पर पूर्ण विवरण के साथ पूर्व-योग्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण विवरण के साथ आवेदन 14.08.2024 तक स्वीकार किए जाएंगे।

आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:
एस.एल. पंड्या, महाप्रबंधक (परियोजना)
कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड
कृभको भवन, ए-10 सेक्टर-1, नोएडा-201 301, (उ.प्र.)

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
68, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : 23730418, 23721472, 23351099
ई-मेल : mdniy@yahoo.co.in, वेबसाइट : www.yogamdniy.nic.in

प्रवेश सूचना 2024-25
स्नातकों हेतु योगा साइंस (D. Y.Sc.) में डिप्लोमा

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तहत, शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु **एक वर्ष की अवधि** (02 सेमेस्टर) के स्नातकों हेतु **डिप्लोमा इन योगा साइंस (DYSc.)** एक नियमित गैर आवासीय पाठ्यक्रम हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

पात्रता: एग्रीगेट में न्यूनतम 50% अंकों सहित एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। किंतु एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस / विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 45% होगा।

आयु सीमा: इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा नहीं है। लेकिन आवेदक चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिये एवं यदि सरकारी कर्मचारी है तो उचित माध्यम से अपना आवेदन भेजें।

सीटों की संख्या: 75 (सामा.- 33, ओबीसी-18, एससी-10, एसटी-06, ईडब्ल्यूएस-08)/ इसके अतिरिक्त 22 सीटें आरक्षित श्रेणियों अर्थात् विदेशी छात्रों (09), दिव्यांगजनों (PWD) (03), अण्डमान निकोबार द्वीप समूह / लक्षद्वीप (02), पूर्वोत्तर राज्यों (02), स्पोर्ट्स/NCC/NSS (02), युद्ध में शहीद / पूर्व सैनिकों के आश्रितों (02), MDNIY कर्मचारियों के बच्चों (01) एवं जे एण्ड के (01) की होगी। आरक्षण भारत सरकार की नियमावली के अनुसार लागू होगा।

चयन: 11/08/2024 को संचालित अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में सामा. / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस श्रेणी हेतु 40% या अधिक अंक एवं एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी हेतु 35% या अधिक अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों पर मेरिट पर प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा। आवेदन फार्म एवं प्रवेश ब्रोशर संस्थान की वेबसाइट: **www.yogamdniy.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदकों को आवेदन फार्म जमा करते समय **"मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली"** के पक्ष में, नई दिल्ली में देय, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा संस्थान के बैंक खाता सं. में ऑनलाइन माध्यम से अथवा नगद में रु. 1000/- जमा करने होंगे। चेक स्वीकार्य नहीं होंगे। आवेदन फार्म प्रस्तुति की अंतिम तिथि 02/08/2024 **(सायं 4.30 बजे तक)** है।

आवेदन फार्म की ऑनलाइन प्रस्तुति हेतु हमारी वेबसाइट: **www.yogamdniy.nic.in** देखें और अधिक विवरण हेतु संस्थान की वेबसाइट देख सकते हैं अथवा एमडीएनआईवाई के कार्यालय (फोन: 011-23730418, 23351099) में सम्पर्क करें।

निदेशक
CBC-17213/11/0004/2425

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)
विकास पथ गाजियाबाद

पत्रांक / 178 / क0अनु0 / 2024 — दिनांक 23 / 07 / 2024

सार्वजनिक सूचना

प्राधिकरण की वर्ष- 2013 में निजी विकासकर्ता द्वारा विकसित योजना संख्या-001 सम्पत्ति श्रेणी-410 (ई०डब्ल्यू०एस) एवं सम्पत्ति श्रेणी-310 (एल०आई०जी) में आवंटियों द्वारा पंजीकरण शुल्क के अलावा भवनों के मूल्य का भुगतान न करने के कारण 50 (ई०डब्ल्यू०एस) तथा 93 (एल०आई०जी) भवनों का आवंटन लॉटरी ड्रॉ 607 पात्र आवेदकों के मध्य दिनांक 06.08.2024 को हिन्दी भवन, लोहिया नगर, गाजियाबाद में 11.00 बजे से किया जाना प्रस्तावित है।

लॉटरी ड्रॉ से पूर्व प्राधिकरण की वेबसाइट www.gdaghaziabad.in एवं प्राधिकरण के जन सम्पर्क कार्यालय में पात्र आवेदकों की सूची की प्रविष्टियों में आपत्ति एवं आवश्यक संशोधन हेतु दिनांक- 25.07.2024 से 27.07.2024 तक आवेदक निर्धारित अवधि में आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। समस्त पात्र आवेदक लॉटरी ड्रॉ के समय स्वयं उपस्थित रह सकते हैं।

विशेषकार्याधिकारी/प्रभारी कम्प्यूटर

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, @Gda Ghaziabad : gdagzb
हेल्पलाईन नं. 0120-4418384 व्हाट्सएप 9990988004, वेबसाईट www.gdaghaziabad.in
एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
क्षेत्रीय कार्यालय : प्लॉट नं.- 43, सेक्टर-44, गुरुग्राम (पूर्व) हरियाणा - 122003

सार्वजनिक सूचना

निधि आपके निकट 2.0

सभी भविष्य निधि अंशदाताओं, नियोक्ताओं एवं पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि भविष्य निधि संगठन अपने कार्यक्रम 'निधि आपके निकट 2.0' के तत्वाधान में दिनांक 29.07.2024 (सोमवार) को प्रातः 9.00 बजे से 5.45 बजे शाम तक मै० जी. डी. गोयंका वर्ल्ड स्कूल, सोहना रोड, गुरुग्राम, हरियाणा और मै० सिंटेक्स बी.ए.पी.एल लिमिटेड, प्लॉट नं. 4, इंटस्ट्रियल एरिया, रोजका मेव, नूंह (मेवात), हरियाणा, पिन-122107 में कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में औद्योगिक दुर्घटनाएँ, पीएफ सदस्यता मुद्दा और पीएफ सदस्यता को बनाए रखना, हर नौकरी बदलने पर पीएफ निकासी के लाभ या प्रतिकूल प्रभाव, नाम सुधार, बैंक खाता जोड़ने आदि पर जागरूकता, एकीकृत सदस्य पोर्टल एवं अन्य मुद्दे के बारे मे विस्तृत जानकारी और तंत्र के दायरे का विस्तार कर उसे अंशदाताओं, नियोक्ताओं एवं पेंशनरों के और नजदीक लाना है।

कृते/-
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
गुरुग्राम (पूर्व)

CTR LUDHIANA केन्द्रीय टूल रूम

एम.एस.एम.ई. टैक्नोलॉजी केन्द्र,
केन्द्रीय टूल रूम, लुधियाना
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
रोजगारपरक प्रशिक्षण फायर सेफ्टी पाठ्यक्रम

संख्या	कोर्स के नाम	अवधि	योग्यता
1.	फायर टैक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी	1 साल	12वी पास
2.	हेल्थ सैनेटरी इंस्पेक्टर	1 साल (780 घण्टे)	10वी पास
3.	फायरमैन	6 माह	10वी पास
4.	सब फायर ऑफिसर	1 साल (780 घण्टे)	12वी पास +1 Yr.Exp.
5.	सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी	1 साल	12वी पास

प्रवेश प्रारम्भ

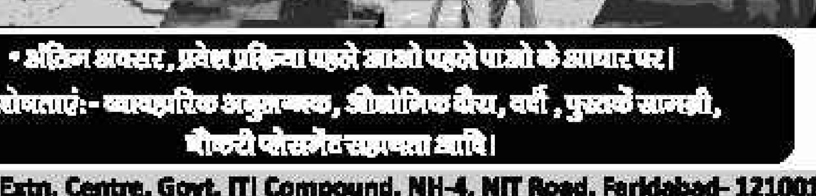

• अंतिम अवसर, प्रवेश प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर।
• विशेषताएं:- व्यावहारिक अनुभव, औद्योगिक दौरा, वर्दी, पुस्तकें सामग्री, नौकरी प्लेसमेंट सहायता आदि।

Contact us: Extn. Centre, Govt. ITI Compound, NH-4, NIT Road, Faridabad- 121001
Mob. No. : 9105111333, Email: faridabad@ctrludhian.com
प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पी-2, सैक्टर ओमेगा-1 ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतमबुद्ध नगर,
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक संख्या: वाई.ई.ए./भूलेख/तह.-वी.पी.एम./2543/2024 — दिनांक: 23.07.2024

सार्वजनिक सूचना

निम्नलिखित भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर काश्तकारों से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। क्रय हेतु काश्तकार, गाटा संख्या, क्षेत्रफल व काश्तकार का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में अंकित है-

(सैक्टर-28, ग्राम रबूपुरा, कॉमर्शियल)

क्रम सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे. में)	तहसील की आख्यानुसार काश्तकार का भाग	तहसील की आख्यानुसार काश्तकार का हिस्सा	काश्तकार का नाम
1.	631	1081	1.0700	में से	0.1458	शमीम, नईम, फईम पुत्रगण सलीम व सलमा पत्नी सलीम नि. रबूपुरा
2.	631	1081	1.0700	में से	0.1881	शको उर्फ शहजाद पुत्र सुलेमान नि. रबूपुरा

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिवस के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के कार्यालय/सी.आर.सैल में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

विशेष कार्याधिकारी
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अतिरिक्त प्लॉटिंग / हाउसिंग / कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

प्रापर्टी से मिलने वाले किराये को बिजनेस इनकम दिखाकर नहीं हो सकेगी टैक्स की चोरी

साक्षात्कार

सरकार की ओर से आम बजट में संपत्ति बिक्री पर लांग टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसे लेकर निवेशकों में दुविधा की स्थिति है कि आखिरी इससे फायदा होगा या नुकसान। इसके साथ ही राजकोषीय घाटे को कम करने को लेकर भी सरकार कमर कस रही है। दैनिक जागरण के राजीव कुमार से बात करते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने लोगों से जुड़े इन प्रश्नों का उत्तर दिया।

● आपने बताया है कि 70 प्रतिशत करदाता टैक्स की नई व्यवस्था अपना चुके हैं तो फिर पुरानी व्यवस्था की जरूरत क्या है?

– जैसा कि वित्त मंत्री ने भी कहा है कि जो पुरानी व्यवस्था है, उसे हम समाप्त नहीं करेंगे। अभी पुरानी टैक्स व्यवस्था जारी रहेगी। हालांकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग नई टैक्स प्रणाली को अपनाए क्योंकि यह सरल है।

● इस बार के बजट में टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए, इनकम टैक्स तो लगभग तीन करोड़ लोग ही देते हैं?

–बजट के पार्ट बी में हमने टीडीएस, टीसीएस, लग्जरी गुड्स के टैक्स में बदलाव किया है। जो पार्टनर लोग है उनकी सैलरी पर टीडीएस का प्रविधान लेकर आए हैं। वैसे ही, अब हाउस प्रापर्टी को बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें टैक्स की चोरी हो रही थी। कुछ लोग क्या करते थे कि वह हाउस प्रापर्टी की इनकम को बोलते थे कि यह हमारा बिजनेस हैं। एक करोड़ रुपये का मकान खरीदा और उससे किराया आठ लाख रुपए मिले, लेकिन 10 लाख रुपए उसने मकान का डिप्रिसिएशन दिखा दिया और ऐसे करके टैक्स से बच रहे थे। अब उन्हें किराए पर टैक्स देना ही पड़ेगा।

● रियल एस्टेट बिक्री में कैपिटल गेन को लेकर इंडेक्सेशन प्रणाली खत्म करने से क्या राजस्व बढ़ेगा?

–नहीं। शार्ट टर्म और लांग टर्म इक्विटी कैपिटल गेन की दरों में जो बदलाव हुआ है, उससे हमें 17,000 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन प्रणाली को समाप्त करने से प्रापर्टी मालिकों को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इस प्रणाली के तहत 20 प्रतिशत का टैक्स था जो अब 12.5 प्रतिशत हो गया। रियल एस्टेट अमूमन 10-11 प्रतिशत की दर से रिटर्न देता है। कोई पुरानी जगह हो जहां रिटर्न नहीं आ रहा हो तो अलग बात है।

● छोटे निवेशक जो बाजार में 5-7 लाख रुपये तक के निवेश से कुछ कमा रहे थे, उन्हें तो इक्विटी के कैपिटल गेन के टैक्स बढ़ने से फर्क पड़ेगा, पहले 10 प्रतिशत लगता था, अब 12.5 प्रतिशत लगेगा?

–जो 5-7 लाख रुपये तक बाजार में निवेश करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लांग टर्म के निवेश से होने वाले 1.25 लाख रुपये तक के मुनाफे को टैक्स से मुक्त रखा गया है। कोई 10 लाख रुपये बाजार में लगाता है और एक साल बाद 11.25 लाख रुपये में उस शेयर को बेच देता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखा जाए तो हर महीने 10,000 रुपये की कमाई को सरकार ने टैक्स मुक्त कर दिया है।

● लेकिन एक साल से कम समय में यानी कि शार्ट टर्म वाले निवेश से मुनाफे पर तो आपने 20 प्रतिशत का टैक्स लगा दिया?

–मेरा मानना है कि शार्ट टर्म कोई निवेश नहीं है, शार्ट टर्म तो व्यापार है। इसलिए उस पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए।

● आप राजकोषीय घाटे को कम कर रहे हैं और चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी का 4.9 प्रतिशत का लक्ष्य है, लेकिन जीडीपी के अनुपात में हमारा कर्ज क्यों नहीं कम हो रहा है?

–अभी हमारा केंद्रीय कर्ज जीडीपी के अनुपात में 55 प्रतिशत के पास है। अभी हम जीडीपी के अनुपात में राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य रखते हैं, वर्ष 2027 से हम जीडीपी के अनुपात में कर्ज के अनुपात को कम करने का लक्ष्य रखेंगे। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इसलिए हमारा राजकोषीय घाटा ज्यादा भी हो सकता है।

● इस साल अब तक चार करोड़ लोगों ने ही आइटीआर फाइल किए हैं और इस बार रिफंड मिलने में भी देर हो रही है, पहले सप्ताह भर में रिफंड मिल जाता था?

–वित्त वर्ष 2023-24 में 8.5 करोड़ करदाताओं ने आइटीआर फाइल किए थे। दो दिन पहले तक 4.3 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं और पिछले साल की समान अवधि की तुलना में हम रिटर्न फाइलिंग में आगे हैं। रिफंड देने में हमारा प्रोसेसिंग टाइम हर वर्ष कम हो रहा है। वैसे रिफंड के लिए हमारी समय सीमा अलग है। रिटर्न फाइल करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद इसमें और तेजी आएगी। अभी रिटर्न फाइलिंग का काम चल रहा है और यह पीक समय है। अभी जो फाइल करेगा उन्हें स्वाभाविक रूप से देर से रिफंड मिलेगा, जिन्होंने पहले फाइल कर दिया है उन्हें मिल रहा है। सिटिजन चार्टर के हिसाब से रिफंड के लिए 90 दिन की समय सीमा है।

बेनामी संपत्ति निषेध कानून में संशोधन का प्रस्ताव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: आम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेनामी परिसंपत्ति निषेध कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इस संशोधन के जरिये बेनामी परिसंपत्तियों को लेकर संबंधित सरकारी एजेंसियों की तरफ से मांगी गई सूचना का समय पर जवाब देने वाले व्यक्तियों को अर्थदंड और अभियोग यानी मुकदमे से राहत देने की व्यवस्था होगी।

इसके अलावा, वित्त विधेयक, 2024 में विदेश में छिपाए गए काले धन की जानकारी को लेकर लागू काला धन (विदेशों में अर्जित अघोषित आय व परिसंपत्तियों) कानून में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपनी संपत्तियों या धन की जानकारी भारत में किए गए आयकर रिटर्न में नहीं देता है तो उस पर 10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।

जीडीपी-उधारी अनुपात घटाने पर होगा फोकस

2026 के बाद 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा राजकोषीय घाटा, मौजूदा उधारी चिंता का विषय नहीं

जयप्रकाश रंजन • जागरण

नई दिल्ली: आम बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इस वर्ष सरकार 14.01 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी और यह वर्ष 2023-24 के मुकाबले 12 हजार करोड़ रुपये कम है। बजट के एक दिन बाद वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने विदेशी और घरेलू उधारी को लेकर सरकार की दीर्घकालिक रणनीति के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि उधारी को सिर्फ राजकोषीय घाटे के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सरकार का उद्देश्य वर्ष 2026 के बाद न सिर्फ राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का होगा बल्कि जीडीपी के मुकाबले उधारी का अनुपात भी कम किया जाएगा। गौरतलब है कि विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जा रही है कि कुल व्यय में 19 प्रतिशत हिस्सा उधारी का ब्याज चुकाने में जा रहा है। जबकि वित्त मंत्रालय के अधिकारी इसे चिंता का विषय नहीं मानते हैं।

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के मुताबिक, 'वर्ष 2026-27 के बाद से हम जीडीपी के मुकाबले उधारी के स्तर को लगातार नीचे लाने पर ज्यादा फोकस करेंगे। जहां तक विदेशी कर्ज की बात है तो भारत जैसे तेज विकास दर वाली बड़ी इकोनमी में इसका महत्व सुस्त विकास दर वाले देशों के मुकाबले अलग होता है। भारत न सिर्फ तेज विकास दर वाला देश है बल्कि इसका विशाल विदेशी मुद्रा भंडार (661 अरब डालर) है।

दुनिया के दूसरे देशों की मुद्राओं के मुकाबले स्थिर करेंसी और लगातार बढ़ता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऐसी प्रमुख वजहें जो विदेशी कर्ज के खतरे को कम करते हैं। अगर दो दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण में भारत पर विदेशी कर्ज की राशि का आकलन करें तो यह दिखाई पड़ता है कि सरकार विदेशी कर्ज के स्तर को एक निश्चित सीमा में रखने में सफल रही है।

मार्च, 2023 में जीडीपी और विदेशी कर्ज का अनुपात 19 प्रतिशत था जो मार्च, 2024 में घटकर 18.7 प्रतिशत पर आ गया है। इस दौरान एक वर्ष के भीतर चुकाए जाने वाले विदेशी कर्ज का हिस्सा कुल विदेशी कर्ज में 20.6 प्रतिशत से घटकर 18.5 प्रतिशत पर आ गया है। वर्ष 2021 में देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 100.6 प्रतिशत विदेशी कर्ज था जो आज की तारीख में घट कर 99.7 प्रतिशत हो गया है।

कुछ दिन पहले उधारी पर आइएमएफ ने चेताया था

दिसंबर, 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत पर कुल उधारी का स्तर उसके जीडीपी के बराबर (100 प्रतिशत से ज्यादा) होने की तरफ अग्रसर है। इसने जो आंकड़ा दिया था, उसके मुताबिक वर्ष 2021-22 में देश के जीडीपी के अनुपात में कुल उधारी 83.8 प्रतिशत थी। इसमें घरेलू कर्ज का अनुपात 59.5 और विदेशी कर्ज का अनुपात 19.7 प्रतिशत था। अब इस आंकड़े में सुधार दिख रहा है। जीडीपी के अनुपात में कुल कर्ज का स्तर घट कर 82 प्रतिशत पर आ गया है। वित्त मंत्रालय मान रहा है कि इसमें आने वाले समय में और तेज गति से गिरावट होगी।

● स्थिर मुद्रा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण विदेशी कर्ज को लेकर खतरा नहीं

● उधारी को सिर्फ राजकोषीय घाटे के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए

तेज विकास दर हासिल करने के लिए नई उधारी लेने से पीछे नहीं हटेगी सरकार

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से जब यह पूछा गया कि क्या कुल व्यय में ब्याज भुगतान का हिस्सा भी मौजूदा 19 प्रतिशत से कम होगा तो उनका जवाब था कि सरकार की योजना लगातार 7-8 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने की है। हमारा आकलन है कि राजस्व संग्रह भी तेजी से बढ़ेगा और व्यय भी तेज होगा। अगर राजस्व संग्रह में सुधार होता रहेगा और योजना के मुताबिक आगे बढ़ते हैं तो समय से पहले भी उधारी चुकाने पर विचार किया जा सकता है। ऐसा पहले भी किया गया है। हालांकि तेज विकास दर के लिए हमें लगातार नई उधारी भी लेने की जरूरत होगी क्योंकि हमें विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधाओं को लगाना होगा, सामाजिक विकास की गुणवत्ता को बेहतर करना है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि ब्याज अदायगी में बोझ को कम किया जा सकता है या नहीं।

निवेश पर नहीं लगाया जाना चाहिए था एंजल टैक्स, अब स्टार्टअप मजबूत होंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र: स्टार्टअप से एंजल टैक्स हटाने का मुद्दा लंबे समय से लंबित था और चूंकि यह कर देश में आने वाले निवेश पर लगाया जाता था और इस तरह के विदेशी निवेश पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस फैसले से विदेशी निवेश आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

सिंह ने बताया कि एंजल टैक्स का मुद्दा ईज आफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ कर का भी मुद्दा था। दरअसल, यह आय पर नहीं बल्कि निवेश पर कर था और निवेश पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, और यही मूल विचार है। सिंह ने कहा कि इस फैसले से विवाद और मुकदमेबाजी भी कम होगी। निवेशक नए नवाचार पर निवेश करता है और यह कर उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा, ''वास्तव में यह भारत में एफडीआइ (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को कम करता है। ऐसे निवेश से जुड़े मनी लांड्रिंग संबंधी मुद्दों के बारे में अधिकारियों की चिंता पर सिंह ने कहा कि इसके लिए पहले से कानून मौजूद है। आप एक, दो या तीन प्रतिशत लोगों से निपटने के लिए ऐसे 97 प्रतिशत लोगों पर बोझ डाल रहे हैं जो वास्तव में नवोन्मेषी है और एक विचार को मूर्तरूप देने के लिए निवेश प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई स्टार्टअप विदेश से कोई निवेश हासिल करता है तो उस निवेश को अन्य माध्यम से आय मानते हुए उस पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगता है, जिसे एंजल टैक्स कहा जाता है। अपनी फेयर वैल्यू से जितनी अधिक राशि स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से जुटाता है, उस पर एंजल टैक्स वसूला जाता है।

● डीपीआइआइटी सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा-सरकार के फैसले से नवाचार को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद

● कहा- एक, दो या तीन प्रतिशत लोगों से निपटने के लिए 97 प्रतिशत लोगों पर बोझ नहीं डाल सकते

एफडीआइ मंजूरी के लिए तैयार होगी सख्त समयसीमा

डीपीआइआइटी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) प्रस्तावों की मंजूरी के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विभागों के लिए सख्त समयसीमा तैयार करेगा। सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इन मंजूरियों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है, लेकिन फिर भी देर हो रही है, क्योंकि एसओपी का पालन नहीं किया जा रहा है। एफडीआइ को सुविधाजनक बनाने और प्राथमिकता को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश के नियमों और विनियमों को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रालयों और विभागों को आवेदनों को प्राथमिकता देने और अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

एक नजर में

मोबाइल पीएलआइ में 8,282 करोड़ रुपये का निवेश

नई दिल्ली: मोबाइल और इससे जुड़े उपकरणों की उत्पादन प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ) में जून 2024 तक 8,282 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि अब तक 32 कंपनियों के 11,324 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है। पीएलआइ के तहत 10.7 लाख करोड़ रुपये के उत्पाद बनाए जाने हैं। (प्रेट्र)

ईएसआइसी से मई में 23.05 लाख नए सदस्य जुड़े

नई दिल्ली: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) से मई में 23.05 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। श्रम मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि मई के दौरान 20,110 नए संस्थान ईएसआइसी के दायरे में आए हैं। इस कारण ज्यादा कामगारों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। मंत्रालय ने बताया कि मई 2023 के 20.23 लाख के मुकाबले इसमें 14 प्रतिशत की वृद्धि रही है। (प्रेट्र)

यस बैंक को जून तिमाही में 502 करोड़ का लाभ

नई दिल्ली: निजी क्षेत्र के यस बैंक को अप्रैल-जून 2024 तिमाही के दौरान 502 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इसमें 46.7 प्रतिशत की वृद्धि रही है। बीती तिमाही में बैंक की ब्याज से शुद्ध आय 12.2 प्रतिशत बढ़कर दो हजार करोड़ रुपये रही है। इस दौरान बैंक के कर्ज वितरण में 20 प्रतिशत की वृद्धि रही है। तिमाही के दौरान बैंक की अन्य आय 5.1 प्रतिशत बढ़कर 1,141 करोड़ रुपये रही है। (वि.)

कैंट ने पेश किया क्रिस्टल स्टार बी वाटर प्यूरिफायर

नई दिल्ली: कैंट आरओ सिस्टम्स ने बारिश के मौसम को देखते हुए नया क्रिस्टल स्टार बी वाटर प्यूरिफायर लांच किया है। इस प्यूरिफायर में आरओ, यूवी, यूएफ और टीडीएस कंट्रोल टेक्नोलाजी को शामिल किया गया है। इस बेहतरीन सिस्टम को यूवी-एलटी की टेक्नोलाजी और भी शानदार बनाती है। कैंट आरओ सिस्टम्स के चेयरमैन डा. महेश गुप्ता का कहना है कि पानी को स्टोर करने की जगह में यूवी एलईडी लगाया गया है जो पानी की शुद्धता को बरकरार रखता है। (वि.)

अनुपालन को आसानी के लिए कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव

● विभिन्न परिसंपत्ति निवेश की अवधि को तर्कसंगत बनाया गया

● सभी सूचीबद्ध परिसंपत्तियों की होल्डिंग अवधि अब एक वर्ष होगी

नई दिल्ली, प्रेट्र: आयकर विभाग ने बुधवार को पूंजीगत लाभ कर में हुए बदलावों पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) की एक सूची जारी की है। एफएक्यू में कहा गया है कि पूंजीगत लाभ कर में परिवर्तन कर ढांचे को सरल बनाने और अनुपालन में आसानी को बढ़ावा देगा। इसके तहत विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए होल्डिंग (निवेश की अवधि) को तर्कसंगत बनाया है।

लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) के उद्देश्य से सभी सूचीबद्ध परिसंपत्तियों की होल्डिंग अवधि अब एक वर्ष होगी। इसलिए, व्यावसायिक ट्रस्टों (रीट और इनविट) की सूचीबद्ध इकाइयों के लिए होल्डिंग अवधि 36 महीने से घटाकर 12 महीने कर दी गई है। सोना, गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (गैर-सूचीबद्ध शेयरों के अलावा) की होल्डिंग अवधि भी 36 महीने से घटाकर 24 महीने कर दी गई है। अचल संपत्ति और गैर-सूचीबद्ध शेयरों की होल्डिंग अवधि पहले की तरह 24 महीने ही रहेगी। आयकर विभाग ने एफएक्यू में कहा, 'किसी भी कर ढांचे के सरलीकरण से अनुपालन में आसानी जैसे गणना, फाइलिंग, रिकार्ड का रखरखाव आदि के लाभ मिलते हैं।' 23 जुलाई से लिस्टेड इक्विटी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स पर शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एसटीसीजी) की दर 15 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह, लांग टर्म के लिए इन संपत्तियों के लिए दर 10 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 फीसदी हो गई है। हालांकि, इन संपत्तियों पर एलटीसीजी के लिए एक लाख रुपये की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है। सोना, प्रापर्टी, लिस्टेड और अनलिस्टेड बांड और डिबेंचर जैसी अन्य संपत्तियों पर शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एसटीसीजी) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इंडेक्सेशन खत्म होने से कोई नुकसान नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय का दावा है कि बजट में लांग टर्म कैपिटल गेन के तहत संपत्ति बिक्री पर जो 12.5 प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है, उससे विक्रेता को पहले के मुकाबले कोई नुकसान नहीं है। अब तक लांग टर्म में रियल एस्टेट की बिक्री पर इंडेक्सेशन प्रणाली के तहत 20 प्रतिशत का टैक्स लगता था। इंडेक्सेशन प्रणाली के तहत महंगाई दर को समायोजित करने के बाद प्रापर्टी की तय कीमत पर टैक्स लगता था।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक मान लीजिए वर्ष 2014-15 में 100 रुपये में किसी प्रापर्टी को खरीदा गया था। वर्ष 2024-25 में कास्ट आफ इंफ्लेशन इंडेक्स (सीआइआइ) 363 है जो वित्त वर्ष 2014-15 में 240 था। इस हिसाब से इस साल 100 रुपये में खरीदी गई उस प्रापर्टी की इंडेक्सेशन कास्ट 151 रुपये बनती है। अगर 100 रुपये की उस प्रापर्टी को अभी 800 रुपये में बेचते हैं तो इंडेक्सेशन कास्ट 151 रुपए घटाने पर कैपिटल गेन 649 रुपए बनता है और 20 प्रतिशत की दर से उस पर 129 रुपए का टैक्स लगेगा। वहीं अगर नई प्रणाली के तहत उस प्रापर्टी की बिक्री 800 में करने पर 700 रुपये पर 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा और उस पर 87.5 रुपये का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो पुरानी व्यवस्था की टैक्स राशि से 42 रुपये कम है। इस तरह नई व्यवस्था में 32.6 प्रतिशत टैक्स की बचत हो रही है।

वैसे ही, 100 रुपये की उस प्रापर्टी को अगर आज 300 रुपये में भी बेचते हैं तो इंडेक्सेशन कास्ट के तहत 151 रुपए को घटाने पर 149 रुपये का कैपिटल गेन होता है, जिस पर 20 प्रतिशत की दर से 29.8 रुपये का टैक्स लगेगा। वहीं नई प्रणाली के तहत 300 रुपये में बेचने पर 200 रुपये पर 12.5 प्रतिशत की दर 25 रुपये का टैक्स लगेगा। यहां भी टैक्स राशि में 4.8 रुपये की बचत हो रही है। अगर प्रापर्टी का रिटर्न काफी कम है तो नई प्रणाली से बेचने पर नुकसान है।

66 प्रतिशत करदाताओं ने नई कर प्रणाली चुनी

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बुधवार को बताया कि चालू सत्र में अब तक करीब चार करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल कर दिया है। इसमें से 66 प्रतिशत करदाताओं ने नई कर प्रणाली चुनी है। बजट बाद एक साक्षात्कार में सरकार और प्रत्यक्ष कर बोर्ड का ध्यान आइटीआर दाखिल करने और अन्य कारोबार करने सहित कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर है। सरकार का मानना है कि आप जितना सरलीकरण करेंगे, लोगों के लिए अनुपालन करना उतना ही आसान होगा। इससे अनुपालन भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अब तक दाखिल किए गए आइटीआर की संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले काफी अधिक है। सीबीडीटी चेयरमैन ने बताया कि लंबित कर मामलों के निपटान के लिए बजट में घोषित विवाद से विश्वास स्कीम 2024 में करदाता 31 दिसंबर से इस योजना का लाभ ले सकेंगे। योजना के संबंध में अधिसूचना और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) जल्द जारी किए जाएंगे।

इक्विटी कैश श्रेणी में 70% इंट्राडे ट्रेडर्स को घाटा

अध्ययन

● सेबी के अध्ययन के मुताबिक, चार सालों में इंट्राडे ट्रेडर्स की संख्या में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई

● इंट्रा-डे में हिस्सा लेने वाले ऐसे युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है

नई दिल्ली, प्रेट्र: मार्केट रेगुलेटर सेबी के एक अध्ययन से पता चलता है कि इक्विटी कैश सेगमेंट में 10 में से 7 यानी 70 प्रतिशत व्यक्तिगत इंट्राडे ट्रेडर्स को वित्त वर्ष 2022-23 में घाटा हुआ है। इसके साथ ही अध्ययन से यह भी पता चला है कि 2018-19 की तुलना में 2022-23 में इक्विटी कैश सेगमेंट में इंट्रा-डे ट्रेडिंग में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों की संख्या में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिलचस्प तथ्य यह है कि घाटे में रहने वालों द्वारा किए गए ट्रेडों की औसत संख्या लाभ कमाने वालों की तुलना में अधिक थी। अध्ययन के अनुसार, इंट्रा-डे में हिस्सा लेने वाले ऐसे युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है।

सेबी ने इक्विटी कैश सेगमेंट में व्यक्तियों द्वारा इंट्राडे ट्रेडिंग में भागीदारी और लाभ-हानि के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन किया है। इसने महामारी से पहले और बाद के रुझानों का तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए वित्त वर्ष 2018-19, वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि को शामिल किया गया है। शीर्ष-10 स्टाक ब्रोकर के यहां पंजीकृत ग्राहकों पर आधारित यह अध्ययन 2022-23 के दौरान इक्विटी कैश सेगमेंट के इंट्रा डे ट्रेडिंग में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या का 86 प्रतिशत है। अपने अध्ययन में सेबी ने पाया कि इक्विटी कैश सेगमेंट में व्यापार करने वाले तीन में से लगभग एक व्यक्ति इंट्रा-डे ट्रेड करता है। इसके अलावा, 30 वर्ष से कम आयु के युवा इंट्राडे ट्रेडर्स की हिस्सेदारी 2018-19 में 18 प्रतिशत थी जो 2022-23 में बढ़कर 48 प्रतिशत हो गई है।

घाटे में रहने वालों ने 57% ट्रेडिंग लागत के रूप में खर्च किया

अध्ययन में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में इक्विटी कैश सेगमेंट में बहुत बार-बार (एक वर्ष में 500 से अधिक ट्रेड) ट्रेडिंग गतिविधि करने वाले ट्रेडर्स के लिए घाटे में रहने वालों का अनुपात बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया। इस दौरान घाटे में रहने वालों ने अपने ट्रेडिंग घाटे का अतिरिक्त 57 प्रतिशत ट्रेडिंग लागत के रूप में खर्च किया। लाभ वालों में यह 19 प्रतिशत था। इसके अलावा, दूसरे आयु समूहों की तुलना में 2022-23 में युवा ट्रेडर्स में घाटे में रहने वालों का प्रतिशत 76 प्रतिशत अधिक था।

महामारी में एफएंडओ में हिस्सा लेने वालों की संख्या बढ़ी

सेबी का मानना है कि इस अध्ययन से इंट्रा-डे ट्रेडिंग में शामिल जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। महामारी के दौरान एफएंडओ सेगमेंट में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस सेगमेंट वित्त वर्ष 2018-19 में इंडिविजुअल ट्रेडर्स की संख्या 7.1 लाख थी जो 2020-21 में 500 प्रतिशत बढ़कर 45.24 लाख हो गई।

बजट के दूसरे दिन 678 अंक तक लुढ़का सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र: वित्तीय और बैंकिंग शेयरों में मुनाफावसूली के चलते घरेलू शेयर बाजार बुधवार को लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 280.16 अंक की गिरावट के साथ 80,148.88 अंक पर बंद हुआ। बजट के दूसरे दिन कारोबार के दौरान इसमें 678.53 अंक तक की गिरावट हुई थी। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 65.55 अंक गिरकर 24,413.50 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में बजाज फिनसर्व के शेयरों में दो प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनीलिवर, कोटक महिंद्रा बैंक, अदाणी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक और एसबीआइ के शेयर भी गिरकर बंद हुए।

रोजगार सृजन के लिए सरकार संग काम करे निजी क्षेत्र : महिंद्रा

नई दिल्ली, प्रेट्र: महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने बुधवार को कहा कि भारत के निजी क्षेत्र को रोजगार सृजन तथा युवाओं को रोजगार योग्य बनाने की दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास के अभाव में देश का जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसांख्यिकीय आपदा में बदल सकता है।

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ वृद्धि का महत्व पहचानती है। आनंद महिंद्रा ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर लिखा, 'हमारी आर्थिक विकास दर में होने वाली लगातार वृद्धि दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय बन रही है। हमारे भविष्य को लेकर आश्वस्त होने के कारण हम निवेश के लिए दुनिया का पसंदीदा गंतव्य हैं।' उन्होंने कहा, 'हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह सुनिश्चित करना है कि इस वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी तेजी आए।'

विशेषज्ञ टिप्पणी

बजट में दिखती है सरकार की निरंतरता की झलक

निमेश चंदन

कुछ समय पहले इलिनोइस विश्वविद्यालय के डेनियल सीमंस और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के क्रिस्टोफर चैब्रिस द्वारा एक दिलचस्प अध्ययन किया गया था। उन्होंने छात्रों का एक समूह बनाया और उसे एक वीडियो देखने को कहा। वीडियो में दो समूह (एक सफेद टी-शर्ट और दूसरा काली टी-शर्ट) बास्केटबाल खेल रहे थे। छात्रों के समूह से यह कहा गया कि वह खेल के दौरान इस बात को नोट करें कि आखिर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को कितनी बार पास दिए। जब छात्र टीमों की गतिविधि पर नजर रख रहे थे तो कभी-कभी एक व्यक्ति छाता लेकर टीमों के बीच गुजर जाता था। थोड़ी देर बाद जब छात्र समूह से इस संदर्भ में पूछा गया तो आधे से अधिक ने ऐसी किसी गतिविधि से इन्कार किया। इस शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि कभी-कभी जब हम एक चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा ध्यान उन चीजों पर भी नहीं जाता है, जो हमारी आंखों के सामने होती हैं।

मंगलवार को पेश कए गए बजट में बाजार से जुड़े लोगों को पूरा ध्यान कैपिटल गेन टैक्स में हुए परिवर्तन पर रहा। अब इस मुद्दे को अलग रखें और पेश किए गए बजट का मूल्यांकन करें। पेश किए गए बजट में सरकार की निरंतरता की झलक मिलती है। यह सरकार का तीसरा कार्यकाल है और इसलिए वित्त मंत्री ने केवल उन क्षेत्रों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया, जिन्हें पिछले बजट में छोड़ दिया गया था। राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने आश्चर्यजनक एलान किया। फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में उन्होंने 5.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे की बात कही थी, लेकिन पूर्ण बजट में उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 में इस लक्ष्य को घटाकर 4.9 प्रतिशत कर दिया। साथ ही सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को कम करके 4.6 प्रतिशत पर लाने की बात कही है। रोजगार पर भी सरकार का प्रमुख ध्यान रहा। इस संबंध में वित्त मंत्री तीन प्रमुख योजनाएं शुरू करने का एलान किया है। 1-पहली बार नौकरी पाने वालों को 15,000 रुपये की योजना 2-मैन्यूफैक्चरिंग में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए प्रोत्साहन 3-सभी नए कर्मचारियों के लिए दो साल के लिए 3,000 रुपये का ईपीएफओ में योगदान। कुल मिलाकर, इन योजनाओं से परिवारों की आय में वृद्धि होगी। बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए एलान किया गया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे कर्ज और नकदी की सबसे अधिक जरूरत होती है। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने इस सेक्टर के लिए एक नई ऋण गारंटी योजना लाने का प्रस्ताव किया है। मुद्रा लोन की सीमा भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के लिए, सरकार ने नई कर व्यवस्था में बेहतर कर स्लैब प्रस्तावित किए हैं, जिससे 17,500 रुपये तक की बचत होगी। मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इन उपायों से अर्थव्यवस्था और कारोबार दोनों को मदद मिलनी चाहिए। बजट में की गई इन घोषणाओं को बाजार ने हाथोंहाथ लिया, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान पूंजीगत लाभ कर में बदलावों की घोषणाओं ने खींचा। एफएंडओ पर एसटीटी में वृद्धि की बाजार को उम्मीद थी। हालांकि, बाजार अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर को 15% से बढ़ाकर 20% और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10% से बढ़ाकर 12.5% करने से आश्चर्यचकित था। कुल मिलाकर, इस बजट से फिक्सड इनकम मार्केट सेगमेंट जहां खुश होगा, वहीं इक्विटी कर दरों में बदलाव से आगे बढ़कर आय में वृद्धि और मूल्यांकन पर फिर से ध्यान होगा। बाजार के मौजूदा स्वरूप को देखें तो निवेशक बड़ी कंपनियों की तरफ एक बार फिर से लौट सकते हैं, क्योंकि मिडकैप और स्मालकैप की तुलना में जोखिम कम है।

लेखक बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के सीईओ हैं

****

27 लाख कैंसर रोगियों को सीमा शुल्क हटाए जाने से मिलेगा लाभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंसर के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने के बजट प्रस्ताव का किया स्वागत। बता दें, वित्त मंत्रालय ने कैंसर रोगियों को ध्यान में रखते हुए ट्रासट्रूजुमब डेरूक्सटिकेन, ओसिमर्टिनिब, डूरवालूमाब पर लगने वाले 10 प्रतिशत शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इससे मरीजों को सस्ता इलाज सुलभ हो सकेगा।

बजट में भेदभाव का आरोप लगा विपक्ष ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: कांग्रेस के नेतृत्व में आइएनडीआइए ने बजट में विपक्षी दल शासित राज्यों के साथ 'भेदभाव' का आरोप लगाते हुए संसद के बाहर और भीतर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में आइएनडीआइए के दलों की सरकार है और जहां भाजपा का चुनावी प्रदर्शन खराब रहा है, उन सभी राज्यों की बजट में अनदेखी की गई है। लोकसभा और राज्यसभा में एकजुट विपक्ष ने आंध्र प्रदेश और बिहार के अलावा अन्य राज्यों को किसी तरह की वित्तीय मदद नहीं देने का सवाल उठाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही राजग सरकार को घेरा। विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों से वाकआउट भी किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ ही कांग्रेस शासित तीनों राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए मंगलवार को ही प्रधानमंत्री द्वारा 27 जुलाई को बुलाई गई नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी थी। वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर बजट को सबके हित में सर्वसमावेशी बताया। सरकार का कहना है कि बजट में जो भी योजनाएं हैं, वह पूरे देश के लिए हैं।

बजट पेश होने के दूसरे दिन संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सबेरे ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत आइएनडीआइए के विभिन्न नेताओं ने संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने राजग सरकार के बजट को भेदभावपूर्ण करार देते हुए नारेबाजी भी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बजट जनविरोधी है। इसमें विशेष पैकेज की बात कही गई है। विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। वहीं तमाम विपक्षी सांसदों ने कहा कि असल में यह राजग का बजट है। हमें भारत का बजट चाहिए।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम आंध्र प्रदेश और बिहार को धन देने के खिलाफ नहीं हैं। मगर अन्य राज्यों के साथ भी न्याय होना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया गया है। इस सरकार ने पहले नौकरियां छीन लीं और अब बजट में बस अप्रेंटिसशिप की बात कर रही है। विपक्ष ने विरोध की इस आवाज को दोनों सदनों में भी मुखरता से उठाया।

लोस की कार्यवाही शुरू होते ही आइएनडीआइए के सांसदों ने बजट में भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए गहमागहमी शुरू कर दी। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने एतराज किया। इसको लेकर हुए संक्षिप्त शोरगुल के बीच समूचे विपक्ष ने लोकसभा से वाकआउट किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा बजट के भेदभावपूर्ण होने पर दिए गए कार्यस्थगन नोटिस को सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया। हालांकि खरगे ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि बजट में दो राज्यों को ही थाली में पकौड़ा और जलेबी मिली। बाकी राज्यों की थाली खाली है। हमने किसी को खुश कर कुर्सी बचाने का ऐसा बजट नहीं देखा और इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं।

नई दिल्ली में बुधवार को संसद भवन परिसर में आम बजट 2024 को भेदभावपूर्ण बताते हुए इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी को प्रणाम करते समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ● प्रेट्र

निर्मला पर खरगे का तंज-माताजी बोलने में एक्सपर्ट हैं

नई दिल्ली, एएनआइ: खरगे ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट को लेकर सवाल किए और दावा किया कि बजट आवंटन में बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर किसी राज्य को कुछ नहीं मिला। आइएनडीआइए की सभी पार्टियां इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। सभापति जगदीप धनखड़ ने खरगे को टोका और कहा कि अब वित्त मंत्री को बोलने दीजिए। इस पर खरगे ने तंज कसा और कहा, माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट हैं। मुझे मालूम है। इस पर धनखड़ ने खरगे को फिर टोका और कहा कि यह माताजी नहीं, यह तो आपकी बेटी के बराबर हैं।

बौखलाहट में कांग्रेस कर रही है बजट का विरोध : भाजपा

- कहा, राजग को कमजोर करने की कांग्रेस की कोशिश हुई नाकाम
- सरकार के बजट का सभी वर्गों ने स्वागत किया

जीवीएल नरसिम्हा राव ● फाइल फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा बजट के विरोध को भाजपा ने बौखलाहट का नतीजा करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि बजट का सभी वर्गों ने स्वागत किया है और इसमें शिक्षा और रोजगार का विशेष ध्यान रखा गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 2014 के बाद सभी बजट में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर जोर देती रही है और यह सहायता भी उसी का परिणाम है।

भाजपा नेता ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे मुद्दा उठाकर जदयू और तेदेपा को राजग से अलग करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो पाई। एकजुट और मजबूत राजग को देखकर कांग्रेस के नेता बौखलाहट में बजट का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र को दिखाते हुए कहा कि इसमें सिर्फ आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। अब वही कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा राजधानी के निर्माण के लिए विशेष सहायता दिए जाने का विरोध कर रही है। आंध्र प्रदेश की मौजूदा स्थिति के लिए पूरी तरह से कांग्रेस की पुरानी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि वहां की जनता कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। भाजपा प्रवक्ता ने साफ किया कि 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि सभी राज्यों के संतुलित विकास पर जोर दिया गया है।

चीन की सीमा से लगे गांवों के लिए 1050 करोड़ का बजट

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीन की सीमा से लगे सुदूर गांवों में समग्र विकास के लिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में 1,050 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। 'वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम' (वीवीपी) के तहत सीमावर्ती राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के 19 जिलों के चुनिंदा गांवों को विकास परियोजनाओं के लिए चुना गया है।

सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्कीम वीवीपी को विगत 15 फरवरी, 2023 को मंजूरी दी थी। वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच उत्तरी सीमा से लगे गांवों के 46 ब्लाकों के लिए 4,800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट में वर्ष 2024-25 के लिए 1050 रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य इन सीमावर्ती गांवों में जीवन की गुणवत्ता कायम रखना और आव्रजन होने देने के चयन में वहां से स्थानीय लोगों के विस्थापन को रोकना मकसद होता है। वीवीपी के तहत कृषि उत्पादों के विज्ञापन के तहत आय के स्रोत बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इन गांवों में कृषि, पर्यटन, हार्टीकल्चर और सांस्कृतिक विरासत आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। वीवीपी योजना के तहत ही 136 सीमावर्ती गांवों को 113 आल वेदर 113 सड़क परियोजनाओं से जोड़ा गया है, जिसकी लागत 2,420 करोड़ रुपये थी।

बोलीं सीतारमण- बिहार और आंध्र प्रदेश को दी गई अतिरिक्त सहायता को गलत ठहराना ठीक नहीं

बजट प्रविधान से पूरे देश का होता है विकास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से वित्तीय प्रविधान पर विपक्ष के आरोप के जवाब में वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि बजट प्रविधान से पूरे देश का विकास होता है और इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है। सूत्रों का कहना है कि बजट में पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) के मद में 11.11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है तो क्या यह राशि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश पर खर्च की जाएगी। यह राशि पूरे देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर खर्च होगी। अगर बिहार और आंध्र के विकास के लिए अलग से सहायता नहीं दी जाती तो यह कहा जाता कि इन्हें कुछ नहीं दिया। विपक्ष की तरफ से इस प्रकार की धारणा फैलाना कहीं से सही नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्रालय के सूत्रों पूछा कि क्या संप्रग शासनकाल में भी कई राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जाती थी? अभी यह कहा जा रहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा किसी राज्य को कुछ नहीं दिया गया है। यह आरोप भी गलत है। बजट में जो औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है, उससे देश के सभी राज्यों में नौकरियां निकलेंगी।

सूत्रों के मुताबिक किसी को विशेष राज्य का दर्जा देने की व्यवस्था संप्रग के शासनकाल में समाप्त की गई। रघुराम राजन कमेटी और वित्त आयोग की सिफारिश की वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। सूत्रों ने यह भी कहा कि किसी नई योजना की घोषणा और आवास योजना तथा आरोग्य योजना जैसी मौजूदा योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि से सभी राज्यों को लाभ होगा। यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से धन मांगें। बजटीय परामर्श के दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और हिमाचल के सीएम सुक्खू ने पीएम से मुलाकात कर अधिक धन की मांग की थी। सूत्रों का कहना है कि पीएम ने सीएम सुक्खू की बात सुनी और बाढ़ राहत के लिए धन आवंटित करने का फैसला किया।

संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को राज्यसभा में बोलती केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ● एएनआइ

कई बड़ी कंपनियों ने मांगी है चीन से प्रौद्योगिकी मंगाने की इजाजत

सूत्रों के मुताबिक कई बड़ी कंपनियों ने चीन से प्रौद्योगिकी मंगाने को लेकर इजाजत देने की मांग की है। अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। कुछ बड़ी कंपनियों का कहना है कि चीन से आयात की जगह हम उसकी प्रौद्योगिकी को साझा कर सकते हैं और इसके लिए चीन की कंपनियों को यहां बुलाया जा सकता है। लेकिन अभी इस पर चर्चा ही हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में चीन से आयात कम करने के लिए वहां से निवेश को इजाजत देने की सिफारिश की गई है।

चिदंबरम ने की अग्निपथ योजना, नीट समाप्त करने की मांग

जाब्यू, नई दिल्ली: राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अग्निपथ योजना और नीट समाप्त करने की मांग की। बजट में घोषित रोजगार प्रोत्साहन योजना के अमल पर संदेह जताया व कहा कि इसकी पूरी आशंका है कि इसका भी हाल हर साल दो करोड़ नौकरी देने वाले जुमले जैसा होगा। पूर्व वित्त मंत्री ने बजट की कई घोषणाओं को कांग्रेस के घोषणापत्र से नकल करने का आरोप लगाया।

बुजुर्गों से जुड़ी अटल वयो अभ्युदय योजना अब फिर पकड़ेगी रफ्तार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुजुर्गों से जुड़ी अटल वयो अभ्युदय योजना को फिर रफ्तार देने का फैसला लिया है। बजट में सरकार ने इसके लिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से 279 करोड़ का विशेष आवंटन किया है। यह राशि देश के वृद्धाश्रमों के अपग्रेडेशन के साथ उन्हें मेडिकल सुविधाओं से लैस करने और वयोश्री योजना के तहत बुजुर्गों को मुहैया कराए जाने उपकरणों पर खर्च होगी। इनमें बुजुर्गों को चश्मा, छड़ी, सुनने की मशीन, वाकर आदि मुहैया कराया जाता है।

बुजुर्गों के बीच लोकप्रिय इस योजना को पिछले सालों में इससे जुड़ी दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ दिया गया था। इसके चलते इस योजना पर उतना काम नहीं हो पाया, जैसी उम्मीद थी। वहीं, इस योजना की मांग राज्यों सहित संसद सदस्यों की ओर से बड़े पैमाने पर की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक मांग को देखते हुए सरकार ने इस पूरी योजना को फिर से अलग से शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए बजट में अलग से आवंटन किया गया है।

वैसे भी इसके लिए जो राशि मुहैया कराई गई है, उससे सरकार पर कोई बोझ भी आने वाला है क्योंकि बुजुर्गों के लिए यह राशि सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से दी गई है।

योजना इसलिए लोकप्रिय

इस स्कीम के लोकप्रिय होने की बड़ी वजह बुजुर्गों को वह उपकरण प्रदान करना है, जिसकी बुढ़ापे में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इनमें चश्मा, सुनने की मशीन, छड़ी, वाकर, व्हील चेयर, बत्तीसी (दांत), ट्राई पाइस जैसे उपकरणों के साथ गले और घुटने के कालर सहित कमर के दर्द को कम करने के लिए बेल्ट जैसे करीब दस और उपकरण शामिल है। खास बात यह है कि ये उपकरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी कंपनी एडसिल इंडिया खुद तैयार करती है।

बजट में यात्रियों की सुरक्षा पर रेलवे का सबसे ज्यादा जोर

अरविंद शर्मा ● जागरण

बेपटरी हो रही ट्रेनों की घटनाओं से रेलवे ने लिया सबक, सेफ्टी पर कुल बजट का 40 प्रतिशत से ज्यादा होगा खर्च

नई दिल्ली : हाल के कुछ दिनों में ट्रेनों के बेपटरी होने की घटनाओं में वृद्धि का सबक है कि रेलवे ने सुरक्षा पर फोकस बढ़ा दिया है। आम बजट में ट्रेनों के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा कुल बजट का लगभग 40 प्रतिशत से अधिक खर्च का प्रबंध किया गया है। दस हजार किलोमीटर रेल ट्रैक पर कवच लगाया जाना है। नए ट्रैक एवं डबल गेज पटरियों के निर्माण पर 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार, नई तकनीक, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने पर जोर दिया जाएगा।

आम बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रेलवे के पूंजीगत व्यय के लिए 2,62,200 करोड़ रुपये का रिकार्ड आवंटन किया गया है। पिछले वित्त वर्ष में सकल बजटीय सहायता 2,40,200 करोड़ रुपये थी। यानी इस बार यह 22 हजार करोड़ रुपये अधिक है। रेलवे को इतनी राशि पहली बार मिली है। 2013-14 के आम बजट में रेलवे को सिर्फ 28,174 करोड़ रुपये मिले थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि इस बजट के प्रविधानों से रेलवे को विश्वस्तरीय बनाने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा रेलवे के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना हुआ है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुल आवंटित बजट में से 1.08 लाख करोड़ रुपये सिर्फ सुरक्षा प्रबंधन पर खर्च किए जाएंगे। ज्यादा भीड़ वाले रूटों पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ट्रेनों को टकराने से बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक से कवच प्रणाली विकसित की गई है। दो दिन पहले ही कवच-4.0 को मंजूरी दी गई है। एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों के आने के बाद उनके ब्रेक को नियंत्रित करने और ड्राइवरों को सतर्क करने के लिए इंजन, सिग्नलिंग सिस्टम के साथ रेल पटरियों में इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाए जाते हैं। ट्रेनों को टक्कर से बचाने लिए अब तक 4,275 किलोमीटर रूट पर आप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं। दक्षिण मध्य रेलवे के 1,465 रूट किलोमीटर और 121 इंजनों में पहले ही कवच सिस्टम लगाया जा चुका है। आगरा डिवीजन ने मथुरा और पलवल के बीच 80 किलोमीटर ट्रैक पर कवच नेटवर्क लगाया है। आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में अभूतपूर्व तेजी आई है।

नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी इसी साल बनेगी

- इसके गठन के लिए सरकार ने किया 100 करोड़ का आवंटन
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों व उच्च संस्थानों में कोर्स होंगे शुरू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर इंतजार अब खत्म होगा। इस साल के अंत तक यह बन जाएगी। केंद्र सरकार ने बजट में इसके गठन के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया है। यह विश्वविद्यालय से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर व अध्ययन सामग्री आदि जुटाने पर खर्च होगा। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का एलान केंद्र सरकार ने 2022 में किया था। 2023-24 में सरकार ने अपने बजट में इसके गठन के लिए सिर्फ चार करोड़ रुपये का आवंटन किया था।

इस बीच, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन से जुड़ी तैयारियां लगभग पूरी हो गईं हैं। साथ ही इसका ढांचा भी तैयार कर लिया गया है। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित देश के सभी शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े कोर्स मुहैया कराए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसके संचालन के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का भी स्वरूप तैयार कर लिया गया है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन सचिव सहित उच्च शिक्षा सचिव, केंद्रीय और राज्य विवि के दो-दो कुलपति और दो अन्य शिक्षाविद् को रखने का प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि बजट में नए आवंटन के बाद अब इसके गठन में तेजी आएगी।

सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सों से शुरुआत, बाद में मिलेगी डिग्री: प्रस्तावित डिजिटल यूनिवर्सिटी का दायरा शुरुआत में देश तक ही रहेगा लेकिन बाद में दुनिया भर में विस्तार देने की तैयारी है। यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सों में छात्रों को बारहवीं के बाद ही दाखिला मिलेगा। इसकी शुरूआत वैसे सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्सों के होगी, लेकिन बाद में डिग्री कोर्स भी संचालित होंगे। वहीं, उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में छात्रों के पलायन को थामने में जुटी केंद्र सरकार ने देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने की मुहिम जारी रखी है। इसके लिए सरकार ने बजट में इस बार भी 18 सौ करोड़ रुपये की राशि आवंटित की। यह पिछले साल के बजट के मुकाबले पांच सौ करोड़ रुपये अधिक है। संस्थानों को यह मदद मिलने वाली नियमित मदद से अलग है।

संसद परिसर में सोनिया-जया बच्चन की भेंट...

नई दिल्ली में बुधवार को संसद भवन परिसर में बेहद प्रसन्नता से बातचीत करतीं कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी और समाजवादी पार्टी की पांच बार की सांसद जया बच्चन। बुधवार को आम बजट 2024 को भेदभावपूर्व बताते हुए इसके विरोध में इंडिया ब्लाक के सदस्यों के प्रदर्शन में शामिल होने जब सोनिया जा रही थीं, वहीं पर उनकी भेंट जया बच्चन से हो गई और फिर दोनों के बीच कुछ बातें हुईं जिस पर दोनों अपनी हंसी नहीं रोक सकीं ● प्रेट्र

आवंटन का बढ़ा ग्राफ, गंगा होंगी तेजी से साफ

- केंद्र सरकार का नमामि गंगे पर फोकस कायम, आवंटित राशि में 945 करोड़ रुपये की वृद्धि

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गंगा को साफ-सुथरा बनाने के लिए चलाए जा रहे नमामि गंगे मिशन के परिणाम पर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार इस साल योजना पर और अधिक खर्च करने जा रही है। बजट में इस अभियान के लिए आवंटित राशि में 945 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गई। मोदी सरकार की तीसरी पारी में जलशक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले सीआर पाटिल ने हाल ही में इस अभियान की समीक्षा की थी। उन्होंने इस मिशन के क्रियान्वयन में नए तौर-तरीके अपनाने पर जोर दिया था।

नमामि गंगे मिशन को पिछली बार 2,400 करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन इस बार यह आवंटन 3,345 करोड़ रुपये है। अब तक इस मिशन में 25 हजार करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की जा चुकी है। पानी के मामले में केंद्र सरकार ने बजट के जरिये दो और संदेश देने की कोशिश की है। अटल भूजल योजना के लिए बजट बढ़ाने के साथ पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए भी इस बार ज्यादा राशि दी गई है।

अटल भूजल योजना सात राज्यों में सामुदायिक सहयोग से भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए चार साल पहले लांच की गई थी और हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने इस योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय कार्य किया है। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार अटल भूजल योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। अटल भूजल योजना के लिए इस बार 1,778 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले साल यह राशि एक हजार करोड़ रुपये थी।

इसी तरह पीएम कृषि सिंचाई योजना को भी खेती में पानी के इस्तेमाल के तौर-तरीके सुधारने की दिशा में अहम योजना माना जा रहा है। इसी का नतीजा है कि इस योजना के लिए आवंटन में 2,308 करोड़ रुपये की बड़ी बढ़ोतरी की गई है। पीएम कृषि सिंचाई योजना को इस बार 9,339 करोड़ रुपये मिले हैं।

विकसित भारत का लक्ष्य साकार करेगा बजट : यूआइसीसी

- यूएसए इंडिया चैंबर आफ कामर्स ने कहा-यह बजट कौशल विकास करने के साथ बेरोजगारी को कम करेगा
- बजट अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक विकास पथ पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा

वाशिंगटन, प्रेट्र : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए भविष्य के मद्देनजर तैयार बजट को यूएसए इंडिया चैंबर आफ कामर्स (यूआइसीसी) ने सराहा है। उसने कहा है कि इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खर्च बढ़ाकर विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करना है। यह बजट कौशल विकास करने के साथ बेरोजगारी को कम करके अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक विकास पथ पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा।

यूआइसीसी के अध्यक्ष करुण ऋषि ने वित्त वर्ष 2025 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर जीडीपी के 4.9 प्रतिशत करने की सराहनीय पहल पर प्रकाश डाला जोकि अंतरिम बजट में 5.1 प्रतिशत था। उन्होंने सतत आर्थिक विकास और निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए राजकोषीय अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। बजट में रोजगार सृजन के माध्यम से विकास को गति देने के लिए एमएसएमई पर ध्यान दिया गया है। ऋषि ने कहा कि भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए एमएसएमई विकास के इंजन के रूप में काम कर सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में उनका योगदान बढ़ सकता है।

एंजेल टैक्स खत्म करना ऐतिहासिक सुधार: अमेरिका-भारत रणनीतिक एवं भागीदारी फोरम (यूएसआइएसपीएफ) ने कहा कि सभी निवेशक वर्गों पर एंजल टैक्स को समाप्त करना एक ऐतिहासिक सुधार है, जिससे भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा। फोरम ने इसके साथ ही केंद्रीय बजट में विदेशी कंपनियों के टैक्स कर की दर घटाकर 35 प्रतिशत करने के प्रस्ताव की सराहना की। यूएसआइएसपीएफ ने कहा कि यह महत्वपूर्ण सुधार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्रोतों से स्टार्टअप फंडिंग को बढ़ावा देगा।

आर्थिक चुनौतियों से निपटने की कवायद: एसआइसीसीआइ

सिंगापुर इंडियन चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (एसआइसीसीआइ) ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें कौशल विकास, उच्च शिक्षा, युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एसआइसीसीआइ के चेयरमैन नील पारेख ने कहा कि यह भारतीय नागरिकों को भविष्य की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण है। कहा कि एसआइसीसीआइ वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा घोषित प्रयासों की सराहना करता है। भारत को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के वास्ते युवा पीढ़ी को तैयार करने की दूरदर्शिता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की सराहना करता है।

कृषि बजट में वादे तो बहुत, पूरा करने को पैसे पर्याप्त नहीं

- नई घोषणाओं पर अमल के लिए बड़ी राशि की है जरूरत
- प्राकृतिक खेती की बात है, लेकिन इस मद में पैसे कम कर दिए गए

अमृतसर में धान की फसलों पर उर्वरक छिड़कते हुए एक किसान ● एएफपी/फाइल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी के अंतरिम बजट में किसान कल्याण के लिए कई वादे किए गए थे। हालांकि आम बजट में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। वित्त मंत्री ने अपने सातवें बजट में कृषि क्षेत्र को तो प्राथमिकता दी है, लेकिन कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए आवंटित 1.52 लाख करोड़ को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नई घोषणाओं पर अमल के लिए बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी। कृषि एवं पशुपालन से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चुप्पी भी अखरती है।

बजट में बताया गया है कि उत्पादन एवं उत्पादकता में तेज विकास के लिए शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से यह काम तो दशकों से किया जा रहा है। जलवायु के अनुकूल खेती के लिए भी लंबे समय से काम हो रहा है। आम बजट में कृषि शिक्षा एवं शोध के लिए 9941.09 रुपये का आवंटन दिखाया गया है, किंतु इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस काम के लिए लगभग इतनी ही राशि (9876 करोड़) पिछले बजट में भी थी। इसी तरह उत्पादकता बढ़ाने के लिए 32 फसलों की 109 नई किस्मों को विकसित करने का वादा किया गया है। किंतु यह काम भी एक-दो वर्षों में तो होने से रहा। प्राकृतिक खेती से दो करोड़ किसानों को जोड़ने की बात कही गई है, किंतु आश्चर्य यह कि इसके लिए सिर्फ 365 करोड़ रुपये का ही बजट रखा गया है, जो पिछले वर्ष से 94 करोड़ रुपये कम है। बिना जोत वाले किसानों को भी इस बार के बजट से किसान सम्मान निधि की तर्ज पर राहत की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे किसानों की संख्या भी अब करोड़ों में है।

जीडीपी में लगातार गिर रही कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी: बजट में कृषि क्षेत्र के आवंटन का हिस्सा भी निराश करने वाला है। कृषि में सुधार की पहल करते हुए मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट का 5.44 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था, जो अब घटकर 2024-25 के बजट में सिर्फ 3.15 प्रतिशत रह गया है। एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई थी कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार गिर रही है। इससे उम्मीद बंधी थी कि आम बजट में सरकार कृषि क्षेत्र की इस हिस्सेदारी को बढ़ाने का प्लान बताएगी, लेकिन यहां पर भी झटका लगा। पिछले वर्ष से मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम कराए जा रहे हैं।

****

पेरिस में एथलेटिक्स में **29 भारतीय खिलाड़ी** पेश करेंगे चुनौती, सभी की निगाहें गोल्डन ब्वाय चोपड़ा पर

नीरज एथलेटिक्स में पदक के बड़े दावेदार

नई दिल्ली, जेएनएन : तीन साल पहले टोक्यो में ओलिंपिक इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद अब भारतीय खिलाड़ी पेरिस में अपनी छाप छोड़ने को बेताब हैं। टोक्यो में भारत ने एक स्वर्ण सहित सात पदक जीते थे और यह स्वर्ण पदक दिलाया था स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने। नीरज का यह पदक ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला पदक था। इस बार भारत की ओर से 117 सदस्यीय दल पेरिस में शिरकत करेगा, जिसमें से 29 एथलीट ट्रैक एंड फील्ड में दम दिखाएंगे। इन 29 खिलाड़ियों में से एक बार फिर नीरज चोपड़ा ही पदक जीतने के सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं।

इस साल नीरज ने पावो नूरमी खेलों में स्वर्ण पदक जीता और फेडरेशन कप में शीर्ष स्थान हासिल किया। वह दोहा डायमंड लीग में भी दूसरे स्थान पर रहे और उम्मीद है कि वह ओलिंपिक में भी अपना चमकदार प्रदर्शन जारी रखेंगे और पदक जीतेंगे। नीरज के अलावा भाला फेंक में किशोर जेना, तजिंदर पाल तूर, अविनाश साबले, पारुल चौधरी व ज्योति याराजी जैसे एथलीट सबसे बड़े मंच पर असाधारण प्रदर्शन कर पोडियम पर स्थान सुनिश्चित करने का दम रखते हैं।

96 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए हैं एथलेटिक्स में खिलाड़ियों की तैयारी पर

5.72 करोड़ रुपये अकेले नीरज की तैयारियों पर खर्च किए गए

1 ही पदक जीत सका है भारत ट्रैक एंड फील्ड में अब तक ओलिंपिक इतिहास में

जब पदक के करीब आकर चूक गए थे मिल्खा सिंह

भारत ने 1920 के एंटवर्प खेलों में भारतीय ओलिंपिक संघ के तहत अपना पहला दल भेजा था, जिसमें चार खिलाड़ी थे। लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाया। इसके बाद 1924 में दलीप सिंह ने 6.635 की छलांग के साथ लंबी कूद के सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। 24 साल बाद गुरनाम सिंह ने पुरुषों की ऊंची कूद के फाइनल में जगह बनाकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया। 1960 में भारत को पहले पदक की आस थी, मिल्खा सिंह से, लेकिन ये महान धावक सेकेंड के दसवें हिस्से से कांस्य पदक से बाल-बाल चूक गए। उन्होंने 400 मीटर की स्पर्धा में 45.6 सेकेंड का समय निकाला, जबकि कांस्य पदक विजेता ने 45.5 सेकेंड का समय निकाला था। 1964 में गुरबचन सिंह रंधावा ने 110 मीटर बाधा दौड़ में प्रभावशाली प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने 10 एथलीटों में से पांचवें स्थान पर फाइनल पूरा किया। इसके बाद अंजू बाबी जार्ज ने किया, जिन्होंने एथेंस 2004 में लंबी कूद के फाइनल में 6.83 मीटर की छलांग लगाकर पांचवें स्थान पर रहीं।

मिल्खा सिंह, फाइल फोटो

इनसे होगी पदक की आस

नीरज चोपड़ा 26 वर्ष, हरियाणा (भाला फेंक)

उपलब्धियां
- टोक्यो ओलिंपिक: स्वर्ण
- विश्व चैंपियनशिप 2023 : स्वर्ण
- एशियाई खेल 2023 : स्वर्ण
- डायमंड लीग फाइनल्स : चैंपियन
- राष्ट्रमंडल खेल 2018 : स्वर्ण

अविनाश साबले 30 वर्ष, महाराष्ट्र

3000 मीटर स्टीपलचेज

उपलब्धियां
- एशियाई खेल 2022 : स्वर्ण (3000 मीटर स्टीपलचेज)
- एशियाई खेल 2022 : रजत (5000 मीटर)
- राष्ट्रमंडल खेल 2022 : रजत (3000 मीटर स्टीपलचेज)

अन्नू रानी (भाला फेंक) 32 वर्ष, मेरठ (यूपी)

उपलब्धियां
- एशियाई खेल 2022 : स्वर्ण
- एशियाई खेल 2014 : कांस्य
- राष्ट्रमंडल खेल 2022 : कांस्य पदक
- एशियाई चैंपियनशिप 2019 : रजत

ज्योति याराजी 25 वर्ष, आंध्र प्रदेश

100 मीटर बाधा दौड़

उपलब्धियां
- एशियाई खेल 2022: स्वर्ण
- एशियाई चैंपियनशिप 2023: स्वर्ण
- एशियाई चैंपियनशिप 2023 : रजत (200 मीटर)
- यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 : कांस्य

पारुल चौधरी 29 वर्ष, मेरठ (यूपी)

उपलब्धियां (3000 मीटर स्टीपलचेज)
- एशियाई खेल 2022: स्वर्ण (5000 मीटर)
- एशियाई खेल 2022: रजत (3000 मीटर स्टीपलचेज)
- एशियन चैंपियनशिप 2023: रजत पदक
- एशियन चैंपियनशिप 2019 : कांस्य पदक

तजिंदरपाल सिंह तूर 30 वर्ष, पंजाब (गोला फेंक)

उपलब्धियां
- एशियाई खेल 2022 : स्वर्ण
- एशियाई खेल 2018 : स्वर्ण
- एशियाई चैंपियनशिप 2023 : स्वर्ण
- एशियाई चैंपियनशिप 2019 : स्वर्ण

ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय दल

खिलाड़ी	स्पर्धा
नीरज चोपड़ा	भाला फेंक
किशोर जेना	भाला फेंक
सर्वेश कुशारे	ऊंची कूद
तजिंदरपाल सिंह तूर	गोला फेंक
अविनाश साबले	3000 मीटर स्टीपलचेज
पारुल चौधरी	3000 मीटर स्टीपलचेज
अक्षदीप सिंह	20 किमी रेसवाक
विकास सिंह	20 किमी रेसवाक
परमजीत बिष्ट	20 किमी रेसवाक
सूरज पंवार	20 किमी रेसवाक मिक्स्ड रिले
प्रियंका गोस्वामी	मिक्स्ड रेसवाक मैराथन
अजमल वरियाथोडी	4 गुणा 400 मीटर रिले
संतोष कुमार	4 गुणा 400 मीटर रिले
राजेश रमेश	4 गुणा 400 मीटर रिले
अमोज जैकब	4 गुणा 400 मीटर रिले
मुहम्मद अनस याहिया	4 गुणा 400 मीटर रिले
अब्दुल्ला अबूबकर	त्रिकूद
प्रवीण चित्रावेल	त्रिकूद
जेसविन एल्ड्रिन	लंबी कूद
अन्नू रानी	भाला फेंक
पहल किरण	400 मीटर- 4 गुणा 400 मीटर रिले
ज्योति याराजी	100 मीटर बाधा दौड़
अंकिता	5000 मीटर
ज्योतिका	महिलाओं की 4 गुणा 400 मीटर रिले
पूवम्मा राजू माचेत्तिरा	4 गुणा 400 मीटर रिले
सुभा वेंकटेशन	4 गुणा 400 मीटर रिले
विथ्या रामराज	4 गुणा 400 मीटर रिले
प्राची	रिजर्व एथलीट
मिजो चाको	रिजर्व एथलीट

फुटबाल, रग्बी के साथ ओलिंपिक शुरू

पेरिस, एपी: पेरिस में बुधवार को फुटबाल और रग्बी समेत कुछ खेलों के शुरुआती मुकाबले खेले जाने के साथ ही ओलिंपिक की आधिकारिक शुरुआत हो गई। हालांकि ओलिंपिक का उद्घाटन समारोह शुक्रवार को सीन नदी पर किया जाएगा। फुटबाल में शुक्रवार को स्पेन और अर्जेंटीना जैसी टीमों ने अपने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान फीफा के अध्यक्ष जियानी इंफेंटिनो भी उपस्थित रहे। स्पेन ने उज्बेकिस्तान को 2-0 से हराया, जबकि अर्जेंटीना और मोरक्को के बीच मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। इस दौरान मोरक्को का एक प्रशंसक मैदान में घुस आया। फुटबाल मुकाबलों को लेकर पेरिस में प्रशंसकों के बीच गजब का उत्साह देखा गया। लियोन मेसी के बिना खेल रही अर्जेंटीना टीम के प्रशंसक महान डिएगो माराडोना के पोस्टर लेकर पहुंचे थे। करीब 150 उज्बेकिस्तान प्रशंसक पोर्ट डीआइल सबवे स्टेशन के पास जमा हुए और झंडे लहराते, गाते और ढोल बजाते हुए स्टेडियम में दाखिल हुए।

उत्सव सा माहौल: ओलिंपिक खेलों को लेकर पार्क डेस प्रिंसेस की ओर जाने वाली सड़कों पर लोगों के बीच उत्सव जैसा माहौल है। इसी के पास फ्रेंच ओपन के घर रोलां गैरो में टेनिस की स्पर्धाएं खेली जाएंगी। दुनियाभर से खेल प्रशंसक पेरिस पहुंच चुके हैं। इस बार ओलिंपिक में सबसे ज्यादा 86 लाख टिकट बेचे गए हैं।

अर्जेंटीना के विरुद्ध गोल दागने के बाद मोरक्को के खिलाड़ी ● एपी

आज होगा तीरंदाजी का क्वालीफिकेशन राउंड

पेरिस ओलिंपिक में गुरुवार को तीरंदाजी का क्वालीफिकेशन राउंड खेला जाएगा। तीरंदाजी में भारत की ओर से दीपिका कुमारी, तरुणदीप राय और धीरज बोम्मादेवरा समेत छह खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय तीरंदाज इस बार पदकों का सूखा खत्म करने उतरेंगे।

बिना व्यवधान के होगा उद्घाटन समारोह

नई दिल्ली, जेएनएन : पेरिस में 2024 ओलिंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह शुक्रवार को होना है। इसमें 3,000 नर्तक, संगीतकार और अभिनेता सीन नदी के किनारे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह पहली बार किसी पारंपरिक स्टेडियम के बाहर आयोजित होने वाला ओलिंपिक का उद्घाटन समारोह होगा। कार्यक्रम से दो दिन पूर्व कलाकारों ने हड़ताल की धमकी दे दी थी। इससे समारोह का रंग फीका पड़ने की संभावना प्रबल हो गई थी। हालांकि, कलाकारों के संघ ने मांग पूरी होने पर हड़ताल की धमकी वापस ले ली है। इससे अब उद्घाटन समारोह का रास्ता साफ हो गया है।

फ्रांसीसी प्रदर्शनकारी कलाकारों के संघ ने इस सप्ताह हड़ताल की अधिसूचना जारी की थी। इसकी प्रस्तुति के लिए नियुक्त कलाकारों के बीच व्यवहार में स्पष्ट असमानताओं की ओर इशारा किया गया था। फ्रांसीसी कलाकारों के संघ ने कहा था कि मांग पूरी नहीं होने से वे नाराज थे। संघ के अनुसार, उसने समारोह के कार्यकारी निर्माता को समझौते के उल्लंघन के बारे में सूचित किया था और संदिग्ध प्रथाओं, उपचार में महत्वपूर्ण असमानताओं और कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के दौरान सामाजिक संवाद की कमी के बारे में भी चिंता जताई थी।

अमेरिका की महिला ध्वजवाहक होंगी कोको गफ

पेरिस, एपी : टेनिस स्टार कोको गफ शुक्रवार को होने वाले ओलिंपिक उद्घाटन समारोह में अमेरिकी टीम की महिला ध्वजवाहक होंगी। अमेरिका बास्केटबाल स्टार लेब्रोन जेम्स को पहले ही पुरुष ध्वजवाहक बनाने की घोषणा कर चुका है। गत अमेरिकी ओपन चैंपियन गफ पेरिस खेलों में अपने ओलिंपिक पदार्पण की तैयारी कर रही हैं। वह अमेरिका की ध्वजवाहक बनने वाली पहली टेनिस खिलाड़ी होंगी। टीम अमेरिकी एथलीट ने उन्हें और जेम्स को ध्वजवाहक के रूप में चुना है। 20 वर्ष की गफ ने टोक्यो ओलिंपिक में जगह बनाई थी, लेकिन कोविड-19 पाजिटिव पाए जाने के कारण वह हिस्सा नहीं ले पाई थीं।

एक नजर में

खेल मंत्री ने एनएसएस कैडेट्स से की बात

नई दिल्ली: केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को देशभर के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) कैडेट्स के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की। इसका उद्देश्य इन युवाओं को पहचानना और प्रेरित करना था जो सामुदायिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। (जेएनएन)

2030 शीतकालीन ओलिंपिक की मेजबानी करेगा फ्रांस

पेरिस: अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) ने बुधवार को 2030 में होने वाले शीतकालीन ओलिंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस को सौंपने का फैसला लिया, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। इन खेलों का आयोजन फ्रेंच आल्प्स में किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आइओसी को आश्वासन दिया कि ग्रीष्मकालीन ओलिंपिक खेल 2024 के संपन्न होने के बाद जो भी सरकार गठित होगी वह सभी शर्तों को पूरा करेगी। (एपी)

रोहित-विराट के नहीं होने का लाभ उठाए श्रीलंका : जयसूर्या

पल्लेकेले, प्रेट्र : श्रीलंका के अंतरिम मुख्य कोच सनथ जयसूर्या ने बुधवार को कहा कि भारत के विरुद्ध सीरीज में उनकी टीम को टी-20 सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों के टी-20 से संन्यास लेने के बाद उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाना चाहिए।

जयसूर्या ने बुधवार को कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। उनकी प्रतिभा और उन्होंने जिस तरह का क्रिकेट खेला है, उसे देखते हुए हम सभी जानते हैं कि वे और जडेजा किस स्थान पर हैं। उनकी गैरमौजूदगी भारतीय टीम के लिए नुकसान है और हमें इसका अधिकतम फायदा उठाना होगा।

जुबिन ने की मदद : जयसूर्या ने कहा कि टीम की तैयारियों में आइपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रायल्स के हाई परफार्मेंस निदेश जुबिन भरुचा ने सहायता की। श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों के एलपीएल से जुड़ा होने के बावजूद भरुचा के साथ छह दिन के शिविर का आयोजन किया गया।

सनथ जयसूर्या ● एएफपी

दुष्मंता चमीरा भारत के विरुद्ध नहीं खेलेंगे

पल्लेकेले : भारत के विरुद्ध सीरीज शुरू होने से पहले ही श्रीलंका के तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। चमीरा की जगह असिथा फर्नांडो को टीम में शामिल किया जा सकता है। फर्नांडो ने हाल ही में समाप्त हुई लंका प्रीमियर लीग के फाइनल में शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट चटकाए थे।

नीता अंबानी फिर चुनी गईं आइओसी सदस्य

पेरिस, प्रेट्र : रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को बुधवार को पेरिस में सर्वसम्मति से दोबारा भारत से अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) का सदस्य चुना गया। पेरिस में चल रहे आइओसी के 142वें सत्र के दौरान हुए मतदान में नीता को शत प्रतिशत मत मिले। नीता को पहली बार 2016 में रियो डि जिनेरियो ओलिंपिक खेलों के दौरान इस प्रतिष्ठित संस्था में शामिल किया गया था। वह आइओसी में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला हैं। नीता ने फिर से सदस्य चुने जाने पर कहा, मैं आइओसी के सदस्य के रूप में फिर से चुने जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। फिर से चुना जाना ना केवल एक व्यक्तिगत मील का पत्थर है बल्कि वैश्विक खेल क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव की मान्यता भी है। मैं हर भारतीय के साथ खुशी और गर्व के इस पल को साझा करती हूं।

नीता अंबानी

गंभीर आगे की सोचते हैं, जो उन्हें अलग बनाता है : उथप्पा

भारत के पूर्व क्रिकेटर रोबिन उथप्पा भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच गौतम गंभीर की अगुआई में खेल चुके हैं। श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में गंभीर का पहला दौरा है। उथप्पा ने कोच गंभीर को लेकर बताया कि वह हमेशा आगे की सोचते हैं, जो उन्हें अलग बनाता है। 27 जुलाई से शुरू हो रहे दौरे का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। सुकांत सौरभ ने रोबिन उथप्पा से विशेष बातचीत की, पेश हैं मुख्य अंश...

साक्षात्कार

● टी-20 में अलग कप्तान, वनडे में अलग और नए कोच के साथ श्रीलंका दौरे से भारतीय क्रिकेट के एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं?

-यह बहुत ही रोचक समय है। युवाओं के लिए यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। टीम में स्थान बनाने के लिए भी यह जरूरी है। युवाओं पर प्रदर्शन करने का दबाव होगा। हमेशा जब कोई नया कप्तान और नया कोच आता है तो खिलाड़ियों को पता होता है कि चीजें बदलेंगी। एक-दो दौरे के बाद यह पता चल जाएगा कि स्थायी टीम क्या होगी, इसलिए यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम गंभीर की बात करूं तो वह थोड़ा आगे की सोचते हैं। मैंने उनके नेतृत्व में खेला है तब भी वह एकाध ओवर आगे की सोचते थे। कोच के रूप में भी वह आगे की सोच को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे। यही उन्हें अलग बनाता है।

● सूर्यकुमार अब टी-20 के नए कप्तान हैं। काफी चर्चा के बावजूद हार्दिक को कप्तानी नहीं मिली। आपके अनुसार क्या इसका प्रभाव टीम पर पड़ेगा?

-टी-20 में टीम में सूर्यकुमार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह बहुत ही परिपक्व हैं। गौतम गंभीर के साथ उनका संबंध भी बहुत अच्छा रहा है। वह अपना दायित्व बखूबी निभाते हैं। मेरे अनुसार यह एक सकारात्मक पहल है। हार्दिक के कार्यभार प्रबंधन को ध्यान में रखकर भी यह पहल की गई है। मुझे नहीं लगता है कि उनका दायित्व कम होने वाला है, पर कप्तानी का अतिरिक्त दबाव प्रबंधन उन्हें नहीं देना चाहता है। तेज गेंदबाजी आलराउंडर भारत में बहुत कम रहे हैं और उनपर स्वयं बहुत दबाव होता है। हार्दिक के चोटिल होने की संभावना अधिक होती है, इसे भी ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है।

● गुरु गंभीर पर क्या भारतीय टीम का कोच होने का अतिरिक्त दबाव होगा? आप इसे कैसे देखते हैं?

- मुझे लगता है कि दर्शक के रूप में हमें अपनी गलतियों से सीखना भी चाहिए। हमारे खिलाड़ियों, कोच सब भी बहुत दबाव होता है। आप अगर ये टी-20 विश्व कप छोड़ दें तो हमने इससे पहले तक राहुल भाई (द्रविड़) के बारे में ज्यादा अच्छी बातें नहीं की है। मेरे हिसाब से हमें धैर्य रखना चाहिए। इस नई टीम, कोच और कप्तान सभी को स्थिरता प्राप्त करने का समय देना चाहिए क्योंकि जब भी नेतृत्व बदलता है यह मानव स्वभाव है कि संतुलित होने में समय लग जाता है। हम सर्वश्रेष्ठ की आशा करेंगे, परंतु उन्हें थोड़ा समय देना सबसे जरूरी है।

● श्रीलंका दौरे पर रुतुराज और अभिषेक के चयन नहीं होने को आप कैसे देखते हैं? क्या उनका टीम में स्थान बनाना मुश्किल है?

- जब भी नेतृत्व बदलता है आप सभी को खुश नहीं कर सकते हो। मुझे भरोसा है कि रुतुराज क्योंकि स्वयं कप्तान हैं इस बात को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह दौड़ से बाहर हैं। उन्होंने जिंबाब्वे में दिखाया है कि उनका क्लास क्या है। यह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छी समस्या है कि हमारे पास इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि कई अच्छे खिलाड़ी हमारे बैकअप में हैं। यही बात अभिषेक शर्मा पर भी लागू होती है। वह भी जल्द टीम का हिस्सा होंगे।

राष्ट्रीय जागरण

वाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेटा एआइ हिंदी में भी उपलब्ध

- कंपनी एक एडिट विद एआइ बटन के लांच की तैयारी में
- इसका उपयोग तस्वीरों को और बेहतर बनाने के लिए हो सकेगा

नई दिल्ली, आइएएनएस: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस असिस्टेंट मेटा एआइ अब सात नई भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें हिंदी, हिंदी रोमनीकृत लिपि के अलावा फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पुर्तगीज और स्पेनिश में भी उपलब्ध है। यह जानकारी मेटा ने बुधवार को दी है। यूजर्स वाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेटा एआइ का अब नई भाषाओं में उपयोग कर सकते हैं। कंपनी जल्द ही और नई भाषाओं को शामिल करने वाला है। साथ ही अगले महीने एक एडिट विद एआइ बटन लांच करने की तैयारी में है, जिसका उपयोग तस्वीरों को और बेहतर बनाने में किया जा सकेगा।

कंपनी प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने यूजर्स को अपने विचारों और कल्पनाओं को तस्वीरों में बदलने में मदद करना आसान बनाने के लिए नया क्रिएटिव टूल भी पेश किया है। इसके अलावा पहली बार इसे लैटिन अमेरिका के सात नए देशों में जोड़ा गया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि हम मेटा एआइ तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। आपकी सहायता के लिए नई सुविधाएं पेश कर रहे हैं। मेटा एआइ अब 22 देशों में उपलब्ध है। तकनीकी दिग्गज मेटा ने लामा 3.1 एआइ माडल का भी अनावरण किया। यह सबसे बड़ा व सबसे सक्षम ओपन सोर्स एआइ माडल है। कंपनी ने कहा, 'लामा की बेहतर तर्क क्षमता मेटा एआइ के लिए आपके जटिल सवालों, खासकर गणित व कोडिंग विषयों को समझना व जवाब देना संभव बनाती है।'

वहीं, आगामी इमेजिन मी फीचर यूजर्स को खुद को सुपरहीरो, राकस्टार या पेशेवर एथलीट के रूप में कल्पना करने में सहायता करेगा। यह अमेरिका में बीटा संस्करण में जारी किया जाएगा। एआइ में नई क्रिएटिव एडिटिंग फीचर की मदद से यूजर्स आसानी से आब्जेक्ट को जोड़ या हटा सकेंगे। उन्हें चेंज और एडिट कर सकेंगे। बाकी तस्वीर को वैसे ही रखते हुए यूजर्स नई चीजें इसमें समायोजित कर सकेंगे।

राजस्थान में एनकाउंटर केस में सात पुलिसकर्मियों पर चलेगा हत्या का केस

जासं, जयपुर: राजस्थान में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर करने वाले सात पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। जोधपुर के सीबीआइ मामलों के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इन अधिकारियों पर हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। जिन पर हत्या का केस चलेगा, उनमें चूरू के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विधा प्रकाश चौधरी, उप अधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौड़, हेड कांस्टेबल कैलाश, कांस्टेबल धर्मवीर सिंह, कांस्टेबल सोहन सिंह व अन्य हैं।

चूरू के मालासर गांव में गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर का यह मामला 24 जून 2017 का है। एनकाउंटर को लेकर वर्ष 2020 में सीबीआइ ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट को आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने चुनौती दी थी। राजकंवर के वकील ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने छल से आनंदपाल को निकट से एक के बाद एक गोली मारी थी, जिसकी पुष्टि चिकित्सकों ने भी की।

पर्यावरण प्रहरी बनकर सतत विकास को गति दे रहा सीमा पर बसा गांव

दरकते पहाड़ों की पारिस्थितिकी संरक्षित करने को उत्तरकाशी जिले के झाला गांव में युवाओं ने छेड़ा विशेष सफाई अभियान

जागरण विशेष
प्रथम गांव

शैलेंद्र गोदियाल ● जागरण

उत्तरकाशी: चीन सीमा के निकट वाइब्रेंट विलेज में शामिल उत्तरकाशी जिले का झाला गांव पर्यावरण प्रहरी बनकर सतत विकास को भी गति दे रहा है। दरकते पहाड़ों की पारिस्थितिकी संरक्षित करने के लिए यहां युवा प्रतिदिन दो घंटे स्वच्छता अभियान चलाते हैं। इसके तहत वह गांव के सभी 140 घरों और बाजार से कचरा एकत्र कर संग्रहण केंद्र पहुंचाते हैं। इस दौरान प्लास्टिक युक्त अजैविक कचरे पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विकास और सुविधाओं के साथ ग्रामीणों का दैनिक स्वच्छता मंत्र अन्य के लिए भी प्रेरणा बन रहा है।

भागीरथी नदी के किनारे स्थित झाला गांव जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 70 किमी दूर है। यह हर्षिल घाटी के प्रमुख गांवों में शामिल है। इससे गंगोत्री की दूरी 30 किमी है। गांव के निकट चारधाम यात्रा का यात्री पड़ाव भी है। इस गांव में हर तरफ साफ-सफाई नजर आती है। झाला बाजार से झाला गांव को जोड़ने वाला मार्ग ही नहीं, गांव का हर घर-आंगन और गलियां कूड़ा-कचरा मुक्त हैं। झाला, उत्तरकाशी जिले का पालीथिन मुक्त गांव बनने की श्रेणी में भी पहली पायदान पर है। यह सब संभव हो पाया गांव के युवक मंगल दल के अध्यक्ष अभिषेक रौतेला के प्रयासों से। उन्होंने गांव को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया तो उपाध्यक्ष अभिराज रौतेला, प्रियांशु रौतेला, अमित शाह, प्रवेश रौतेला व कोषाध्यक्ष सूरज रौतेला सहित 19 अन्य युवा भी उनके इस संकल्प से जुड़ गए और इस साझा पहल को नाम दिया गया 'धन्यवाद प्रकृति अभियान'। अभियान से गांव की प्रधान सुरजा देवी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तनुजा उनियाल भी जुड़ी हैं।

लोगों की बदल रहे आदत

बीती आठ जुलाई से लेकर अब तक ये युवा 22 बोरे प्लास्टिकयुक्त कूड़ा एकत्र कर चुके हैं। यही नहीं, झाला बाजार की हर दुकान, होटल और गांव में घर-घर जाकर ये युवा लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, ताकि कूड़े को इधर-उधर फेंकने के बजाय उसे अलग-अलग बैग में एकत्र करना सभी की आदत का हिस्सा बन जाए। इससे कूड़े को संग्रहण केंद्र तक पहुंचाने और उसकी छंटाई में भी आसानी रहेगी। अभियान में गांव के सभी लोग युवाओं का पूरा सहयोग करते हैं।

अभियान के दौरान कचरा इकट्ठा करते युवक मंगल दल के सदस्य ● जागरण

ग्रामीणों को प्लास्टिक कूड़ा अलग-अलग रखने के लिए प्रेरित कर रहे युवक मंगल दल के सदस्य ● जागरण

ग्रामीणों व व्यापारियों को प्लास्टिक युक्त कूड़े को तीन हिस्सों में जमा करने के लिए प्रेरित किया जा है। इसमें रैपर, प्लास्टिक बोतल और अन्य प्लास्टिक कचरा शामिल है।

अभिषेक, अध्यक्ष, युवक मंगल दल, झाला

युवक मंगल दल झाला की यह पहल सराहनीय है। इसी तरह की पहल अन्य गांवों में भी की जाएगी, ताकि गांव स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त हो सकें। ऐसे कार्य करने वाले ग्रामीणों व संगठनों को पूरा सहयोग किया जाएगा।

जय किशन, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी

इस तरह बढ़ रही आर्थिकी : महिला स्वयं सहायता समूह सोमेश्वर ग्राम संगठन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से पांच वर्षों से स्वरोजागर पर कार्य कर रहा है। इस से जुड़ी 25 से अधिक महिलाएं एप्पल जेम, एप्पल चटनी, एप्पल साइडर विनेगर, सीबथोर्न स्क्वाश भी तैयार कर रही हैं।

ये उत्पाद चारधाम यात्रा मार्ग पर बिक रहे हैं। इस समूह ने गांव की ओर से 2023 में पीएमओ में उप सचिव मंगेश घिल्डियाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सेब का जेम और चटनी भिजवाई थी। इन उत्पादों की सराहना में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से धन्यवाद पत्र भी आया था।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

भारत और ब्रिटेन मिलकर प्रौद्योगिकी सुरक्षा अभियान की करेंगे शुरुआत

- भारत दौरे पर आए ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी, पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से हुई वार्ता
- एफटीए पर जल्द समझौता करने पर बनी सहमति, प्रौद्योगिकी सुरक्षा अभियान शुरू करने का एलान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद भारत के साथ इसके रिश्तों को लेकर जो थोड़ी बहुत अनिश्चितता थी, वह खत्म हो गई। बुधवार को भारत के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लैमी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। लैमी-जयशंकर की अगुआई में हुई बैठक में ब्रिटेन-भारत प्रौद्योगिकी सुरक्षा अभियान (टीएसआइ) शुरू करने का एलान किया गया। इस तरह का समझौता भारत ने अमेरिका के साथ भी किया है जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग का दायरा बड़ा करता है। यह दोनों सरकारों, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालयों व रिसर्च संस्थानों को एक साथ मिलकर संचार, क्रिटिकल मिनिरल्स, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, एआइ जैसे नए क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग का मंच देगा। माना जा रहा है कि यह समझौता भारत में प्रौद्योगिकी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को रोजगार के नए अवसर भी देगा।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को दोनों देश काफी प्राथमिकता से ले रहे हैं। बुधवार की बैठक में यह सहमति बनी है कि भारत व ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय मिलकर ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे क्रिटिकल व इमर्जिंग टेक्नोलोजी में आपसी कारोबार करना आसान हो। इसके लिए लाइसेंस व नियमन संबंधी बाधाओं को दूर किया जाएगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर भी बात हुई है और इस पर जल्द ही समझौता करने की सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच इसको लेकर तीन वर्षों से गहन वार्ता चल रही है और पहले दिसंबर, 2023 तक इस पर समझौता करने का एलान भी किया गया था। लेबर पार्टी ने पहले तो इस समझौते के लेकर कुछ विरोध किया था, लेकिन अब वह इसका पूरा समर्थन कर रही है। लैमी और जयशंकर ने पूर्व में भारत-ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए वर्ष 2030 तक के लक्ष्यों की भी समीक्षा की।

लैमी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनके देश की पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने की इच्छा का स्वागत किया। कहा कि भारत, ब्रिटेन के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में रक्षा व सुरक्षा संबंधों को ब्रिटेन के साथ और प्रगाढ़ किया जाएगा। इस बैठक में माइग्रेशन व मोबिलिटी साझेदारी की भी समीक्षा की गई। सेमीकंडक्टर व एआइ निर्माण में खास तौर पर सहयोग का रोडमैप बनाने पर सहमति बनी है। साथ ही संचार के समूचे नेटवर्क को किस तरह ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए, इस पर एजेंसियों में सहयोग किया जाएगा। इनका चयन भी हो गया है।

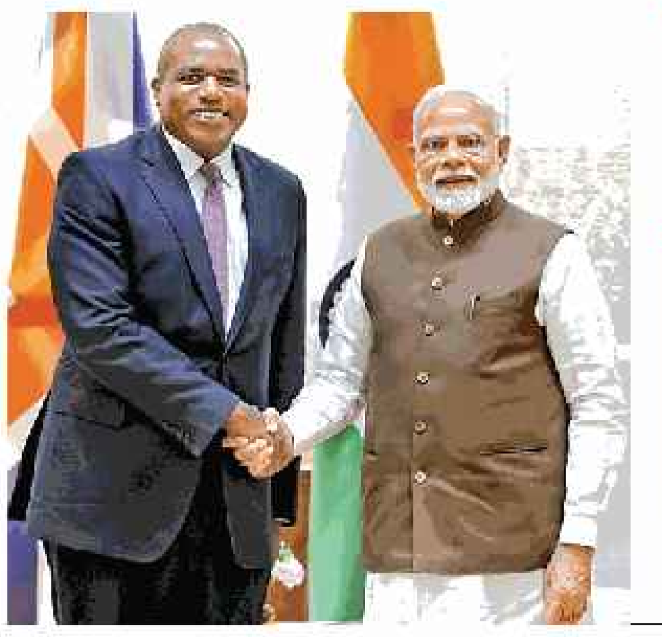

« ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की ● प्रेट्र

> ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से मिलकर खुशी हुई। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को व्यापक और गहरा बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर की प्राथमिकता की सराहना करता हूं। - **नरेन्द्र मोदी**, प्रधानमंत्री

प्रशिक्षु आइएएस अफसर पूजा नहीं पहुंचीं अकादमी, और बढ़ेंगी मुश्किलें

नियुक्ति फर्जीवाड़े में घिरी वर्ष 2023 बैच की प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी पूजा को एलबीएस अकादमी ने किया था तलब

जागरण संवाददाता, देहरादून: नियुक्ति फर्जीवाड़े में चौतरफा घिरी वर्ष 2023 बैच की प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी पूजा खेडकर को 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) मसूरी में रिपोर्ट करना था। अकादमी सूत्रों के मुताबिक पूजा अकादमी नहीं पहुंचीं हैं। ऐसे में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

पुणे में तैनाती के दौरान वरिष्ठ आइएएस अधिकारी के साथ विवाद और निजी आडी कार पर लाल-नीली बत्ती लगाने के बाद चर्चा में आईं प्रशिक्षु आइएएस पूजा खेडकर विवादों में घिरती चली गईं। अब उनकी नियुक्ति पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही उन पर संघ लोकसेवा आयोग ने एफआइआर दर्ज करा नोटिस भी जारी किया है। वहीं, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एलबीएसएनएए ने उनकी फील्ड ट्रेनिंग को रद कर 23 जुलाई तक अकादमी में रिपोर्ट करने को कहा था।

पहले बताया जा रहा था कि पूजा खेडकर मसूरी पहुंचकर अपनी बात रखेंगी। लेकिन, जब उन पर चौतरफा जांच का शिकंजा कसता चला गया तो वह गायब हो गईं। अकादमी सूत्रों के अनुसार, पूजा खेडकर ने रिपोर्ट नहीं किया है। लिहाजा, अकादमी निदेशक उन पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

एक नजर में

आदिवासी परिवार को मिला एक करोड़ का हीरा

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की कृष्णा कल्याणपुर पटी की उथली हीरा खदान से आदिवासी परिवार को जैम क्वालिटी का 19 कैरेट 22 सेंट का हीरा मिला है। हीरा एवं खनिज अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि पिछले सात महीनों में मिले हीरों में यह सबसे बड़ा है। बुधवार को जमा कराए गए हीरे की अनुमानित कीमत एक करोड़ रुपये है। जैम क्वालिटी का मतलब वह हीरा, जिसमें कोई छींटन या दाग न हो। हीरा मिलने से अत्यधिक प्रसन्न पन्ना के ही अहिरगुरवा निवासी चुनवादा आदिवासी ने बताया कि बुधवार दोपहर जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट स्थित हीरा कार्यालय में हीरा जमा करा दिया है। (नईदुनिया प्रतिनिधि)

जैम क्वालिटी का हीरा ● नईदुनिया

जरांगे ने मराठा आरक्षण मुद्दे पर अनशन किया स्थगित

जालना: मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण मुद्दे पर पांच दिन पहले शुरू किया गया अपना अनिश्चितकालीन अनशन बुधवार को यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि उनके समुदाय के सदस्यों का कहना है कि वे इस मुद्दे के लिए लड़ने के लिए उन्हें जीवित देखना चाहते हैं। उन्होंने जालना जिले में अपने पैतृक गांव अंतरवाली सरती में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। जरांगे ने अपनी मांगों को लेकर 20 जुलाई को अपना अनशन शुरू किया था। (प्रेट्र)

आंध्र सरकार के खिलाफ जगन का दिल्ली में धरना

नई दिल्ली: आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने आंध्र के तेलगु देशम पार्टी पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन में सपा नेता अखिलेश यादव व शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत भी शामिल हुए थे। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि राज्य में जो कुछ भी हो रहा है वह उचित नहीं है। उन्होंने कहा, 'सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश एक लाल किताब प्रदर्शित कर रहे हैं, जो पूरे राज्य में होर्डिंग के रूप में लगी है। इस किताब में उन अधिकारियों, राजनेताओं की एक सूची है, जिन पर वे कार्रवाई करना चाहते हैं। (एएनआइ)

'असम में बड़े भूभाग को अतिक्रमण मुक्त कराया'

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार की सक्रियता से बड़े पैमाने में अतिक्रमण की गई भूमि को मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में राज्य में कम से कम 167 वर्ग किलोमीटर भूमि पुन: प्राप्त की गई, जो चंडीगढ़ शहर के भूभाग से भी बड़ी है। मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट कर यह जानकारी दी है। (प्रेट्र)

लारेंस बिश्नोई गिरोह मुझे और मेरे परिवार को जान से मारना चाहता था: सलमान

मुंबई: बालीवुड अभिनेता सलमान खान ने पुलिस को बताया है कि लारेंस बिश्नोई गिरोह ने मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को जान से मारने के उद्देश्य से इस साल अप्रैल में मेरे आवास के बाहर गोलीबारी की थी। उनका यह बयान मुंबई पुलिस द्वारा अदालत में दायर आरोप पत्र का हिस्सा है। सलमान ने पुलिस को बताया है कि 14 अप्रैल की सुबह गैलेक्सी अपार्टमेंट में सोते समय मैंने पटाखे जैसी आवाज सुनी। सुरक्षाकर्मी ने सुबह 4.55 बजे बताया कि मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने पहली मंजिल की बालकनी पर गोलीबारी की है। पहले भी मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। (प्रेट्र)

एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाने का राहुल गांधी ने दिया भरोसा

दर्जनभर किसान नेताओं ने नेता विपक्ष से संसद भवन में मुलाकात कर की चर्चा

- नेता विपक्ष ने कहा आइएनडीआइए घटकों को साथ लेकर दिलाएंगे एमएसपी का हक
- पंजाब और हरियाणा के कांग्रेस सांसद भी बैठक में हुए शामिल किसानों ने सरकार से आस छोड़ी

« नई दिल्ली में बुधवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान नेताओं से मिलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ● प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : संसद में छात्रों का मुद्दा उठाने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को किसान नेताओं से चर्चा के दौरान एमएसपी की कानूनी गारंटी की किसानों की मांग को मुखर समर्थन देने का एलान कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के दर्जनभर नेताओं के साथ हुई अपनी बैठक में राहुल गांधी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी को किसानों का अधिकार बताते हुए आश्वासन दिया कि विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए इस मामले में किसानों के साथ है।

संसद भवन में नेता विपक्ष के कार्यालय में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक से आए 12 किसान नेताओं की राहुल गांधी के साथ बैठक हुई, जिस दौरान किसानों की तमाम समस्याओं समेत एमएसपी के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक के बाद किसान नेताओं के साथ राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया गया था। हमने इसका पूरा आकलन किया है और इसका कार्यान्वयन संभव है। नेता विपक्ष ने कहा कि इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आइएनडीआइए के सभी घटक दलों के नेताओं से चर्चा कर हम संयुक्त रूप से सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलना सुनिश्चित की जा सके। हरियाणा में किसानों के खिलाफ हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच का मुद्दा भी इन नेताओं ने उठाया और नेता विपक्ष ने संसद में इस मामले को उठाने का आश्वासन दिया। राहुल गांधी की किसान नेताओं के साथ बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पंजाब के कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, अमर सिंह के साथ हरियाणा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जय प्रकाश भी मौजूद थे। जबकि, बैठक में किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में जगजीत सिंह, लखविंदर सिंह, शांता कुमार, अभिमन्यु, एन वेंकटेश्वर राव, पांडियन रामलिंगम, तेजवीर सिंह, स्वर्ण सिंह पंधेर, सुरजीत सिंह, रमनदीप सिंह मान, गुरमनीत सिंह और अमरजीत सिंह शामिल थे। राहुल गांधी ने किसान नेताओं को संसद भवन में अपने कार्यालय में बैठक के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन, शुरुआत में किसानों नेताओं को संसद परिसर में प्रवेश से रोक दिया गया। जब राहुल स्वयं उनसे जाकर बाहर मिलने के लिए निकले तो फिर किसान नेताओं को नेता विपक्ष के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी गई।

वेणुगोपाल ने बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट में कहा कि सरकार द्वारा ठुकराए जाने, लाठियों से पीटे जाने और गोलियों से स्वागत किए जाने के कारण किसानों ने सरकार से सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं।

'परीक्षा प्रक्रिया को फ्राड बताने पर माफी मांगें राहुल'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: लोकसभा में बहस के दौरान नीट को फ्राड बताने पर भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि नीट का पेपर व्यवस्थित तरीके से लीक नहीं हुआ है। पटना और हजारीबाग में लीक हुआ पेपर कुल 155 प्रतिभागियों तक पहुंचा था, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और उन्हें आगे परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी गई है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पिछले एक महीने से देश की परीक्षा प्रक्रिया के खिलाफ अविश्वास फैलाने और देश की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, वह अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए सदन के अंदर और बाहर देश की परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देकर देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022, 2023 और 2024 के परीक्षा परिणामों की समीक्षा करने के बाद उनमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने नीट दोबारा कराने की जरूरत नहीं बताई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यहां तक कह दिया कि नीट की पवित्रता और ईमानदारी से कोई समझौता नहीं हुआ है।

रविशंकर प्रसाद ● फाइल फोटो

पांच वर्ष में आरक्षित वर्ग से 1,195 आइएएस, आइपीएस अफसर

जितेंद्र सिंह ● फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि आरक्षित व पिछड़े वर्गों से 1,195 अभ्यर्थियों को पिछले पांच वर्षों में आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।

केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखित जवाब में बताया कि इनमें से 233 अधिकारी 2018 में, 231 अधिकारी 2019 में, 223 अधिकारी 2020 में, 250 अधिकारी 2021 में और 258 अधिकारी 2022 में नियुक्त किए गए। उन्होंने बताया कि 2018 से अभी तक लैटरल एंट्री के जरिये विभिन्न क्षेत्रों के 63 विशेषज्ञों की नियुक्तियां की गईं हैं जिनमें से 35 नियुक्तियां निजी क्षेत्र से की गईं। वर्तमान में ऐसे 57 अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत हैं।

जनशिकायतों से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के जनशिकायत पार्टल के जरिये दाखिल केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित 1,200 शिकायतें लंबित हैं। आरक्षित श्रेणी की लंबित रिक्तियों के संबंध में बताया कि मंत्रालयों व विभागों से ऐसी रिक्तयों को चिह्नित करने के लिए इन-हाउस कमेटी बनाने और उन्हें विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरने के लिए कहा गया है। कहा कि आरक्षित श्रेणी की लंबित रिक्तियों समेत पदों का रिक्त होना और उन्हें भरना एक निरंतर प्रक्रिया है।

सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब तक 362 करोड़ दिए गए : शाह

संसद प्रश्नोत्तर

नई दिल्ली, प्रेट्र: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद को बताया कि इस साल 16 जुलाई तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.2 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 362.91 करोड़ रुपये दिए गए हैं। शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से इसे आसान बनाया गया है, जिसे 29 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जमाकर्ताओं को उनके धन को पुनः प्राप्त करने में सहायता करना था। आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से जांच के बाद जमाकर्ता को 10,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जांच कर और जमा राशि का प्रमाण प्रस्तुत करने पर धनराशि वापस की जा रही है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल है, जिसकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रेड्डी और एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल कर रहे हैं।

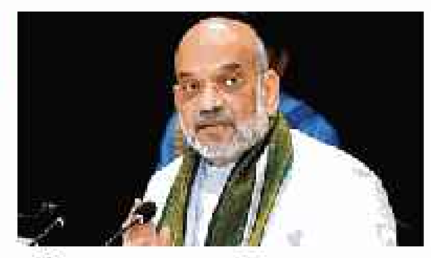

अमित शाह ● फाइल फोटो

गडकरी बोले, चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर जीएनएसएस-आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू होगी: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सभा में बताया कि सड़क मंत्रालय ने फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में पायलट आधार पर चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (जीएनएसएस)-आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। **उधर** गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्य सभा में बताया कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित करने का निर्णय लिया है। अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रविधान किया गया है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पांच वर्षों में मादक पदार्थों की तस्करी में डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल से संबंधित 92 मामले दर्ज किए हैं। **वहीं** एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए स्थापित 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' के माध्यम से 7.6 लाख से अधिक साइबर अपराध मामलों में 2,400 करोड़ से अधिक की बचत की गई है।

इस वर्ष 201 हज यात्रियों की हुई मौत : किरेन रिजिजू

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि इस साल हज के दौरान कुल 201 भारतीय हज यात्रियों की मौत हुई। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सजदा अहमद के प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ज्यादातर मौतें सांस संबंधी परेशानी के कारण हुई।

आपदा की सूची में शामिल नहीं होगा हीटवेव: 15वें वित्त आयोग ने लू (हीट वेव) को शामिल करने के लिए अधिसूचित आपदाओं की सूची का विस्तार करने के राज्यों के अनुरोध की जांच की थी, लेकिन इसमें कोई सार्थकता नहीं पाई गई। यह अपदा की सूची में शामिल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के एक सवाल का जवाब देते हुए लोस में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये बात कही।

ज्यादा कीमतें लेने पर व्यक्त की चिंता: कांग्रेस नेता हिबी ईडन ने राजमार्गों के किनारे स्थित दुकानों द्वारा गलत मूल्य निर्धारण पर चिंता जताई। सांसद ने उन रिपोर्टों के बारे में सरकार से सवाल किया, जिनमें आरोप लगाया गया है कि सीमित विकल्पों के कारण यात्री ज्यादा कीमतों का भुगतान करने पर मजबूर हैं।

राजद विधायक से नीतीश बोले- तुम महिला हो, कुछ नहीं जानती

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना : बिहार विधानसभा में बुधवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए। मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप लोग कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं।

सभी पार्टियों के साथ मेरी पहल पर जातिवार गणना करवाई गई थी। आप लोग बैठकर इस पर चर्चा करते, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सभी पार्टियों ने जातिवार गणना का सपोर्ट किया था।

मुख्यमंत्री नीतीश जब बोल रहे थे, उसी समय राजद की विधायक रेखा देवी ने टोका। मुख्यमंत्री ने उन्हें टोका, कहा- तुम महिला हो, तुम कुछ नहीं जानती हो। राजद के लोग पहले महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाते थे? 2005 के बाद हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। सदन की कार्यवाही के दौरान नीतीश ने विपक्षी विधायकों के हंगामे के बीच कहा कि जातिवार गणना में हमने सब जानकारी ली। जातिवार गणना के बाद 94 लाख गरीबों की पहचान की। उनके विकास के लिए सरकार ने दो- दो लाख रुपये देना शुरू कर दिया।

नीतीश कुमार ● फाइल फोटो

ममता की टिप्पणी पर बांग्लादेश नाराज, कहा-इससे भ्रम होगा

ढाका, प्रेट्र: बांग्लादेश ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत सरकार के सामने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पड़ोसी देश के संकट में फंसे लोगों को आश्रय देने की हालिया टिप्पणी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। कहा है कि उनकी टिप्पणी लोगों में "भ्रम" पैदा कर सकती है और उन्हें 'गुमराह" कर सकती है। हाल ही में कोलकाता में ममता बनर्जी ने कहा था कि वह पड़ोसी देश के संकट में फंसे लोगों के लिए बंगाल के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय देंगी। इस पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री की टिप्पणियों ने कुछ हद तक भ्रम उत्पन्न किया है। हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है।

जम्मू-कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग मानेगी जमात-ए-इस्लामी

नवीन नवाज ● जागरण

- प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जम्मू-कश्मीर) अपने संविधान में संशोधन की तैयारी में
- जमात के पूर्व प्रधान गुलाम कादिर वानी ने केंद्र सरकार के संपर्क में होने की बात मानी

जम्मू : कश्मीर में आतंकी हिंसा और अलगाववाद की जननी मानी जाने वाली जमात-ए-इस्लामी (जम्मू-कश्मीर) के नेताओं में अब मुख्य धारा में लौटने की छटपटाहट दिख रही है। यही वजह है कि वह अपने संविधान में संशोधन करने की तैयारी में है। जमात जम्मू-कश्मीर को विवादित क्षेत्र और भारत-पाकिस्तान के बीच एक अनसुलझा मुद्दा बताती रही है। लेकिन, अब वह जम्मू-कश्मीर को भारत के अविभाज्य अंग के रूप में परिभाषित करने पर विचार कर रही है। उसके नेताओं को उम्मीद है कि ऐसा करने पर केंद्र सरकार उस पर लगी पाबंदी हटा सकती है और करीब 37 वर्ष बाद उसके विधानसभा चुनाव में शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार और जमात के प्रतिनिधियों के बीच इसको लकर पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। जमात अध्यक्ष डा. फैयाज हमीद व उसके कई वरिष्ठ साथियों की रिहाई को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जमात के पूर्व अध्यक्ष गुलाम कादिर वानी ने स्वीकारा है कि वे लोग केंद्र के संपर्क में हैं।

जमात-ए-इस्लामी (जम्मू-कश्मीर) 1987 तक विधानसभा और संसदीय चुनावों में हिस्सा लेती रही, लेकिन बाद में चुनाव बहिष्कार के राह पर बढ़ गई। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाते हुए जमात को गैर कानूनी घोषित किया था। इसके बाद इसके अधिकांश नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि जमात ने प्रतिबंध को हटवाने के लिए अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं की एक शूरा (समिति) बनाई है, जिसकी कमान जमात के पूर्व प्रधान गुलाम कादिर वानी ने संभाल रखी है। यह समिति देख रही है कि उसे कश्मीर में गतिविधियों को फिर शुरू करने का अवसर कैसे मिले। समिति कथित तौर पर प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ संपर्क में है। डा. फैयाज हमीद समेत जमात के चार प्रमुख नेता बीते एक पखवाड़े के दौरान ही रिहा हुए हैं। डा. फैयाज ने गत सोमवार को समिति की बैठक के बाद एक वीडियो संदेश में कहा कि वह समिति के सभी निर्णयों के साथ होंगे। जमात के पूर्व महासचिव फहीम रमजान ने कहा कि प्रतिबंध को हटवाने के लिए समिति चाहे तो जमात के संविधान में आवश्यक बदलाव कर सकती है।

नहीं मिलनी चाहिए जमात को छूट: डा. अजय च्रंगू

कश्मीर मामलों के जानकार डा. अजय च्रंगू ने कहा कि जमात पर प्रतिबंध हटाना अत्यंत घातक होगा। जमात के नेता गुलाम कादिर वानी ने ही मई में कहा था कि जमात का मकसद है कि लोकतांत्रिक तरीके से शरिया लागू करना। कश्मीर में जिहाद की जननी जमात है। इसके पूरे तंत्र को नष्ट किया जाना जरूरी है।

राशन के लिए सुहागिन, पेंशन के लिए विधवा

पवन मिश्र ● जागरण

- गोंडा जिले में 4,487 महिलाएं निराश्रित पेंशन के साथ पति के नाम का राशन भी ले रहीं
- शासन ने जिला पूर्ति अधिकारी को भेजी अपात्रों की सूची, तीन वर्ष में 16 करोड़ पेंशन में दिए गए

गोंडा: लालच जो न कराए... वे सुहागिन भी हैं और विधवा भी। कागज इसकी पुष्टि कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का उदाहरण है, जहां राशन कार्ड में घर की मुखिया के रूप में दर्ज 4,487 महिलाएं, विधवा बनकर निराश्रित महिला पेंशन लेने के साथ ही राशनकार्ड में सुहागिन बनकर पति के हिस्से का राशन भी ले रही हैं। राशनकार्ड में आधार जुड़ने के बाद यह सच सामने आया कि हजारों महिलाएं दोनों विभागों की लाभार्थी हैं। खाद्य रसद विभाग ने महिला कल्याण विभाग से सूची मंगाई तो पता चला कि 4,487 महिलाएं, महिला कल्याण विभाग से पेंशन लेने के बावजूद राशनकार्ड में दर्ज पति के हिस्से का राशन भी उठा रही हैं।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक यह गड़बड़ी लगभग तीन वर्ष से चल रही है। एक महिला को एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। इस तरह आकलन करें तो सोलह करोड़ रुपये से अधिक की राशि तीन वर्ष में इनको पेंशन के रूप में दी गई है। इसके अलावा एक यूनिट पर पांच किलो अधिक राशन का लाभ भी महिलाओं ने उठाया। एक विभागीय अधिकारी ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि यह तो महज एक जिले का आंकड़ा है, शासन ने इसकी जांच पूरे उत्तर प्रदेश में कराई है। इस जांच से गरीब कल्याण योजना में बड़े पैमाने की धांधली की आशंका बढ़ती जा रही है।

इससे पहले हुई जांच में सामने आया था कि जिले में नौ हजार आयकरदाता और सक्षम लोग राशनकार्ड बनवाकर कोटे का मुफ्त अनाज डकारते रहे, जबकि जरूरतमंद वंचित रह गए। इस मुफ्त राशन का लाभ लेने में 9,313 बड़े किसान भी शामिल हैं, जिन्होंने खेत का अनाज सरकार को समर्थन मूल्य पर बेचा।

> शासन से निराश्रित महिला पेंशन लाभार्थियों की सूची मिली है, जो राशन कार्ड के जरिये मृत पति के हिस्से का भी अनाज कोटे से ले रही थीं। सत्यापन करने के बाद जो महिला जिस योजना की पात्र होगी, उसका पालन करवाया जाएगा। - **कृष्ण गोपाल पांडेय**, जिला पूर्ति अधिकारी

चाय पीकर विजयवर्गीय ने कांग्रेस में मचाई खलबली

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और मप्र सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक और कदम से प्रदेश कांग्रेस में खलबली मच गई है। दरअसल, गत 12 जुलाई को विजयवर्गीय इंदौर में गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों को प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित वृहद पौधारोपण कार्यक्रम का निमंत्रण देने गए थे। वहां उनका स्वागत करने के साथ उन्हें गुलाब जामुन परोसते हुए चाय-नाश्ता कराकर कांग्रेस के जिला और शहर अध्यक्ष मुसीबत ले बैठे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने नोटिस देकर पूछा है कि जिन भाजपा नेता ने हमारा उम्मीदवार तोड़ लिया, उन्हें पार्टी कार्यालय में बुलाकर उनका इस तरह स्वागत-सत्कार क्यों किया गया?

फतेहपुर सीकरी में भगवान विष्णु की नौवीं शताब्दी की मूर्ति मिली

जागरण संवाददाता, आगरा: आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी के गांव सांथा में भगवान विष्णु की नौवीं शताब्दी की मूर्ति मिली है। श्मशान घाट में की जा रही खोदाई में भगवान विष्णु की गरुड़ पर बैठी हुई मूर्ति के साथ कुबेर और अन्य प्रतिमाएं भी निकली हैं। ग्रामीणों ने उन्हें खुले में चबूतरे पर रख दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) इन प्रतिमाओं को पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मान रहा है। एएसआइ की टीम सांथा पहुंचकर प्रतिमाओं की जांच करेगी।

श्मशान घाट के टीले को समतल करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा खोदाई कराई जा रही है। खड़ी मुद्रा में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति करीब चार फीट ऊंची है। एएसआइ के अधीक्षण डा. राजकुमार पटेल का कहना है कि गांव में शीघ्र ही टीम भेजी जाएगी।

फतेहपुर सीकरी में मिली भगवान विष्णु की नौवीं शताब्दी की मूर्ति ● इंटरनेट मीडिया

****

अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली दुनिया की पहली महिला बनीं स्वेतलाना

1984 में आज ही सोवियत अंतरिक्ष यात्री स्वेतलाना सवित्स्काया अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला बनी थीं। स्वेतलाना सोयुज टी-12 मिशन का हिस्सा थीं। उन्होंने साल्युत-7 अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर तीन घंटे बिताए थे। वह दो बार अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भी हैं।

विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुई जाय ब्राउन का जन्म हुआ

1978 में आज ही ब्रिटेन की लुई जाय ब्राउन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आइवीएफ) के जरिये जन्म लेने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बनी थीं। इस तकनीक की खोज डा. पैट्रिक स्टेप्टो और राबर्ट एडवर्ड्स ने की थी। आइवीएफ से अबतक 60 लाख से अधिक बच्चों का जन्म हो चुका है।

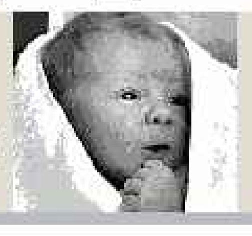

जिम कार्बेट के प्रयासों से मिला था भारत को पहला नेशनल पार्क

प्रकृतिवादी एडवर्ड जेम्स कार्बेट (जिम कार्बेट) का जन्म 1875 में आज ही नैनीताल में हुआ था। बचपन से ही वन्य जीवन से काफी आकर्षित थे। पेशेवर शिकारी के रूप में शुरुआत में कई आदमखोर बाघों का शिकार किया। बाद में बाघों के संरक्षण में जुट गए। उन्हीं के प्रयासों से 1936 में भारत के पहले नेशनल पार्क (जिम कार्बेट नेशनल पार्क) की स्थापना हुई थी। वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मैन इटर्स आफ कुमाऊं सहित कई किताबें लिखीं। 19 अप्रैल, 1955 को उनका निधन हो गया।

इधर-उधर की

आनलाइन आर्डर किया एयर फ्रायर, मिली छिपकली

सोफिया ने एमेजोन से आर्डर किया था एयर फ्रायर ● इंटरनेट मीडिया

बोगोटा, एजेंसी: आनलाइन शापिंग करने के दौरान गलत आर्डर मिलने या बाक्स में सामान की जगह ईंट-पत्थर मिलने के आपने कई मामले सुने होंगे। हालांकि कोलंबिया की सोफिया को आनलाइन आर्डर में ऐसी चीज मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना न्हीं की होगी। सोफिया ने एमेजोन से एयर फ्रायर आर्डर किया था। जब पार्सल आया तो उसके अंदर जो था, उसे देखकर वह बुरी तरह घबरा गईं। दरअसल पार्सल के अंदर एयर फ्रायर के बजाय एक बड़ी छिपकली थी। सोफिया ने पैकेज की एक तस्वीर एक्स पर पोस्ट की है जो अब तेजी से प्रसारित हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार एमेजोन ने अभी तक सोफिया को कोई समाधान नहीं दिया है। छिपकली की पहचान स्पैनिश राक लिजर्ड के रूप में की गई है।

काठमांडू में उड़ान भरते ही विमान दुर्घटनाग्रस्त

18 लोगों की मौत, पायलट गंभीर रूप से घायल, पोखरा के लिए जा रहा था विमान

काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त विमान में जीवित बचे घायल पायलट को इलाज के लिए ले जाते हुए जवान ● प्रेट्र

- विमान में चालक दल के दो सदस्य समेत 19 लोग थे सवार, ज्यादतर एयरलाइन के तकनीकी कर्मी थे
- सौर्य एयरलाइंस के इस विमान का निर्माण कनाडाई कंपनी बंबार्डियर ने अप्रैल 2003 में किया था

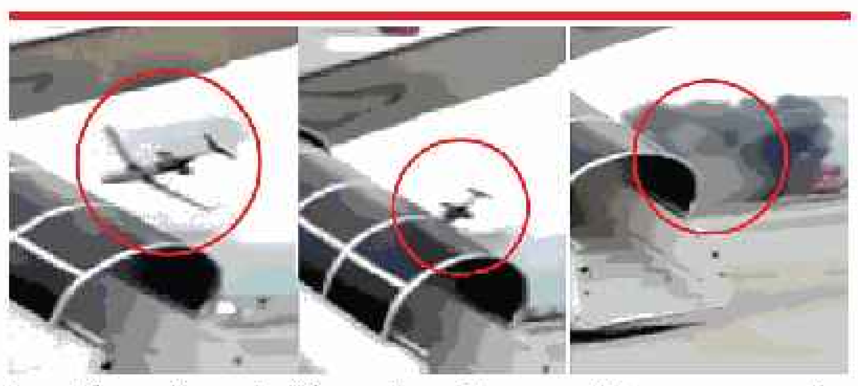

नेपाल की राजधानी काठमांडू में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाइअड्डे से उड़ान भर रहा हवाई जहाज (लाल घेरे में)। जो अगले कुछ पलों में ही दुर्घटना का शिकार हो गया और तत्पश्चात उसमें आग लग गई ● वीडियोग्रैब

काठमांडू, प्रेट्र: नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार को एक निजी कंपनी का विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक बच्चे समेत 18 लोगों की मौत गई है। विमान का पायलट गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विमान में चालक दल के दो सदस्य समेत 19 लोग सवार थे। इनमें अधिकांश एयरलाइन के तकनीकी कर्मचारी थे।

हिमालयन टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, विमान त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (टीआइए) से बुधवार सुबह 11:11 बजे पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था। लेकिन कुछ ही देर में रनवे पर फिसल जाने के बाद वह गड्ढे में गिर गया और उसमें आग लग गई। घटनास्थल से सामने आए फुटेज में घने धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है।

विमान में आग लगने के बाद पुलिसकर्मी और अग्निशमन दल के कर्मचारी बचाव कार्य में लग गए और थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया। सौर्य एयरलांइस का 50 सीट वाला घरेलू विमान सेवा का 9एन-एएमई (बंबार्डियर सीआरजे200) विमान नियमित मरम्मत सेवा के लिए पोखरा जा रहा था। विमान का निर्माण कनाडाई कंपनी बंबार्डियर ने अप्रैल 2003 में किया था।

टीआइए के प्रवक्ता सुबास झा ने बताया कि 15 लोगों की तुरंत मौत हो गई थी, जबकि तीन लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतकों में एयरलाइन के एक कर्मचारी की पत्नी और चार वर्ष का बेटा शामिल हैं। विमान के पायलट 37 वर्षीय कैप्टन मनीष रत्न शाक्य की हालत गंभीर है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

हवाईअड्डे के अधिकारियों ने बताया कि टीआइए से एहतियातन विमानों का संचालन रोक दिया गया है। इसके चलते दर्जनों अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर असर पड़ा है। मालूम हो कि हवाई सुरक्षा को लेकर नेपाल का खराब रिकार्ड रहा है। इसके चलते यहां 2000 से अब तक विमान दुर्घटनाओं में 350 लोग मारे जा चुके हैं। पिछले वर्ष जनवरी में यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें 72 लोग मारे गए थे।

यूएस की नागरिकों को सलाह, मणिपुर व जम्मू-कश्मीर की न करें यात्रा

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका ने अपने नागरिकों से मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, भारत-पाकिस्तान सीमा और देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों की यात्रा न करने की सलाह दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के लिए संशोधित यात्रा सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि अपराध और आतंकवाद के कारण भारत में सावधानी बढ़ा दी गई है। कुछ क्षेत्रों में जोखिम बढ़ गया है। कुल मिलाकर भारत को लेवल-2 पर रखा गया है। लेकिन देश के कई हिस्सों को लेवल-4 पर रखा गया है। इनमें जम्मू-कश्मीर, भारत-पाक सीमा, मणिपुर और मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं। कहा है कि सशस्त्र संघर्ष की संभावना के कारण भारत-पाक सीमा के 10 किमी के क्षेत्र की यात्रा न करें।

खालिस्तानियों ने कनाडा का माहौल दूषित किया : सांसद आर्य

पन्नू को सांसद आर्य का जवाब, कनाडा ही हमारा देश, खालिस्तानी आतंकी ने की है कनाडाई-हिंदुओं से भारत वापस जाने की मांग

ओटावा, प्रेट्र: कनाडा के भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने बुधवार को कहा कि देश के माहौल को खालिस्तानी चरमपंथियों ने दूषित कर दिया है, जो अधिकारों के चार्टर के तहत दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। कनाडा में बढ़ते हिंदूफोबिया के बीच अल्बर्टा राज्य के एडमंटन में सोमवार सुबह स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और भारत विरोधी नारे लिखे गए। चंद्र आर्य ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर मांग की है कि आर्य और उनके हिंदू-कनाडाई दोस्त भारत वापस चले जाएं, क्योंकि उन्होंने (आर्य ने) कनाडा में खालिस्तान समर्थकों द्वारा हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ व हिंसा की निंदा की थी।

एएनआइ के अनुसार, आर्य ने कहा कि कनाडाई हिंदू कहीं नहीं जाने वाले। कनाडा ही हमारा देश है। कनाडा में हिंदू केवल भारत से ही नहीं अन्य भागों से भी आकर बसे हैं। इनमें दक्षिण एशिया के सभी देश, अफ्रीका व कैरिबियाई देश शामिल हैं। अब कनाडा हमारा देश है। हम इसे मजबूत करना जारी रखेंगे। कहा, हमने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कनाडाई-हिंदुओं का हिंदू संस्कृति और विरासत का लंबा इतिहास रहा है।

कुपवाड़ा में भीषण मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, एक जवान बलिदान

राज्य ब्यूरो, जागरण ● श्रीनगर : उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में भीषण मुठभेड़ में बुधवार को एक आतंकी मारा गया और एक जवान भी वीरगति को प्राप्त हुआ। सेना की घेराबंदी में तीन से चार पाकिस्तानी आतंकियों के फंसे होने की सूचना है। उनको मार गिराने का अभियान जारी है।

सैन्य अधिकारियों ने बताया कि एलओसी से सटी लोलाब घाटी से आतंकियों के एक दल के कश्मीर के भीतरी इलाकों की तरफ जाने की सूचना मिलने पर अभियान चलाया गया था। मंगलवार शाम त्रिमुखा की पहाड़ियों में तलाशी ले रहे जवानों ने स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों के एक दल को जंगल से गुजरते देखा। जवानों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन आतंकी भागने लगे। भागते वक्त वे पीछा कर रहे जवानों को रोकने के लिए गोलीबारी भी करते रहे। जवानों ने जवाबी फायर किया और इसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान तड़के एक आतंकी मारा गया और एक जवान दिलावर खान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जो कि उपचार के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ।

पठानकोट में सात संदिग्ध देखे जाने के बाद एक का स्केच जारी

जासं, पठानकोट : पठानकोट जिले के फंगतोली में मंगलवार रात दिखे संदिग्ध लोगों में से किसी का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने उनमें से एक का स्केच बनाया है। डीएसपी सिटी सुमेर सिंह मान ने बताया कि पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला। लोगों के बताए हुलिया के आधार पर एक व्यक्ति का स्केच जारी किया गया है।

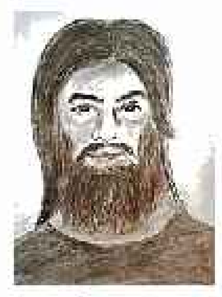

एक संदिग्ध का पुलिस द्वारा जारी स्केच ● सौ. पुलिस

इथियोपिया में भूस्खलन की चपेट में आकर 229 की मौत

अदीस अबाबा, एपी: इथियोपिया के एक दूरदराज हिस्से केनचो शाचा गोजदी जिले में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की चपेट में आकर 229 लोगों की मौत हो गई। बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री अबी अहमद ने इसे भयानक क्षति बताया है। स्थानीय प्रशासक दग्मावी अयेले ने कहा कि पांच लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है।

सोमवार देर रात हुए हादसे में पहले मरने वालों की संख्या 55 बताई जा रही थी। प्रधानमंत्री अबी अहमद ने कहा है कि खोज और बचाव प्रयासों में सहायता के लिए संघीय आपदा निवारण कार्य बल को तैनात किया गया है। गोफा जोन में आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी के निदेशक मार्कोस मेलेसे ने कहा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो मां, पिता, भाई और बहन सहित पूरे परिवार को खो चुके हैं।

पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में अक्सर घातक भूस्खलन होते हैं। अप्रैल में केन्या के रिफ्ट वैली क्षेत्र में 45 लोग मारे गए, जब अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से घर बह गए थे।

कमला के राष्ट्रपति बनने से बने रहेंगे भारत से गतिशील संबंध

- द्विपक्षीय संबंधों के पैरोकार समूह ने कहा, सब कुछ अच्छा रहेगा
- डेमोक्रेटिक पार्टी को दो दिनों में मिला 10 करोड़ डालर का चंदा

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका में उप राष्ट्रपति कमला हैरिस के चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनने से भारत के साथ अमेरिकी संबंधों में कोई अंतर नहीं आएगा। हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाएंगी जिन पर राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडन चल रहे हैं। यह बात भारत व यूएस व्यापार को बढ़ावा देने की पैरवी करने वाले समूह ने कही है।

यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के प्रमुख मुकेश अघि ने कहा, उन्हें नहीं लगता है कि हैरिस के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका की नीतियों में कोई बदलाव आएगा। खासतौर से भारत को लेकर कुछ भी नहीं बदलेगा।

50 घंटों से भी कम समय में डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनाव प्रचार निधि में 10 करोड़ डालर से ज्यादा की धनराशि एकत्रित हो जाने से साबित होता है कि नाम प्रस्तावित होने के तीन दिनों में कमला का समर्थन लगातार बढ़ा है।

केनेडी हत्याकांड पढ़कर थामस ने ट्रंप पर किया हमला

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका में 13 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के इरादे से फायरिंग करने वाला थामस क्रुक्स पूरी तैयारी से आया था। उसने छह जुलाई को करीब 61 वर्ष तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जान एफ केनेडी की हत्या से संबंधित जानकारियों को गूगल पर पढ़ा था। यह बात थामस के लैपटाप की पड़ताल में सामने आई है। मामले की जांच कर रही एजेंसी एफबीआइ के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने संसद की न्यायिक मामलों की समिति को यह जानकारी दी है। पेनसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में जनसभा के दौरान ट्रंप पर सामने की छत से थामस ने आठ गोलियां चलाई थीं। इनमें से एक गोली ट्रंप का कान चीरते हुए निकल गई थी जबकि अन्य गोलियों से एक ट्रंप समर्थक की मौत हो गई थी और दो घायल हो गए थे। निदेशक रे ने बताया कि थामस ने हमले के लिए एआर-15 असाल्ट राइफल का प्रयोग किया था जिसमें कोलेप्सिबिल स्टाक लगाकर हथियार का आकार छोटा किया था ताकि वह आसानी से सभास्थल के नजदीक पहुंचा सके।

फलस्तीनी राष्ट्रपति से बोले ट्रंप, चिंता न करें सब अच्छा होगा

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से शुक्रवार को होने वाली मुलाकात से पहले मंगलवार को फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कहा कि चिंता न करें सबकुछ अच्छा होगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसके साथ ही 13 जुलाई को उन पर हुए जानलेवा हमले के एक दिन बाद लिखे अब्बास के पत्र का स्क्रीनशाट भी अटैच किया है, जिसमें उन्होंने हमले को लेकर चिंता जाहिर की थी। ट्रंप ने लिखा कि महमूद चिंता की बात नहीं सबकुछ अच्छा होगा। मालूम हो कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ट्रंप अपने आवास फ्लोरिडा के पाम बीच के मार-ए-लागो में शुक्रवार को पश्चिम एशिया में शांति को लेकर पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करने वाले हैं।

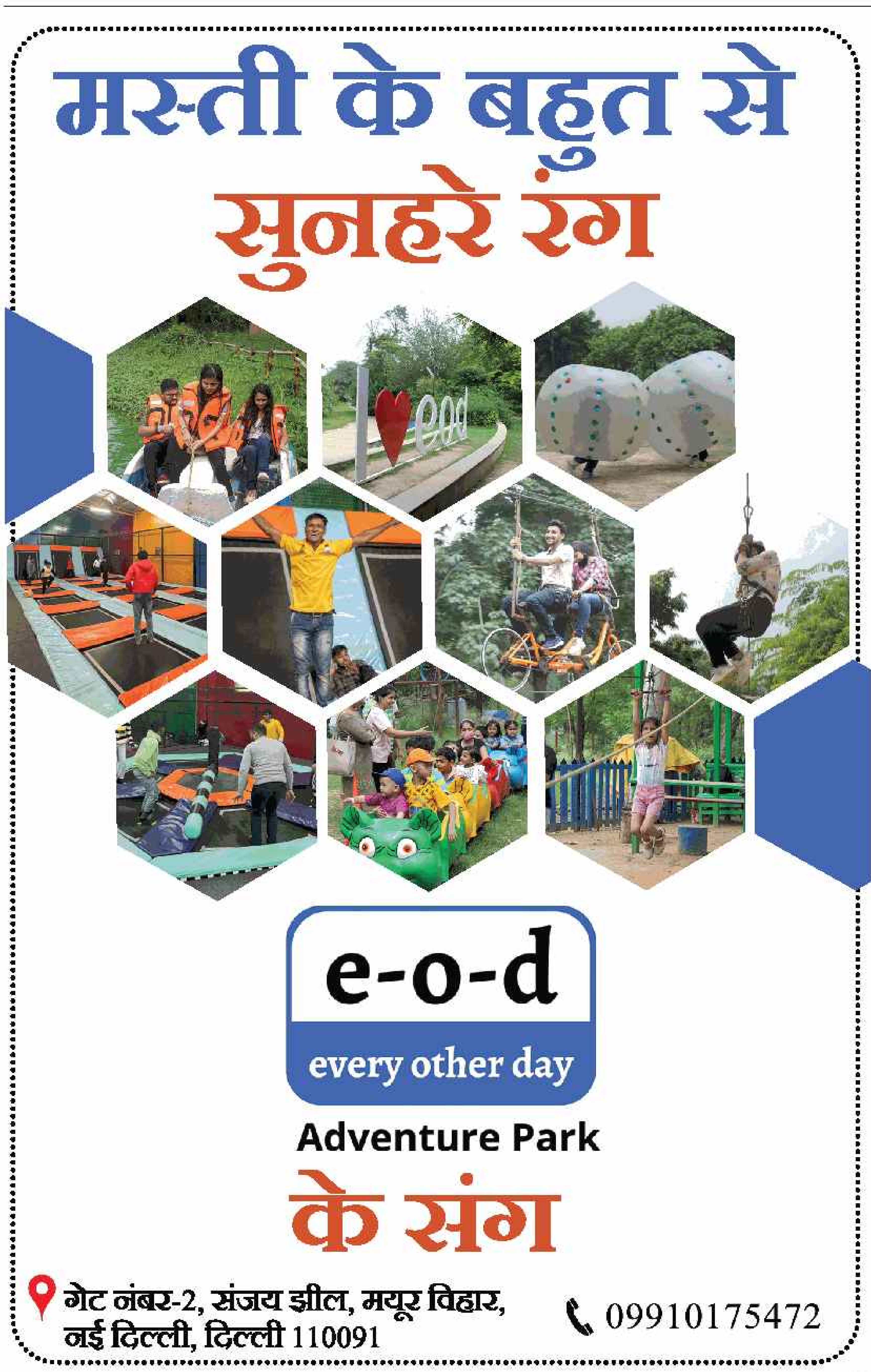

नई दिल्ली, गुरुवार, 25 जुलाई, 2024

जागरण सिटी

दैनिक जागरण
दिल्ली

चांदनी चौक के विकास की हुई अनदेखी : मुदित अग्रवाल

www.jagran.com

लोगों को सही माप व अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराए विभाग : इमरान हुसैन

प्रणाम

चित्रकला प्रदर्शनी

- इंडिया हैबिटेट सेंटर में चित्रकार रोहित शर्मा की ओर से चित्रकला प्रदर्शनी, कनवेंशन सेंटर फायर। सुबह 11 से शाम छह बजे तक। प्रदर्शनी 25 जुलाई तक लगी रहेगी।
- इंडिया हैबिटेट सेंटर में सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी, ओपन पाम कोर्ट गैलरी। सुबह 11 से शाम छह बजे तक। प्रदर्शनी 28 जुलाई तक लगी रहेगी।

दैनिक जागरण कार्यालय

स्थानीय ब्यूरो

प्यारे लाल भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, आइटीओ, दिल्ली

प्रिय पाठकगण,

आप एक जागरूक शहरी के रूप में दैनिक जागरण अखबार व अपने समाज की आंख व कान बन सकते हैं। आप अपने शहर की जिन समस्याओं, मुद्दों व बातों को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हमें बताएं। हम समाचार पत्र के माध्यम से आपकी आवाज को उन लोगों तक ले जाएंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। संपर्क करें: 8175813532 ईमेल: reporter@nda.jagran.com

अगर आपको अपना प्रिय समाचार पत्र दैनिक जागरण मिलने में कोई परेशानी हो रही है तो कृपया हमें जरूर बताएं।

9873067812

जलभराव व जाम से जूझी राजधानी

आधे घंटे की दूरी तय करने में लगे दो घंटे, यातायात पुलिस को करना पड़ा ट्रैफिक डायवर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: बुधवार सुबह हुई तेज वर्षा के कारण राजधानी की सड़कों पर कई जगहों पर जलभराव के कारण भीषण जाम लग गया। इससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आफिस जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। आधे घंटे की दूरी तय करने में लोगों को दो घंटे से अधिक का समय लगा। रिंग रोड हो या एनएच नौ हर जगह वाहन रेंगते हुए नजर आए। अंडरपास में जलभराव के कारण वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी। यूपी गेट पर लोग घंटों जाम में फंसे रहे।

यातायात पुलिस के मुताबिक वर्षा का सबसे बुरा असर यमुनापार, दक्षिण, दक्षिण-पूर्वी व नई दिल्ली जिले में देखने को मिला, क्योंकि इन इलाकों में कई जगहों पर निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिससे सड़कें खस्ताहाल हैं। जगह-जगह पानी भरने से पैदल चलने वाले लोगों को भी दिक्कत हुई। बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में लोग फंसे रहे। सुबह वर्षा के कारण जखीरा फ्लाईओवर के नीचे आनंद पर्वत लाल बत्ती पर जलभराव हो गया। इसके चलते ट्रैफिक पुलिस को यह रास्ता बंद करना पड़ा और दूसरे रास्तों पर ट्रैफिक को भेजा गया। जलभराव के कारण इंडिया गेट, आइटीओ, विकास मार्ग, कनाट प्लेस, निजामुद्दीन, लाजपत नगर, पहाड़गंज, करोल बाग, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, लालकिला के पास, कश्मीरी गेट बस अड्डा, तीस हजारी बस अड्डा, आजाद मार्केट, उत्तम नगर, मोती बाग, सफदरजंग, आश्रम, सराय काले खां, तीस हजारी कोर्ट, सदर बाजार, झंडेवालान चौक, पटपड़गंज, डाबड़ी मोड़, आजादपुर मार्केट, बुराड़ी, संत नगर, लक्ष्मी नगर, पीतमपुरा, मथुरा रोड, दिल्ली कैंट आदि जगहों पर भीषण जाम लगा रहा। यातायात पुलिस को निगम बोध घाट के पास ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा। जलभराव की समस्या वाले इलाके जखीरा अंडरपास, एनएच-24, मोती बाग, तुगलक रोड, अक्षरधाम फ्लाईओवर और आरके पुरम में वाहन चालकों को अधिक परेशानी हुई। ट्रैफिक ने एडवाइजरी जारी कर सलाह दी कि अगर कोई मजनू का टीला से आइटीओ की तरफ आ रहा है तो चंदगी राम अखाड़ा-आइपी कालेज- श्याम नाथ मुखर्जी मार्ग- युधिष्ठिर सेतु के नीचे होते हुए- लोथियन रोड- छत्ता रेल-एनएस मार्ग- निषाद राज मार्ग- शांतिवन-राजघाट की ओर जाए। वीर बंदा बैरागी मार्ग पर भी ट्रैफिक प्रभावित हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने इस रूट पर आने-जाने वालों को बचने की सलाह दी। आनंद पर्वत पर भी ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। आनंद पर्वत में जलभराव की वजह से न्यू रोहतक रोड पर एक घंटे तक ट्रैफिक प्रभावित हुआ।

वर्षा से जलभराव के कारण एनसीआर में रहने वाले लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटों तक जाम से जूझना पड़ा। एनएच-नौ पर आइपी पार्क से आइटीओ व सराय काले खां की तरफ जाने वाले मार्ग पर भयंकर जाम लगा रहा ● विपिन शर्मा

निर्माण कार्य चलने के कारण यमुनापार, दक्षिण, दक्षिण-पूर्वी और नई दिल्ली जिले में सबसे अधिक खराब रहे हालात

गुरुग्राम में 15 एमएम वर्षा में ही डूबे सरकारी दावे

गांव नरसिंह दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन में जलभराव से कई वाहन खराब हो गए और खेड़कीदौला टोल से राजीव चौक तक जाम लग गया ● संजय गुलाटी

8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम खेड़कीदौला टोल प्लाजा से दिल्ली लेन पर हीरो होंडा चौक तक लग गया

12 बजे तक वाहन ट्रैफिक जाम में रेंगते रहे। सर्विस लेन पर नरसिंहपुर में दो से तीन फीट तक जलभराव हो गया

जखीरा अंडरपास में जलभराव होने से फंस गया ट्रक, दोपहर बाद खुला रास्ता

जखीरा अंडरपास से वर्षा का पानी निकालने के बाद खुला रास्ता और गुजरते वाहन चालक ● जागरण

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली: जखीरा अंडरपास में वर्षा का पानी भरने से बुधवार को जलभराव हो गया। इस कारण अंडरपास में एक ट्रक और उसमें सवार पांच लोग पानी में फंस गए, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया। लोक निर्माण विभाग ने इस समस्या का संज्ञान लेकर दो घंटे की मशक्कत के बाद पानी को पंपिंग मशीन से निकालकर टैंकर में भरा। फिर दोपहर के बाद वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से सुचारु हुआ है।

बुधवार सुबह हुई वर्षा के कारण उत्तरी दिल्ली के जखीरा अंडरपास में जलभराव हो गया। इस वजह से आधा अंडरपास पानी में डूब गया। पानी में गुजरते हुए सुबह एक ट्रक बीच में ही फंस गया, जिसमें पांच लोग सवार थे। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पास में खड़ी एक मशीन पर चढ़ गए। काफी देर तक इन लोगों को मजबूरी में उसी पर बैठना पड़ा। वाहन चालकों ने इस समस्या का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर साझा किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को टैग किया। इसके बाद दोनों तरफ के रास्ते को वाहन चालकों के लिए बंद कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। सुबह 11 बजे के पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी टैंक लेकर अंडरपास के पास पहुंचे। उन्होंने पंपिंग जेट की मशीन से पानी को अपने टैंकर में भरा। इससे वहां फंसे ट्रक और लोग निकल पाए। पानी निकालने का सिलसिला दो घंटे तक चला। दोपहर दो बजे के बाद दोनों तरफ का रास्ता खुला, जिससे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली।

पहले भी हो चुकी है अंडरपास की ऐसी स्थिति

जखीरा अंडरपास में जलभराव यह पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी यहां पर कई बार जलभराव की समस्या हो चुकी है। जून में हुई वर्षा के दौरान भी अंडरपास में पानी भर गया था। पीडब्ल्यूडी ने पानी की निकासी के लिए नौ मोटर पंप लगाए थे, जिसमें कुछ मोटर पंप तो पानी में ही डूब गए थे, जबकि कुछ ऐसे मोटर पंप जो बाहर लगे हुए थे, वे काम कर रहे थे। फिर यहां से पानी को निकालकर पास के ही एक नाले में डाला रहा था, जो पहले से ही जाम था।

गांव शाहबाद मोहम्मदपुर में भी भरा वर्षा का पानी

एयरपोर्ट से सटे गांव शाहबाद मोहम्मदपुर में भी वर्षा का पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है।

मैं इस रास्ते से अक्सर आवागमन करता रहता हूं। वर्षा से अंडरपास पानी से भर गया था। आना जाना बंद था। काफी दिक्कत हुई।

-करण, वाहन चालक

वर्षा के कारण सुबह से अंडरपास बंद है। हर बरसात में अंडरपास का यही हाल रहता है, जिसकी वजह से फिर पंजाबी बाग से घूमकर जाना पड़ता है।

-देवेश्वर, वाहन चालक

एक नजर में

मुंबई से दिल्ली आते ही बदमाश को दबोचा

नई दिल्ली: उत्तरी जिले के सदर बाजार थाना पुलिस ने राजेंद्र नगर थाने में दर्ज झपटमारी के मामले में भगोड़ा घोषित बदमाश मोहम्मद शान आजम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ दिल्ली के विभिन्न थानों में 13 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह सदर बाजार थाने का घोषित बदमाश है। जमानत पर बाहर आने पर उसने जेल में समर्पण नहीं किया, जिससे अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। उसने मुंबई, महाराष्ट्र में अपना ठिकाना बना रखा था। मुंबई से दिल्ली स्थित अपने घर आते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। डीसीपी उत्तरी जिला मनोज कुमार मीना के मुताबिक 22 जुलाई को सदर बाजार थाना पुलिस को सूचना मिली कि मोहम्मद शान आजम अपने घर आया है। (जासं)

चोरी के मामले में शामिल अरोपित को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली : उत्तरी जिले के बाड़ा हिंदू राव पुलिस स्टेशन की टीम ने 2.25 लाख की नकदी और सोने की चेन की चोरी के मामले में शामिल एक आरोपित राहुल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक रिसीवर सहित दो आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके पास से 51 हजार रुपये की चोरी की गई नकदी और 60 ग्राम वजन की एक सोने की चेन बरामद की गई है। उत्तरी जिले के डीसीपी मनोज कुमार मीना ने बताया कि 11 जून 2024 को सदर बाजार के तेलीवाड़ा से दो बदमाशों द्वारा दो की नकदी और 60 ग्राम वजन वाले लाकेट के साथ एक सोने की चेन छीनने के बारे में थाना बाड़ा हिंदू राव में शिकायत दर्ज हुई थी। (जासं)

अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा सचिव से की वेतन बढ़ाने की मांग

जासं, नई दिल्ली: राजधानी के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 17 हजार अतिथि शिक्षक बीते सात वर्षों से वेतन बढ़ने और नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा सचिव से वेतन बढ़ाने और उन्हें नियमितीकरण करने का अनुरोध किया।

आल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव शोएब राणा ने कहा कि हर वर्ष महंगाई बढ़ती जा रही है। बीते सात वर्षों से वेतन में एक रुपये भी नहीं बढ़ने से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। हाल ही में समग्र शिक्षा के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संविदा के तौर पर काम करने वाली आया व सहायक का वेतन बढ़ाया गया है। पहले इनका प्रतिमाह वेतन 16,506 रुपये था, जो अब बढ़ाकर 17,494 रुपये कर दिया गया है। दिल्ली में हजारों अतिथि शिक्षक जो वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनका सात वर्षों से वेतन नहीं बढ़ाया गया। राणा ने बताया कि वेतन बढ़ाने को लेकर कई बार अतिथि शिक्षक पूर्व शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं। इसके बाद उन्हें शिक्षा मंत्री की ओर से वेतन बढ़ने का न सिर्फ आश्वासन मिला था, बल्कि वेतन बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया गया था।

डीयू के उर्दू के विद्यार्थियों को पढ़ाए जाएंगे संत कबीर के दोहे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में संत कबीर के दोहे पढ़ाए जाएंगे। इसको लेकर संशोधन प्रस्ताव 27 जुलाई को प्रस्तावित कार्यकारी परिषद की बैठक में लाया जाएगा।

डीयू के एक अधिकारी ने कहा कि कला संकाय की ओर से अनुशंसित संशोधनों के हिस्से के रूप में विद्यार्थियों को पहले सेमेस्टर में 'कबीर बानी' के 40 दोहों को चयनित कर पढ़ाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए कला संकाय की ओर से एमए उर्दू प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में दो पाठ्य सामग्री शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें सुझाए गए पाठों में अली सरदार जाफरी लिखित कबीर बानी और प्रभाकर मांचवे लिखित कबीर शामिल हैं। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो पाठ्यक्रम में बदलाव अगस्त में शुरू होने वाले 2024-25 शैक्षणिक सत्र से लागू किया जा सकता है। कला संकाय ने उर्दू विभाग में पढ़ाए जाने वाले ''बेसिक टेक्स्ट: अर्ली उर्दू लिटरेचर'' नामक पेपर के पाठ्यक्रम में इन संशोधनों की सिफारिश की है। परिवर्तन लाने का निर्णय संकाय द्वारा 19 फरवरी को आयोजित एक बैठक में लिया गया था। इसे

विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कार्यकारी परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया है। उर्दू विभाग के पाठ्यक्रम प्रोस्पेक्टस में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य विद्यार्थियों को दक्षिण और उत्तर भारत की प्रारंभिक साहित्यिक परंपराओं से परिचित कराना है। इसमें कहा गया है, इस पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, छात्र प्रारंभिक साहित्यिक उर्दू परंपराओं के संदर्भ में शास्त्रीय कविता और गद्य को समझने और सराहने में सक्षम होंगे। प्रस्तावित संशोधनों के तहत, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी पाठ्यक्रम कबीर के मुंतखब दोहे से शुरू करेंगे। कबीर बानी से 40 दोहे पाठ्यक्रम की इकाई का हिस्सा बन जाएगा। पहले, विद्यार्थियों को यूनिट एक के तहत मुल्ला वाझी (पहली छमाही) का उप-रस सिखाया जाता था। प्रस्तावित संशोधनों को डीयू की अकादमिक परिषद ने मंजूरी दे दी, जिसकी जुलाई को बैठक हुई थी।

भतीजी को तंग करने पर गोली मारकर की थी हत्या, गिरफ्तार

जासं, नई दिल्ली: गाजियाबाद के मुरादनगर में दिनदहाड़े लाखन सिंह नाम के युवक के सिर में गोली मार हत्या करने वाले आरोपित विनीत मलिक को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में यह मामला कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहा था। भतीजी को तंग करने के कारण विनीत ने लाखन सिंह की हत्या कर दी थी और गिरफ्तारी से बचने के लिए एनसीआर में छिप रहा था। क्राइम ब्रांच ने उसे दिल्ली के जगतपुरी से दबोच लिया।

डीसीपी क्राइम ब्रांच संजय कुमार सेन के मुताबिक विनीत मलिक ने 12वीं तक पढ़ाई की है। वह मुरादनगर स्थित आर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था। आठ जून को मेरठ के कंकरखेड़ा थाना पुलिस ने लाखन सिंह के स्वजन की शिकायत पर विनीत मलिक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। मुरादनगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि विनीत मेरठ छोड़कर दिल्ली भाग गया है। यह सूचना दिल्ली पुलिस को दे दी गई। क्राइम ब्रांच के एसीपी सुशील कुमार व इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह की टीम को सूचना मिली कि विनीत जगतपुरी में छिपा हुआ है।

फिर गिरी इंजीनियरों पर गाज, जेई और एई निलंबित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के आयुक्त अश्विनी कुमार के आने के बाद भवन विभाग इंजीनियर पर लगातार कार्रवाई हो रही है। करोल बाग जोन के बाद अब नगर निगम आयुक्त ने सेंट्रल जोन में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता (जेई) और सहायक अभियंता(एई) पर कार्रवाई की है। आयुक्त ने अवैध निर्माण को लेकर आ रही शिकायतों पर यह कार्रवाई की है।

निगमायुक्त की ओर से जारी आदेश के तहत सेंट्रल जोन के जेई अमित कुमार शर्मा और एई महेश कुमार को निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है निगमायुक्त अश्विनी कुमार ने आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद करोल बाग जोन में भवन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की थी। अब दूसरी कार्रवाई सेंट्रल जोन में हुई है। सेंट्रल जोन के अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिस पर कोर्ट ने निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। माना जा रहा है कि उन्हीं शिकायतों को लेकर यह कार्रवाई हुई है।

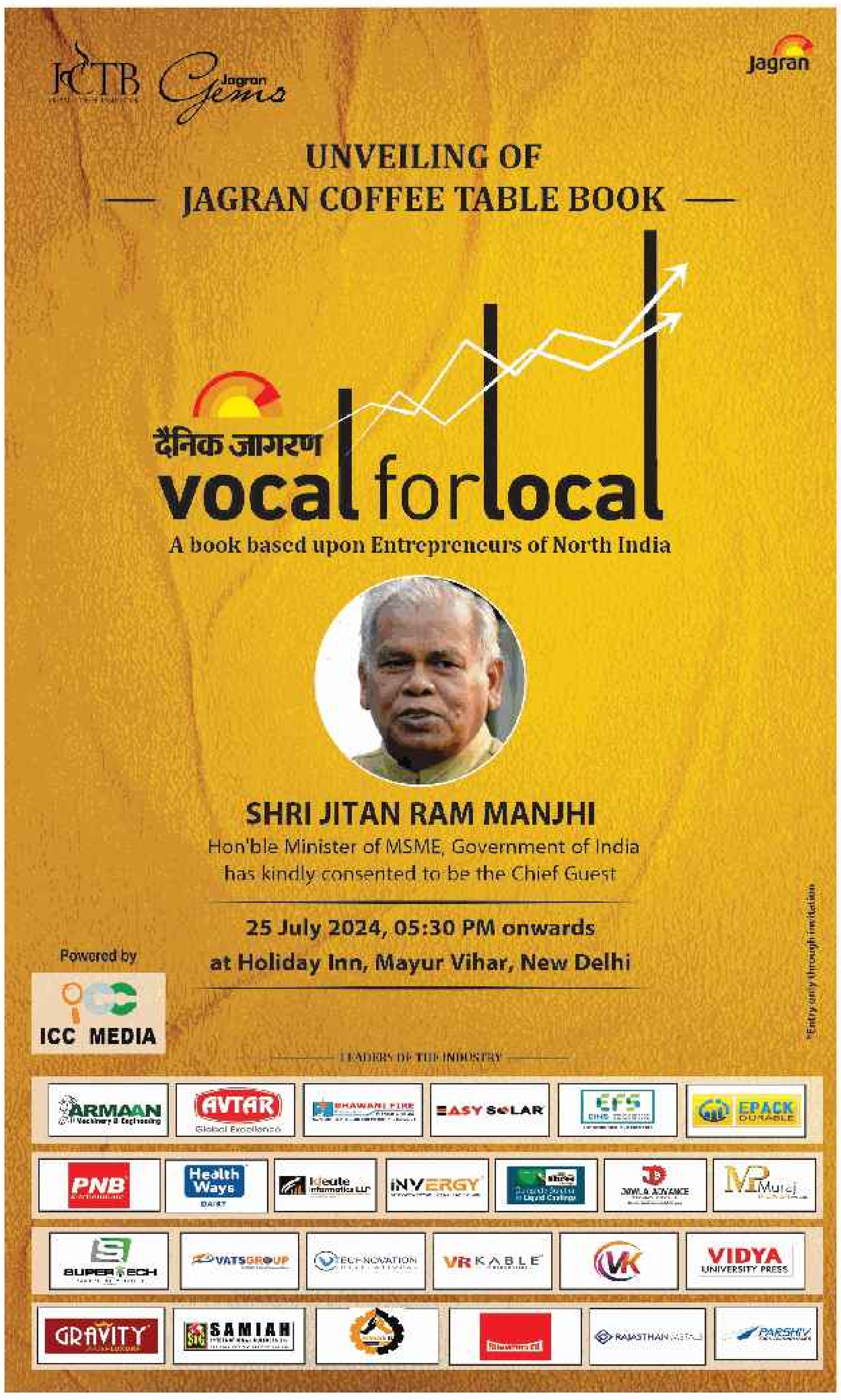

पेरिस ओलिंपिक में देश का परचम लहराएंगे डीयू के नौ विद्यार्थी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: पेरिस में 26 जुलाई से होने वाले ओलिंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल में नौ खिलाड़ी दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्र हैं। वे सभी ओलिंपिक में अपना परचम लहराने के लिए तैयार हैं। इनमें छह खिलाड़ी शूटिंग में भाग ले रहे हैं। एक एथलेटिक्स और एक टेबल टेनिस में प्रतिभाग कर रहे हैं। एक पूर्व विद्यार्थी शूटिंग कोच के तौर पर भी ओलिंपिक में भागीदारी करने जा रहे हैं।

डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि 2020 के टोक्यो ओलिंपिक में डीयू के चार विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इस बार यह संख्या दोगुने से भी अधिक हो गई है। डीयू के खेल निदेशक डा. अनिल कुमार कलकल ने बताया कि इस बार भाग लेने वाले नौ खिलाड़ियों में तीन खिलाड़ी मनु भाकर, अमोज जैकब और मनिका बतरा 2020 के टोक्यो आलिंपिक में भी भाग ले चुके हैं। कहा, शूटिंग प्रतियोगिता में भारत से 21 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें से 11 महिला खिलाड़ी हैं और छह डीयू की छात्राएं हैं। टेबल टेनिस में भारतीय दल के आठ खिलाड़ियों में से चार महिला खिलाड़ी हैं, जिनमें से एक डीयू से है।

मनु भाकर ●

रमिता जिंदल ●

राजेश्वरी कुमारी ●

अमोल ●

रिदम ●

महेश्वरी ●

दो वर्तमान और सात पूर्व छात्र हैं ओलिंपिक का हिस्सा : डीयू के खेल निदेशक डा. अनिल कुमार कलकल ने बताया कि शूटिंग में भाग लेने वाली रमिता जिंदल इस समय हंसराज कालेज की बीकाम (आनर्स) तृतीय वर्ष और रिदम सांगवान लेडी श्री राम कालेज की इंग्लिश (आनर्स) द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। पूर्व विद्यार्थियों में श्रेयसी सिंह ने हंसराज कालेज से 2012 में बीए किया है। मनु भाकर ने लेडी श्री राम कालेज से 2022 में राजनीतिक विज्ञान (आनर्स) किया है। महेश्वरी चौहान ने लेडी श्री राम कालेज से 2017 में फिलासफी (आनर्स) किया है और राजेश्वरी 2010 में श्री वेंकटेश्वर कालेज की बीए की छात्रा रही हैं। टेबल टेनिस में भाग लेने वाली मनिका बत्रा 2016 में जीसस एंड मैरी कालेज की समाजशास्त्र (आनर्स) प्रोग्राम की छात्रा रही हैं। एथलेटिक्स (4x400 मीटर, रिले) में भाग लेने जा रहे अमोज जैकब ने श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कालेज से 2016-2019 में बीकाम किया है। डा. कलकल ने बताया कि मनु के कोच के तौर पर पेरिस ओलिंपिक में जाने वाले जसपाल राणा भी श्री अरबिंदो कालेज के विद्यार्थी रहे हैं।

****

सिम वेरिफिकेशन के नाम पर हाल में साइबर ठगों ने बेंगलुरु की एक महिला के खाते से 1.2 करोड़ रुपये उड़ा लिए। फर्जी नंबरों से इस तरह लोगों को ठगने की खबरें आए दिन चर्चा में रहती हैं। सिम के सही प्रयोग, निगरानी, सिम स्वैपिंग के विविध पहलुओं की चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र...

फोटो : प्रतीकात्मक

गंभीर है सिम स्वैप फ्राड

अगर सिम अचानक काम करना बंद कर दे, तो संभव है आप सिम स्वैपिंग के शिकार हो गए हों। इसमें स्कैमर आपके नंबर पर किसी अन्य सिम को एक्टिवेट करा लेते हैं। इसके बाद आपका फोन नंबर काम करना बंद कर देता है। सारे फोन और मैसेज स्कैमर की डिवाइस में रिसीव होने लगते हैं। स्कैमर बैंक अकाउंट तक भी पहुंच सकते हैं।

कैसे होता है सिम स्वैप

स्कैमर पहले फिशिंग मेल, मालवेयर या इंटरनेट मीडिया पर रिसर्च कर फोन नंबर और अन्य जानकारियों को एकत्र करते हैं या फिर वे डार्क वेब से भी किसी की निजी या वित्तीय जानकारियों को खरीद सकते हैं। इसके बाद टेलीकाम कंपनी को फोन कर नया सिम जारी कराते हैं। नया सिम जारी होते ही वे साइबर ठगी के कारोबार में जुट जाते हैं।

सिम स्वैप स्कैम से स्वयं को कैसे बचाएं

- किसी भी तरह के अनजान लिंक, फिशिंग मेल पर क्लिक करने और अपने बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड या कोई अन्य जानकारी साझा करने से बचें।
- अकाउंट की सुरक्षा के लिए पासवर्ड हमेशा मजबूत बनाएं। पासकोड या पिन को सेट करते समय सावधान रहें।
- कालिंग, मैसेजिंग में समस्या होने पर टेलीकाम कंपनी से और बैंक खाते में अवांछित लेनदेन होने पर बैंक की कस्टमर सपोर्ट टीम से संपर्क करें।

टेक सिक्योरिटी

अधिक सिम न बन जाए समस्या!

पिछले महीने की शुरुआत में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सामने एक जमानत याचिका आई, जिसमें साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार मध्य प्रदेश के सुमित नंदवानी का जिक्र था। न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। इस निर्णय में एक बड़ा संदेश भी है-अगर आपके नाम पर जारी सिम कार्ड का धोखाधड़ी जैसे अपराधों में प्रयोग हुआ, तो आप कानूनी शिकंजे से कतई बच नहीं पाएंगे। दरअसल, सुमित के नाम और आधार कार्ड पर अलग-अलग कंपनियों के 35 से अधिक सिम जारी हुए और इन सभी का प्रयोग ठगी के लिए किया गया, जैसे-ओटीपी स्कैम, वाट्सएप स्कैम आदि। हाल के दिनों में घर से पार्ट टाइम इनकम के नाम पर भी ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। जिस तरह फर्जी दस्तावेजों के सहारे सिम कार्ड प्राप्त कर ठगी हो रही है, उसे देखते हुए सिम कार्ड के प्रयोग, जारी करने की प्रक्रिया, सिमों की संख्या और निगरानी को लेकर बहस तेज हो गई है। बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए इंटरनेशनल कालिंग की डिफाल्ट ब्लाकिंग, सिम के अवैधानिक प्रयोग और फ्राड कम्युनिकेशन पर भी रोक लगाने की मांग होती रही है।

सिम के जरिए धोखे का कारोबार: टेलीकम्युनिकेशन विभाग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (एआइ एंड डीआइयू) की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग दो करोड़ लोगों के पास निर्धारित से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं, जबकि देश में प्रति व्यक्ति कनेक्शन प्राप्त करने की सीमा तय की गई है। जांच में ऐसे सिम भी चिह्नित किए गए, जिन्हें सर्विस प्रदाता द्वारा बल्क कनेक्शन के बजाय व्यक्तिगत कनेक्शन के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया। अधिकांश मामलों में कनेक्शन के लिए फर्जी डाक्यूमेंट लगाया गया। रिपोर्ट बताती है कि 21 लाख से अधिक सिम को एक्टिवेट करने के लिए अवैध, फर्जी, अस्तित्वहीन और जाली दस्तावेजों का प्रयोग हुआ है। इनमें अधिकांश कनेक्शन का प्रयोग साइबर अपराध या फ्राड के लिए किया गया। खास बात है कि अवैध नामों से जारी सिम की निगरानी और कार्रवाई करना जांच एजेंसियों और पुलिस के लिए मुश्किल होता है।

ऐसे जांचें अपने नाम से जारी सिम कार्ड के बारे में

आपके नाम पर कितने सिम कार्ड पंजीकृत हैं, इसे सरकार के डेडिकेटेड पोर्टल 'संचार साथी' से पता कर सकते हैं। चूंकि, यह आधार आइडी से लिंक नहीं होता, ऐसे में आधार नंबर दर्ज करके जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते।

- https://tafcop.sancharsaathi.gov.in/telecomUser/ ओपन करें।
- निर्धारित कालम में मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करें। इसके बाद ओटीपी प्राप्त होगा।
- नए वेबपेज पर आपके नाम से जारी नंबरों की सूची दिखेगी। यहां 'नाट माय नंबर', 'नाट रिक्वायर्ड' और 'रिक्वायर्ड' चुन सकते हैं।
- यदि किसी नंबर को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए 'नाट रिक्वायर्ड' आप्शन पर क्लिक करना होगा।

कितने सिम कर सकते प्रयोग: देश में अलग-अलग क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति सिम कनेक्शन जारी होने की सीमा अलग-अलग है। पूरे देश में प्रति व्यक्ति नौ सिम कनेक्शन (जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में छह सिम) प्राप्त किया जा सकता है। टेलीकाम संसाधनों के उचित प्रयोग और प्रबंधन के साथ-साथ अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए इन नियमों की व्यवस्था बनाई गई है। नियमों के उल्लंघन पर पहली बार 50 हजार रुपये, दूसरी बार दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है। टेलीकाम अधिनियम 2023 के तहत आनलाइन फ्राड में शामिल होने पर 50 लाख रुपये तक के जुर्माने और तीन साल के कारावास जैसी सख्त कार्रवाई का भी प्रविधान किया गया है।

इंटरनेट मीडिया

वाट्सएप पर बिना इंटरनेट भी फाइल शेयरिंग

मैसेजिंग प्लेटफार्म वाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे आइओएस डिवाइसेज पर इंटरनेट के बिना फाइलों को साझा करना संभव होगा। फाइल ट्रांसफर के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले एपल के एयरड्राप की तरह यह फीचर काम करेगा। डब्ल्यूएबीटा इन्फो के मुताबिक, वाट्सएप के इस नए फीचर से फोटो, वीडियो, डाक्यूमेंट और अन्य मीडिया फाइलों को भी बिना इंटरनेट के साझा किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के तहत डिवाइस को स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड जेनरेट होगा। एंड्रायड वर्जन में नियरबाय डिवाइसेज को सर्च किया जाता है। इंटरनेट-फ्री शेयरिंग फीचर बेहतर इंटरनेट कनेक्शन या वाइ-फाइ नहीं होने की स्थिति में उपयोगी हो सकता है। वाट्सएप विभिन्न भाषाओं में मैसेज को अनुवाद करने के एक फीचर पर भी काम कर रहा है।

टेक अपडेट

एनपीसीआइ का वन वर्ल्ड यूपीआइ वालेट

भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआइ) ने वन वर्ल्ड यूपीआइ वालेट की घोषणा की है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआइ) तकनीक आधारित इस यूपीआइ पेमेंट हेतु पर्यटकों को भारतीय सिम कार्ड या किसी भारतीय बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होगी। एनपीसीआइ के अनुसार, पर्यटक अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूपीआइ वन वर्ल्ड की सहायता ले सकेंगे। भारत में विकसित रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का अनुभव प्राप्त करने के लिए देश में इंटर कनेक्टेड ग्लोबल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है।

वर्ग पहेली - 2701

बाएं से दाएं

1. बुद्धिमानी (5) I 3. कृष्ण पक्ष की अंतिम रात (4) I 6. नवल, नूतन, नवीन (2) I 7. नहीं आया हुआ (4) I 11. साहूकार (4) I 13. हवालात, कैदखाना (3) I 14. सिद्ध करना, उपासना (3) I 15. मान अपमान (4) I 17. मंसूबा (4) I 19. विचार, मत (2) I 21. जो जायज न हो (4) I 22. बिहार के इस शहर में कोयला आधारित विद्युत स्टेशन है (5) I

ऊपर से नीचे

1. समान होने का भाव (4) I
2. मुग्ध होना, आसक्त होना, प्रेम में पड़ना (3) I
4. हार (2) I 5. वस्तु के विभिन्न अंगों में होने वाला तुलनात्मक संबंध (5) I
8. पार्वती के पुत्र (4) I
9. जिसका नाम कोई न जानता हो (4) I
10. कहानी का बहुवचन (4) I
12. अवैध माल जमा रखने वाला (4) I
14. हिम्मत हार जाना (3,2) I
16. परिवर्तन, हेर-फेर (4) I
18. नापने का मानदंड (3) I
20. दुख सूचक अव्यय (2) I

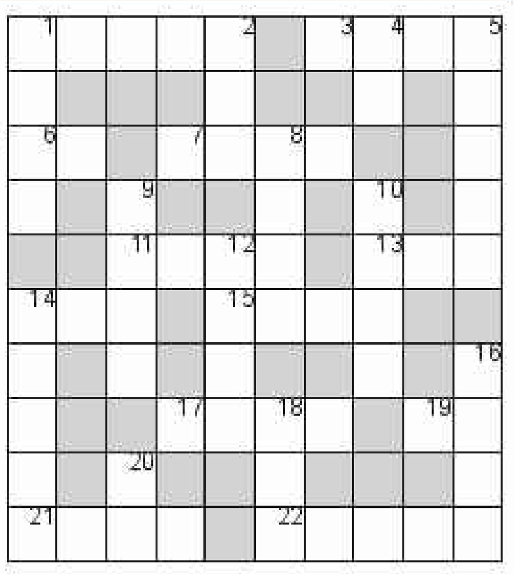

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

अ		स	म	र		क	म	क	स
भि		म				मा			
शा		य	त्न		अ	ना	व	श्य	क
प	रा	या			का		ज्ञ		स
		न	वं	ब	र				म
ग				ल	थ	प	थ		
री		अ		खा			र	म	ना
ब	ल	ब	ला	ना		सा	थ		म
			ड				रा		ची
अ	ल	बे	ला		ने	हा	ना		न

जागरण सुडोकू-2701

	9			6		1		3
6				2				8
	4	1	3		9	2		
7				1	2		3	
		4		9				2
9	2		8			7		6
	5		9			3		
3	1			7			8	5
		8	1		5		2	

कल का हल

4	7	9	3	6	1	5	2	8
2	1	3	4	8	5	7	9	6
6	8	5	2	7	9	4	3	1
3	5	7	1	2	6	8	4	9
9	4	2	8	5	7	1	6	3
1	6	8	9	4	3	2	5	7
5	9	4	6	1	8	3	7	2
7	3	1	5	9	2	6	8	4
8	2	6	7	3	4	9	1	5

आज का भविष्यफल- 25 जुलाई, 2024 गुरुवार

के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: श्रावण मास कृष्ण पक्ष पंचमी। आज का राहुकाल: दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक। आज का दिशाशूल: दक्षिण। विशेष: पंचक।

कल 26 जुलाई, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल: पश्चिम
कल की भद्रा: रात्रि 11:31 बजे से 27 जुलाई को प्रात: 10:25 पर समाप्त।
विशेष: पंचक
श्रावण मास कृष्ण पक्ष षष्ठी, सप्तमी उत्तरभाद्रपद नक्षत्र, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र सुकर्मा योग 25 घंटे 32 मिनट तक, तत्पश्चात धृति योग मीन में चंद्रमा।

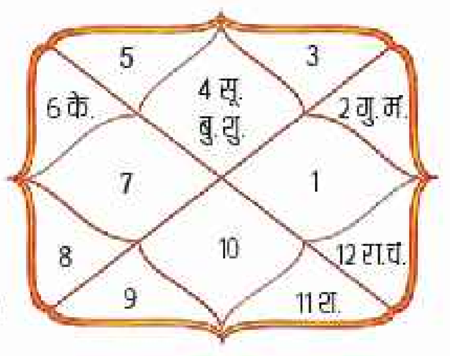

मेष: आर्थिक मामलों में सुधार होगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा।
वृष: शासनसत्ता का सहयोग मिलेगा। पिता या धर्म गुरु का आशीर्वाद रहेगा।
मिथुन: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।
कर्क: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। योजना फलीभूत होगी।
सिंह: आर्थिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा।
कन्या: सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी। रिश्तों में निकटता आएगी।
तुला: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। दांपत्य जीवन सुखमय होगा।
वृश्चिक: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रचनात्मकता सफल होगी।
धनु: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।
मकर: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
कुंभ: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
मीन: आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाई-बहन का सहयोग रहेगा।

डिजिटल वालेट

पेमेंट फंसने पर क्या करें उपाय

चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे लेनदेन के तमाम साधनों के विकल्प के रूप में मोबाइल पेमेंट आज सहज माध्यम बन गया है। लेकिन, यूपीआइ आइडी दर्ज करते या क्यूआर कोड स्कैन करते हुए छोटी असावधानी बड़ा नुकसान कर सकती है। इससे बचने के लिए जानें कुछ जरूरी टिप्स ...

डिजिटल वालेट ने बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, बुकिंग, खरीदारी को आसान बनाने के साथ-साथ गली-मोहल्ले से लेकर ई-कामर्स तक डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बना दिया है। तकनीक के विकास के साथ-साथ अब 'बाय नाउ-पे लैटर' (बीएनपीएल), वियरेबल पेमेंट और वायस असिस्टेंट-बेस्ड पेमेंट का भी चलन लोकप्रिय हो रहा है। एक हालिया रिपोर्ट की मानें तो साल 2030 तक भारत में डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा सात ट्रिलियन डालर तक पहुंच जाएगा। दूसरी ओर, यूपीआइ (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) लेनदेन जैसी डिजिटल पेमेंट की तमाम सुविधाओं के बीच पेमेंट फंसने, डिजिटल फ्राड होने, कनेक्टिविटी और ट्रस्ट से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ी हैं।

यूपीआइ पेमेंट से जुड़ी सामान्य समस्याएं: जब एप के जरिए किसी यूपीआइ आइडी से पेमेंट या क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या किसी गलत यूपीआइ एड्रेस पर पेमेंट चली जाती है, जिससे आपको वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि, अच्छी बात है कि यूपीआइ पेमेंट को सुरक्षित रखने और पैसे वापस पाने के उपाय भी हैं, जिसे आपको जानना चाहिए।

कैसे होती है गलत यूपीआइ पेमेंट

गलत यूपीआइ एड्रेस: गलत टाइपिंग या यूपीआइ एड्रेस को सही ढंग से नहीं समझने से गलत पेमेंट हो जाता है। मिलते-जुलते यूपीआइ एड्रेस, जैसे नाम या सामान्य टर्म के चलते भी पेमेंट फंस जाता है।

क्यूआर कोड स्कैनिंग: गलत क्यूआर कोड जेनरेट होने या स्कैनिंग एरर से भी कई बार गलत पेमेंट हो जाती है।

स्कैम: साइबर अपराधी ठगी के लिए यूपीआइ का सहारा लेते हैं।

तकनीकी व्यवधान: यूपीआइ एप या सर्वर में व्यवधान आने के कारण भी गलत यूपीआइ एड्रेस पर पेमेंट हो जाता है।

इन तरीकों से करें पेमेंट रिकवर

प्राप्तकर्ता से संपर्क: जिस व्यक्ति को गलती से पेमेंट ट्रांसफर हो गया है, अपने पैसे की वापसी के लिए आप उससे अनुरोध कर सकते हैं।

यूपीआइ एप की मदद: गलत ट्रांजैक्शन होने पर यूपीआइ एप के कस्टमर सपोर्ट टीम की मदद ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारियां और साक्ष्य देकर आप रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

एनपीसीआइ में शिकायत: एप के कस्टमर सपोर्ट से निस्तारण नहीं होने पर एनपीसीआइ में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

बैंक की लें मदद: गलत ट्रांजैक्शन होने की दशा में तुरंत बैंक से संपर्क करना चाहिए। आवश्यक जानकारी और साक्ष्य देने पर बैंक फंड को रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है।

ब्रह्मानंद मिश्र

जागरण सिटी दिल्ली

प्रोन्नत होने के लिए छात्र को प्राप्त करने होंगे 28 क्रेडिट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक में अगले वर्ष में प्रोन्नत होने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। छात्र को दोनों सेमेस्टर मिलाकर 44 में से 28 क्रेडिट लाने होंगे। तभी उन्हें दूसरी कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। इससे पहले उन्हें 22 क्रेडिट लाने पर ही प्रोन्नत किया जाता था। डीयू ने छात्रों की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए यह निर्णय लिया है।

डीयू ने स्पष्ट किया है कि खेल, पाठ्येतर गतिविधियों, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) में विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को उनके कालेज के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अधीन मानदंड से छूट दी जा सकती है। डीयू की डीन आफ एकेडमिक्स प्रो. के रत्नाबली ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) स्नातक पाठ्यचर्या रूपरेखा (यूजीसीएफ) 2022 के कार्यान्वयन में कमी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यूजीसीएफ के तहत प्रत्येक सेमेस्टर में कुल 22 क्रेडिट के सात पेपर शामिल होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में 44 क्रेडिट के साथ चौदह (14) पेपर होते हैं। इसके अतिरिक्त, छात्रों के पास 4 क्रेडिट के एक और कोर (डीएससी) पेपर का चयन करने का विकल्प होता है, जिससे एक छात्र को एक सेमेस्टर में अधिकतम 26 क्रेडिट और एक शैक्षणिक वर्ष में 52 क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति मिलती है। छात्र इसमें से 22 क्रेडिट लाकर प्रोन्नत हो जाते थे। जिसमें बदलाव किया गया है। डीयू के पूर्व परीक्षा नियंत्रक और रामजस कालेज के प्राचार्य प्रो. अजय अरोड़ा ने कहा, एनईपी लागू होन के बाद छात्रों को सहूलियत हो गई थी। एक सेमेस्टर में सात पेपर होते हैं। इनमें तीन पेपर मुख्य विषय के होते हैं। एक जेनरिक इलेक्टिव, एक एईसी, वीएसी और एक एसईसी का पेपर होता है। इनमें तीन मुख्य पेपर और जेनरिक इलेक्टिव के चार क्रेडिट होते हैं। शेष तीन के दो-दो क्रेडिट होते हैं। ऐसे एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट होते हैं। दूसरे समेस्टर को मिलाकर यह 44 हो जाते हैं। इनमें 22 क्रेडिट छात्रों को लाने होते थे। छात्र पहले सेमेस्टर में 20 क्रेडिट तक हासिल कर लेते थे। अक्सर दूसरे सेमेस्टर में मुख्य विषयों को नहीं पढ़ते थे और अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत हो जाते हैं। इसलिए नई व्यवस्था में कि छात्र 28 क्रेडिट हासिल करे और दो सेमेस्टर में दो मुख्य विषय जरूर पढ़े। हर सेमेस्टर में एक-एक मुख्य विषय पढ़ना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि एक छात्र को दोनों सेमेस्टर से तीन पेपर (एईसी, एसईसी, वीएसी) और एक जेनरिक इलेक्टिव पेपर पास करके, 44 में से केवल 16 क्रेडिट अर्जित करके अगले वर्ष में पदोन्नत किया जा सकता है। कुल क्रेडिट का यह केवल 36 प्रतिशत है, लेकिन नियमों के मुताबिक 50 महत्वपूर्ण बात यह है कि सेमेस्टर उत्तीर्ण करने और आगे की पदोन्नति के लिए, आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने के लिए मुख्य शैक्षणिक विषयों को लेने की कोई बाध्यता नहीं है। इस मुद्दे पर सात मई को डीन, एकेडमिक्स और कंट्रोलर आफ एग्जामिनेशन (सीओई) के साथ मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल कालेज और लेडी श्री राम सहित डीयू के कई कालेजों के प्राचार्यों की 12 सदस्यीय समिति बुलाई गई और इस पर विचार किया गया और सिफारिश की गई। इन सिफारिशों को बाद में डीयू के कुलपति योगेश सिंह ने 28 मई को मंजूरी दे दी। सत्यवती कालेज के छात्र अमृत राज पांडे ने कहा, 28 क्रेडिट स्कोर कोई ज्यादा नहीं है और इसे आसानी से किया जा सकता है।

श्री रामलला की आरती का लाइव दर्शन डीडी पर

वि.नई दिल्ली: श्री राम मंदिर अयोध्या से राम लला की दैनिक श्रृंगार आरती दर्शन का अब दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर सजीव प्रसारण सुबह छह बजे प्रतिदिन से हो रहा है। भक्ति, एकता और सामासिक संस्कृति के प्रतीक के रूप में, जन्मभूमि से रामलला की दैनिक श्रृंगार आरती दर्शन का प्रसारण 12 मार्च से हो रहा है। विश्व भर के श्रद्धालु हर दिन सुबह छह बजे इस दिव्य आरती के दर्शन कर रहे हैं।

श्री राम मंदिर से रामलला के दिव्य आरती दर्शन को दूरदर्शन राष्ट्रीय पर शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। इस पहल का उद्देश्य उन सभी भक्तों को भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन कराना है जो स्वयं श्रीराम मंदिर जाकर आरती में सम्मिलित होने में असमर्थ है।

जागरण की काफी टेबल बुक 'वोकल फार लोकल' का विमोचन आज

जासं, नई दिल्ली: उत्तर भारत के सफल उद्यमियों पर आधारित दैनिक जागरण की काफी टेबल बुक 'वोकल फार लोकल' का विमोचन आज होगा। मयूर विहार स्थित होटल हालीडे इन में आयोजित कार्यक्रम में देश के एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी इसका विमोचन करेंगे। काफी टेबल बुक में 25 उद्यमियों के सफलता की कहानी है।

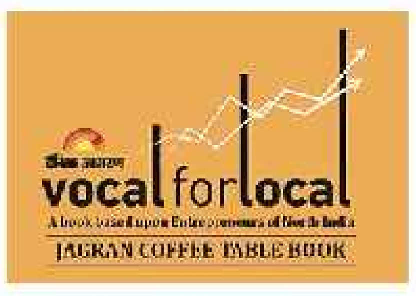

इस मौके पर समरकूल होम अप्लायंसेज लिमिटेड, जय श्री पेंट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री शक्ति एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, ईन्स टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड,

भवानी फायर प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड, अरमान मशीनरी एंड इंजीनियरिंग, सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स लिमिटेड,

सुपरटेक ईवी लिमिटेड, ग्रेविटी बाथ प्राइवेट लिमिटेड, वीआर केबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वत्सग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ईजी सोलर साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड,

हेल्थवेज मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, अवतार फाउंड्री एंड वर्कशाप, इनवर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आइडियाट इंफार्मेटिक्स एलएलपी, प्रणाम जी इंजीनियरिंग वर्क्स, टेक्नोवेशन इंटरनेशनल, पारशिव टूल टेक्नोलाजीज, विद्या यूनिवर्सिटी प्रेस, मुराज प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, वी के एंटरप्राइजेज, जावला एडवांस टेक्नोलाजी एलएलपी व ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड से जुड़े दिग्गज उद्यमियों की मौजूदगी रहेगी। इस आयोजन में आइसीसी मीडिया विशेष सहयोगी है।

सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम 27 को

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राजधानी के सरकारी स्कूलों में 27 जुलाई को सभी कक्षाओं के लिए मेगा पीटीएम (अभिभावक शिक्षक मीटिंग) आयोजित की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि इस संबंध में सभी विद्यार्थियों के माता-पिता और अभिभावकों को लिखित रूप में सूचित किया जाए। इसके लिए या तो विद्यार्थियों की डायरी में एक नोट लिखा जाए या अभिभावकों के मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाए। पहली पाली में पीटीएम सुबह साढ़े आठ से 12:30 बजे तक और शाम की पाली में पीटीएम दोपहर दो से शाम छह बजे तक होगी।

निदेशालय ने कहा कि प्रधानाचार्यों को स्कूल की प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को अपने माता-पिता या अभिभावकों को आगामी पीटीएम के बारे में सूचित किया जाए। पीटीएम के दौरान कक्षा शिक्षक अपनी-अपनी कक्षाओं में उपस्थित हो और प्रत्येक छात्र के माता-पिता को कम से कम पांच से दस मिनट के लिए व्यक्तिगत रूप से शैक्षणिक गतिविधियों और छात्रों के सीखने के स्तर को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताएं।

मनोरंजन

चेहरे की वजह से नहीं मिलती हारर व नकारात्मक भूमिकाएं

दर्शकों के सामने अपनी कला के विविध पहलू प्रस्तुत करने के लिए यूं तो कलाकार हर तरह की भूमिकाएं निभाना चाहता है। हालांकि, कभी शारीरिक बनावट या चेहरे के कारण कई बार फिल्मकार उन्हें कुछ भूमिकाएं देने से कतराते हैं। क्रूक और यमला पगला दीवाना 2 फिल्मों की अभिनेत्री नेहा शर्मा सोनी लिव पर हालिया प्रदर्शित वेब सीरीज 36 डेज में पहली बार नकारात्मक भूमिका में नजर आईं। दैनिक जागरण से बातचीत में नेहा कहती हैं, 'मैंने अभी तक सिर्फ दो ही वेब सीरीज में काम किया है, एक ये और दूसरी इल्लीगल। 36 डेज में मैंने पहली बार निगेटिव भूमिका निभाई। मेरे लिए निगेटिव भूमिका निभाना काफी मजेदार था। मेरी कोशिश तो हमेशा कुछ अलग करने की रहती है, लेकिन शायद मेरी शक्ल देखकर फिल्मकार मुझे हारर और निगेटिव भूमिकाओं में नहीं देखते हैं।'

जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है

साल 2010 में फिल्म क्रूक से हिंदी सिनेमा में पदार्पण करने वाली नेहा अपने पेशेवर सफर को लेकर कहती हैं, 'मैंने जब से शुरुआत की है, तब से अब तक सिर्फ एक चीज वैसी की वैसी रही है, वो है दर्शकों का प्यार। तभी आप इंडस्ट्री में इतने लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। जिंदगी में अनुशासन होना बहुत जरूरी है, जो मेरे अंदर शुरू से है। मुझे समय की पाबंदी पसंद है। जब आप इंडस्ट्री में नए होते हैं, तो सफलता व असफलता से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं या फिर जब आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती है, तो आपके आस-पास के लोग बदल जाते हैं। इससे आपका व्यवहार भी बदल जाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ।'

देसी भूमिका की लालच

नेहा मूलत: भागलपुर से आती हैं, हालांकि उन्हें कभी उत्तर भारतीय पृष्ठभूमि से जुड़ी या किसी देसी लड़की की भूमिका निभाने का मौका नहीं मिला। वह कहती हैं, 'मैं हमेशा सोचती हूं कि ऐसी भूमिका मिलनी चाहिए। मैं उत्तर भारतीय भाषा व एक्शन आसानी से पकड़ लूंगी लेकिन अभी तक भाग्य का साथ नहीं दिया है।'

बहन की मेहनत के लड्डू

नेहा के अनुसार, पहले वह पीआर गेम (अपने प्रचार प्रसार) में होशियार नहीं थी। अब उनके और उनकी बहन के वीडियो अक्सर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होते रहते हैं। वह कहती हैं, 'पहले मेरा पीआर गेम बहुत बुरा था। फिर मेरी बहन आयशा शर्मा ने मेरे लिए एक पीआर एजेंसी खोजकर उसे मेरे प्रचार का काम दिया है। मेहनत सारी वही (आयशा) करती हैं मैं सिर्फ लड्डू खाती हूं।'

नेहा की बहन आयशा शर्मा

एक्शन की तैयारी

हालिया प्रदर्शित विक्की कौशल अभिनीत फिल्म बैड न्यूज में मेहमान भूमिका में नजर आई नेहा अब एक्शन फिल्म करने जा रही हैं। वह बताती हैं, 'बैड न्यूज में मेहमान भूमिका के बाद मेरी एक बड़ी अच्छी एक्शन फिल्म को लेकर बात चल रही है। मैंने इससे पहले कभी कोई एक्शन फिल्म नहीं की है। पहली बार एक्शन करने को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं। अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है।'

« एक्शन फिल्म करने की तैयारी में हैं नेहा ● मिडडे आर्काइव

शाह रुख के साथ काम करना है

किसी चीज को दिल से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। शाह रुख खान के इस डायलाग पर किल फिल्म से सराहना बटोर चुके अभिनेता राघव जुयाल भी यकीन रखते हैं। वह इस बात को ब्रह्मांड में फैलाना चाहते हैं कि उन्हें शाह रुख खान के साथ काम करने का मौका मिले। दरअसल, राघव को लेकर पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि वह शाह रुख के साथ काम कर सकते हैं। अब राघव ने इस पर बात की है। मुंबई में बुधवार को अपनी नई वेब सीरीज ग्यारह ग्यारह के ट्रेलर लांच पर राघव ने कहा, 'फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं उनके साथ काम करना चाहता हूं। अब बात छिड़ ही गई है, तो यूनिवर्स तक जाएगी और कुछ न कुछ शायद हो जाएगा।' ग्यारह ग्यारह सीरीज अतीत को वर्तमान से जोड़ेगा, जहां पिछली सदी के नौवें दशक का एक पुलिस अफसर वर्तमान के अफसर से जुड़ेगा। राघव अतीत के बारे में ज्यादा सोचते हैं या वर्तमान में रहते हैं? इस पर वह कहते हैं, 'मैं अतीत या भविष्य में यकीन नहीं करता। मैं इस पल में रहने वाला इंसान हूं। मुझे अपने जीवन में कुछ नहीं बदलना है। जो चल रहा है, जो हुआ है, उसी कारण आज यहां पर हूं।' यह सीरीज नौ अगस्त को जी5 पर रिलीज होगी।

ग्यारह ग्यारह में पुलिस अफसर बनेंगे राघव ● @raghavjuyal

आपरेशन खुकरी पर फिल्म बनाएंगे अमित

फिल्मकार अमित शर्मा ने अपनी पिछली फिल्म मैदान में भारतीय फुटबाल टीम के पूर्व मैनेजर और कोच सैयद अब्दुल रहीम की जिंदगानी दिखाई थी। अब उनकी अगली फिल्म साल 2000 में भारतीय सेना द्वारा अफ्रीकी देश सिएरा लिओन में अंजाम दिए गए आपरेशन खुकरी पर आधारित होगी। जुलाई, 2000 में एक भारतीय कमांडर के नेतृत्व में भारत सहित कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत सिएरा लियोन में अपनी सेनाएं भेजी थी। वहां भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया गया गया था। इसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न अंगों ने मिलकर आपरेशन खुकरी नामक बचाव मिशन को अंजाम दिया था। फिल्म केसरी के लेखक गिरीश कोहली फिल्म की पटकथा लिखने में जुटे हैं। इस फिल्म को लेकर अमित कहते हैं, 'इस कहानी और इसकी भव्यता को न्यायसंगत तरीके से दिखाना मुश्किल होगा। सबसे बड़ी चुनौती इस मिशन को वास्तविकता के करीब रखते हुए बड़े स्तर पर दिखाने की होगी।' अभी तक इस फिल्म के नाम या इसके कलाकारों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

युद्ध के दृश्यों को भव्यता के साथ दिखाना चाहते हैं अमित ● @iamitrsharma (इंस्टाग्राम)

****

बैंकाक से लौटी भगवान श्रीकृष्ण की कालिया मर्दन की 10वीं-11वीं सदी की मूर्ति

वी के शुक्ला ● जागरण

नई दिल्ली: भगवान श्रीकृष्ण की कालिया मर्दन प्रसंग की एक मूर्ति बैंकाक से वापस आई है। भारत मंडपम में धरोहर समिति की बैठक में चल रही बैठक के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी में इसे पहली बार सामने रखा गया है। कालिया मर्दन की यह मूर्ति 10वीं-11वीं सदी की है। दुनिया भर से यहां आए धरोहर प्रेमी मूर्ति की तारीफ कर रहे हैं।

खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इन मूर्तियों को वापस लाए जाने की प्रशंसा की है। मूर्ति में कालिया नाग के फन पर भगवान श्रीकृष्ण को नृत्य करते दिखाया गया है।

पुरातत्वविदों का कहना है कि जिस दौर की मूर्ति है, इस समय में दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य था। उस समय यह कला का धनी क्षेत्र था, चोल बहुत शक्तिशाली राजा थे और हिंदू धर्म को उन्होंने दूसरे देशों तक फैलाया था। भारत के अलावा आसपास के देशों में भी उनका प्रभाव था।

बताया जा रहा है कि मूर्ति तस्करी से बैंकाक के रास्ते अमेरिका भेजी जा रही थी। अमेरिका की जांच एजेंसी ने इस मूर्ति को पकड़ा था। मूर्ति को ले जा रहे व्यक्ति ने तब बताया कि अगर मूर्ति चोरी की है तो वह उसे वापस कर देगा। जांच में मूर्ति चोरी की बात साबित हुई इस पर उस व्यक्ति ने मूर्ति जांच एजेंसी को सौंप दी। यह मूर्ति तमिलनाडु से चुराई गई थी, जिसे कुछ समय पहले ही भारत वापस लाया गया है।

भारत मंडपम में दूसरे देशों से वापस लाए गए प्रमुख पुरावशेषों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शित किए गए 25 पुरावशेष में से अधिकतर मूर्तियां हैं। ये पुरावशेष कभी चोरी कर दूसरे देशों में करोड़ों रुपये में बेच दिए गए थे। वर्ष 2011 में पकड़े गए, अंतरराष्ट्रीय मूर्ति तस्कर सुभाष कपूर के जेल जाने के बाद से इन मूर्तियों के बारे में जानकारी मिली थी। उसके बाद 2015 से चोरी गई मूर्तियों के वापस आने का सिलसिला तेज हुआ है और तब से अब तक करीब 350 मूर्तियां वापस आ चुकी हैं। इसमें अधिकतर अमेरिका से वापस आई हैं।

- तमिलनाडु से चुराई गई थी मूर्ति, जिसे कुछ समय पहले ही भारत वापस लाया गया है
- वर्ष 2011 में पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय मूर्ति तस्कर के जेल जाने के बाद से जानकारी मिली थी

इन धरोहरों को भारत मंडपम में किया गया है कि प्रदर्शित

- भारत मंडपम में प्रदर्शित मानव आकृति 2000 साल पुरानी है, जो 2021 में अमेरिका से वापस आई थी
- 13 वीं सदी की नृत्य करती महिला की प्रतिमा,
- नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति
- 2015 में कनाडा से वापस आई 11वीं सदी की पैरट लेडी की प्रतिमा को खजुराहो से चोरी किया गया था
- 17वीं सदी की तलवार और म्यान
- अल्मोड़ा से चुराई गई 10वीं-11वीं सदी की महिषासुरमर्दनी की मूर्ति 2018 में अमेरिका से वापस आई है।
- उत्तर प्रदेश के भीतरगांव की गण की प्रतिमा को 1991 में अमेरिका से लाया गया था।
- कई फीट लंबा भिक्षुओं का विचित्र निमंत्रण पत्र है जिसे 2022 में आस्ट्रेलिया से वापस लाया गया था

श्रीकृष्ण की कालिया मर्दन मूर्ति ● जागरण

श्रद्धा का महासावन

भगवान शिव ही हैं सृष्टि के पालक व संहारक

शिव के बिना विश्व कल्पना की कल्पना तक नहीं की सकती है। शिव ही इस सृष्टि के पालक हैं और शिव ही संहारक भी हैं। ब्रह्माजी को सृष्टि का रचयिता, श्रीविष्णु को पालक और भगवान शिव को संहारक माना गया है लेकिन मूलतः शक्ति तो एक ही है, जो तीन अलग-अलग रूपों में अलग-अलग कार्य करती है। वह मूल शक्ति शिव ही हैं। 'स्कंद पुराण' के केदारखंड में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु व शंकर की उत्पत्ति महेश्वर अंश से ही होती है। सृष्टि का आदि कारण शिव हैं। शिव ही ब्रह्म हैं। शिव पूजा के रूप में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिव पुराण, लिंगपुराण व स्कंद पुराण में लिंगोत्पति का विस्तार से वर्णन है। 'स्कंद पुराण' में कहा गया है कि वर्तमान श्वेत वराह कल्प से जब देवताओं की सृष्टि समाप्त हो गई, पशु पक्षी, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व सब सूर्य के ताप से भस्म हो गए, सारी सृष्टि जलमग्न हो गई, चारों दिशाओं में अंधकार छा गया, तब भी अनादि तत्व के रूप में शिव ही दृश्यमान थे। शिव ही कारण हैं सृष्टि, स्थिति और प्रलय का। शिव का ही स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में है और इस ज्योतिर्लिंग में ही सब कुछ समाहित है। पूरा ब्रह्मांड शिव का ही साकार स्वरूप है। श्रावण मास शिव को अत्यंत प्रिय है। इस माह भगवान शिव की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक विशेष फलदायी होता है।

रावल भीमाशंकर लिंग, श्री केदारनाथ धाम

खंभों पर तारों का मकड़जाल, बढ़ा खतरा

दिल्ली के दक्षिणी इलाकों की पाश कालोनियों में बना रहता है करंट फैलने का भय

जागरण पड़ताल

मोहम्मद साकिब ● जागरण

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में प्राइवेट केबल टीवी और इंटरनेट का जाल फैला हुआ है। दिल्ली के पाश इलाकों में भी कालोनियों में लगे खंभों से निकलता तारों का मकड़जाल लोगों के लिए खतरा बना है। इन तारों के कटने और बिजली के तारों के संपर्क में आने से करंट लगने का खतरा रहता है। बीते सोमवार को प्रशासन की लापरवाही से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस ये पता नहीं कर पाई है कि आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। बुधवार को दैनिक जागरण द्वारा दिल्ली के दक्षिणी इलाकों की कालोनियों में लगे बिजली खंभों की पड़ताल की गई, जिसमें देखा गया कि अधिकतर खंभों की हालत खतरनाक स्थिति में हैं। इनमें तारों का मकड़जाल बना हुआ है और तार टूटकर लटके हुए हैं।

लाइब्रेरी के बाहर मौत बनकर खड़ा खंभा: करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास ब्राइट लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में अभ्यर्थियों का दिन भर आना जाना रहता है। इसके बाहर ही एक बिजली का खंभा है। कई केबल बाहर लटके हुए हैं तो कई बिजली के बाक्स भी टूटे हैं। खंभे पर केबल टीवी और इंटरनेट के सैकड़ों तार लटक रहे हैं। ऐसे में यहां वर्षा के दौरान करंट फैलने का खतरा हर वक्त बना रहता है।

घरों के ऊपर से निकल रहे जानलेवा तार: राजेंद्र प्लेस वो इलाका है, जहां अधिकतर पीजी व कोचिंग संस्थान हैं। यहां की हालत भी कम डराने वाली नहीं है। मेट्रो स्टेशन के पास बनी कालोनी में आफिस व घर बने हुए हैं। तारों के मकड़जाल से कई खंभे झुके हुए हैं। इनमें स्थिति इतनी जर्जर है कि ये कभी भी गिर सकता है। इस खंभे से जाने वाले तार घरों व आफिसों के ऊपर से जा रहे हैं। कुछ तार टूटकर लटक रहे हैं। इंटरनेट माफिया व केबल टीवी आपरेटर ने इन खंभों पर बेतरतीब कब्जा कर तार डाले हुए हैं, जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं।

पाश कालोनियों में भी बदतर स्थिति: पूर्वी पटेल नगर में बनी कालोनियां दिल्ली की पाश कालोनियों में गिनी जाती हैं। यदि अव्यवस्था की बात करें तो यहां भी प्रशासन की लापरवाही देखी जा सकती है। यहां कालोनी में खड़े अधिकतर खंभे अपनी बदहाली खुद बयां कर रहे हैं। खंभों पर अवैध रूप से इंटरनेट के तार डाले हुए हैं। इससे यहां मकड़जाल बना हुआ है। वहीं कई खंभों पर लगे बक्से टूटे हुए हैं। करंट उतरने की संभावना बनी रहती है।

राजेंद्र नगर में बिजली के खंभों पर लटके केबल व इंटरनेट के तार ● ध्रुव कुमार

खंभे की सफाई का चलाया जाता है अभियान

टाटा पावर-डीडीएल के एक प्रवक्ता ने कहा टाटा पावर-डीडीएल ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर बिजली के खंभों पर अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने के लिए नियमित निगरानी और खंभों की सफाई कराई जाती है। कंपनी स्थानीय आरडब्ल्यूए/मार्केट एसोसिएशनों से सहयोग चाहती है कि वह स्थानीय आपरेटरों को इंटरनेट या केबल टीवी के लिए उनके संचालन को फिर से शुरू करने से सख्ती से रोक सकें।

खंभों पर झूले इन तारों को देखकर डर लगता है। कई बार प्रशासन से समस्या की शिकायत कर चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती। कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। -बब्लू, किराना विक्रेता, करोल बाग

बिजलीकर्मी जब भी कालोनी में आते हैं, उनको ये समस्या बताई जाती है पर वह खानपूर्ति करके चले जाते हैं। ये तार घरों के ऊपर से गुजर रहे हैं। बरसात में तो डर और भी बढ़ जाता है। -ममता, कालोनीवासी, राजेंद्र प्लेस

कालोनी में तारों को बेतरतीब तरीके से डाला जा रहा है, जिससे खंभों पर लोड बढ़ रहा है। कई खंभे झुक भी गए हैं। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। -केतन, अभ्यर्थी

सीसीटीवी फुटेज खंगाली, बिजली वितरण कंपनियों से किया संपर्क

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली के पटेल नगर में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे नीलेश राय की करंट लगने से मौत के मामले में पुलिस घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बिजली वितरण कंपनियों से संपर्क कर रही है, ताकि करंट उतरने की वजह को समझा जा सके।

यूपी के गाजीपुर निवासी नीलेश राय की मौत के दो दिन बाद टाटा पावर डिस्काम के एक अधिकारी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह घटना क्षतिग्रस्त मोटर वायरिंग से करंट उतरने की वजह से हुआ है। वायरिंग लोहे के गेट के संपर्क में आ गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि नीलेश पास की लाइब्रेरी से जलभराव के बीच अपने पीजी में जा रहा था, तभी पैर फिसलने से उसने लोहे का गेट छू लिया, जिसमें करंट उतरा हुआ था। करंट लगने से उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि हम बिजली वितरण कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम टाटा पावर डिस्काम से भी पूछताछ करेंगे। टाटा पावर डिस्काम के अधिकारी ने कहा कि हम ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी ने लोगों से मानसून के मौसम में सतर्क रहने, जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने जैसे सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।

नीलेश की मौत के मामले में आतिशी ने जारी किए आदेश

जासं, नई दिल्ली: दिल्ली के पटेल नगर इलाके में यूपीएससी अभ्यर्थी नीलेश राय की करंट लगने से मौत के मामले में दिल्ली सरकार में बिजली मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को आदेश दिया है कि वह इस मामले की जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक रिपोर्ट शुक्रवार 26 जुलाई तक भेजी जाए। वह यह भी पता लगवाएं कि आखिर इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? मंत्री ने पीड़ित को मुआवजा देने का भी आदेश जारी किया है।

स्वजन के लिए की एक करोड़ के मुआवजे की मांग: यादव

राब्यू, जागरण ● नई दिल्ली: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पटेल नगर में नीलेश राय की करंट लगने से हुई मौत के लिए सीधे तौर पर आप सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना नहीं है, बल्कि सरकारी सिस्टम की नाकामी है। कांग्रेस मांग करती है कि नीलेश के परिवार को एक करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए। यादव ने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा निजी बिजली कंपनियों को बेलगाम दर वसूलने की इजाजत तो दे रखी है, लेकिन बिजली से सुरक्षा के लिए इंतजाम के लिए कोई दिशा निर्देश नही दिए हैं।

विविध गतिविधियां

कांवड़ियों को न हो कोई समस्या : आतिशी

राब्यू, जागरण ● नई दिल्ली: कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए राजस्व मंत्री आतिशी ने बुधवार को कश्मीरी गेट स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क के कांवड़ शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन अलर्ट पर रहे जिससे कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही शिविर में कांवड़ियों को हर जरूरी सुविधाएं मिलें। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए हर कदम सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा विकास समिति के चेयरमैन कमल बंसल व सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे। कश्मीरी गेट स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क में कांवड़ शिविर देश के सबसे बड़े कांवड़ शिविरों में से एक है, जहां एक समय में लगभग 20,000 कांवड़ियों के रुकने का इंतजाम किया जा सकता है। यहां महिला-पुरुष कांवड़ियों के विश्राम के लिए अलग-अलग हाल व कांवड़ियों के प्रसाद ग्रहण करने के लिए एक बड़ा डाइनिंग हाल भी तैयार किया गया है। दिल्ली सरकार कांवड़ियों के लिए 185 स्थानों पर शिविर लगा रही है।

कांवड़ शिविरों की व्यवस्था नहीं हुई : भाजपा

राब्यू, जागरण ● नई दिल्ली: भाजपा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने कांवड़ शिविर व्यवस्था को राजनीति का अखाड़ा बना लिया है। बृहस्पतिवार से कांवड़ यात्री दिल्ली पहुंचने लगेंगे, लेकिन इनके स्वागत की तैयारी नहीं हुई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, कांवड़ शिविरों की व्यवस्था एक माह पहले शुरू हो जाती है। आम आदमी पार्टी की लापरवाही के चलते श्रावण माह प्रारंभ होने के बाद भी अधिकांश कांवड़ शिविरों में टेंट नही लगे हैं। कई शिविरों में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। अब तक मुश्किल से एक सौ शिविर आयोजकों तक सरकारी सहायता पहुंची है। दिल्ली सरकार की मंत्री 185 शिविर स्थापित किए जाने की बात कर रही हैं, परंतु सच्चाई यह है कि इनमें से 150 से अधिक अभी भी तैयार नहीं हैं।

चांदनी चौक के विकास की हुई अनदेखी : मुदित

जासं, नई दिल्ली: दिल्ली कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने चांदनी चौक के विकास की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके कारण पूरा इलाका समस्याओं से घिरा है। वह चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र स्थित पटौदी हाउस में विवादित पंप हाउस का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक प्रह्लाद सिंह साहनी के खास आदमियों ने फुटपाथ पर कब्जा कर कमरा बना लिया है। उन्हें स्थानीय लोगों ने बताया कि यह कमरा किराये पर दिया गया है। उधर, प्रह्लाद सिंह साहनी ने कांग्रेस पार्टी के नेता के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि पूरा काम दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार हो रहा है, वहां नया ट्यूबवेल लगाने को कमरों का निर्माण किया जा रहा है। वे मुदित के विरुद्ध वह मानहानि का केस करेंगे।

मुदित अग्रवाल ●

एकजुट होकर काम करें कार्यकर्ता : देवेंद्र यादव

राब्यू, जागरण ● नई दिल्ली: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अल्पसंख्यक विभाग की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए बुकहा कि संगठन को मजबूत करने लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें। कहा कि कांग्रेस शुरू से ही गरीब, मध्यम वर्ग, पिछड़ा, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग, मजदूर, रेहड़ी पटरी, खोमचा वाले, युवा और महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ती आ रही है। पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश कांग्रेस जल्द ही संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए 258 ब्लाक कांग्रेस कमेटियों का विस्तार कर प्रत्येक ब्लाक को दो मंडलों में विभाजित करने की घोषणा कर देगी। मंडल बनाने के साथ-साथ मंडलों को सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी पांच से सात बूथ का एक सेक्टर भी बनाने जा रही है। राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हमें मजबूती के साथ तैयार होना पड़ेगा। बैठक में प्रदेश कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी शहनवाज शेख, अब्दुल वाहिद कुरेशी आदि रहे।

'लोगों को सही माप व अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराए विभाग'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली: खाद्य-आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने बुधवार को कंट्रोलर, विधिक माप विभाग एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ माप-तौल विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि आने वाले त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लोगों को कमोडिटी नियमों का पालन कराते हुए सही वजन के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले पैक्ड उत्पाद उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री ने कंट्रोलर माप-तौल विभाग को निर्देशित किया कि बाजार की दुकानों, पेट्रोल पंपों, गैस सिलेंडर, सीएनजी एजेंसियों आदि का नियमित निरीक्षण किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके माप-तौल वाली इकाइयों पर वैध सत्यापन मुहर लगी हो।

इमरान हुसैन ●

लाजपत नगर बम विस्फोट मामले में आरोपित को जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने वर्ष 1996 के लाजपत नगर बम विस्फोट मामले में एक आरोपित को नियमित जमानत दे दी है। आरोपी को विस्फोट की घटना के 28 साल बाद गिरफ्तार किया गया था। उसे 19 फरवरी, 1997 को भगोड़ा घोषित किया गया था और नौ जुलाई, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने मेहराजुद्दीन भट्ट उर्फ जुबेर को जमानत दे दी। अदालत ने उस पर जमानत की कई शर्तें भी लगाई हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपित अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि फरीदा डार उर्फ बहनजी और लतीफ अहमद बाजा नामक दो सह-आरोपितों से पूछताछ में कोई भी आपत्तिजनक बात रिकार्ड में नहीं आई है।

कोर्ट ने जमानत की कई शर्तें भी लगाई हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि आरोपित अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा

अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि आठ अप्रैल, 2010 को सह-आरोपित फरीदा डार को साजिश के आरोप से बरी कर दिया गया था और सह-आरोपित लतीफ अहमद बाजा को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

मेहराजुद्दीन की ओर से पेश अधिवक्ता कार्तिक वेणु ने दलील दी कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और उसके भागने का खतरा नहीं है। अधिवक्ता ने कहा कि उनका मुवक्किल वर्ष 1989 से इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नटिपोरा का स्थायी कर्मचारी है। यह भी दलील दी कि उस पर साजिश का हिस्सा होने का आरोप है। आरोपित जांच में बाधा डालने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सभी साक्ष्य दस्तावेजी हैं। इस मामले में पहले लाजपत नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में जांच स्पेशल सेल को सौंप दी गई। इस मामले में 17 आरोपितों में से चार को दोषी करार दिया गया, छह को बरी कर दिया गया, छह को भगोड़ा घोषित किया गया और एक आरोपी की मौत हो चुकी है।

21 मई, 1996 को लाजपत नगर मार्केट में एक शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ था, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।

... मतलब, अध्यक्ष जी आए हुए हैं!

दांव पेच

संजीव गुप्ता

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अगर कुछ रौनक नजर आए तो समझ लीजिए अध्यक्ष जी आए हुए हैं। अगर वीराना हो तो अंदाजा लगा लीजिए कि अध्यक्ष जी नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही नजारा राजीव भवन में आए दिन देखने को मिल जाता है। कई बार तो लगता ही नहीं कि छह माह के भीतर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। होना तो यह चाहिए कि अध्यक्ष जी के न होने पर भी उनकी बनाई हुई व्यवस्था के तहत सभी नेता और कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते नजर आएं। लेकिन ज्यादातर नेता दिन भर पार्टी कार्यालय के स्टाफ को फोन मिलाकर यही पूछते रहते हैं कि अध्यक्ष जी आए हैं क्या? या अध्यक्ष जी आ रहे हैं क्या? मानो पार्टी के लिए काम करने से अधिक जरूरी अध्यक्ष जी को चेहरा दिखाना अथवा उनकी निगाह में नंबर बनाना है। जानकारों की सलाह तो यही है कि अब नंबर गेम छोड़कर चुनावी तैयारी में जुट जाना चाहिए।

पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चांदनी चौक क्षेत्र का दौरा करते पूर्व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ● सौजन्यः कांग्रेस

अध्यक्ष या प्रभारी!

दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव इस समय दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो हैं ही, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, लेकिन चर्चा चल रही है कि जल्द ही कांग्रेस विभिन्न राज्यों के प्रभारी बदलने वाली हैं। ऐसे में, संभव है कि पंजाब कांग्रेस का प्रभार भी यादव से लेकर किसी और को दे दिया जाए। लंबे समय तक एक साथ दो दो जिम्मेदारी संभालने में दिक्कत हो सकती है। फिर उनकी जरूरत दिल्ली में ज्यादा बताई जा रही है। यहां विधानसभा चुनाव सिर पर हैं जबकि पंजाब में विधानसभा चुनाव अभी काफी दूर हैं। हालांकि कुछ नेता कयास भी लगा रहे हैं कि यादव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे या फिर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी। इस कयास के पीछे एक वजह यह भी है कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस में अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि पंजाब की जिम्मेदारी किसी और को देकर उन्हें दिल्ली का ही पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाएगा।

नाम तय नहीं, सक्रिय हुए नेताजी

दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस किस- किस टिकटार्थी को प्रत्याशी बनाएगी, अभी तय नहीं है। किंतु बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशी सक्रिय हो गए हैं। न केवल जनता के बीच पहुंच रहे हैं बल्कि अलग -अलग मुद्दों को भी उठा रहे हैं। मसलन, चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल की सक्रियता बढ़ गई है। पिछले दिनों खैबर पास क्षेत्र में डीडीए का बुलडोजर चला तो वहां भी वह पीड़ितों के बीच नजर आए तो दो दिन पूर्व वह चांदनी चौक में विकास की अनदेखी को लेकर आप विधायक प्रहलाद सिंह साहनी के खिलाफ बयान देते दिखाई पड़े। इसी तरह मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व पार्षद जितेंद्र कोचर भी सक्रिय हो रहे हैं। कुछ नेता अध्यक्ष की परिक्रमा कर टिकट पक्का कराने में लगे हुए हैं। दिलचस्प होगा कि समय आने पर प्रत्याशियों की सूची में किस किस का नाम शामिल रहता है।

भुलाए नहीं भूल रहे अरविंदर सिंह लवली

अरविंदर सिंह लवली को कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए करीब तीन महीने होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेसी अभी भी उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। आलम यह है कि जब भी दो चार कांग्रेसियों के बीच चर्चा चलती है तो उनकी जुबां पर अरविंदर सिंह लवली का नाम आ ही जाता है। अधिकांश नेता कहते हैं, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी पार्टी की मजबूती के लिए खासी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो उत्साह लवली के वक्त नजर आ रहा था, फिलहाल उसमें कुछ कमी देखी जा रही है। पहले पार्टी कार्यालय में रौनक मेला भी लगा रहता था, लेकिन अब वह बात नहीं दिखाई दे रही। हालांकि ऐसा कहने वाले नेता बाद में यह उम्मीद भी जताने लगते हैं कि चुनाव की बेला आने तक यादव भी पार्टी की स्थिति बेहतर बनाने के साथ साथ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ लेंगे।

मस्जिद को हटाने के खिलाफ आपत्तियों पर होगा विचार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ जनता की आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। एनडीएमसी ने मस्जिद के इमाम की याचिका पर जवाब दाखिल किया। इमाम अब्दुल अजीज ने 24 दिसंबर 2023 को जारी एनडीएमसी के सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी है। इसमें जनता से मस्जिद को हटाने पर आपत्तियां या सुझाव देने को कहा गया था। न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।

- अदालत ने याचिकाकर्ता और एनडीएमसी का पक्ष सुनने के बाद याचिका का निपटारा किया
- इमाम ने याचिका दायर कर सुनहरी मस्जिद के ध्वस्तीकरण की तैयारी का किया था विरोध

नई दिल्ली स्थित सुनहरी बाग मस्जिद

हाई कोर्ट ने आम जनता से धार्मिक ढांचे को हटाने के संबंध में आपत्तियां/सुझाव देने को कहा और अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के बयान को रिकार्ड पर लिया कि जनता की आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष दावा किया कि सार्वजनिक नोटिस कानून के अनुसार जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों को कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है तो वह याचिका वापस ले लेंगे।

इस पर पीठ ने कहा कि इस स्तर पर अदालत कोई आदेशात्मक निर्देश पारित नहीं करेगी। पीठ ने कहा कि अदालत अतिरिक्त सालिसिटर जनरल के बयान को रिकार्ड पर लेती है कि आपत्तियों पर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने कहा कि मस्जिद हटाने के मुद्दे पर हेरिटेज कमेटी के फैसले का अभी भी इंतजार है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस स्तर पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है और संबंधित अधिकारी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के खिलाफ उसकी याचिका से सहमत हो सकते हैं और याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी। यातायात पुलिस ने फरवरी में अदालत को बताया था कि सुनहरी बाग मस्जिद के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण का मुद्दा इसकी सिफारिश के लिए विरासत संरक्षण समिति (एचसीसी) को भेजा गया था। एनडीएमसी के पूर्व में कहा था कि कार्रवाई पर अंतिम फैसला एचसीसी को लेना है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि मस्जिद 150 साल से अधिक पुरानी है और सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत है।

पंचकूला में नौकरी करते हुए जेएनयू में पीएचडी की नहीं मिली छूट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद के फैसले को बरकरार रख दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा और अनुसंधान कार्य में शैक्षणिक अनुशासन देश के लिए महत्वपूर्ण है और नामांकन नियमों का उल्लंघन कर ऐसा करना छात्र के लिए सुविधा का विषय नहीं हो सकता है। पीएचडी छात्र की याचिका को खारिज कर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि संस्थानों का मतलब व्यक्ति पैदा करने वाली मशीनें न होकर लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ होने के नाते राष्ट्र के भविष्य निर्माण को छात्रों को उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद करना है।

अदालत ने कहा कि इसके लिए विश्वविद्यालयों और उसके छात्रों दोनों द्वारा अध्ययन और शोध कार्य के उच्च स्तर पर भी शैक्षणिक अनुशासन और मानकों को बनाए रखना देश के लिए महत्वपूर्ण है।

- हाई कोर्ट ने कहा, उच्च शिक्षा व अनुसंधान कार्य में शैक्षणिक अनुशासन बेहद महत्वपूर्ण
- जेएनयू की अकादमिक परिषद के फैसले को बरकरार रखते हुए अदालत ने की टिप्पणी

अदालत ने जेएनयू अकादमिक परिषद के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एक पीएचडी छात्र का पंजीकरण रद करने और उसे बाद के चरण में अपनी नौकरी के साथ-साथ डाक्टरेट की पढ़ाई फिर से शुरू करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। जेएनयू ने तर्क दिया कि अध्यादेश के तहत एक उम्मीदवार के लिए दिल्ली में रहते हुए न्यूनतम दो साल का निवास पूरा करना अनिवार्य है, लेकिन याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और इस अवधि में पंचकूला में हरियाणा सरकार के एक विभाग में सहायक वैज्ञानिक के रूप में नौकरी ले ली।

****

क्या आप मानते हैं कि एनसीआर के सरकारी अस्पतालों में होने वाले अपराध के लिए बदहाल सुरक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है? 92% हां, 8% नहीं

क्या एनसीआर के सरकारी अस्पतालों में अपराध होने पर सीधे प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए? 99% हां, 1% नहीं

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया muddad@jagran.com पर भेज सकते हैं।

अस्पताल में सुरक्षा का पोस्टमार्टम

अस्पताल में हत्या। वो भी हमलावर किसी और के धोखे में किसी अन्य मरीज की हत्या कर गए। यह घटना राजधानी के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था का पोस्टमार्टम करने के लिए काफी है। देखा जाए तो अस्पताल चाहे किसी भी शहर के हों, वहां की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा कठघरे में रहती है। एनसीआर के सरकारी अस्पतालों में पूर्व में भी मरीजों के तीमारदारों द्वारा डाक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट और गाली-गलौज की घटनाएं सामने आती रही हैं। घटना के कुछ दिन तक डाक्टर व स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल करते हैं। विरोध जताते हैं। कथित आश्वासन के बाद सब शांत हो जाते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने पर काम नहीं किया जाता है। एनसीआर के निजी अस्पतालों की बात करें तो वहां सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी ऐसी होती है कि हथियार के साथ अपराधी का घुसना तो दूर, मरीज के स्वजन भी अस्पताल के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। सरकारी अस्पतालों में आपसी अहम टकराव के कारण व्यवस्था चौपट रहती है। सवाल है कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं हो पाते, यह किसकी है लापरवाही, जिम्मेदारों के खिलाफ क्यों नहीं होती कार्रवाई, इसी की पड़ताल करना हमारा आज का मुद्दा है :

सुरक्षा में खामियां

- किसी सरकारी अस्पताल के गेट पर मेटल डिटेक्टर नहीं लगे होते हैं।
- निजी सुरक्षा गार्ड भी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते।
- सरकारी अस्पतालों में कई ब्लाक होने से प्रवेश व निकास के लिए कई गेट होते हैं जिससे व्यवस्था प्रभावित होती है।
- निजी अस्पतालों में गार्ड सख्त होते हैं, बगैर पास के वार्ड में किसी भी व्यक्ति का अवैध प्रवेश मुश्किल, ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में ऐसी सख्ती नहीं दिखती।

अस्पतालों में तीन स्तरीय सुरक्षा मानदंड जरूरी

डा. अजय लेखी
पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली मेडिकल काउंसिल

दिल्ली के बड़े अस्पतालों में शामिल जीटीबी अस्पताल के वार्ड में घुसकर मरीज को गोली मारने की घटना बेहद चिंताजनक है। सरकारी अस्पतालों में पहले भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर डाक्टरों से मारपीट व तोड़फोड़ की घटनाएं होती रही हैं। इसके मद्देनजर डाक्टर लंबे समय से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने की आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। हाल ही में हुई घटना के बाद ये आवाज एक फिर उठी है। अस्पतालों में दोबारा ऐसी घटनाएं न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होना जरूरी है। साथ ही अस्पतालों में नियुक्त होने वाले निजी सुरक्षा गार्डों के लिए मानदंड व योग्यता तय की जानी चाहिए, तभी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो पाएगी।

एक समय ऐसा था जब अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था के खास बंदोबस्त नहीं किए जाते ते। तब डाक्टर, नर्स व पैरामेडिकल कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं अधिक हुआ करती थीं। इसके मद्देनजर अस्पतालों में निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए। इसके बाद अस्पतालों में मारपीट की घटनाएं कुछ कम हुईं, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुईं। अब भी सरकारी अस्पतालों में मारपीट की घटनाएं अक्सर ही सामने आती हैं। इमरजेंसी व गायनी इमरजेंसी में मारपीट की घटनाएं अधिक होती हैं। जीटीबी, एलबीएस अस्पताल में पहले भी इस तरह की आपराधिक घटना हुई थी। सरकारी अस्पतालों में तैनात सुरक्षा गार्ड सिर्फ दिखावटी बनकर रह गए हैं। निजी सुरक्षा गार्डों की तैनाती में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक-दो एजेंसियां ही नाम बदल-बदलकर सेवाएं दे रही होती हैं। निजी सुरक्षा गार्डों की कद काठी, अधिकतम उम्र, शैक्षणिक योग्यता व काम के घंटे का निजी सुरक्षा एजेंसियां ध्यान नहीं रखतीं। अस्पताल प्रशासन भी इस तरफ ध्यान नहीं देता।

इस वजह से कई अस्पतालों में बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड ड्यूटी करते देखे जाते हैं। ओवर टाइम के लिए गार्ड 16 से 18 घंटे ड्यूटी करते हैं। कई बार तो लगातार 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। ऐसी स्थिति में गार्डों की सक्रियता ठीक नहीं रहती। वे सिर्फ नाम के लिए ड्यूटी पर होते हैं। किसी से कोई पूछताछ नहीं करता। मरीज से मिलने के लिए एक साथ कई स्वजन पहुंच जाते हैं, फिर भी वे नहीं रोकते। इससे अस्पताल में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को तो खतरा होता ही है। यही वजह है कि अस्पताल में हथियार लेकर बदमाश घुस गए और किसी को पता नहीं चल सका।

सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। एम्स की ओपीडी में प्रतिदिन करीब 13 हजार, सफदरजंग में करीब दस हजार, आरएमएल में करीब आठ हजार, लोकनायक, जीटीबी, जीबी पंत, डीडीयू सहित दिल्ली के कई अन्य सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। अस्पतालों में हजार से कहीं अधिक स्वास्थ्य कर्मी मौजूद होते हैं। इसके मद्देनजर जीटीबी अस्पताल की घटना से सबक लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाना चाहिए। अस्पतालों में निजी सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति के लिए एक मानक तय होने चाहिए। इसी के अनुरूप अस्पताल में सभी प्रवेश गेट, इमरजेंसी, ओपीडी, आइपीडी वार्ड इत्यादि महत्वपूर्ण जगहों पर निजी गार्ड तैनात किए जाने चाहिए। यदि सुरक्षा में कोई खामी आती है तो इसके लिए निजी सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इमरजेंसी वार्ड के पास गेट पर बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए जाने चाहिए। वार्ड में गेट के पास सुरक्षा जांच के लिए सुरक्षा गार्ड हैंड हेल्थ मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी में 24 घंटे पुलिस के दो से तीन जवान तैनात रहने चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की निगरान के लिए पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए।

अस्पतालों में मरीजों से मिलने के लिए निर्धारित समय पर ही स्वजन को मिलने देना चाहिए। इस दौरान प्रत्येक वार्ड के गेट के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए। और अस्पताल के वार्ड में प्रवेश करने से पहले हर व्यक्ति से पूछताछ व हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से जांच करनी चाहिए। तभी बड़े निजी अस्पतालों की तरह सरकारी अस्पतालों में भी सुरक्षा बेहतर हो पाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा एक निश्चित समय के अंतराल पर अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी जरूरी है। इसके अलावा नियमित तौर पर निजी सुरक्षा गार्डों के साथ मिलकर माकड्रिल हो, ताकि निजी सुरक्षा गार्ड बेहतर तरीके से ड्यूटी निभा सकें।

-रणविजय सिंह से बातचीत पर आधारित

अस्पतालों में मारपीट

14 जुलाई 2024 : जीटीबी अस्पताल के वार्ड में घुसकर मरीज को मारी गई गोली।

10 जून 2024 : जीटीबी अस्पताल में प्रसव के बाद एक महिला की मौत के बाद 50-60 लोगों की भीड़ ने डाक्टरों पर हमला कर दिया था।

15 अगस्त 2023 : हिंदू राव अस्पताल में अस्पताल के ही कर्मचारियों ने एक डाक्टर की पिटाई कर दी थी।

17 जुलाई 2023 : अंबेडकर अस्पताल में डाक्टर से मरीज के तीमारदारों ने मारपीट की थी।

05 मार्च 2023 : जहांगीरपुरी स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल में मरीज के तीमारदारों ने डाक्टर के साथ मारपीट की थी।

12 नवंबर 2022 : दीपचंद बंधु अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची महिला मरीज और उसके तीमारदारों ने एक डाक्टर से मारपीट की। डाक्टरों ने उस दौरान एक सप्ताह में इसे मारपीट की तीसरी घटना बताते हुए अस्पताल में हड़ताल कर दी थी।

18 मई 2022 : लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के कलावती सरन अस्पताल में मरीज के तीमारदारों ने एक महिला डाक्टर से मारपीट की थी। इसके बाद रेजिडेंट डाक्टरों ने हड़ताल कर दी थी।

16 फरवरी 2021 : मरीज के तीमारदारों ने सुरक्षा गार्ड व एक डाक्टर के साथ मारपीट की। घटना में एक डाक्टर के सिर में गंभीर चोट आई थी।

29 अगस्त 2019 : सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत होने के बाद तीमारदारों ने दो रेजिडेंट डाक्टरों से मारपीट की थी। इसके बाद रेजिडेंट डाक्टरों ने हड़ताल कर दी थी।

07 जुलाई 2019 : लोकनायक अस्पताल में एक मरीज के तीमारदारों ने डाक्टर की पिटाई की थी।

उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में आपसी सामंजस्य होना चाहिए बेहतर

डा. रोहन कृष्णन
चेयरमैन, फेडरेशन आफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (फाइमा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों में ही है, सब जगह नियमों को ताख पर रखकर अस्पताल चल रहे हैं। दिन-प्रतिदिन सुरक्षा के इंतजाम बढ़ने और मजबूत होने के बजाय कमजोर होते जा रहे हैं। इसका खामियाजा मरीजों से लेकर चिकित्सकों तक को अपने ऊपर हमले के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इंटरनेट मीडिया के जमाने में तो आजकल घटना का वीडियो भी कुछ मिनटों में ही देशभर में प्रसारित हो जाता है। ऐसे मामलों की सूचना बाहर आने पर अस्पताल प्रशासन से लेकर दिल्ली सरकार तक के अधिकारियों की बदनामी होती है। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था व सुविधाओं की कमी में सुधार के लिए निष्कर्षहीन बैठकें सरकार और अस्पताल प्रशासन के बीच होती हैं।

मेरा मानना है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण अस्पताल प्रशासन में मौजूद चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) या चिकित्सा निदेशक (एमडी) के स्तर पर। दूसरा कारण दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच सामंजस्य नहीं है। अस्पताल प्रशासन के स्तर पर यह है कि राजधानी में बीते कई वर्षों से प्रशासनिक स्तर पर भर्तियां नहीं की गई हैं। एक चिकित्सक को किसी प्रमुख अस्पताल में एसएस या एसडी के पद पर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद उसी चिकित्सक को दो से तीन अन्य अस्पतालों के एसएस या एमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया जाता है। ऐसे में उन्हें अपने मुख्य अस्पताल की मूलभूत जानकारियों का तो पता रहता है। लेकिन एक साथ तीन-चार अस्पतालों की प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलने पर प्रत्येक अस्पताल में मौजूद मूलभूत सुविधाओं, जानकारियों, खामियों, वार्ड, कर्मचारियों की संख्या व अन्य कामकाज पर उचित ढंग से ध्यान नहीं दे पाते हैं।

इसके अलावा लापरवाही के लिए जिम्मेदार दिल्ली सरकार भी है। दिल्ली सरकार का नियंत्रण इतना भी कम नहीं होता है, जितना वे बताती है। दिल्ली सरकार के मंत्री चाहें तो अस्पतालों का समय-समय पर निरीक्षण कर सकते हैं, कमियों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। लापरवाही के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित कर सकते हैं या उपराज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, मैं यह मानता हूं कि एलजी उस सिफारिश पर काम कर भी सकते हैं या नहीं भी। पूरा निर्णय एलजी के हाथ में होता है। चूंकि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच राजनीतिक मतभेद चलते रहते हैं, ऐसे में फाइलों के निपटारे में देरी होती ही है। यदि एलजी के स्तर पर दिल्ली सरकार को किसी मामले की फाइल भेजनी है तो अवश्य भेजें। ऐसा नहीं कि एलजी ने कुछ फाइलें किसी कारणवश रोक दी हैं, तो अन्य मामलों की संस्तुति ही नहीं की जाए। आपसी मतभेद को दूर रखकर, जनता व चिकित्सकों की भलाई के लिए दोनों ओर से खुलकर बात करने की आवश्यकता होती है।

राजधानी के सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई का मुख्य कारण यह भी है कि कोई भी चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा निदेशक उचित समय पर कार्रवाई नहीं करता है। यदि उन्हें लगता है कि उनके अस्पताल (जैसे दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी, मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी, दरियागंज स्थित लोक नायक अस्पताल) अपराध क्षेत्र में स्थित हैं, तो नजदीकी थाने से संपर्क रखें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। यह अस्पताल के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वह अपराध क्षेत्र में रहने वाली स्थानीय भीड़ से मरीजों, चिकित्सकों व कर्मचारियों की सुरक्षा करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अस्पताल की ओर से किसी भी मरीज के उपचार में लापरवाही न बरती जाए। सबको अपने स्तर से मरीजों व चिकित्सकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। चिकित्सकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। बीते दिनों पांच दिन के अंतराल में जीटीबी में हुए दो बड़े मामलों को मैं अस्पताल प्रशासन और दिल्ली सरकार की सामूहिक विफलता के रूप में देखता हूं। चिकित्सकों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुरक्षित नहीं रह सकेगा। बड़े मामलों के बाद भी अस्पताल प्रशासन और दिल्ली सरकारी की नींद नहीं टूट रही है, तो यह चिंता का विषय है। केवल आश्वासन देने से कुछ नहीं होता है, धरातल पर कार्यवाही होनी चाहिए।

-निखिल पाठक से बातचीत पर आधारित

सुरक्षा की सेहत खराब

दिल्ली की बड़ी आबादी की निर्भरता सरकारी अस्पतालों पर है, लेकिन वहां सुरक्षा के इंतजाम एकदम चौपट हैं। या तो कहीं सुरक्षा को लेकर सतर्कता ही नहीं है या कुछ अस्पतालों के हालात ऐसे हैं कि मरीज गार्डों की 'गुंडई' से परेशान रहते हैं। एनसीआर के अस्पतालों की हालत ये है वहां ओपीडी में मरीज तो दो हजार तक आते हैं, साथ में तीमारदार भी होते हैं लेकिन सुरक्षाकर्मी 30 भी नहीं होते। सभी अस्पतालों में असंतुलन है।

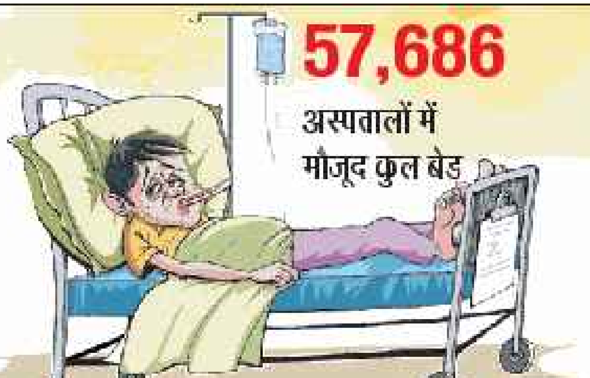

57,686 अस्पतालों में मौजूद कुल बेड

दिल्ली के प्रमुख पांच अस्पताल

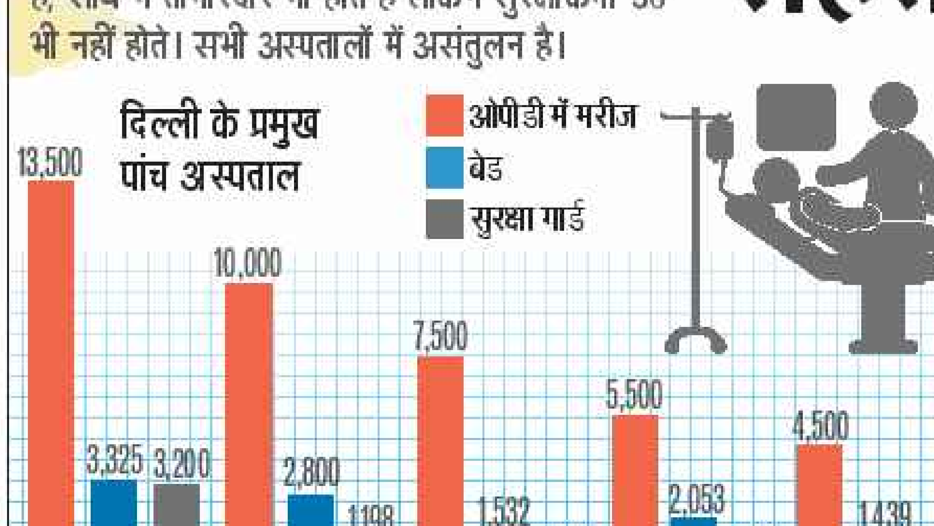

नोट : इन अस्पतालों में पुलिस चौकी है, लेकिन अस्पताल की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी तैनात नहीं रहते। पुलिस का दायित्व आपराधिक घटनाएं होने पर कार्रवाई करने तक ही सीमित है।

113 दिल्ली में अस्पताल

40 दिल्ली सरकार के अधीन

25 केंद्र सरकार के अधीन

47 नगर निगम **2** एनडीएमसी के अधीन

14,244 दिल्ली सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध बेड

13,172 केंद्र सरकार के अस्पतालों में उपलब्ध बेड

3,372 नगर निगम के अस्पतालों में उपलब्ध बेड

गाजियाबाद में अस्पतालों की स्थिति

10 राज्य सरकार **4** केंद्र सरकार

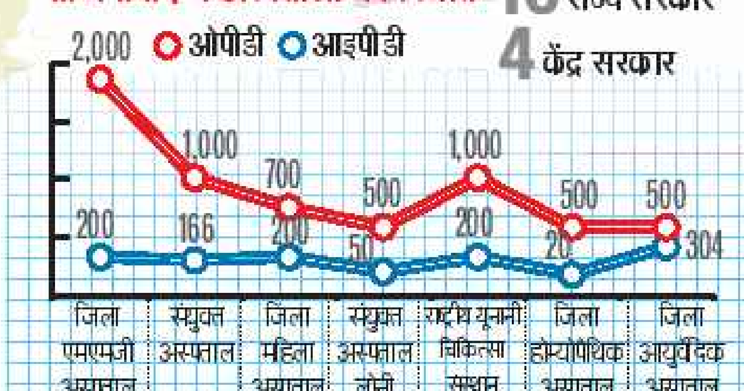

	जिला एमएमजी अस्पताल	संयुक्त अस्पताल	जिला महिला अस्पताल	संयुक्त अस्पताल लोनी	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान	जिला होम्योपैथिक अस्पताल	जिला आयुर्वेदिक अस्पताल
सुरक्षा कर्मी	10	10	10	5	40	3	4

फरीदाबाद में अस्पतालों की संख्या

3 राज्य सरकार द्वारा संचालित **1** ईएसआइ कारपोरेशन, दिल्ली

अस्पताल	ओपीडी	आइपीडी	सुरक्षा कर्मी
जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल	2,500	250	20
तीन नंबर ईएसआइ अस्पताल	5,000	900	180
सेक्टर-आठ ईएसआइ अस्पताल	500	50	0
बल्लभगढ़ सरकारी अस्पताल	1,500	50	15

नोट : जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सुरक्षा कर्मचारी हैं। तीन नंबर ईएसआइ अस्पताल में पूर्व सैनिक बोर्ड के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल के अलावा कहीं भी स्थायी चौकी नहीं है।

गौतमबुद्ध नगर में एक अस्पताल केंद्र सरकार के अधीन और तीन राज्य सरकार के अधीन

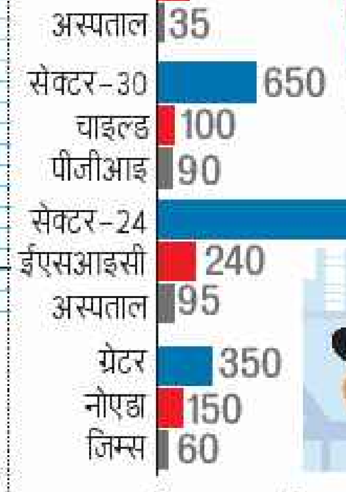

नोट : जिला अस्पताल के अलावा सभी जगह पूर्व सैनिक कल्याण निगम के पास है सुरक्षा का जिम्मा। कहीं भी स्थायी चौकी नहीं।

गुरुग्राम में एक नागरिक और 2 ईएसआइसी अस्पताल

अस्पताल	ओपीडी	आइपीडी	सुरक्षा कर्मी
सेक्टर-10 जिला अस्पताल	2,500	45	31
सेक्टर-31 पालीक्लीनिक	1,000	शून्य	05
सेक्टर-9 ईएसआइसी अस्पताल	2,000	25	29

नोट : जिला अस्पताल में स्थायी चौकी है। ईएसआइसी अस्पताल में सुरक्षा का जिम्मा मिरर टच निजी कंपनी को दिया हुआ है।

जागरण इन्फो

स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत

- गुरुग्राम के सेक्टर 37डी स्थित बीपीटीपी पार्क सिरीन सोसायटी के स्विमिंग पूल में हुई घटना
- पूल के लाइफ गार्ड की लापरवाही से मौत का आरोप, पुलिस ने उसे हिरासत में लिया

संवाद सहयोगी, जागरण • नया गुरुग्राम : सेक्टर 37डी स्थित बीपीटीपी पार्क सिरीन सोसायटी के स्विमिंग पूल में डूबने से पांच वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। आरडब्ल्यूए तथा स्थानीय निवासियों का आरोप है कि स्विमिंग पूल की देखरेख और निगरानी के लिए रखे हुए लाइफ गार्ड की लापरवाही की वजह से घटना हुई है। पुलिस ने मौके से एक लाइफ गार्ड को हिरासत में लिया है।

मिवांश का फाइल फोटो •

बीपीटीपी के टावर जे के फ्लैट नंबर 502 में रहने वाले बिन्नी सिंगला का पांच वर्षीय बेटा मिवांश शाम को स्विमिंग पूल में तैरने के लिए उतरा। आरोप है कि रखरखाव एजेंसी की तरफ से वहां मौजूद लाइफ गार्ड ने ध्यान नहीं दिया। जिसकी लापरवाही से बच्चा डूब गया, बच्चे को सिग्नेचर अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोगों की शिकायत पर पुलिस के पहुंचने के बाद स्थानीय निवासियों ने बिल्डर प्रबंधन और रखरखाव एजेंसी के विरुद्ध कारवाई करने की मांग की है। खबर लिखे जाने तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। हालांकि पुलिस ने लाइफ गार्ड को हिरासत में ले लिया है। बच्चे के पिता बिन्नी सिंगला मारुति कंपनी में कार्यरत हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी आशु देवी और एक बेटा मिवांश सिंगला व एक बेटी रुसदा सिंगला हैं। इनमें से बेटे मिवांश की डूबने से मौत हो गई।

सोसायटी में स्विमिंग पूल के लाइफ गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया •

टीन शेड में चल रहे निगम स्कूल को पक्का करने को याचिका दायर

अधिवक्ता ने कहा, 40 डिग्री से अधिक तापमान में कक्षाओं में बैठे बच्चे पसीने से मिले तर, निगम स्कूलों की हालत बदहाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कोंडली में टीन शेड में चल रहे दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के प्राइमरी कोएड विद्यालय को पक्का करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट ने याचिका दायर कर कहा है कि स्कूल में 754 बच्चे हैं, जो प्री-प्राइमरी से लेकर प्राइमरी कक्षा में पढ़ते हैं। प्रधानाचार्य का कक्ष भी टीन शेड में बना है।

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा कि 20 जुलाई को जब वो स्कूल का दौरा करने गए, तो देखा कि कुछ कक्षाओं में विद्यार्थी दरी पर बैठे हैं। दोपहर 12 बजे के आसपास सभी छात्र 40 डिग्री से अधिक तापमान में घुटन भरी कक्षाओं में बैठे थे और पसीने से तर थे। उन्होंने कहा कि जिन कक्षाओं में मेज थीं, तो वो टूटी हुई थीं।

निगम स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद अधिवक्ता के हवाले से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि निगम स्कूलों की स्थिति खस्ताहाल है। कोई टीन शेड में चल रहा है। कहीं मेज टूटी है, तो कहीं विद्यार्थी दरी में बैठ रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनका प्लास्टर उखड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 17 स्कूलों का निरीक्षण किया। इनमें कुल 7,567 विद्यार्थी पंजीकृत हैं और कुल 137 शिक्षक हैं। कहा, निगम स्कूलों में पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू माध्यम में शिक्षा की सुविधा है। शिक्षकों की कमी के कारण सभी माध्यम के बच्चे एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक से बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं।

केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन

राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, डा संदीप पाठक समेत आप के अन्य सांसदों ने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए की नारेबाजी

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के सांसदों ने ईडी-सीबीआइ से सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराने का आरोप लगाते हुए बुधवार को मोदी सरकार के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान आप के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, डा संदीप पाठक, राघव चड्ढा समेत अन्य सांसदों ने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने केंद्र से सीएम केजरीवाल को तत्काल रिहा करने और ईडी-सीबीआइ का दुरुपयोग बंद करने की मांग की।

संजय सिंह ने कहा कि जेल में अब तक केजरीवाल का शुगर लेवल 36 बार 50 से नीचे आ चुका है। ऐसे में व्यक्ति कोमा में जा सकता है। मोदी सरकार उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन केंद्र के इशारे पर ईडी ने हाई कोर्ट से उस पर स्टे ले लिया और फिर सीबीआइ से उनके खिलाफ एक फर्जी केस दर्ज करा दिया गया। इसलिए यह मामला केवल गिरफ्तारी भर का नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल को जेल में जान से मारने की गहरी साजिश का है।

दिल्ली में अपराधों पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपराधों पर भाजपा की केंद्र सरकार और एलजी पर तीखा हमला बोला है। आप ने कहा है कि दिल्ली की कानून-व्यवस्था लगातार चरमराती जा रही है। अपराधियों में दिल्ली पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है और वो खुलेआम सीसीटीवी कैमरे के सामने संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। आप ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने लोगों को सुरक्षा देने के लिए दिल्ली भर में सीसीटीवी लगाए हैं। लेकिन ऐसी कई वीडियो प्रसारित हो रही हैं, जिसमें अपराधी उसके सामने निडर होकर गंभीर अपराध करते देखे जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि अपराधियों को विश्वास है कि वो दिल्ली पुलिस से बचकर आसानी से निकल जाएंगे। दिल्ली पुलिस व कानून-व्यवस्था केंद्र और एलजी के अधीन आता है, लेकिन वो इस कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस बार तो केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस का बजट भी कम कर दिया गया।

****